रूस के युद्ध में भारतीय

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती की खबरों के बीच विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर सख्त संदेश देते हुए रूस से अपनी सेना में भारतीयों की भर्ती न करने के लिए कहा, साथ ही, भारतीयों को रूसी सेना में शामिल होने के प्रस्तावों से दूर रहने को कहते हुए इसे खतरों से भरा बताया है. भारत लंबे समय से इस मामले में रूस से बात कर रहा है. पिछले वर्ष अपने रूस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने व्लादिमीर पुतिन के साथ इस बारे में बातचीत की थी, तो सरकार ने रूसी अधिकारियों के समक्ष भी इस मुद्दे को उठाते हुए भारतीयों की भर्ती न करने की मांग की थी. सीबीआइ ने मानव तस्करी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई कर उन एजेंटों को पकड़ा भी था, जो देश के कई हिस्सों से भारतीयों को नौकरी देने के लालच में रूस ले जा रहे थे.

यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में भारतीय सैनिकों की भर्ती के खिलाफ सरकार का सख्त संदेश बताता है कि इस मुद्दे को रूस के सामने उठाये जाने के बावजूद खतरा अभी टला नहीं है. भारतीय नागरिकों को भी इस मामले में सतर्क रहने की जरूरत है.

पिछले एक वर्ष में कई बार इस बारे में चेतावनी जारी की गयी है तथा यह मुद्दा कई बार संसद में भी उठ चुका है. जुलाई, 2025 में राज्यसभा को विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया था कि 127 भारतीय नागरिकों के रूसी सेना में सेवा देने की सूचना मिली थी. भारत और रूस के बीच उच्च स्तरीय बातचीत के बाद 98 भारतीयों की सेवा समाप्त कर दी गयी. कम से कम 15 भारतीयों के तब यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में फंसने की जानकारी भी दी गयी थी. यह बात भी सामने आई थी कि इन भारतीयों को रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है. पिछले एक वर्ष में कुछ भारतीयों के जहां रूस-यूक्रेन युद्ध में मारे जाने की सूचना मिली है, वहीं जो भारतीय रूस में फंसे हैं, उनके परिजनों की तरफ से बताया गया कि एजेंटों की तरफ से गलत सूचना के आधार पर उन्हें वहां ले जाया गया और युद्ध में शामिल होने के लिए दबाव बनाया गया. भारत की तरफ से यह मुद्दा उठाने के बाद नयी दिल्ली स्थित रूसी दूतावास ने बताया था कि वह अपनी सेना में भारतीयों की भर्ती कतई नहीं करेगा. यह भी बताया गया कि रूस को युद्ध के लिए भारतीयों की जरूरत नहीं है. लेकिन मीडिया रिपोर्ट बताती है कि अब भी कुछ भारतीयों को वहां ले जाया गया है. विदेश मंत्रालय का ताजा बयान बताता है कि रूस की सेना में भारतीयों को शामिल करने वाली एजेंसियां किसी न किसी तरह से सक्रिय हैं.

नया शहरी भारत गढ़ते प्रधानमंत्री मोदी

हरदीप सिंह पुरी
केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री
delhi@prabhatkhabar.in

पाटलिपुत्र और नालंदा जैसे भारत के प्राचीन शहर कभी शहरी सभ्यता की उच्चता के प्रतीक थे. आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय शहर फिर उसी राह पर हैं, आधुनिक लेकिन मानवीय, महत्वाकांक्षी होते हुए भी समावेशी, वैश्विक दृष्टिकोण वाले होते हुए भी जड़ों और मूल्यों से जुड़े हुए. नया शहरी भारत हर दिन बन रहा है-ईंट दर ईंट, ट्रेन दर ट्रेन, घर दर घर. और यह पहले से ही करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रहा है. इस बदलाव को आंकड़ों से समझा जा सकता है. वर्ष 2004 से 2014 के बीच शहरी क्षेत्र में केंद्र सरकार का कुल निवेश करीब 1.57 लाख करोड़ रुपये था, वर्ष 2014 के बाद से यह 16 गुना बढ़कर करीब 28.5 लाख करोड़ रुपये हो गया.

आजादी के दशकों बाद तक भारत के शहर एक उपेक्षित विचार थे. नेहरू की सोवियत शैली की केंद्रीकृत सोच ने हमें शास्त्री भवन और उद्योग भवन जैसे कंक्रीट के विशाल भवन दिये, जो 1990 के दशक तक ही ढहने लगे थे. एक्सप्रेस-वे बहुत कम थे, मेट्रो कुछ ही शहरों तक सीमित थी और बुनियादी ढांचा तेजी से टूट-फूट का शिकार हो रहा था. देश की राजधानी उपेक्षा और बदहाल स्थिति का प्रतीक बन चुकी थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात को बदल दिया. उन्होंने शहरों को विकास के इंजन और राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक बनाया. यह बदलाव आज हर जगह दिखाई देता है. सेंट्रल विस्टा के पुनर्निर्माण ने कर्तव्य पथ को जनता की जगह बना दिया, नयी संसद को भविष्य के अनुरूप संस्थान में बदल दिया और कर्तव्य भवन को सुचारु प्रशासनिक केंद्र बना दिया.

इस बदलाव को आंकड़ों से समझा जा सकता है. वर्ष 2004 से 2014 के बीच शहरी क्षेत्र में केंद्र सरकार का कुल निवेश करीब 1.57 लाख करोड़ रुपये था, वर्ष 2014 के बाद से यह 16 गुना बढ़कर करीब 28.5 लाख करोड़ रुपये हो गया. वर्ष 2025–26 के बजट में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय को 96,777 करोड़ रुपये दिये गये, जिसमें एक-तिहाई हिस्सा मेट्रो के लिए और एक-चौथाई आवास के लिए रखा गया. वर्ष 2014 में भारत में सिर्फ पांच शहरों में करीब 248 किलोमीटर मेट्रो लाइन चल रही थी. आज यह बढ़कर 23 से अधिक शहरों में 1,000 किलोमीटर से ज्यादा हो गयी है, जो हर दिन एक करोड़ से अधिक यात्रियों को ढोती है. पुणे, नागपुर, सूरत और आगरा जैसे शहरों में नये कॉरिडोर बन रहे हैं, जिससे सफर तेज, सुरक्षित और प्रदूषण-रहित हो रहा है.

शहरी कनेक्टिविटी की तस्वीर बदल गयी है. एनसीआर के जाम से भरे इलाकों को नयी बनी यूइआर-दो (दिल्ली की तीसरी रिंग रोड) से राहत मिल रही है, जो एनएच-44, एनएच-9 और द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़कर पुराने जाम के बिंदुओं को आसान बना रही है. भारत की पहली क्षेत्रीय तेज यातायात प्रणाली-दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस (नमो भारत)-पहले ही बड़े हिस्से पर चल रही है और पूरा संचालन जल्द ही शुरू होने वाला है, जिससे पूरा सफर एक घंटे से कम समय में तय होगा. ये तेज और एकीकृत परिवहन प्रणालियां नये भारत के लिए एक नयी महानगरीय सोच को आकार दे रही हैं.

एक्सप्रेस-वे अब शहरों के बीच की आवाजाही का नया चेहरा बन रहे हैं. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे, बेंगलुरु-मैसूरु एक्सप्रेस-वे, दिल्ली- मेरठ एक्सेस-नियंत्रित कॉरिडोर और मुंबई कोस्टल रोड ने दूरी घटा दी है और बड़े वाहनों को शहर की गलियों से बाहर निकालकर हवा साफ की है. मुंबई में देश का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु अब टापू जैसे शहर को मुख्यभूमि से सीधे जोड़ता है. मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है और पश्चिम भारत में विकास का नया केंद्र बनने जा रही है. ऊर्जा सुधार ने शहरी जीवन को और सुविधाजनक बनाया है. पहले जहां रसोई महंगे और अनिश्चित गैस सिलेंडर बुकिंग पर निर्भर थी, अब पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) आम होती जा रही है, जो अधिक सुरक्षित, साफ और सुविधाजनक है. सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन 2014 में सिर्फ 57 क्षेत्रों तक सीमित था, जो अब बढ़कर 300 से अधिक हो गया है. घरेलू पीएनजी कनेक्शन 25 लाख से बढ़कर 1.5 करोड़ से ऊपर पहुंच गये हैं, जबकि हजारों सीएनजी स्टेशन सार्वजनिक परिवहन को और स्वच्छ बना रहे हैं. अब लाखों शहरी घरों में नल घुमाकर ईंधन मिलना हकीकत बन चुका है.

भारत ने अब दुनिया की मेजबानी करने का आत्मविश्वास हासिल कर लिया है. भारत मंडपम ने सफलतापूर्वक जी20 नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया. यशोभूमि अब दुनिया के सबसे बड़े सम्मेलन परिसरों में शामिल है, जहां एक साथ हजारों प्रतिनिधियों का स्वागत किया जा सकता है. इंडिया एनर्जी वीक ने बेंगलुरु, गोवा और नयी दिल्ली में दुनिया की ऊर्जा कंपनियों और विशेषज्ञों को आकर्षित किया, जिससे यह साबित हुआ कि हमारे शहर बड़े पैमाने पर और बेहतरीन ढंग से दुनिया की मेजबानी कर सकते हैं. परिवहन का आधुनिकीकरण बड़े पैमाने पर और तेजी से हो रहा है. वर्ष 2014 में जहां सिर्फ 74 हवाई अड्डे चालू थे, आज वह संख्या बढ़कर लगभग 160 हो गयी है. यह संभव हुआ है उड़ान योजना और लगातार निवेश की वजह से. वंदे भारत ट्रेनें अब 140 से अधिक रूटों पर चल रही हैं, जिससे अलग-अलग क्षेत्रों में यात्रा का समय काफी घटा है. अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जा रहा है, जिनमें से सौ से ज्यादा का उद्घाटन हो चुका है. दिल्ली में विस्तारित टर्मिनल-1 ने आईजीआई हवाई अड्डे की क्षमता 10 करोड़ यात्रियों से अधिक कर दी है, जिससे हमारी राजधानी दुनिया के बड़े हवाई केंद्रों की सूची में शामिल हो गयी है.

मैंने लंबे समय तक एक राजनयिक के रूप में विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है. वहां मैंने देखा कि कैसे शहर किसी देश का चेहरा बन जाते हैं. वियना की रिंगस्ट्रासे, न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतें या पेरिस की चौड़ी सड़कें-ये सब राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा का प्रतीक थीं. तब मुझे समझ में आया कि दुनिया की नजरें सबसे पहले किसी देश के शहरों पर जाती हैं. यही विश्वास मेरे शहरी कार्य मंत्रालय के काम का आधार बना कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और हमारे दूसरे शहर एक उभरते भारत का आत्मविश्वास, आधुनिकता और आकांक्षाएं दिखायें. जैसे मेरे राजनयिक करियर ने मुझे सिखाया कि भारत की छवि दुनिया में कैसे प्रस्तुत करनी है, वैसे ही मंत्री के रूप में मेरा काम रहा है कि हमारे शहर उस छवि के लायक बनें. यह है बदलाव की यात्रा. शास्त्री भवन की जर्जरता से कर्तव्य भवन की महत्वाकांक्षा तक. गड्ढों वाली सड़कों से एक्सप्रेस-वे और हाई-स्पीड कॉरिडोर तक. धुएं से भरे रसोईघरों से पाइप्ड नेचुरल गैस तक. झुग्गियों से लाखों पक्के घरों तक. टूटे-फूटे हॉल से विश्वस्तरीय सम्मेलन केंद्रों तक.

पाटलिपुत्र और नालंदा जैसे भारत के प्राचीन शहर कभी शहरी सभ्यता की उच्चता के प्रतीक थे. आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय शहर फिर उसी राह पर हैं, आधुनिक लेकिन मानवीय, महत्वाकांक्षी होते हुए भी समावेशी, वैश्विक दृष्टिकोण वाले होते हुए भी जड़ों और मूल्यों से जुड़े हुए. नया शहरी भारत हर दिन बन रहा है-ईंट दर ईंट, ट्रेन दर ट्रेन, घर दर घर. और यह पहले से ही करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रहा है.

भविष्य की ओर बढ़ती भारत-मॉरीशस साझेदारी

आनंद कुमार
एसोसिएट फेलो, एमपी-आइडीएसए
anandkmrai@gmail.com

मॉरीशस के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जो दोनों की बहुआयामी साझेदारी को दर्शाते हैं. यह आपसी रिश्ता केवल सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जुड़ाव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सशक्त आर्थिक, रणनीतिक और भू-राजनीतिक साझेदारी में बदल चुका है.

भारत और मॉरीशस ने फिर अपने संबंधों की मजबूती और रणनीतिक गहराई को साबित किया है. मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम की भारत यात्रा ने दिखाया कि यह रिश्ता केवल सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जुड़ाव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सशक्त आर्थिक, रणनीतिक और भू-राजनीतिक साझेदारी में बदल चुका है. जब हिंद महासागर क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है, तब दोनों प्रधानमंत्रियों की मुलाकात ने स्पष्ट किया कि भारत क्षेत्रीय संतुलन बनाये रखने और अपने करीबी साझेदारों के विकास को समर्थन देने के लिए दृढ़ संकल्पित है.

दोनों देशों के बीच संबंध केवल राजनीति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सदियों पुरानी सभ्यतागत कड़ियों से जुड़े हैं. मॉरीशस में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं और यह साझा सांस्कृतिक धरोहर दोनों को गहरे विश्वास और आत्मीयता से जोड़ती है. प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना कि 'भारत और मॉरीशस सिर्फ साझेदार नहीं, बल्कि परिवार हैं' इसी स्नेह और विश्वास को अभिव्यक्त करता है. भारत ने मॉरीशस को 680 मिलियन डॉलर का विशाल आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की, जिसमें 25 मिलियन डॉलर की बजटीय सहायता भी शामिल है. यह पैकेज अनुदान और ऋण, दोनों के रूप में कई परियोजनाओं को गति देगा. इन योजनाओं में पोर्ट लुईस बंदरगाह का पुनर्विकास, चागोस समुद्री संरक्षित क्षेत्र का विकास और निगरानी, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण और राष्ट्रीय राजमार्गों व रिंग रोड का विस्तार शामिल है. ये परियोजनाएं केवल बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं हैं, बल्कि मॉरीशस की समुद्री क्षमता को मजबूत करेंगी, उसकी कनेक्टिविटी बढ़ायेंगी और आर्थिक विकास को नयी दिशा देंगी. हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा और समुद्री मार्गों के नियंत्रण की बढ़ती अहमियत को देखते हुए ये कदम भारत के रणनीतिक हितों को सुदृढ़ करेंगे. यात्रा का सबसे अहम पहलू चागोस द्वीपसमूह पर दिया गया जोर था. हाल ही में मॉरीशस ने ब्रिटेन के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किये हैं, जिसने चागोस द्वीपों पर उसकी संप्रभुता को मान्यता दी है, हालांकि डिएगो गार्सिया सैन्य अड्डा ब्रिटेन और अमेरिका के पास रहेगा. भारत ने लंबे समय से मॉरीशस के दावे का समर्थन किया है. चागोस समुद्री क्षेत्र के विकास और निगरानी में भारत की मदद न केवल मॉरीशस की संप्रभुता को मजबूत करती है, बल्कि हिंद महासागर को मुक्त, सुरक्षित और स्थिर बनाये रखने की भारत की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है. प्रधानमंत्री रामगुलाम का यह कहना कि वह चागोस द्वीप की यात्रा भारतीय पोत से करना चाहेंगे, इस गहरे विश्वास और रणनीतिक समझ को स्पष्ट करता है.

भारत-मॉरीशस के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जो दोनों देशों की बहुआयामी साझेदारी को दर्शाते हैं. मॉरीशस के विशेष आर्थिक क्षेत्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वे और नौवहन चार्टिंग में भारत सहयोग करेगा, जिससे कि मॉरीशस अपने समुद्री संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सके. ऊर्जा और बिजली क्षेत्र में 17.5 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित करने और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में उपग्रह नेविगेशन व रिमोट सेंसिंग सहयोग पर भी सहमति बनी है. भारत ने मॉरीशस में पहला जनऔषधि केंद्र खोलने की घोषणा की, ताकि सस्ती दवाएं उपलब्ध करायी जा सके. मॉरीशस हिंद महासागर में भारत की सुरक्षा नीति का अहम अंग है. इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति और बंदरगाह परियोजनाओं को देखते हुए भारत के लिए आवश्यक है कि वह मॉरीशस के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाए. मोदी ने हिंद महासागर को 'मुक्त, सुरक्षित और स्थिर' रखने की बात दोहराते हुए यह स्पष्ट किया कि भारत इस क्षेत्र में पहला मददगार और सुरक्षा प्रदाता बनने के लिए तैयार है.

दोनों देशों के बीच 2021 में व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता हुआ था, जो भारत का किसी अफ्रीकी देश के साथ पहला व्यापारिक समझौता है. वर्ष 2000 से 2025 के बीच भारत में एफडीआइ का करीब एक चौथाई हिस्सा मॉरीशस से आया. बदले में भारत मॉरीशस को पेट्रोलियम, दवाएं, अनाज, कपास और समुद्री खाद्य निर्यात करता है, जबकि मॉरीशस से वनीला, चिकित्सा उपकरण, एल्यूमीनियम मिश्र धातु और परिष्कृत तांबा आयात करता है. हालांकि आपसी रिश्तों में चुनौतियां भी हैं. मॉरीशस की भारतीय सहायता पर निर्भरता उसे अपने साझेदारों में विविधता लाने के लिए प्रेरित कर सकती है. चीन की बढ़ती निवेश गतिविधियां भारत के लिए प्रतिस्पर्धा पैदा करती हैं. समुद्री डकैती, नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध मछली पकड़ने जैसी समुद्री सुरक्षा चुनौतियां भी बनी हुई हैं. इनके बावजूद भारत–मॉरीशस संबंधों की दिशा सकारात्मक है. कोविड-19 महामारी, 2020 के वकासियो तेल रिसाव और 2024 के चक्रवात चिदो के दौरान भारत ने लगातार मदद कर अपनी विश्वसनीयता साबित की है. मॉरीशस भी भारत की 'पड़ोस प्रथम' नीति और क्षेत्रीय पहलों का महत्वपूर्ण हिस्सा है. दोनों देशों के बीच गहरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक निकटता भविष्य में इस साझेदारी को और मजबूत आधार प्रदान करती है.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

देश दुनिया

वैश्विक मंच पर अपनी पकड़ को लगातार मजबूत कर रहा है कतर

कतर में वंशानुगत राजतंत्र है. इसके बावजूद वह मध्य पूर्व की कूटनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. अपनी सॉफ्ट पावर, यानी कूटनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर यह वैश्विक मंच पर भी अपनी पकड़ को लगातार मजबूत कर रहा है. कभी मोती निकालकर अपनी अर्थव्यवस्था चलाने वाला एक गरीब देश, आज तेल से कमाई करने वाला अमीर देश बन गया है. कतर के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गैस भंडार है. ईंधन निर्यात से होने वाली जबरदस्त कमाई ने कतर के सामाजिक और बुनियादी ढांचे में एक बड़ा बदलाव ला दिया है. हालांकि, कतर अब केवल जीवाश्म ईंधन पर ही निर्भर नहीं रहना चाहता है. दुनिया में ग्रीन एनर्जी के बढ़ते इस्तेमाल के साथ कतर ने भी अपनी रणनीति बदली है. अब वह विनिर्माण, निर्माण, वित्त और पर्यटन जैसे दूसरे क्षेत्रों में भी ज्यादा निवेश कर रहा है. कतर ने खुद की पहचान वैश्विक संघर्षों के मध्यस्थ के तौर पर भी स्थापित कर ली है. उसे एक तटस्थ देश माना जाता है. अपनी आर्थिक ताकत और अलग-अलग देशों के साथ अच्छे संबंधों के कारण, उसकी तुलना स्विट्जरलैंड से की जाती है. कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में अमेरिका और कतर के बीच अच्छे संबंध रहे हैं. मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा कतर में ही है. कतर ने हाल ही में चल रहे इस्राइल-हमास संघर्ष में महत्वपूर्ण राजनयिक मध्यस्थ की भूमिका निभायी है. इसे रूस-यूक्रेन वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए एक संभावित पुल के रूप में भी देखा जा रहा है. कतर ने पहले भी अपने पड़ोसी खाड़ी देशों को नाराज किया है, क्योंकि उसने ईरान और दूसरे इस्लामी समूहों के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की थी. इन सबके बीच, संघर्षों को सुलझाने में इसका रिकॉर्ड लगातार बेहतर हो रहा है. यहां तक कि अफ्रीका में भी यह एक वैश्विक 'शांति साझेदार' के तौर पर अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है.

-मैथ्यू वार्ड आगीयूस

बोधि वृक्ष

युवा शक्ति को प्रोत्साहन

इस बात में कोई दो राय नहीं है कि समाज एवं राष्ट्र के नवनिर्माण में सदा से ही युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है. प्राचीन काल से लेकर आज तक युवाओं के योगदान से ही न सिर्फ समाज में समय-समय पर सकारात्मक बदलाव आते रहे हैं, अपितु राष्ट्र को भी नयी दिशा मिलती रही है. परंतु वर्तमान में देखा जा रहा है कि जिस युवा पीढ़ी के सामने देश का भविष्य संवारने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, उसकी ऊर्जा रचनात्मक कार्यों में लगने के बजाय विध्वंसकारी गतिविधियों में खर्च हो रही है. कुछ वर्ष पूर्व तक देश की युवा पीढ़ी को ऊर्जावान, विचारशील, कल्पनाशील एवं जुझारू माना जाता था और उसके इन्हीं गुणों के आधार पर उम्मीद की जाती थी कि वह समझदार निर्णय लेने वाली, सक्षम प्रतिस्पर्धा में टिकने वाली और सकारात्मक दृष्टिकोण वाली होगी. परंतु, दुर्भाग्यवश आज की युवा पीढ़ी उम्मीदों के विपरीत निराश, कुंठाग्रस्त एवं आक्रोश की भावना से भरी, अपने भविष्य के प्रति आशंकित एवं अनिश्चित नजर आ रही है. ये सभी मनोभाव बड़ी आसानी से हम किसी भी युवा के चेहरे पर आज पढ़ सकते हैं. पहले समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक युवा तत्पर रहता था, परंतु आज क्या हाल है? आज के युवा को तो समाज को बदलने के बजाय स्वयं बदल जाना ज्यादा रुचिकर लगने लगा है. उसके लिए उच्च आदर्श एवं नैतिकता सिर्फ किताबी बातें बनकर रह गयी हैं और इसी वजह से उसने भौतिक मूल्यों के सामने जीवन मूल्यों को पूरी तरह से भुला दिया है. आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में हर युवक एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ में अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से विमुख होता जा रहा है. जो राष्ट्र अपने युवाओं को अनुशासनहीनता और हिंसा के पथ पर चलने की अनुमति देता है, वह अनजाने में ही खुद को निकट भविष्य में अराजकता की स्थिति में धकेल देता है. इसीलिए बेहतर यही होगा कि हम अपने युवाओं को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखें और उनके अंदर छुपी हुई अनेक विशेषताओं को सकारात्मक प्रोत्साहन देकर उन्हें हौसला दें और उनका आत्मविश्वास बढ़ायें.

-ब्रह्माकुमार निकुंज जी

प्रबंध सूत्र

जो करना हो, हैसियत देख कर करें

आलोक पुराणिक
स्तंभकार
puranika@gmail.com

आपने क्या किया, इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर है कि आप कौन हैं. व्यक्तियों से लेकर देशों तक के मामले में यह बात लागू होती है. इस्राइल ने अमेरिका के सहयोगी देश कतर में घुस कर कुछ आतंकियों के ठिकाने उड़ा दिये. कतर ने चूं-चूं की, अमेरिका ने कहा, कोई बात नहीं, अब आगे नहीं होगा. उधर इस्राइल ने कहा कि फिर मारेंगे, अगर आतंकी कतर में हुए तो. इस्राइल के प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र में बोलते हुए कहा जिस तरह से अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ओसामा बिन लादेन को मारा था, वैसे ही हमने किसी दूसरे देश में जाकर आतंकी को मारा है. लादेन के मारे जाने पर सबने खुशी मनायी थी, पर इस्राइल की निंदा की जा रही है.

तारीफ और निंदा काम की नहीं, हैसियत की होती है. इस्राइल की हैसियत अभी अमेरिका वाली नहीं है, तो उसकी निंदा हो रही है. विकट पाखंड है सब तरफ. रिश्तेदारियों में देख सकते हैं कि किसी कुटुंब में कोई फूफा जी या चाचा जी बहुत भ्रष्ट अमीर होते हैं. सब पीठ पीछे बुराई करते हैं कि देखो फूफा जी कितने भ्रष्ट हैं, पर हर बंदा फूफा जी को अपने उत्सव आयोजनों में बुलाता है और उनकी खुशामद करता है. यही दुनिया का हाल है. पाकिस्तान को भीख अमेरिका दिलवाता है, तो अमेरिका की बुराई कभी ना कर सकता पाकिस्तान, पर इस्राइल कुछ भी देने की स्थिति में नहीं है.

भूलकर भी अपने बॉस या किसी असरदार रिश्तेदार को फॉलो मत कीजिए. असरदार रिश्तेदार से सलूक अलग होता है. करोड़पति फूफा जी शराब पीते हैं, तो कहा जाता है कि बड़ा कारोबार है, इतने तनाव में हैं, थोड़ी-सी ले लेते हैं, क्या बुराई है. कोई चपरासी रिश्तेदार शराब पिए, तो कहा जाता है कि बताओ, कैसी दारूबाजी करता है. हैसियत के मुताबिक ही लोग भलाई-बुराई करते हैं. तो जो भी करना हो, अपनी हैसियत देखकर करना चाहिए. दूसरों की ताकत के सहारे किसी से लड़ाई मोल नहीं लेनी चाहिए. दुर्गति हो जाती है. यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जैसी.

किसी और के बर्ताव को देखकर अपना बर्ताव नहीं बदल लेना चाहिए. अपनी ताकत, हैसियत का आकलन कर लेना चाहिए. अधिकांश लोगों को अपनी हैसियत के बारे में गलतफहमी होती है. इस चक्कर में गहरा नुकसान उठाते हैं. जेलेंस्की इस बात के उदाहरण हैं. ट्रंप भी इस बात के उदाहरण हैं. उनके बड़बोले बयान थे कि राष्ट्रपति बनते ही वह तमाम युद्ध बंद करवा देंगे. अब कोई युद्ध बंद नहीं करवा पा रहे वह. कोई नहीं सुन रहा है ट्रंप को. ऐसी गति हर उस व्यक्ति और देश की होती है, जिसे अपनी हैसियत का सही अंदाज ना होता.

आपके पत्र

बच्चों में बढ़ता मोटापा चिंताजनक

कुपोषण शब्द का इस्तेमाल पहले वैसे बच्चों के लिए किया जाता था, जिन्हें भरपेट पौष्टिक भोजन नहीं मिलता था और जिसके चलते उनका वजन बढ़ने के बजाय घटता चला जाता था, मगर अब कुपोषण शब्द को मोटापा महामारी भी कहा जाने लगा है. यूनिसेफ की ताजा रिपोर्ट की मानें, तो आज 18.8 करोड़ स्कूली बच्चे और किशोर मोटापे से ग्रस्त हैं. यह स्थिति चिंताजनक है. हमें बच्चों के आहार में अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की जगह पौष्टिक चीजों को शामिल करना चाहिए.

जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

एक देश, एक शिक्षा बोर्ड की जरूरत

देश में अभी साठ से अधिक स्कूली बोर्ड हैं. सभी बोर्ड के अलग-अलग पाठ्यक्रम हैं. उनकी मूल्यांकन पद्धति भी अलग-अलग है तथा परीक्षा का समय भी अलग अलग है. अलग-अलग बोर्ड में विद्यार्थियों के प्राप्तांक में भिन्नता पायी जाती है. कोई बोर्ड नंबर देने में उदार होता है, तो कोई बोर्ड कठोर हो है. इन भिन्नताओं की वजह से राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षाओं में विद्यार्थियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है. छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए एक देश, एक शिक्षा बोर्ड के सिद्धांत को लागू करना चाहिए.

हिमांशु शेखर, गयाजी

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001 ■ **फैक्स करें :** 0651-2544006 ■ **मेल करें :** eletter@prabhatkhabar.in पर ■ ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है.

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

कटु अतीत से आगे निकलता मणिपुर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मणिपुर यात्रा बहुप्रतीक्षित थी। दो साल से ज्यादा वक्त से यह राज्य अशांत है। छिटपुट हिंसा का दौर अब भी जारी है। पीएम के दौरे और विकास परियोजनाओं के ऐलान से शांति व स्थायित्व बहाल करने में मदद मिल सकती है। मणिपुर का मौजूदा संकट मार्च 2023 में वहां के हाईकोर्ट के उस आदेश से शुरू हुआ था, जिसमें राज्य सरकार से मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने पर जल्द विचार करने को कहा गया था। इसके कुछ दिनों बाद ही कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जातीय हिंसा भड़क उठी। इसमें 250 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और हजारों विस्थापितों की तरह रहने को मजबूर हैं। इस संघर्ष ने राज्य की दो प्रमुख जनजातियों के बीच अविश्वास को और गहरा कर दिया है। मामले की जटिलता यह है कि कुकी और मैतेई ही नहीं, कई दूसरी जनजातियां भी हैं, जिनको वार्ता का हिस्सा बनाए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। उम्मीद की जा सकती है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस दिशा में ठोस पहल होगी। पीएम मोदी राजधानी इंफाल के साथ चुराचांदपुर भी गए । हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में चुराचांदपुर है। वहां पीड़ित परिवारों की महिलाओं से बात की। उनके आंसू पोछे। उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं आपके साथ, पूरे मणिपुर के साथ मजबूती से खड़ा हूं। पीएम मोदी के दौरे का ऐलान होने के बाद भी यहां से पुलिस और सुरक्षाबलों के साथ कुछ लोगों की झड़प की खबरें आई थीं। इससे जाहिर होता है कि कुछ अराजक तत्व शांति बहाली की कोशिशों को पटरी से उतारना चाहते हैं।लेकिन पीएम मोदी के दौरे के समय जिस तरह सड़क के किनारे युवा-बच्चे हाथों में तिरंगा लहराते दिखे वह एक नए मणिपुर का दर्शन कराता है , जो मिलजुल कर शांति के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाना चाहता है। राज्य के लोगों को यह भरोसा दिलाने की जरूरत है कि सरकार किसी एक समुदाय या वर्ग के साथ नहीं, पूरे मणिपुर के साथ है और उनकी सामूहिक भलाई के लिए काम कर रही है। दरअसल, निवर्तमान सीएम एन बीरेन सिंह को इसीलिए इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि उन्हें लेकर कुकी समुदाय आश्वस्त नहीं था। यह भी आरोप लगे थे कि उन्होंने हिंसा से निपटने के लिए जरूरी तत्परता नहीं दिखाई। मणिपुर का सामाजिक तानाबाना बहुत नाजुक है। यहां पहले भी कुकी-पाइते और मैतेई-पंगल संघर्ष हो चुका है। केंद्र की एक्ट-ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा होने और म्यांमार से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा के कारण मणिपुर में ज्यादा संवेदनशीलता व सावधानी बरतने की जरूरत है।

हिंदी : राजभाषा, राष्ट्रभाषा और विश्व भाषा

प्रो. संजय द्विवेदी

(अध्यक्ष, जनसंचार विभाग, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल)

एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है, बल्कि हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति और संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचायक भी है। बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है, जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। यह विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है,

देश की स्वतंत्रता से लेकर हिंदी ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत सरकार द्वारा विकास योजनाओं तथा नागरिक सेवाएं प्रदान करने में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। हिंदी तथा प्रांतीय भाषाओं के माध्यम से हम बेहतर जन सुविधाएं लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय द्वारा विश्व हिंदी सम्मेलन और अन्य अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के माध्यम से हिंदी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जिसमें विश्व भर में रहने वाले प्रवासी भारतीय भाग लेते हैं। विदेशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों की उपलब्धियों के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम से भारतीय मूल्यों का विश्व में और अधिक विस्तार हो रहा है। विश्व भर में करोड़ों की संख्या में भारतीय समुदाय के लोग एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं।

जो हमारे पारंपरिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच एक सेतु भी है। हिंदी भारत संघ की राजभाषा होने के साथ ही ग्यारह राज्यों और तीन संघ शासित क्षेत्रों की भी प्रमुख राजभाषा है। संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल अन्य इक्कीस भाषाओं के साथ हिंदी का एक विशेष स्थान है। आज देश में तकनीकी और आर्थिक समृद्धि के साथ-साथ अंग्रेजी पूरे देश पर हावी होती जा रही है। देश की राजभाषा हिंदी होने के बावजूद आज हर जगह अंग्रेजी का वर्चस्व कायम है। हिंदी जानते हुए भी लोग हिंदी में बोलने, पढ़ने या काम करने में हिचकने लगे हैं। इसलिए भारत सरकार का प्रयास है कि हिंदी के प्रचलन के लिए उचित माहौल तैयार किया जा सके। राजभाषा हिंदी के विकास के लिए खासतौर से भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग का गठन किया गया है। भारत सरकार का राजभाषा विभाग इस दिशा में प्रयासरत है कि केंद्र सरकार के अधीन कार्यालयों में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में हो।

केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करना अधिक आसान एवं सुविधाजनक हो गया है। राजभाषा विभाग द्वारा वेब आधारित सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है, जिससे भारत सरकार के सभी कार्यालयों में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट तथा अन-?य रिपोर्ट राजभाषा विभाग को त्वरित गति से भिजवाना आसान हो गया है। सभी मंत्रालयों और विभागों ने अपनी वेबसाइटें हिंदी में भी तैयार कर ली हैं। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा संचालित जन कल्याण की विभिन्न योजनाओं की जानकारी आम नागरिकों को हिंदी में मिलने से गरीब, पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोग भी लाभान्वित होते हुए देश की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं।

हिंदी दिवस पर विशेष

देश की स्वतंत्रता से लेकर हिंदी ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत सरकार द्वारा विकास योजनाओं तथा नागरिक सेवाएं प्रदान करने में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। हिंदी तथा प्रांतीय भाषाओं के माध्यम से हम बेहतर जन सुविधाएं लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय द्वारा विश्व हिंदी सम्मेलन और अन्य अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के माध्यम से हिंदी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जिसमें विश्व भर में रहने वाले प्रवासी भारतीय भाग लेते हैं। विदेशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों की उपलब्धियों के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम से भारतीय मूल्यों का विश्व में और अधिक विस्तार हो रहा है। विश्व भर में करोड़ों की संख्या में भारतीय समुदाय के लोग एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को एक नई पहचान मिली है। भारतीय विचार और संस्कृति का वाहक होने का श्रेय हिंदी को ही जाता है। आज संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं में भी हिंदी की गूंज सुनाई देने लगी है।

हिंदी आम आदमी की भाषा के रूप में देश की एकता का सूत्र है। सभी भारतीय भाषाओं की बड़ी बहन होने के नाते हिंदी विभिन्न भाषाओं के उपयोगी और प्रचलित शब्दों को अपने में समाहित करके सही मायनों में भारत की संपर्क भाषा होने की भूमिका निभा रही है। हिंदी जन-आंदोलनों की भी भाषा रही है। हिंदी के महत्व को गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने बड़े सुंदर रूप में प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था, भारतीय भाषाएं नदियां हैं और हिंदी महानदी। हिंदी के इसी महत्व को देखते हुए तकनीकी कंपनियां इस भाषा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं। यह खुशी की बात है कि सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। आज वैश्वीकरण के दौर में, हिंदी विश्व स्तर पर एक प्रभावशाली भाषा बनकर उभरी है। आज पूरी दुनिया में 260 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा पढ़ाई जा रही है। ज्ञान-विज्ञान की पुस्तकें बड़े पैमाने पर हिंदी में लिखी जा रही हैं। सोशल मीडिया और संचार माध्यमों में हिंदी का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है।

भाषा का विकास उसके साहित्य पर निर्भर करता है। आज के तकनीकी के युग में वि?ज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी हिंदी में काम को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि देश की प्रगति में ग्रामीण जनसंख्या सहित सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसके लिए यह अनिवार्य है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में तकनीकी ज्ञान से संबंधित साहित्य का सरल अनुवाद किया जाए। इसके लिए राजभाषा विभाग ने सरल हिंदी शब्दावली भी तैयार की है। राजभाषा विभाग द्वारा राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन योजना के द्वारा हिंदी में ज्ञान-विज्ञान की पुस्तकों के लेखन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे हमारे विद्यार्थियों को ज्ञान-विज्ञान संबंधी पुस्तकें हिंदी में उपलब्ध होंगी। हिंदी भाषा के माध्यम से शिक्षित युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें, इस दिशा में निरंतर प्रयास भी जरूरी है।

भाषा वही जीवित रहती है, जिसका प्रयोग जनता करती है। भारत में लोगों के बीच संवाद का सबसे बेहतर माध्यम हिंदी है। इसलिए इसको एक-दूसरे में प्रचारित करना चाहिये। हिंदी भाषा के प्रसार से पूरे देश में एकता की भावना और मजबूत होगी।

आत्मालोचना की प्रवृति और हमारा हिन्दी समाज

प्रेमकुमार मणि

(साहित्यकार एवं राजनीतिक चिंतक)

हिन्दी भाषी क्षेत्र के लेखकों-बुद्धिजीवियों की सोच का अलग व्याकरण होता है. एक विशेष प्रकार की उत्तेजना, एक बग्गापन और सपाटता उन के विशेष गुण होते हैं. यदि वह तुलसीदास को पसंद या नापसंद करता है, तो पूरी तरह करता है. वह सोचता ही नहीं कि उन में कुछ खूबियां या खामियां भी हो सकती हैं. ऐसा ही हर किसी के साथ होता है. प्रेमचंद को वह इस तरह पसंद करेगा कि उनके समय से इतना आगे बढ़ जाने पर भी वह उनसे एक कदम आगे जाने की नहीं सोचेगा. प्रदक्षिणा और स्तुति उसके चरित्र के केंद्रीय तत्व होते हैं. विखंडन-विश्लेषण को वह हेय समझता रहा है. इसलिए सम्यक विवेचन उससे शायद ही संभव हो पाता है. अतीतजीवी होना उसकी फितरत में शामिल है. इसीलिए मैं कहता हूँ अपनी चेतना में वह धुर हिन्दू है.

चेतना को हिन्दू कहने का एक विशेष अर्थ है. सनातनी हिन्दू चिंतन परंपरा में मान्यता है कि प्राचीन सुन्दर और श्रेष्ठ था. बाद का समय क्रमशः विघटन का है. चीजें लगातार खराब होती जा रही हैं. हिन्दू पौराणिकता में काल के चार चरण हैं. सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग. सतयुग श्रेष्ठता का प्रतीक है. कृष्णावतार की पूर्णता को यदि अपवाद मान लिया जाय तो त्रेता और द्वापर निरंतर कमतरी के शिकार होते गए और अब कलयुग सारे अवगुणों का जमावड़ा लिए बैठा है. भाषा के स्तर पर वह कहेगा देवताओं की सुसंस्कृत और सुगठित भाषा संस्कृत बिगड़ते-बिगड़ते हिन्दी और अन्य आधुनिक भाषाएं बन गयीं. और तो और देवता बिगड़ते-बिगड़ते कलयुगी आदमी हो गए. उनकी चिन्तन परम्परा विकासवादी नहीं, विघटनवादी है.

आज का हिन्दी बुद्धिजीवी भी ऐसा ही सोचता है. वह जिसे पकड़ लेगा, उसके खूंटा से बंध जाएगा. प्रेमचंद या निराला या उसके पहले जाएं तो कबीर और तुलसी को यदि उसने पकड़ा तो उससे हिलना नहीं चाहेगा. गांधी को पकड़ेगा तब उसकी व्याख्या होगी, बिल्कुल वहीं रुक जाओ. नेहरू ने तो गांधीवाद का सत्यानाश कर दिया. असली गांधीवादी तो विनोबा हैं.

अगर जातक मार्क्सवादी है तो मार्क्स के जमाने में तमाम विचारों को रोक देना चाहेगा. और तो और यदि वह अम्बेडकरवादी या लोहियावादी है तो उन्हें पकड़ कर बैठा रहना चाहेगा. इस प्रदक्षिणा और स्तुति में उसे सुख मिलता है. इसका वह आदि हो चुका है. इस आर्किड़िया में उसे सतयुगी दैवी सुख मिलता है.

बहुत पहले जवाहरलाल नेहरू की नजर हिंदी लेखकों की इस प्रवृत्ति पर पड़ी थी. अपनी आत्मकथा में उन्होंने इसका विस्तार से उल्लेख किया है. एक दफा वह बनारस आए थे जहाँ कुछ हिंदी लेखकों के अनुरोध पर उन्होंने लेखकों की एक छोटी-सी संगोष्ठी को सम्बोधित किया. अपनी आदत से लाचार जवाहरलाल जी ने उन्हें कुछ खरी-खरी सुना दी. जैसे कि हिंदी लेखकों का नजरिया बहुत तंग है और उनमें आत्मालोचना का अभाव है. आदि-आदि. इसे लेकर नेहरू की बहुत आलोचना हुई, ऐसा स्वयं नेहरू ने लिखा है. इसी के आसपास (संभवतः १९३५ में) इंदौर के हिंदी साहित्य सम्मेलन में गांधी ने हिंदी लेखकों से पूछा था, आपके यहाँ रवीन्द्रनाथ टैगोर, जगदीशचंद्र बसु और प्रफुलचन्द्र घोष क्यों नहीं हैं?

हिन्दी लेखकों को यह बात अट-पटी लगी कि गांधी आखिर पूछ क्या रहे हैं. जिस तीन को वह हिन्दी क्षेत्र में ढूंढ़ रहे थे, उनमें दो वैज्ञानिक और एक लेखक था. लेकिन शायद गांधी ने साहित्य की पार्श्व भूमि को जानना चाहा था. हिन्दी क्षेत्र में दो वैज्ञानिक और एक लेखक का अनुपात नहीं होता, यहाँ दो बाबा और एक लेखक का अनुपात चलता है. गाय, गंगा और गीता के त्रिकोण से घिरा हिन्दी का लेखक-बुद्धिजीवी हमेश एक आवेश में होता है. वह सेकुलर खेमे का है तो वह अपनी क्रांतिकारिता और आधुनिकता को लेकर फुनफुन करता होता है और यदि मजहबी हुआ तब तो फुनफुनाना वह अपना जन्मसिद्ध अधिकार ही मानता है.

मुझे चिन्ता होती है तथाकथित प्रोग्रेसिव थिंकर जमात की. ये लोग इतना उग्र और आवेशित क्यों हो जाते हैं. विरोधी या प्रतिपक्ष के विचारों को जानना-समझना लोकतान्त्रिक समाज की पहली पहचान होती है. इसे वह नहीं स्वीकार करते तो गलती पर होते हैं. कोई भी बड़ा से बड़ा विचारक प्रश्नों से परे नहीं होना चाहिए. किसी को भी हमें ईश्वरत्व का दर्जा नहीं दे देना चाहिए. चीजों को तोड़ कर देखने की प्रवृति हम में होनी चाहिए. इससे हम सत्य के अधिक निकट पहुंचते हैं.

अगर जातक मार्क्सवादी है तो मार्क्स के जमाने में तमाम विचारों को रोक देना चाहेगा. और तो और यदि वह अम्बेडकरवादी या लोहियावादी है तो उन्हें पकड़ कर बैठा रहना चाहेगा. इस प्रदक्षिणा और स्तुति में उसे सुख मिलता है. इसका वह आदि हो चुका है. इस आर्किड़िया में उसे सतयुगी दैवी सुख मिलता है. बहुत पहले जवाहरलाल नेहरू की नजर हिंदी लेखकों की इस प्रवृत्ति पर पड़ी थी. अपनी आत्मकथा में उन्होंने इसका विस्तार से उल्लेख किया है. एक दफा वह बनारस आए थे जहाँ कुछ हिंदी लेखकों के अनुरोध पर उन्होंने लेखकों की एक छोटी-सी संगोष्ठी को सम्बोधित किया. अपनी आदत से लाचार जवाहरलाल जी ने उन्हें कुछ खरी-खरी सुना दी. जैसे कि हिंदी लेखकों का नजरिया बहुत तंग है और उनमें आत्मालोचना का अभाव है. आदि-आदि. इसे लेकर नेहरू की बहुत आलोचना हुई, ऐसा स्वयं नेहरू ने लिखा है. इसी के आसपास (संभवतः १९३५ में) इंदौर के हिंदी साहित्य सम्मेलन में गांधी ने हिंदी लेखकों से पूछा था, आपके यहाँ रवीन्द्रनाथ टैगोर, जगदीशचंद्र बसु और प्रफुलचन्द्र घोष क्यों नहीं हैं? हिन्दी लेखकों को यह बात अट-पटी लगी कि गांधी आखिर पूछ क्या रहे हैं. जिस तीन को वह हिन्दी क्षेत्र में ढूंढ़ रहे थे, उनमें दो वैज्ञानिक और एक लेखक था. लेकिन शायद गांधी ने साहित्य की पार्श्व भूमि को जानना चाहा था. हिन्दी क्षेत्र में दो वैज्ञानिक और एक लेखक का अनुपात नहीं होता, यहाँ दो बाबा और एक लेखक का अनुपात चलता है. गाय, गंगा और गीता के त्रिकोण से घिरा हिन्दी का लेखक-बुद्धिजीवी हमेश एक आवेश में होता है. वह सेकुलर खेमे का है तो वह अपनी क्रांतिकारिता और आधुनिकता को लेकर फुनफुन करता होता है और यदि मजहबी हुआ तब तो फुनफुनाना वह अपना जन्मसिद्ध अधिकार ही मानता है.

संपादकीय

"हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है।
- सुमित्रानंदन पंत

प्रधानमंत्री की पूर्वोत्तर के तीन राज्यों की यात्रा के दौरान जो घोषणाएं हुईं, वे महत्वपूर्ण होने के साथ ऐतिहासिक भी हैं। घुसपैठ व विश्वास बहाली की चुनौतियां बेशक हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने शांति के साथ विकास का जो पैगाम दिया है, वह जमीनी स्तर पर दिखे भी, तो यह सबसे बड़ी कामयाबी होगी।

पूर्वोत्तर में मोदी

प्रधानमंत्री मोदी की तीन पूर्वोत्तर राज्यों- मिजोरम, मणिपुर और असम की यात्रा के दौरान जो घोषणाएं हुईं, वे महत्वपूर्ण तो हैं ही, इन्हें ऐतिहासिक भी कहा जाए, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि मई, 2023 में इंफाल घाटी में रहने वाले मैतेई समुदाय और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले कुकी-जो समुदाय के बीच शुरू हुए जातीय संघर्ष में अब तक 260 लोग मारे गए और तकरीबन 60 हजार लोग विस्थापित हुए हैं। करीब दो वर्ष पहले भड़की जातीय हिंसा के बाद राज्य के अपने पहले दौरे में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिया गया शांति का संदेश महत्वपूर्ण है। उनका यह कहना कि मणिपुर ही वह भूमि थी, जहां पहली बार भारतीय राष्ट्रीय सेना ने राष्ट्र ध्वज फहराया था, राज्य के गौरवपूर्ण अतीत और स्वतंत्रता संग्राम में इसकी भूमिका को रेखांकित करता है। राज्य को भारत माता के मुकुट का रत्न बताते हुए कुकी बहुल हिंसा से सर्वाधिक प्रभावित चुराचांदपुर के लिए 7,300 करोड़ रुपये से अधिक और मैतेई बहुल इंफाल के लिए करीब 1,200 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की घोषणा कर प्रधानमंत्री ने पीड़ितों को यह संदेश देने की कोशिश की है कि सरकार और समूचा देश उनके साथ है। राजनीति में कई फैसले रणनीतिक आधारों पर लिए जाते हैं। पिछले दो वर्षों में मणिपुर का मुद्दा देश के भीतर और बाहर जिस तरह से उठाया गया, वह किसी से छिपा नहीं है। यह भी नहीं भूला जा सकता कि किस तरह यूरोपीय संघ की संसद में मणिपुर को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ, जिसे सरकार ने देश का आंतरिक मामला बताते हुए उचित ही खारिज कर दिया था। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मणिपुर में शांति बनी रहे और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे ने जो उम्मीदें जगाई हैं, वे पूरी हों। अपनी मिजोरम यात्रा में प्रधानमंत्री ने आठ हजार करोड़ रुपये ,से भी अधिक की सैरांग-बैरवी रेल लाइन का शुभारंभ किया है, जो इस मायने में ऐतिहासिक है कि यह पहली बार मिजोरम की राजधानी को भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी।

जाहिर है कि इससे मिजोरम के किसान और व्यवसायी देश भर के बाजारों तक आसानी से पहुंच सकेंगे; कई क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेंगे, सो अलग। असम यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य को करीब बारह हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात दी है, जो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को यकीनन सहारा देंगी। कुल मिलाकर देखें, तो प्रधानमंत्री का पूर्वोत्तर दौरा केवल परियोजनाओं तक सीमित नहीं, यह एक दृष्टि का प्रतिबिंब है। म्यांमार से हो रही घुसपैठ समेत विभिन्न समूहों के बीच विश्वास बहाली की चुनौतियां बेशक हैं, लेकिन पूर्वोत्तर में प्रधानमंत्री ने शांति के साथ विकास का जो पैगाम दिया है, वह जमीनी स्तर पर दिखे भी, तो यह सबसे बड़ी कामयाबी होगी।

पखवाड़े से हिंदी को बाहर निकालिए

हिंदी को जब पखवाड़े की मर्यादा से बाहर निकाला जाएगा, तभी वह सही मायने में अपना स्थान ग्रहण कर पाएगी। तभी वह नीतियों की बुनियाद होगी, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय लोक की आत्मा गहरे तक समाहित होगी।

पितरों को समर्पित सनातन परंपरा का श्राद्ध पक्ष हिंदू मान्यता के अनुसार, शुभ कार्यों के लिए वर्जित है। लेकिन संविधान सभा में श्राद्ध पक्ष में भी बहसें हुईं और फैसले भी हुए। वर्ष 1949 में आठ सितंबर से 22 सितंबर के बीच श्राद्ध पक्ष था। इसी पखवाड़े में महज ढाई दिनों की बहस के बाद हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया। लगता है कि शुभ कार्यों के लिए वर्जित श्राद्ध पक्ष में हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने का जो शुभ कार्य हुआ, उस पर अशुभ छाया पड़ गई। वास्तविकता के धरातल पर वैधानिक दर्जे के लिए जूझती हिंदी को देखकर ऐसी सोच विकसित होना स्वाभाविक है।

उमेश चतुर्वेदी
मीडिया एवं राजनीतिक टिप्पणीकार

जिस तरह श्राद्ध पक्ष में हर बार पितरों को याद किया जाता है, उसी तरह हिंदी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। श्राद्ध पक्ष के साथ ही तकरीबन हर साल हिंदी पखवाड़ा आता है। हिंदी को लेकर सरकारी दफ्तरों में नव उत्साह का संचार हो जाता है। वाद-विवाद, टाइपिंग, निबंध लेखन, आशु लेखन, भाषण आदि की प्रतियोगिताओं के चलते सरकारी दफ्तर हिंदीयाना रौनक से भर जाते हैं। कुछ लोगों को पुरस्कार मिलता है और कार्यालय के हर व्यक्ति के लिए चाय-नाश्ते का इंतजाम हो जाता है। इस तरह पखवाड़े भर तक हिंदी का एक तरह से तर्पण होता है और फिर दफ्तरी दुनिया अपने पुराने ढर्रे पर फिर से लौट आती है, जिसकी कल्पना 1835 में मैकाले ने की थी।

हिंदी का भविष्य कैसा होगा, इसे समझने के लिए 14-15 अगस्त, 1947 की दरम्यानी रात को हुए कार्यक्रम को देखना होगा। 'ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी' भाषण ने ही तय कर दिया कि भारत में हिंदी का भविष्य क्या होने वाला है। तर्क हो सकता है कि नेहरू का मशहूर भाषण अंग्रेजी में इसलिए हुआ, क्योंकि दुनिया को बताना था कि हजार साल से चली आ रही गुलामी की बेड़ियों को भारत ने काट डाला है। यह ठीक है कि तब दुनिया की निगाह भारत पर थी, लेकिन दुनिया हिंदी में दिए भाषण का अनुवाद करा सकती थी। नियति के साथ समझौते का सीधा प्रभाव भारत और भारतीयों पर पड़ना था, दुनिया पर नहीं। बेशक नियति के साथ भारत के समझौते की विलायती परत को भारतीय रंग देने की कोशिश अगले दिन गांधी ने जरूर की, जब उन्होंने एक विदेशी संवाददाता को भाषा को लेकर स्पष्ट संदेश दिया। तब उन्होंने कहा था, 'पूरी दुनिया को बता दो कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता।' गांधी की तमाम बातों के साथ उनके इस संदेश को भी भुला दिया गया।

तभी से सितंबर के पहले पखवाड़े या कुछ दफ्तरों में पूरे सितंबर हिंदी का तर्पण करने की परंपरा शुरू हो गई। हिंदी को किनारे रखने में द्रविड़ राजनीति की बड़ी भूमिका रही है। हालांकि हिंदी को लेकर बेहतर रूख बाकी दलों का भी नहीं रहा। भारतीय राजसत्ता के इतिहास में हिंदी को लेकर जमीनी स्तर तक प्रभाव डालने वाले कदम उठाने की कोशिश शायद ही नजर आती है। हिंदी को लेकर ज्यादातर रस्मी अंदाज में कदम उठाए गए। ठोस बदलाव लाने की कोशिश नहीं दिखती है। हिंदी को लेकर सरकारी दफ्तरों में एक निश्चित अवधि के लिए कार्यशालाओं का विधान है, जिनमें कुछेक कर्मचारियों के अलावा किसी की भागीदारी नहीं होती। अधिकारी तो हिंदी को लेकर होने वाली ऐसी बैठकों में जाना भी अपनी तौहीन समझते हैं। हिंदी के बढ़ते प्रसार को लेकर हिंदी प्रेमी आए दिन खुश होते रहते हैं, लेकिन वह प्रसार राजकीय कम, लोकपक्षीय ज्यादा है। कॉरपोरेट जगत ने बाजार तक अपनी सीधी पहुंच बनाने के लिए हिंदी समेत भारतीय भाषाओं को अपना हथियार बना लिया है। लेकिन नीतियों, प्रशासन और ऐसे ही दूसरे कार्यों के लिए कॉरपोरेट जगत में हिंदी उतनी ही बेगानी है, जितनी संविधान के तहत कार्य करने वाली संस्थाओं और सरकारी दफ्तरों की दीवारों के पीछे है। इस तरह कह सकते हैं कि हिंदी कमाई की भाषा तो है, लेकिन उसे नियंत्रित करने वाली सोच की भाषा अंग्रेजी ही है। लोहिया के अंग्रेजी हटाओ आंदोलन को समाजवादी खेमा बहुत शानदार मानता है, लेकिन लगता है कि इस आंदोलन ने हिंदी विरोधियों की कुंठा को अभिव्यक्त होने का जोरदार मौका दिया। इसी कुंठा की उपज है कि गैर-हिंदीभाषी राज्यों में हिंदी को लेकर तिरस्कार और अंग्रेजी के प्रति सम्मान दिखता है। लोहिया के आंदोलन ने द्रविड़ दलों में गहरे तक हिंदी को लेकर प्रतिक्रिया बोध को स्थापित किया। यह विडंबना ही है कि आज लोहिया के अनुयायी समाजवादी धारा के दल उन द्रविड़ दलों के साथ खड़े हैं, जो हिंदी को लेकर जहर उगलते हैं और वे चुप्पी साधे रखते हैं। आजादी के बाद की कांग्रेस न तो हिंदी समर्थक रही और न ही विरोधी। परिस्थिति और जगह के हिसाब से उसकी हिंदी नीति चलती रही। जबकि भाजपा ने मोदी-शाह के दौर में हिंदी को प्रतिष्ठित करने की कोशिश की, लेकिन नौकरशाही का रूख नहीं बदला। नौकरशाही का रवैया अब भी अंग्रेजी समर्थक ज्यादा है।

बहरहाल राजकाज की नीतिगत भाषा अब भी हिंदी ही है। संसदीय हिंदी समिति की सिफारिशें हों या फिर राजभाषा कानून के दूसरे प्रावधान, अब भी हिंदी के कथित उत्थान और विकास के लिए रस्म ही पूरी की जाती है। नीतियां अब भी अंग्रेजी में ही बनती हैं, और हिंदी या भारतीय भाषाओं में उनका अनुवाद परोसा जा रहा है। अनुवाद वाली भाषा के जरिये राजकाज को जमीनी हकीकत बनाया तो जा सकता है, लेकिन उस राजकाज में लोक की आत्मा नहीं रहती।

गांधी ने जब *हिंद स्वराज* में भावी स्वाधीन भारत के लिए हिंदी की कल्पना की थी, तो उसका उद्देश्य था, राजकाज और उसकी नीतियों में भारत की आत्मा को सहजता से शामिल करना। आज अगर राजकाज की नीतियां जमीनी हकीकत से दूर दिखती हैं, तो इसकी एक बड़ी वजह नीति निर्माण में लोक भाषाओं की अनुपस्थिति भी है।

ऐसे माहौल में हिंदी सिर्फ सालाना दफ्तरी रस्मों में सिमट कर रह जाती है। कार्यालय की हिंदी वह तब होगी, जब रोजाना उसके जरिये दफ्तरी कामकाज निबटाए जाएंगे। जब हिंदी में सोचा जाएगा, और उस सोच के आधार पर नीतियां बनेंगी, तभी उन नीतियों में राष्ट्रीय लोक की आत्मा होगी। यहां ध्यान रखना होगा कि हिंदी का मतलब सिर्फ हिंदी से नहीं है, बल्कि दूसरी भारतीय भाषाओं से भी है। भारतीय भाषाएं सहोदरी हैं। हिंदी को जब पखवाड़े की मर्यादा से बाहर निकाला जाएगा, तभी वह सही मायने में अपना स्थान ग्रहण कर पाएगी। तभी वह नीतियों की बुनियाद होगी, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय लोक की आत्मा गहरे तक समाहित होगी।

पतन से प्रगति तक : पीएम मोदी कैसे गढ़ रहे हैं नया शहरी भारत ?

रोम एक दिन में नहीं बना था, वैसे ही नया शहरी भारत भी एक दिन में नहीं बनेगा। लेकिन जब हम अपने शहरों से और अधिक की अपेक्षा करते हैं, तो हमें यह भी देखना चाहिए कि हम पहले ही कितनी दूरी तय कर चुके हैं? आजादी के दशकों बाद तक, भारत के शहर एक उपेक्षित विचार थे। नेहरू की सोवियत शैली की केंद्रीकृत सोच ने हमें शास्त्री भवन और उद्योग भवन जैसे कंक्रीट के विशाल भवन दिए, जो 1990 के दशक तक ही ढहने लगे थे और सेवा के बजाय नौकरशाही के स्मारक बनकर रह गए।

2010 के दशक तक दिल्ली की हालत बहुत खराब थी। सड़कों पर गड्ढे थे, सरकारी इमारतें पुरानी, बदरंग और टपकती छतों वाली थीं और एनसीआर की बाहरी सड़कों पर हमेशा जाम लगा रहता था। एक्सप्रेसवे बहुत कम थे, मेट्रो कुछ ही शहरों तक सीमित थी और बुनियादी ढांचा तेजी से टूट-फूट का शिकार हो रहा था। दुनिया का नेतृत्व करने का सपना देखने वाले देश की राजधानी उपेक्षा और बदहाल स्थिति का प्रतीक बन चुकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात को बदल दिया। उन्होंने शहरों को बोझ नहीं माना, बल्कि उन्हें विकास के इंजन और राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक बनाया। यह बदलाव आज हर जगह दिखाई देता है। सेंट्रल विस्टा के पुनर्निर्माण ने कर्तव्य पथ को जनता की जगह बना दिया, नई संसद को भविष्य के अनुरूप संस्थान में बदल दिया और कर्तव्य भवन को सुचारु प्रशासनिक केंद्र बना दिया। जहां पहले जर्जर हालत थी, वहां अब महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास दिखता है।

इस बदलाव का पैमाना आंकड़ों से समझा जा सकता है। 2004 से 2014 के बीच शहरी क्षेत्र में केंद्र सरकार का कुल निवेश लगभग 1.57 लाख करोड़ था। 2014 के बाद से यह 16 गुना बढ़कर लगभग 28.5 लाख करोड़ हो गया है। 2025-26 के बजट में ही आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय को 96,777 करोड़ दिए गए, जिसमें एक-तिहाई हिस्सा मेट्रो के लिए और एक-चौथाई आवास के लिए रखा गया। इतना बड़ा वित्तीय निवेश स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ और इससे अभूतपूर्व रूप से शहरी ढांचे का स्वरूप बदल रहा है। आज हम लगभग 4.2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, जहां डिजिटल व्यवस्था रोजमर्रा की जिंदगी को चला रही है। यूपीआई ने अभी हाल ही में एक महीने में 20 अरब लेन-देन का आंकड़ा पार किया और हर महीने 24 लाख करोड़ से ज्यादा के लेन-देन संभाल रहा है। अब 90 करोड़ से अधिक भारतीय इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और 56 करोड़ जनधन खाते जैम त्रिमूर्ति (जनधन, आधार, मोबाइल) का आधार हैं, जिसके जरिये सब्सिडी सीधे और पारदर्शी रूप से दी जाती है। 2014 में भारत में सिर्फ़ 5 शहरों में लगभग 248 किलोमीटर मेट्रो लाइन चल रही थी। आज यह बढ़कर 23 से अधिक शहरों में 1,000 किलोमीटर से [illegible] हो गई है, जो हर दिन एक करोड़ से अधिक यात्रियों को ढोती है। पुणे, नागपुर, सूरत और आगरा जैसे शहरों में नए कॉरिडोर बन रहे हैं, जिससे सफर तेज, सुरक्षित और प्रदूषण-रहित हो रहा है। एनसीआर के जाम से भरे इलाकों को नई बनी यूईआर-कक (दिल्ली की तीसरी रिंग रोड) से राहत मिल रही है, जो एनएच-44, एनएच-9 और द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़कर पुराने जाम के बिंदुओं को आसान बना रही है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु-मैसूरु एक्सप्रेसवे, दिल्ली- मेरठ एक्सेस-नियंत्रित कॉरिडोर और मुंबई कोस्टल रोड ने दूरी घटा दी है और बड़े वाहनों को शहर की गलियों से बाहर निकालकर हवा को साफ़ किया है। मुंबई में देश का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु अब टापू जैसे शहर को मुख्य भूमि से सीधे जोड़ता है। मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना, तेज़ी से आगे बढ़ रही है और पश्चिम भारत में विकास का नया केंद्र बनने जा रही है। पीएम स्वनिधि योजना ने 68 लाख से [illegible] रेहड़ी-पटरी वालों को बिना गारंटी वाला कर्ज और डिजिटल सुविधा दी है, जिससे छोटे उद्यमियों को रोजगार फिर से खड़ा करने और औपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़ने का मौका मिला है। पीएम आवास योजना (शहरी) के तहत 120 लाख से अधिक मकानों की मंजूरी दी गई, जिनमें से लगभग 94 लाख पूरे हो चुके हैं। लाखों परिवार, जो पहले झुग्गियों में रहते थे, अब सुरक्षित पक्के घरों में रह रहे हैं। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन 2014 में सिर्फ़ 57 क्षेत्रों तक सीमित था, जो अब बढ़कर 300 से अधिक हो गया है। घरेलू पीएनजी कनेक्शन 25 लाख से बढ़कर 1.5 करोड़ से ऊपर पहुंच गए हैं। परिवहन का आधुनिकीकरण बड़े पैमाने और तेजी से हो रहा है। 2014 में जहां सिर्फ 74 हवाईअड्डे चालू थे, आज वह संख्या बढ़कर लगभग 160 हो गई है। यह संभव हुआ है उड़ान योजना और लगातार निवेश की वजह से। वंदे भारत ट्रेनें अब 140 से अधिक रूटों पर चल रही हैं, जिससे अलग-अलग क्षेत्रों में यात्रा का समय काफी घटा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जा रहा है, जिनमें से सौ से ज्यादा का उद्घाटन हो चुका है। पाटलिपुत्र और नालंदा जैसे भारत के प्राचीन शहर कभी शहरी सभ्यता की उच्चता के प्रतीक थे। आज, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय शहर फिर उसी राह पर हैं, आधुनिक लेकिन मानवीय, महत्वाकांक्षी होते हुए भी समावेशी, वैश्विक दृष्टिकोण वाले होते हुए भी जड़ों और मूल्यों से जुड़े हुए। नया शहरी भारत एक दिन में नहीं बन रहा है, बल्कि यह हर दिन बन रहा है- ईंट दर ईंट, ट्रेन दर ट्रेन, घर दर घर। और यह पहले से ही करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रहा है।

केंद्रीय मंत्री
हरदीप सिंह पुरी

(लेखक केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं)

दूसरा पहलू

मानव सभ्यता की शुरुआत से लेकर एक सदी पहले तक पृथ्वी की सतह का तापमान संतुलित था, अब असंतुलित क्यों हो गया है?

पृथ्वी का ऊर्जा बजट बैंक खाते की तरह है

जलवायु परिवर्तन को मापने का एक तरीका है लंबी अवधि में अलग-अलग जगहों पर तापमान को रिकॉर्ड करना। यह अच्छी तरह से काम करता है, लेकिन प्राकृतिक भिन्नता की वजह से लंबी अवधि के रुझान को देखना मुश्किल हो सकता है। लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी गर्मी आ रही है व कितनी बाहर जा रही है, इसका पता लगाने से लंबी अवधि के रुझान को स्पष्ट समझा जा सकता है। यह पृथ्वी का ऊर्जा बजट है, जो अब असंतुलित हो चुका है। हाल के शोध बताते हैं कि पिछले 20 सालों में पृथ्वी का तापमान दोगुने से भी ज्यादा हो गया है। यह असंतुलन जलवायु मॉडलों द्वारा सुझाए गए स्तर से कहीं अधिक है। 2000 के दशक के मध्य में, ऊर्जा असंतुलन औसतन 0.6 वाट प्रति वर्ग मीटर था। हाल के वर्षों में, यह औसतन 1.3 वाट प्रति वर्ग मीटर हो गया है। यानी ग्रह की सतह के पास ऊर्जा संचय की दर दोगुनी हो गई है। ये नतीजे बताते हैं कि आने वाले वर्षों में जलवायु परिवर्तन और तेज हो सकता है। पृथ्वी का ऊर्जा बजट कुछ हद तक बैंक खाते की तरह काम करता है, जहां पैसा आता और जाता है। अगर आप अपने खर्च कम करते हैं, तो आपके खाते में नकदी जमा हो जाएगी। यहां, ऊर्जा ही मुद्रा है। पृथ्वी पर जीवन सूर्य से आने और जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन पर निर्भर करता है। यह संतुलन एक तरफ झुक रहा है। वायुमंडल में 20 खरब टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसें जमा हो चुकी हैं, जो गर्मी को बाहर जाने से रोक रही हैं। इस तापमान का कुछ हिस्सा जमीन को गर्म कर रहा है, तो कुछ ग्लेशियर को पिघला रहा है।

बेनोइट मेसिग्नैक

2000 के दशक के मध्य में, ऊर्जा असंतुलन औसतन 0.6 वाट प्रति वर्ग मीटर था। अब यह औसतन 1.3 वाट प्रति वर्ग मीटर हो गया है।

वायुमंडल में 20 खरब टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसें जमा हो चुकी हैं, जो गर्मी को बाहर जाने से रोक रही हैं। इस तापमान का कुछ हिस्सा ग्लेशियर को पिघला रहा है।

पृथ्वी प्राकृतिक रूप से कई तरीकों से गर्मी छोड़ती है। मानव सभ्यता की शुरुआत से लेकर एक सदी पहले तक पृथ्वी की सतह का औसत तापमान लगभग 14 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन बढ़ते ऊर्जा असंतुलन के कारण औसत तापमान 1.3-1.5 डिग्री तक बढ़ गया है। ऊर्जा असंतुलन तेजी से बढ़ रहा है। नए शोध बताते हैं कि बादलों में बदलाव इसका एक बड़ा कारण है। अत्यधिक परावर्तक सफेद बादलों से ढका क्षेत्र सिकुड़ गया है, जबकि अव्यवस्थित, कम परावर्तक बादलों का क्षेत्र बढ़ गया है। अगर उत्सर्जन को जल्दी कम नहीं किया गया, तो अगले कुछ दशकों में और गंभीर स्थिति होगी। हमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग बंद करना होगा। यदि हमें अप्रत्याशित परिवर्तनों को पहचानना है, तो लंबे समय तक सटीक रिकॉर्ड रखना जरूरी है। सैटेलाइट्स हमारे अग्रिम चेतावनी सिस्टम हैं, जो हमें गर्मी भंडारण में बदलाव के बारे में लगभग एक दशक पहले सूचना देते हैं।

आंकड़े

भारत की ऊर्जा

नवीकरणीय ऊर्जा और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स के प्रति उपभोक्ताओं की रुचि सबसे अधिक भारत में है, जो जलवायु परिवर्तन के लिए बेहतर है।

भारत	39%
चीन	33%
मेक्सिको	32%
ब्राजील	29%
अमेरिका	20%

आंकड़े प्रतिशत में हैं। | स्रोत : statista

भक्ति में जीवन समर्पित

सामतसिंह शिकार खेलने गए, तो जल पी रहे एक मृग को उन्होंने बाण से मार डाला। बाद में पश्चाताप होने पर उन्होंने दीक्षा ले ली।

सालावाड़ प्रांत में योगिराज श्री षट्प्रज्ञ का जन्म हुआ था। उनके पिता श्री योगिराज सिंह झिंझुवाड़ा के महाराज थे। श्रीषट्प्रज्ञ जी के बचपन का नाम सामतसिंह था। एक दिन सामतसिंह झिंझुवाड़ा नगर के निकट सरस्वती झील के तट पर शिकार खेलने गए। वहीं पास में योगींद्र श्रीयादव स्वामी जी का आश्रम था। आश्रम के समीप जल पी रहे एक मृग को सामतसिंह ने अपने बाण से मार डाला।

स्वामी मृग को मृत देखकर उसके पास गए और भगवान का स्मरण करते हुए मंत्र पढ़ा। भगवान की कृपा से मृग जीवित हो गया। सामतसिंह को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। वह श्रीस्वामी जी के चरणों में गिर पड़े और प्रार्थना करते हुए बोले, 'हे भगवन! मैंने कितना बड़ा अपराध किया है! कृपया मुझे दीक्षा प्रदान कर अपनी शरण में स्वीकार करें।' श्रीस्वामी जी बोले, 'राजकुमार! सत्पुरुषों की मर्यादा का रक्षण तो क्षत्रिय ही करते हैं, और राक्षसों का नाश भी। किंतु तुमने भगवान नलेश्वर के आश्रम के निकट मृग का वध करके महान पाप किया है। तथापि, तुम्हारे पश्चाताप को देखकर मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। सामतसिंह बोले, 'गुरुदेव! आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं अब भगवान की भक्ति में जीवन समर्पित करना चाहता हूं।' राजकुमार की ऐसी प्रबल उत्कंठा देखकर श्री स्वामी जी ने उन्हें दीक्षा प्रदान की और उनका नाम श्री षट्प्रज्ञ रखा। इसके बाद श्रीषट्प्रज्ञ आश्रम में रहकर भगवान की भक्ति में लीन हो गए।

अंतर्यात्रा
संकलित

आज का इतिहास

दूरदर्शन का आगमन, छोटे से डिब्बे में समाया सारा जहां

सरकारी प्रसारक के तौर पर दूरदर्शन की स्थापना 1959 में 15 सितंबर को हुई थी। छोटे से पर्दे पर चलती-बोलती तस्वीरें दिखाने वाला और बिजली से चलने वाला यह डिब्बा लोगों के लिए कौतूहल का विषय था। जिसके घर में टेलीविजन होता था, लोग उसे दूर-दूर से देखने आते थे। छत पर लगा टेलीविजन का एंटीना मानो प्रतिष्ठा का प्रतीक हुआ करता था और देश की कला और संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम इस सरकारी प्रसारण सेवा का अभिन्न अंग थे। दूरदर्शन की शुरुआत के समय इसमें कुछ देर के लिए ही कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता था। नियमित दैनिक प्रसारण की शुरुआत 1965 में ऑल इंडिया रेडियो के एक अंग के रूप में हुई। 1876 : उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म। 1909 : डीएमके के संस्थापकों में से एक सीएन अन्नादुरई का जन्म। 1927 : प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म। 1948 : स्वतंत्र भारत का पहला पोत आईएनएस दिल्ली बंबई (अब मुंबई) के बंदरगाह पर पहुंचा। 1971 : दुनिया को हरा भरा और शांति पूर्ण बनाने के संकल्प के साथ ग्रीन पीस की स्थापना।

बाढ़ के बाद पंजाब की दोहरी चुनौती

पंजाब में बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण का एजेंडा दो भागों में विभाजित होना चाहिए-नागरिक पुनर्वास और सुरक्षा पुनर्वास।

चंद्रशेखर बेंजवाल | मुद्दा

पंजाब में बाढ़ से फौरी राहत का मोर्चा तो पंजाबियों ने अपने जज्बे, हिम्मत और हौसले से फतह कर लिया। इसमें हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसान बिरादरी की मदद और सरकारी एजेंसियों के सहयोग का भी बड़ा योगदान रहा। अब जब बाढ़ का पानी उतरने लगेगा, तो पुनर्निर्माण का कार्य तेजी पकड़ेगा। 1988 के बाद आई इस भयानक बाढ़ में सूबे के सभी 23 जिले बाढ़ग्रस्त हो गए और 55 लोगों की मौत हो गई। साढ़े तीन लाख से अधिक लोग इससे प्रभावित हुए। 4.32 लाख एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि में खड़ी फसलें नष्ट हो गईं।

आगे का काम बहुत बड़ा है। बाढ़ के पानी में डूबी लाखों एकड़ जमीन में पानी के साथ आए रेत-पत्थर को निकालकर उसे फिर से खेती योग्य बनाना है। सैकड़ों

निजी घर, सरकारी इमारतें ढह गईं, ग्रामीण सड़कें टूट गई हैं, इन सबका पुनर्निर्माण होना है। रावी, ब्यास व सतलुज नदियों के ध्वस्त हो चुके तटबंधों को फिर से खड़ा करना होगा। इसके अलावा, जो सबसे बड़ी चुनौती है, वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। पंजाब के पश्चिम में भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग 553 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जिसमें से थोड़ा-सा हिस्सा नदियों से बनाई गई सीमा का है और शेष 462 किलोमीटर जमीनी सरहद है, जिसे रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है। पंजाब में आतंकवाद के चरम दौर में पाकिस्तान से घुसपैठ और हथियारों की आवाजाही रोकने के लिए 1988 से 1993 के बीच इस पूरी सीमा पर आठ से 12 फीट ऊंची कंटीली तार की फेंसिंग खड़ी की गई। साथ ही इनका विद्युतीकरण किया गया। रात में घुसपैठियों पर निगाह रखने के लिए फ्लडलाइट्स लगाई गई। निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए इसमें मोशन सेंसर, थर्मल इमेजिंग डिवाइस, नाइट विजन कैमरे एवं अलार्म भी लगाए गए। नदी वाले क्षेत्रों में लेजर बाड़ लगाई गई है, जो इन्फ्रारेड और लेजर बीम से घुसपैठ का पता लगाती है और सैटेलाइट-आधारित सिग्नल सिस्टम से जुड़ी होती है। इस सरहद पर सीमा सुरक्षा बल की सख्त निगरानी और गश्त जारी रहती है। इसी प्रकार सीमा के उस पार पाक रेंजर्स भी चौकस रहते हैं। बाढ़ ने जन-धन की व्यापक हानि तो की ही, सीमा पर की गई सुरक्षा व्यवस्था को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। कंटीली बाड़ क्षतिग्रस्त हो गई, सीमा सुरक्षा बल के कई पोस्ट जलमग्न हो गए। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 30 किलोमीटर बाड़ क्षतिग्रस्त हुई है। यह आंकड़ा अधिक भी हो सकता है। अभी सेना व सुरक्षा बलों का भी ध्यान लोगों की मदद करने पर है। स्वाभाविक है कि जब बाड़ क्षतिग्रस्त हुई है, तो इससे जुड़े निगरानी तंत्र के दूसरे उपकरणों को भी उसी पैमाने पर नुकसान पहुंचा होगा। यह नुकसान ऐसे समय हुआ है, जब पाकिस्तान के साथ हालिया युद्ध के बाद घुसपैठ की आशंकाएं अधिक प्रबल हैं। हालांकि, बाढ़ ने पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन उसकी फितरत अपने घर को ठीक करने से ज्यादा, भारत को नुकसान पहुंचाने की रही है। पाकिस्तान की रणनीति हमेशा से दो स्तरों पर चलती रही है। एक ओर औपचारिक युद्ध, तो दूसरी ओर'प्रॉक्सी वॉर'। सीमा पार से आतंकियों को भेजना, हथियारों की तस्करी करना, नशे की खेप पहुंचा कर पंजाब के युवाओं को अस्थिरता के रास्ते पर धकेलना इस रणनीति के अहम हिस्से हैं। युद्ध में हार या दबाव झेलने के बाद पाकिस्तान अक्सर ऐसे रास्ते अपनाता है, ताकि भारत के भीतर असंतोष, हिंसा और अराजकता का वातावरण बने। ऐसे में पंजाब का पुनर्निर्माण केवल नागरिक जीवन तक सीमित नहीं है। खेतों को फिर आबाद करना, टूटे हुए घरों, दफ्तरों और स्कूलों को बनाना, सड़क नेटवर्क को दुरुस्त करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि सीमा पर सुरक्षा व्यवस्थाओं की बहाली और सुदृढ़ीकरण फौरन किया जाना।

Special arrangements by Amar Ujala

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा.लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक समीर माहेश्वरी द्वारा नवभारत प्रेस, नवभारत भवन, प्रेस कॉम्पलेक्स, जी.ई.रोड, रायपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित. प्रधान संपादक : समीर माहेश्वरी, संपादक : राजेश आर. जोशी* (पी.आर.बी. कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिये जिम्मेदार)
■ रायपुर फोन : 0771-4343434, 2535555-66-77, ■ भुवनेश्वर : 0674-2380511/2380518 ■ बिलासपुर : 07752-230591, 407748, 224563 ■ वर्ष 66 ■ अंक 112 (रजि.नं. 13045/59 आरएनआई), पो. रजिस्टर्ड नं. छ.ग./रायपुर संभाग/61/2025-27 ■ भिलाई फोन : (0788) 2294181, 4030655

https://t.me/AllNewsPaperPaid

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। **–वाल्तेयर**

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

सोशल मीडिया की लत के खतरे से बचने की जरूरत

सोशल मीडिया के खतरों को लेकर पिछले सालों में विभिन्न स्तरों पर चेतावनियां दी जा रही हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक के बारे में यह लगातार कहा जा रहा है कि मोबाइल तथा अन्य डिजिटल डिवाइस पर लगातार चिपके रह कर आभासी दुनिया में खोए रहने व लत की हद तक पहुंचने में स्वास्थ्य से जुड़ीं कई गंभीर समस्याएं पैदा हो जाएंगी। सोशल मीडिया की लत को बीमारी मानकर उपचार की गाइड लाइन तय करने की पीजीआइ चंडीगढ़ की तैयारी को भी इन्हीं खतरों से जोड़कर देखा जाना चाहिए। पीजीआइ का मानना है कि इस गाइड लाइन के जरिए खास तौर से बच्चों और उनके अभिभावकों को डिजिटल दुनिया की जटिलताओं को समझने व उनसे निपटने में आसानी रहेगी।

इससे पहले भी कई अध्ययनों में यह बात सामने आ चुकी है कि सोशल मीडिया की लत व्यक्ति को कई मानसिक और शारीरिक परेशानियां पैदा करने वाली हो रही हैं। खास तौर से नई पीढ़ी में अवसाद, चिंता व अकेलेपन की समस्याएं परिवारों के लिए बड़े खतरे के रूप में सामने आ रही है। बड़ी चिंता यह भी कि आभासी दुनिया के इस दौर में व्यक्ति असली दुनिया के रिश्तों तक की अनदेखी करने लगता है। अमरीका के यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में पाया है कि जो बच्चे अपने सोशल मीडिया अकाउंट को बार-बार चेक करते हैं, उन्हें मस्तिष्क संबंधित विकारों का खतरा रहता है। मोबाइल और सोशल मीडिया की लत से बच्चों में एंजाइटी और ईटिंग डिसऑर्डर जैसी समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस साल की शुरुआत में ही एक केस की सुनवाई करते हुए कहा था कि बच्चों का ऑनलाइन गेम एडिक्शन आने वाले समय में ड्रग्स और मादक पदार्थों की लत की तरह ही साबित होगा। इससे मानसिक और शारीरिक सेहत को कई नुकसान हो सकते हैं। कोर्ट का मानना था कि यह जरूरी है कि इस पर कोई कानून लाया जाए। जाहिर है सबसे बड़ी जरूरत इंटरनेट व सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लत की हद तक ले जाने से रोकना है। वर्चुअल दुनिया में लाइक्स, कमेंट्स व फॉलोअर्स की चाहत व स्क्रीन पर बढ़ता समय डिजिटल लत ही है जो धूम्रपान और मादक पदार्थों के सेवन की लत की तरह खतरा बनकर सामने आ रही है। इस लत से छुटकारा पाने के लिए लोग अस्पतालों की शरण में पहुंचने लगे हैं।

भारत में सोशल मीडिया की लत सचमुच बड़ी समस्या के रूप में उभरने वाली है। दक्षिण कोरिया जैसा देश जो सबसे ज्यादा डिजिटल रूप से जुड़ा है, उसने भी पिछले दिनों ही पढ़ाई के दौरान कक्षाओं में मोबाइल व डिजिटल डिवाइस पर पाबंदी के लिए कानून बनाया है। जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, उसे देखते हुए नशा निवारण की तरह ही सोशल मीडिया के खतरों से भी लोगों को अवगत कराने के लिए अभियान चलाना जरूरी हो गया है।

मस्तिष्क बनाम मशीन : यह सोच विकसित करें कि डिजिटल दुनिया के अंतरंग संबंध बंद कमरे की तरह सुरक्षित नहीं है

डिजिटल दुनिया में अंतरंगता : सुरक्षित दीवार का भ्रम

ऋतु सारस्वत
समाजशास्त्री एवं स्तंभकार
@patrika.com

मस्तिष्क संरचना को इस रूप में ढालना जरूरी है कि वह डिजिटल और भौतिक दुनिया में भेद कर सके। यह समझ सके कि डिजिटल दुनिया एक छद्म संसार है जहां जो दिख रहा है वह वास्तविक हो यह आवश्यक नहीं, विशेषकर जब बात अंतरंग संबंधों की हो।

बीते दिनों ऐसे कई मामले सामने आए जहां एप्स में सांझा किए गए अंतरंग संबंधों को सार्वजनिक कर दिया गया। महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कोई कैसे डिजिटल दुनिया को बंद कमरे की सुरक्षित दीवार के समकक्ष समझने की भूल कर सकता है? यहां प्रश्न अंतरंग संबंधों की निजता का नहीं है अपितु मस्तिष्क के उस भ्रम का है जो डिजिटल दुनिया और वास्तविक दुनिया के मध्य भेद कर पाने में सक्षम नहीं है। मानव मस्तिष्क हजारों वर्षों में ऐसे वातावरण में विकसित हुआ है जो आज की डिजिटल रूप से संतृप्त दुनिया से बिल्कुल अलग है। फिर भी, पिछले कुछ दशकों में, और विशेष रूप से पिछले 15 वर्षों में इंटरनेट, सोशल मीडिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) जैसी तकनीकी प्रगति ने दैनिक जीवन में तेजी से प्रवेश किया है और हमारे संवाद करने, ज्ञान प्राप्त करने और दुनिया के साथ अंतःक्रिया करने के तरीके को नया रूप दिया है।

फिर्थ, जे., फ्रोम और उनके साथियों ने अपने शोध 'फ्रॉम ऑनलाइन ब्रेन्स टू ऑनलाइन लाइव्स अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअलाइज्ड इम्पैक्ट्स ऑफ इंटरनेट यूज अक्रॉस साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल डिमेन्सन्स' में उल्लेखित किया है कि 'तकनीक के इस तीव्र प्रवाह ने हमारे मस्तिष्क की विकासवादी संरचना और आधुनिक डिजिटल संस्कृति की मांगों के बीच एक संभावित बेमेल पैदा कर दिया है।' 2019 में वर्ल्ड साइकियाट्री में प्रकाशित फिर्थ का शोध 'द ऑनलाइन ब्रेनः हाउ द इंटरनेट मे बी चेंजिंग ऑर कॉग्निशन' सहस्त्राब्दियों से मानव मस्तिष्क की संरचना और वर्तमान डिजिटल दुनिया की चुनौतियों के बारे गहन चर्चा करते हुए टिप्पणी करता है कि 'हमारे मस्तिष्क पर एक विकासवादी अतीत की छाप है जिसमें जीवित रहना प्राकृतिक वातावरण के प्रति सजगता और सूक्ष्म आमने-सामने की सामाजिक गतिशीलता पर निर्भर करता था। मस्तिष्क की संरचना और संज्ञानात्मक प्रणालियां वास्तविक समय के सामाजिक संपर्क, दुर्लभ सूचना और भौतिक तात्कालिकता की दुनिया के लिए विकसित हुईं, न कि उस हमेशा ऑनलाइन, सूचना-संतृप्त परिवेश के लिए जिसमें हम आज रहते हैं।'

मस्तिष्क असीम रूप से लचीला नहीं है, देहाने और कोहेन, 'कल्चरल रिसाइकलिंग ऑफ कॉर्टिकल मैप्स : हाउ रीडिंग एंड मैथमेटिक्स रिशेप ह्यूमन कॉर्टेक्स. न्यूरॉन' में इसे विकास में 'जैविक बाधाएं' कहते हैं। जब हम आधुनिक डिजिटल गतिविधियों पर विचार करते हैं तो यह परिप्रेक्ष्य महत्त्वपूर्ण है। इंटरनेट, सोशल मीडिया और एआइ पिछले कुछ दशकों के सांस्कृतिक आविष्कार हैं। तकनीकी एकीकरण की यह तीव्र, अभूतपूर्व गति मस्तिष्क की अनुकूलन क्षमता के लिए एक गंभीर चुनौती पेश करती है, क्योंकि इसे सांस्कृतिक और संज्ञानात्मक मांगों में ऐसे नाटकीय बदलावों के साथ विकासवादी प्रक्रियाओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए आवश्यक विस्तारित अवधि नहीं दी गई है। जिस गति से ये उपकरण दैनिक जीवन में व्याप्त हो गए हैं, वह हमारे मस्तिष्क की विकासवादी संरचना और आधुनिक, डिजिटल दुनिया के बीच बेमेल को और गहरा करता है। इसलिए, महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या हमारे मस्तिष्क का लचीलापन इन परिवर्तनों की गति और तीव्रता के साथ तालमेल बिठा सकता है और इस समायोजन के दौरान क्या चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं।

मस्तिष्क संरचना को इस रूप में ढालना जरूरी है कि वह डिजिटल और भौतिक दुनिया में भेद कर सके। यह समझ सके कि भौतिक संसर्ग जहां वास्तविकता है वहीं डिजिटल दुनिया एक छद्म संसार है जहां जो दिख रहा है वह वास्तविक हो यह आवश्यक नहीं, विशेषकर जब बात अंतरंग संबंधों की हो। दुनिया भर की सामाजिक संरचना एवं ढांचा कुछ इस तरह का रहा है जहां अंतरंग संबंधों में धोखे को हेय दृष्टि से न केवल देखा जाता है अपितु इसे सामाजिक रूप से तिरस्कृत भी किया जाता है और यही व्यवस्था अंतरंग रिश्तों के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है परंतु डिजिटल दुनिया में यह सुरक्षा कवच विलुप्त है। इस चुनौती से निपटने के लिए मस्तिष्क संरचना में बदलाव आवश्यक हो गया है निश्चित रूप से यह एक लंबी प्रक्रिया है परंतु इसका आरंभ होना आवश्यक है। यह आवश्यक है कि मानवीय मस्तिष्क डिजिटल दुनिया की वास्तविकता को आत्मसात करें और यहां स्पष्ट रूप से यह समझने की आवश्यकता है कि इसका संबंध बुद्धिमत्ता से नहीं अपितु मस्तिष्क की संरचना में परिवर्तन की प्रक्रिया से है। यह परिवर्तन ही अंतरंग संबंधों की सुरक्षा में भूमिका निभाएगा और यह समझने की सोच को विकसित करेगा कि डिजिटल दुनिया के अंतरंग संबंध बंद कमरे की तरह सुरक्षित नहीं है बल्कि हजारों आंखें उन्हें देख रही है।

वर्तमान समाज एक अवांछित संघर्ष से गुजर रहा है जहां डिजिटल दुनिया के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता परंतु वह जिस रूप में वर्तमान में है उसको यथावत रूप में स्वीकार भी नहीं जा सकता। विशेषकर जब संदर्भ डिजिटल अंतरंगता का हो। क्योंकि इसकी असुरक्षा ठीक उसी प्रकार से पीड़ादायक और घातक हो सकती है जैसे कि शारीरिक पीड़ा। यद्यपि वर्तमान कानून व्यवस्था मानसिक एवं शारीरिक चोट पहुंचाने वालों को दंडित करने का प्रावधान रखती है परंतु डिजिटल दुनिया में पहुंचाई गई चोट आज भी वैधानिक व्यवस्था का वैसा हिस्सा नहीं बन सकी है। इसमें किंचित भी संदेह नहीं कि डिजिटल दुनिया से प्राप्त मानसिक प्रताड़ना किसी भी स्थिति में शारीरिक पीड़ा से काम नहीं है इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि संपूर्ण वैधानिक व्यवस्था को उस सामाजिक ढांचे की अनुरूप बनाया जाए जहां डिजिटल दुनिया एक प्रमुख हिस्सा बनकर उभर चुकी है।

नेतृत्व

मधुमक्खी से सीखें उद्देश्यपूर्ण कर्म

उसका संपूर्ण जीवन उसके समूह, यानि छत्ते की सेवा में समर्पित होता है

मधुमक्खी आकार में भले ही छोटी हो, परंतु धरती पर जीवन को संजोने में उसका योगदान अपार है। भारतीय शास्त्रों में मधुमक्खी को एकाग्रता, परिश्रम और सहयोग का प्रतीक माना गया है- ये ऐसे नेतृत्व के गुण हैं जो आकार या शक्ति से नहीं, बल्कि दृष्टिकोण और सेवा-भाव से परिभाषित होते हैं।

प्रो. हिमांशु राय
निदेशक
आइआइएम इंदौर
@patrika.com

स्वार्थ से परे उद्देश्य : मधुमक्खी का संपूर्ण जीवन उसके समूह, यानि छत्ते की सेवा में समर्पित होता है, न कि व्यक्तिगत लाभ में। ठीक वैसे ही, अच्छे लीडर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ऊपर उठकर अपने कर्म को दल और समाज के कल्याण से जोड़ते हैं।

सहयोग के माध्यम से नेतृत्व : अकेली मधुमक्खी न तो छत्ता बना सकती है, न जीवन को संजो सकती है। उसकी सफलता सामूहिक उत्तरदायित्व में निहित है। श्रेष्ठ नेतृत्व भी यही सिद्धांत अपनाता है, जिसमें आदेश देने से अधिक, ऐसा वातावरण का निर्माण सम्मिलित है जहां सहयोग स्वाभाविक रूप से पनपे।

एकाग्रता और सटीकता : एक मधुमक्खी दूर-दूर तक उड़ान भरती है, किंतु उसका ध्यान केवल मधु पर रहता है। वह अन्य किसी आकर्षण में नहीं फंसती। नेतृत्व में भी यही क्षमता आवश्यक है, ताकि नेतृत्वकर्ता जान सके कि क्या आवश्यक है और क्या मात्र विकर्षण।

योगदान में विनम्रता : अपनी व्यापक पारिस्थितिक भूमिका के बावजूद मधुमक्खी निःशब्द और अनाम रहकर कार्य करती है। सच्चा नेतृत्व प्रशंसा की चाह में नहीं, प्रभाव में विश्वास रखता है। जो लीडर चुपचाप दूसरों के लिए सफलता के अवसर गढ़ते हैं, वे ही सबसे मजबूत संगठन और समाज रचते हैं।

मधुमक्खी हमें सिखाती है कि नेतृत्व वर्चस्व का नहीं, बल्कि सामूहिक उद्देश्य के प्रति समर्पण, एकाग्र कर्म, विनम्र योगदान और जीवन के साथ सामंजस्य का नाम है।

बुक इनसाइट

डार्क रेनैसां : प्रतिद्वंद्वी मार्लो की कहानी

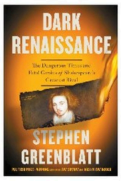

प्रसिद्ध लेखक और पुलित्जर पुरस्कार विजेता स्टीफन ग्रीनब्लैट की नई किताब डार्क रेनैसां पाठकों को शेक्सपियर के समय के अंधेरे, जटिल और रोमांचक संसार में ले जाती है। यह किताब केवल शेक्सपियर की महानता का बखान नहीं करती बल्कि उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी और समकालीन क्रिस्टोफर मार्लो के असाधारण जीवन और दुखद अंत पर भी गहराई से रोशनी डालती है। ग्रीनब्लैट ने बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली अंदाज में यह दिखाया है कि किस तरह 16वीं सदी का इंग्लैंड रचनात्मकता और खतरों से भरा हुआ था। उस दौर में साहित्यकारों और नाटककारों को न केवल दर्शकों को प्रभावित करना होता था बल्कि राजनीति और धार्मिक संघर्षों से भी जूझना पड़ता था। इसी पृष्ठभूमि में मार्लो जैसे प्रतिभाशाली लेखक ने अपनी जगह बनाई, जिसने नाटक लेखन की दुनिया में क्रांति ला दी। ग्रीनब्लैट बताते हैं कि कैसे वह शेक्सपियर का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था और कैसे उसकी प्रतिभा ने नाटकों को नई दिशा दी। यह किताब उनके लिए है जो नाटक, साहित्य और इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं।

फैक्ट फ्रंट

ग्लास स्क्विड : आसानी से नहीं दिखता

ग्लास स्क्विड जिसे वैज्ञानिक भाषा में कांचिया स्क्विड भी कहा जाता है, अटलांटिक महासागर की गहरी परतों में पाया जाता है। इसकी त्वचा इतनी साफ और पारदर्शी होती है कि यह समुद्र के पानी में लगभग अदृश्य हो जाता है और शिकारियों से भी बचा रहता है। ग्लास स्क्विड का शरीर लंबा और पतला होता है। यह 30 सेमी तक लंबा हो सकता है। इसका सिर बड़ा और आंखें चमकदार होती हैं, जो अंधेरे में प्रकाश ग्रहण करने में माहिर हैं। सबसे रोचक बात यह है कि इसके आंतरिक अंग, जैसे पाचन तंत्र, काले रंग के होते हैं ताकि वे बाहर से दिखाई न दें। इससे यह शिकारियों जैसे बड़े मछलियों या समुद्री जानवरों से बच जाता है। इसके अलावा ग्लास स्क्विड में फोटोफोर नामक विशेष ग्रंथियां होती हैं, जो नीले-हरे प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। ग्लास स्क्विड की प्रजनन प्रक्रिया भी अनोखी है। मादा हजारों अंडे एक साथ देती है, जो समुद्र तल पर तैरते रहते हैं। हालांकि इनमें से कुछ ही जीवित रह पाते हैं क्योंकि गहराई का दबाव और शिकारी खतरा बड़ा होता है।

वायु प्रदूषण सबको निभानी होगी अपनी जिम्मेदारी

स्वच्छ वायु आंदोलन : जीवन और अर्थव्यवस्था की जरूरत

डॉ. विवेक एस. अग्रवाल
पर्यावरण विषयों के जानकार
@patrika.com

दुनिया में समय से पहले हो रही सालाना 81 लाख से अधिक मौतों के लिए वायु प्रदूषण को जिम्मेदार माना गया है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए दूसरा सबसे बड़ा खतरा है। संयुक्त राष्ट्र के इन आंकड़ों का अवलोकन किया जाए तो ज्ञात होता है कि वायु प्रदूषण के चलते ही गैर संक्रामक रोगों में वृद्धि हो रही है और 5 साल से छोटे बच्चों में तो बाहरी एवं आंतरिक अस्वच्छ वायु ही मौत का प्रमुख कारण हैं। वायु प्रदूषण के कारण दिल, दिमाग, फेफड़ों आदि की बीमारी दर बहुत तीव्र गति से बढ़ती जा रही है।

वायु प्रदूषण से वैश्विक अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहती। एक अनुमान के अनुसार लगभग 8 लाख करोड़ अमरीकी डॉलर के नुकसान का कारण भी अस्वच्छ वायु ही है, जो कि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत से भी अधिक है। यह राशि मूलतः प्रदूषण जनित रोगों से निपटने के लिए मुहैया करवाई जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च की जा रही है। स्वच्छ वायु प्रदान करने की दिशा में विभिन्न स्तरों पर उपयुक्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता के मध्य भारत में राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ उल्लेखनीय प्रयास हुए हैं। वायु प्रदूषण रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाते हुए भारत ने वैकल्पिक स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन के लिए 2030 के तय लक्ष्यों को पांच वर्ष पूर्व ही हासिल कर लिया है, इसी क्रम में वाहन प्रदूषण रोकने के लिए भी अनेक प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। वायु प्रदूषण के लिए सबसे अधिक दोषी शहरी परिवहन को अंकुश करने के लिए वर्ष 2014 के बाद प्रभावी कदम उठाए गए हैं और उसी का परिणाम है कि इन 10 वर्षों में भारत में मेट्रो रेल का कवरेज 250 किलोमीटर से बढ़कर 1000 किमी हो गया है तथा लगभग 1000 किलोमीटर मेट्रो लाइनें ही अभी निर्माण की प्रक्रिया में हैं।

विद्यालयों समेत शिक्षण संस्थाओं जहां व्यक्ति की नींव रखी जाती है, इस बाबत अपने छोटे कदमों से बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों के आवागमन के लिए निजी वाहनों पर रोक लगा पैदल, साइकिल अथवा स्कूल बस की बाध्यता करने मात्र से बड़ी मात्रा में प्रदूषण कम किया जा सकता है। इसी प्रकार स्वैच्छिक संस्थाओं को अपने अन्य एजेंडे के साथ शहर में फुटपाथ और साइकिल ट्रैक की अनिवार्यता का आंदोलन भी व्यापक बदलाव का माध्यम साबित हो सकता है। जहां एक ओर प्रत्येक व्यक्ति को उत्तरदायी भाव से व्यवहार करना होगा वहीं स्वैच्छिक एवं शिक्षण संस्थाओं, निजी व्यवसायियों, शहरी सरकारों, नीति निर्धारकों आदि को भी संयत, अनुशासित एवं मर्यादित व्यवहार की ओर कदम उठाने होंगे।

विस्तार से पढ़ने के लिए **क्यूआर कोड स्कैन करें**

नॉर्वे का ओड्डा प्रकृति की गोद में रंग-बिरंगा नगर

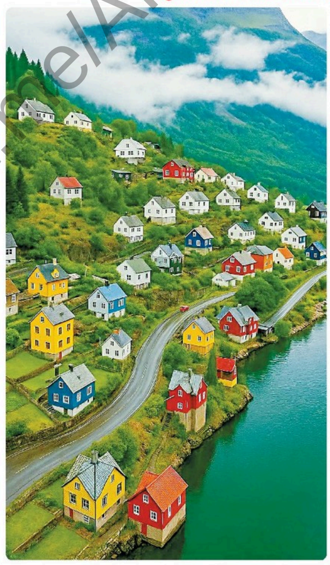

नॉर्वे का ओड्डा पश्चिमी क्षेत्र का एक छोटा लेकिन बेहद आकर्षक नगर है, जो सुरम्य फ्योड्र्स और ऊंचे-ऊंचे पर्वतों के बीच बसा है। सोरफ्योर्डन के अंतिम छोर पर स्थित यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य की अनोखी झलक प्रस्तुत करता है। ओड्डा को प्रसिद्ध ट्रोलटुंगा ट्रेक के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है, जहां हर साल हजारों साहसिक यात्री पहुंचते हैं। यह मार्ग अपने रोमांच, कठिनाई और शानदार नजारों के लिए विश्वभर में चर्चित है। इसके आसपास बहती लातेफॉसेन जैसे झरने इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। यहां रंग-बिरंगे घर, हरे-भरे जंगल और नीला आसमान दिखता है। ओड्डा सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि प्रकृति की अद्भुत कलाकारी का सजीव उदाहरण है।

इंजीनियर्स डे आज देश की प्रगति में अहम भूमिका

तकनीक और नवाचार से बदलती विकास की तस्वीर

सुखवीर सिंह
(लेखक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं)
@patrika.com

इंजीनियर्स दिवस (15 सितंबर) केवल सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती नहीं, बल्कि यह उस दूरदर्शी सोच को याद करने और विचारने का दिन है जिसने एक गरीब उपनिवेश भारत को आज तकनीकी उन्नति के पथ पर अग्रसर राष्ट्र बनाया है। वर्तमान समय में, हमारे इंजीनियर भारत को नए अवसरों और चुनौतियों के बीच संतुलन साधते हुए नए आयाम रच रहे हैं। आइए देखते हैं उनकी कुछ ठोस उपलब्धियां, बड़ी परियोजनाएं और उन अवसरों की एक झलक जिन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है।

भारत ने इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में जनवरी 2025 तक देश की क्षमता लगभग 217.62 गीगावॉट तक पहुंच चुकी है, जिसमें सौर और पवन ऊर्जा की सबसे बड़ी भूमिका है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अकेले 29.52 गीगावॉट की नई क्षमता जोड़ी गई, जो पिछले वर्षों की तुलना में एक बड़ी छलांग है। इसके साथ ही, देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता में नॉन-फॉसिल ईंधन स्रोतों का हिस्सा जून 2025 तक 51.1 प्रतिशत तक पहुंच चुका है, जो वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप है। बुनियादी ढांचे की बात करें तो भारतमाला परियोजना देश की सड़क और राजमार्ग नेटवर्क को नई गति दे रही है। फेज-1 के तहत 34,800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का लक्ष्य तय किया गया था, जिसमें से लगभग 20770 किलोमीटर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसी तरह, डिजिटल हाईवे पहल राजमार्गों के साथ फाइबर-ऑप्टिक केबल बिछाने का मार्ग प्रशस्त कर रही है, ताकि इंटरनेट आधारित सेवाएं गांव-गांव तक पहुंच सकें और डिजिटल इंडिया का सपना साकार हो। आज भारत न केवल तकनीकी आधार पर आगे बढ़ रहा है बल्कि उसने यह साबित कर दिया है कि इंजीनियरों की सक्रिय भागीदारी से हर चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है।

नवाचार, नीति-संयुक्त दृष्टिकोण, सामाजिक जिम्मेदारी और गुणवत्ता-उन्मुख शिक्षा यदि साथ आएं, तो आने वाले वर्षों में भारत न केवल विश्व स्तर पर अभिनव अभियंताओं का केंद्र बनेगा बल्कि ऐसी तकनीकों और परियोजनाओं का जन्मस्थान भी होगा, जो मानवता के लिए स्थायी और व्यापक लाभ प्रदान करेंगी। इंजीनियर्स दिवस पर यह आवश्यक है कि हम केवल अतीत की सफलताओं पर गर्व तक सीमित न रहें, बल्कि भविष्य के लिए ठोस रणनीतियां बनाएं। आखिरकार, तकनीक का असली मापदंड केवल निर्माण नहीं है, बल्कि मानव जीवन की गुणवत्ता और हमारी पृथ्वी की सुरक्षा है।

विस्तार से पढ़ने के लिए **क्यूआर कोड स्कैन करें**

आपकी बात

स्वास्थ्य जांच पर दें ध्यान

महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए शिक्षा, पोषण, स्वच्छता और नियमित स्वास्थ्य जांच पर ध्यान देना आवश्यक है। स्वास्थ्य शिविर, जनजागरूकता अभियान और परिवार का सहयोग उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी कदम हैं। - **पूर्वा जोशी,** श्रीमाधोपुर

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की अन्य प्रतिक्रियाएं

पत्रिकायन का सवाल था, 'महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं?' ऑनलाइन भी देखें।
इसे स्कैन करें https://shorturl.at/9KUsT

आज का सवाल

विवादों को सुलझाने में लोक अदालतों की भूमिका पर आपके क्या विचार हैं?

ईमेल करें : edit@epatrika.com

भारत-नेपाल संबंध दोनों देशों की जनता के बीच ऐतिहासिक रिश्ते इन्हें सामान्य पड़ोसी से कहीं आगे ले जाते हैं

नेपाल में सत्ता परिवर्तन के बाद कूटनीति में बदलाव की उम्मीदें

वेद माथुर
स्वतंत्र लेखक एवं स्तंभकार
@patrika.com

हाल ही नेपाल की राजनीतिक उथल-पुथल ने यह साफ कर दिया कि भारत को वहां की घटनाओं पर चौकस निगाह रखनी होगी। नेपाल की अस्थिरता भारत की उत्तरी सीमाओं पर सीधे असर डाल सकती है। भारत और नेपाल का रिश्ता केवल पड़ोसी होने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह साझा इतिहास, संस्कृति और भौगोलिक नियति का प्रतिबिंब है।

हिमालय की गोद में बसे नेपाल की 1,751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा पांच भारतीय राज्यों- उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम- से जुड़ती है। यह सीमा न केवल व्यापार और आवागमन को सहज बनाती है, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों को भी जोड़ती है। इसीलिए भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति में नेपाल को विशेष महत्त्व दिया गया है। भारत-नेपाल की दोस्ती का आधार सांस्कृतिक और धार्मिक जुड़ाव में निहित है। जनकपुर को सीता जन्मभूमि और लुम्बिनी को भगवान बुद्ध की जन्मभूमि माना जाता है। पशुपतिनाथ (काठमांडू) और काशी विश्वनाथ (वाराणसी) जैसे तीर्थ इन संबंधों को और मजबूत करते हैं। दोनों देशों की जनता के बीच ऐतिहासिक रिश्ते इन्हें सामान्य पड़ोसी से कहीं आगे ले जाते हैं। वर्ष 1816 की सुगौली संधि ने नेपाल की सीमाएं तय कीं।

स्वतंत्र भारत और नेपाल के बीच 1950 की शांति और मैत्री संधि ने दोनों को विशेष अधिकार दिए- नागरिकों को बिना वीजा के रहना, काम करना और संपत्ति खरीदना। यही कारण है कि लाखों नेपाली भारत में काम करके अपने देश को अर्जित आय भेजते हैं। यह नेपाल की अर्थव्यवस्था का महत्त्वपूर्ण सहारा है। व्यापारिक स्तर पर

40 गुना बड़ी है भारत की **जीडीपी नेपाल से**

8-10 लाख नेपाली कार्यरत हैं **भारत में**

एक अरब डॉलर से अधिक की धनराशि प्राप्त होती है नेपाल को **हर साल भारत से**

भारत नेपाल का सबसे बड़ा साझेदार है। 2024 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार लगभग 7.8 अरब डॉलर का रहा। कुल व्यापार में भारत का निर्यात हिस्सा लगभग 89% है, जबकि नेपाल का निर्यात मात्र 11% के आसपास रहता है, जो नेपाल के बड़े व्यापार घाटे को दर्शाता है। नेपाल की अर्थव्यवस्था भारत की सहायता के बिना लंबे समय तक टिकना कठिन होगा, क्योंकि भारत इसका प्रमुख व्यापारिक साझेदार और रेमिटेंस स्रोत है। भारत ने नेपाल में सड़क, रेल और शिक्षा संस्थानों के निर्माण में भी योगदान दिया है। जयनगर-जनकपुर रेललाइन इसका उदाहरण है। दूसरी ओर, नेपाल की नदियां- कोसी, गंडक और महाकाली- भारत की गंगा घाटी के लिए जीवनरेखा हैं। इन्हीं पर आधारित महाकाली संधि और अरुण-3 जैसी परियोजनाएं साझा संसाधनों के उपयोग को दर्शाती हैं। रक्षा सहयोग भी संबंधों का अहम पहलू है।

हालांकि, रिश्तों में चुनौतियां भी रही हैं। कालापानी, लिपुलेख और लिंपीयाधुरा क्षेत्र को लेकर सीमा विवाद दशकों से चला आ रहा है। 2020 में नेपाल ने नया नक्शा जारी कर इन क्षेत्रों को अपने हिस्से में दिखाया, जिसे भारत ने खारिज कर दिया। सुस्ता क्षेत्र भी विवादित है, जहां नारायणी नदी की बदलती धारा ने उलझन पैदा की है। नेपाल की राजनीति में भारत और चीन के बीच संतुलन साधने की कोशिश अक्सर देखी जाती है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली का कार्यकाल भारत के साथ अक्सर तनावपूर्ण रहा। उन्होंने बार-बार भारत पर उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप लगाया और चीन के साथ नजदीकी दिखाई। हाल ही व्यापक जन-आंदोलन के कारण उन्हें पद छोड़ना पड़ा। अब अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के आने से उम्मीद बनती है कि भारत और नेपाल के संबंध मधुर रहेंगे। उन्होंने भारत के साथ 'रोटी-बेटी' के रिश्तों को मजबूत करने और भ्रष्टाचार विरोधी सुधारों का संकल्प लिया है।

निर्विचार अवस्था ही ध्यान है। यह जान लें तो जीवन की हर क्रिया ध्यानपूर्ण होगी।

- बोधिधर्म, बौद्ध दार्शनिक

अपनी दृष्टि जरूरत पर रखिए वैभव पर नहीं

जीवन-सूत्र

स्वामी ज्ञानवत्सल
प्रेरक वक्ता और विचारक

नितदिन नई चीजों से हाट-बाजारों को पाट दिया जाता है। व्यापाक स्तर पर नई चीजों की दस्तक-प्रदर्शन से हमारा मन उलझन में फंस कर भ्रमित हो जाता है। परिणाम, जो भी मनुष्य के पास होता है वह उसे पुराना प्रतीत होने लगता है। नए वर्जन का मोबाइल बाजार में आते ही व्यक्ति को अपना मोबाइल हैंडसेट पुराना ही नहीं अपितु व्यर्थ लगने लगता है। परिधान-चप्पल आदि के साथ भी ऐसा ही भाव सताने लगता है। हर व्यक्ति की अपने इन भावों को परिपूर्ण करने की आर्थिक स्थिति नहीं होती। सभी मनुष्य हर बार नई-नई चीज-वस्तुओं को खरीदने की इच्छापूर्ति नहीं कर पाते और अधूरापन उन्हें घेर लेता है। इन कारणों से कई लोगों के घरों में कहासुनी की स्थितियां बन जाती हैं, संतान इच्छापूर्ति न होने पर तोड़फोड़ के रूप में अपनी निराशा व्यक्त कर बैठती है, कुछ मामलों में गलत मार्ग चले जाते हैं।

सिद्धपुरुष व समदर्शी व्यक्तित्वों का ऐसे पलों में व्यवहार हम मनुष्यों का मार्गदर्शन करता है। बात अगस्त 1977 की है। प्रमुख स्वामी महाराज के आंखों के नंबर में बदलाव हुआ। डॉक्टर ने नए चश्मे की जरूरत बताई। महाराज ने सहजता से कहा कि नए नंबर के कांच को पुरानी फ्रेम में फिट कर दीजिए। सभी हरिभक्त-डॉक्टर भौंचक रह गए। हरिभक्त ने आग्रह के साथ कहा कि- फ्रेम पुराना हो गया है बदलने की इजाजत दीजिए न? प्रमुख स्वामी बोले- देखना कांच से है या चश्मे के फ्रेम से? अनुरोध करने वाले अनुत्तरित थे। उन्होंने समझाया कि मनुष्य अपने अधूरेपन-अक्षमता के मनोभाव से कैसे उबर सकता है। सरल शब्दों में उनकी दृष्टि हमेशा ही जरूरत पर रहती थी, वैभव प्रदर्शन की ओर नहीं।

महान दार्शनिक हेनरी डेविड थोरो ने भी कहा है कि नए परिधानों को पाने की चाह को पूरा करने के लिए ज्यादा उधेड़बुन में न पड़ो, ऐसा करना शक्ति-सार्मथ्य का निर्रथक व्यय ही है। छोटी-मोटी बातों में ही हमारी जीवन ऊर्जा छितरा जाती है। संभलिए और अपना हिसाब का ब्यौरा इतना सटीक-स्पष्ट रखिए कि अंगूठे के नाखून पर लिखा जा सके।

गैर जरूरी विचार जीवनयात्रा में आपकी गति को धीमा कर सकते हैं। कई बार ये आपको बंधक तक बना सकते हैं। इससे आपमें बेचैनी बढ़ तक सकती है।

ऐसा करना हमारी निजी प्रगति के लिए जरूरी है। सीधे ही गणित लगा सकते हैं कि दस किलो वजन लेकर दौड़ने वाले की तुलना में उस व्यक्ति की गति ज्यादा होगी, जो बिना किसी भार के दौड़ रहा है। जीवन यात्रा के मार्ग में भी यह सिद्धांत काम करता है। गैर-जरूरी चीज-वस्तु और विचार न सिर्फ आपकी लय-गति को बाधित करते हैं अपितु कई बार बंधक बना देते हैं। किसी भी वस्तु की आसक्ति की अति यही करती है। इसके पाश में बंधा व्यक्ति खुद को बेचैन महसूस करता है।

अमेरिकी दार्शनिक एमर्सन इसका निदान सादगी को बताते हैं कहते हैं- सादा जीवन ही महान जीवन है। जर्मन दार्शनिक गेटे कहते हैं कि सादगी में स्वास्थ्य व सौंदर्य निहित है।

सादगी की शक्ति सरदार पटेल के पास थी। उनकी घड़ी 30 साल पुरानी थी। संसार छोड़ा तब उनके खाते में 200-250 रुपए ही थे। वे सिर्फ चार जोड़ी कपड़े में ही जीवनयापन कर रहे थे। उनके चश्मे की एक ही डंडी थी दूसरा हिस्सा धागे के सहारे टिकता था। ऐसी महान आत्माओं की छवियां दिलों में छप-बस जाती हैं। अभाव-अधूरेपन का पाश सादगी की साधना करने वालों को कभी अपने पाश में नहीं जकड़ पाता। हम भी सादगी की साधना की राह अपना कर जीवन में शांति-संतोष का प्रकटन कर सकते हैं। ▪ 2 मिनट रीड

खुशी की गाइड

विस्मय से मिलता है एक गहरा संतोष

डॉ. रितु पाण्डेय शर्मा, reetupost@yahoo.com

आश्चर्य हमारे आसपास हर चीज में भरा पड़ा है। जब आप रहस्य मिश्रित आश्चर्य अनुभव करते हैं तो भीतर एक अनकही भावना जन्म लेती है- इसे 'ऑ' कहते हैं। यह सिर्फ एक सुखद क्षण नहीं, अहंकार को छोटा कर देने वाली अनुभूति है, जिसमें व्यक्ति खुद को व्यापक अस्तित्व का हिस्सा मानने लगता है।

- आश्चर्य के अनुभव मस्तिष्क पर छाप छोड़ते हैं तथा संवेदना, स्मृति और आत्म-जागरूकता की प्रणालियों को सक्रिय करते हैं। तब हमारी खुशी भी क्षणिक नहीं रहती, बल्कि स्थिर और गहरी हो जाती है। ये भावनाएं भौतिकता के आकर्षण को भी कम करती हैं। व्यक्ति को लगता है कि खुशी महंगी वस्तुओं या उपलब्धियों में नहीं, उस जुड़ाव में है, जो प्रकृति, ब्रह्मांड और दूसरों के साथ महसूस होता है।
- जब हम किसी बड़ी और रहस्यमय चीज के सामने खड़े होते हैं, तो हमारी छोटी-छोटी चिंताएं तुच्छ लगने लगती हैं। यह अनुभव हमें वर्तमान क्षण में स्थिर करता है, जैसे ध्यान की स्थिति। यही वजह है कि प्रकृति के साथ बिताए क्षण, संगीत का गहन असर या किसी आध्यात्मिक दर्शन का स्पर्श हमें भीतर से शांत और आनंदित कर देता है।
- भारतीय परंपरा ने इसे विस्मय कहा है- ऐसा भाव जो भक्ति, सौंदर्य, चेतना को जोड़ता है। विस्मय हमें याद दिलाता है कि खुशी तब जन्म लेती है, जब हम अपने अहं को पार कर जीवन की विराटता को छूते हैं। ▪ 1 मिनट रीड

सकारात्मक संकल्प

एक किताब कैरी करें...

आज अधिकतर लोग दिन में सौ से भी ज्यादा बार अपना फोन अनलॉक करके नोटिफिकेशंस चेक करते हैं। कल्पना करें जब मोबाइल फोन नहीं था, तब दिन में घंटों स्क्रीन पर बीतने वाला यह समय किन चीजों में व्यतीत होता था? दूसरे तमाम कार्यों के साथ ही डिजिटल क्रांति से पहले की दुनिया में लोग अखबार, पत्रिकाएं या पुस्तकें पढ़ने का मौका नहीं गंवाते थे। आज भले ही यह पहले की तरह सम्भव न हो, कम से कम यात्राएं करते समय तो आप अपने समय का उपयोग कुछ पढ़ने के लिए कर सकते हैं। अगर आप अपने साथ एक किताब कैरी कर रहे हैं तो मोबाइल देखने के बजाय समय का रचनात्मक इस्तेमाल कर सकेंगे।

सकारात्मक संकल्प लें कि दिन में जब भी अवकाश मिले, कुछ पढ़ने का समय निकालेंगे। ▪ 1 मिनट रीड

संघर्ष की कहानी **सुमित नागल,** भारतीय टेनिस खिलाड़ी

पैसों की तंगी के कारण टेनिस छोड़ना चाहते थे सुमित, अब देश के शीर्ष खिलाड़ी

भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल (28) चर्चा में बने हुए हैं। उनके प्रदर्शन के चलते भारत ने स्विटजरलैंड को हराया है। ये 32 सालों में पहली बार है, जब भारत ने यूरोपीय धरती पर यूरोप के देश को हराया है। हरियाणा के सुमित को यहां तक पहुंचने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा है। जानते हैं उनकी संघर्ष से सफलता की कहानी...

7 साल की उम्र तक सुमित की रुचि क्रिकेट में थी। वे रोजाना 7-8 घंटे क्रिकेट खेलते थे। पिता ने सुमित को क्रिकेट से दूर होकर टेनिस खेलने की सलाह दी। उनके पिता म्यूनिसिपल स्कूल में टीचर थे। घर की आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी।

संघर्ष : 2023 में खाते में 80 हजार रुपए ही रह गए थे

टेनिस इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में सुमित को ट्रेनिंग के लिए रोजाना 27 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, वो भी खचाखच भरी बस में। उनके खेल से प्रभावित होकर महेश भूपति ने उन्होंने दो साल तक ट्रेनिंग दी थी। उन्हें अपोलो 2018 प्रोग्राम के लिए छात्रवृत्ति मिली, लेकिन मंदी का हवाला देकर कुछ समय बाद वो बंद हो गई। इसलिए सुमित ने टेनिस छोड़ने तक की ठान ली थी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। महेश भूपति ने उनकी मदद की और सुमित ने टेनिस नहीं छोड़ा। टेनिस में बड़ा नाम बनने के बाद भी साल 2023 में उन्हें वित्तीय संघर्ष से जूझना पड़ा। खाते में 80 हजार रुपए ही रह गए थे। जबकि साल भर में कोच के साथ टूर पर जाने का खर्च ही करीब 1 करोड़ रुपए था। सेविंग्स के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं था। चोटें भी करियर में रोड़ा बनीं।

सफलता: ओलिंपिक खेले, बॉयज विंबलडन जीत चुके

कठिनाइयों के बावजूद हार नहीं मानने के जज्बे की ही वजह से सुमित ने ग्रैंड स्लैम के अपने डेब्यू मैच के पहले सेट में रोजर फेडरर को हरा दिया था। 13 साल की उम्र में वे अंडर-16 नेशनल चैम्पियनशिप जीत चुके थे। 2015 में उन्होंने बॉयज विंबलडन का डबल्स जीता था। इससे विशेषज्ञों को भारतीय टेनिस का भविष्य सुमित में नजर आने लगा था। प्रदर्शन के बूते सुमित टोक्यो ओलिंपिक में भी शामिल हुए। वहां उन्होंने 25 साल बाद भारत के लिए ओलिंपिक में सिंगल्स मैच जीता था। पेरिस ओलिंपिक में भी सुमित ने देश का प्रतिनिधित्व किया था। सुमित नागल एटीपी सिंगल्स में 290वीं रैंक पर हैं। वे भारत के नंबर-1 टेनिस खिलाड़ी हैं। नागल अपने जीवन में 6 एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट जीत चुके हैं। ▪ 1 मिनट रीड

असाधारण रिकॉर्ड **पावेल डुराकिवित्ज,** एथलीट

नंगे पैर बर्फ पर मैराथन दौड़ रचा इतिहास

पोलैंड के पावेल डुराकिवित्ज ने एक अनोखा विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। दरअसल उन्होंने नॉर्वे की बर्फ पर जमी एक झील पर नंगे पैर मैराथन पूरी की है। 42.2 किलोमीटर की उनकी यह कठिन दौड़ 4 घंटे 57 मिनट 54 सेकंड में पूरी हुई। पावेल अनुभव साझा करते हुए कहते हैं कि दौड़ के 500 मीटर बाद ही मन में आया कि दौड़ना असंभव होगा। 10 किमी के बाद तो पैरों से खून बहने लगा था। 12 किमी तक पहुंचते-पहुंचते उन्होंने हार मान ली थी। लेकिन आगे बढ़ते रहे। अपने मन को शांत कर और उन्होंने दर्द को पीछे छोड़ दिया। इस रिकॉर्ड के साथ उन्होंने समाज में नशे के शिकार हुए लोगों के की नई जिंदगी के लिए काम करने वाली डायमंड सोल फाउंडेशन के लिए फंड भी जुटाया। पावेल के इस संकल्प से हम सीख सकते हैं कि जहां हौसला हो, वहां बर्फ भी पिघल जाती है। ▪ 1 मिनट रीड

सीख : पावेल के जज्बे से सीखना चाहिए कि धैर्य, जुनून और दिशा हो तो आप पहाड़ों को भी हिला सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं।

सबक वाला पाठ

शिकारी का गुस्सा

एक शिकारी को अपना एक कुत्ता सबसे प्रिय था और वह वर्षों से उसके साथ था। लेकिन कुत्ता धीरे-धीरे बूढ़ा हो चला और अब उसमें पहले जितना दमखम नहीं रहा। एक दिन शिकारी शिकार पर था। उसका बूढ़ा कुत्ता एक हिरण को पकड़ने के लिए जी-जान से दौड़ा और जैसे-तैसे उसने हिरण को पकड़ लिया, लेकिन उसके कमजोर दांत टूट गए और हिरण उसके चंगुल से भाग निकला। यह देख शिकारी को बहुत क्रोध आया और उसने अपना हंटर उठा लिया। कुत्ते ने शिकारी की ओर देखा और कहा- माना कि मैं अब कमजोर हूं, पर मेरे पुराने दिनों को याद करो और अपने खुद के बुढ़ापे के बारे में सोचो। यह सुनकर शिकारी के हाथ से हंटर छूट गया और वह कुत्ते को प्यार से थपथपाने लगा।

मोरल ऑफ द स्टोरी : जब किसी पर क्रोध आए, उसकी दशा के बारे में सोच लें और खुद को उसकी जगह रखकर भी देख लें। ▪ 1 मिनट रीड

सीनियर सिटीजन

आपकी सेहत **डिमेंशिया-अल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी,** WHO की रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 80 लाख लोग इससे पीड़ित

ये आदतें व खास डाइट बढ़ती उम्र में भी याददाश्त को मजबूत रखेंगी

डॉ. मंजरी त्रिपाठी
एचओडी, न्यूरोलॉजी विभाग, एम्स, नई दिल्ली

डॉ. अर्चना वर्मा
न्यूरोलॉजिस्ट, एमजीएम मेडिकल कॉलेज, इंदौर

भूलने की बीमारियां यानी डिमेंशिया, अल्जाइमर का खतरा 65 की उम्र से ज्यादा बढ़ने लगता है। यदि मानसिक-शारीरिक सक्रियता के साथ आप कुछ खाने-पीने की चीजों का ध्यान रखें तो इसके लक्षण बढ़ने से रोक सकते हैं। इसमें सबसे अहम है 'माइंड डाइट'। इसे अमेरिका में शोध के बाद तैयार किया गया है। जो लोग इस डाइट का अच्छे से पालन करते हैं, उनमें अल्जाइमर का खतरा 53% तक कम हो जाता है। आइए जानते हैं माइंड डाइट क्या होती है? इसमें कौन सी चीजें खाना चाहिए और किन्हें सीमित करें।

अल्जाइमरः न्यूरॉन को नुकसान पहुंचाता है

अल्जाइमर दिमागी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाली बीमारी है। इससे ब्रेन में इंफ्लेमेशन व ऑक्सिडेटिव डैमेज बढ़ता है। यही डिमेंशिया का सबसे आम कारण है। इसका प्रभाव 65 की उम्र के बाद सबसे ज्यादा दिखता है। अल्जाइमर्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स सोसायटी ऑफ इंडिया दिल्ली की अध्यक्ष डॉ. मंजरी त्रिपाठी कहती हैं कि इसे रोकने में शारीरिक-मानसिक सक्रियता के साथ आहार की अहम भूमिका होती है। खासतौर पर जिन चीजों में पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, करक्यूमिन होता उन्हें खाना काफी कारगर है।

व्यायामः हफ्ते में तीन दिन व्यायाम से भी फायदा

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के अनुसार 65 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे बुजुर्ग, जो हफ्ते में चार बार एक्सरसाइज करते हैं, उनमें डिमेंशिया का खतरा एक्सरसाइज नहीं करने वाले बुजुर्गों की तुलना में लगभग आधा हो जाता है। वहीं हफ्ते में तीन दिन तक एरोबिक एक्सरसाइज करने वाले बुजुर्गों में मस्तिष्क का याददाश्त वाला हिस्सा बढ़ता है। दूसरी ओर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक शोध कहता है कि ऐसे बुजुर्ग जो एक से ज्यादा भाषाओं की जानकारी रखते हैं, उनमें भूलने की बीमारियों का जोखिम व तीव्रता कम रहती है।

माइंड डाइट- इसमें हरी सब्जियां, साबुत अनाज शामिल, इनके सेवन से मस्तिष्क का स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा

- **हरी सब्जियांः** सप्ताह में कम से कम 6 टाइम। केले, पालक सहित हरी सब्जियां व सलाद खाएं। फायदाः *कम कैलोरी के साथ फाइबर से भरपूर है।*
- **बेरीजः** हफ्ते में कम से कम दो बार स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी जरूर खाना चाहिए। फायदाः *इनमें ब्रेन के लिए जरूरी एंटीऑक्सीडेंट हैं।*
- **जैतून का तेलः** भोजन को पकाने के लिए पॉम ऑइल की जगह जैतून तेल का उपयोग करें। फायदाः *स्वस्थ मस्तिष्क के लिए लाभकारी होता है।*
- **साबुत अनाजः** ओट्स ब्राउन राइस, गेहूं का पास्ता व ब्रेड खाएं। ये चावल व नूडल्स से बेहतर होते हैं। फायदाः *फाइबर व अन्य पोषण की पूर्ति करते हैं।*
- **हल्दीः** इसमें मौजूद एंटीऑक्सिडेंट करक्यूमिन अल्जाइमर के लक्षणों को कंट्रोल करने में प्रभावी है। फायदाः *डिमेंशिया का खतरा भी टल सकता है।*
- **बीन्सः** सप्ताह में कम से कम चार बार बीन्स का उपयोग करें। इनमें सभी दालें, सोयाबीन शामिल हैं। फायदाः *ये प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत हैं।*

*इन्हें कम करें: **घी-** रोज 14 ग्राम से कम। **पनीरः** 15 दिन में एक बार। **तला फूड** सप्ताह में एक बार से भी कम। **पेस्ट्री-मिठाईः** सप्ताह में एक-दो बार ही खाएं।*

मन के रहस्य

अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक रहें, खुश रहेंगे

मुनि प्रमाण सागरजी
आध्यात्मिक संत और भावना योग का विज्ञान किताब के लेखक

भावनाओं का प्रभाव सिर्फ आत्मिक स्तर तक सीमित नहीं हैं, अपितु यह हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू को गहराई से प्रभावित करती है। हमें अपने मन रूपी उद्यान में उठने वाली प्रत्येक भावना के प्रति जागरूक रहना होगा। शुभ भावनाओं का पोषण करें, अशुभ भावनाओं को विवेक पूर्वक त्यागें। भावनाओं में हमारा आत्मिक उत्थान या पतन सूक्ष्म रूप से छिपा होता है। भावनाओं के विज्ञान को जिसने समझ लिया वह जीवन में सुखी रहता है, क्योंकि ये हमारे जीवन को काफी प्रभावित करती हैं। **आइए जानते हैं शरीर से लेकर कर्म तक जीवन के पांच महत्वपूर्ण स्तरों पर भावनाओं के प्रभाव के बारे में।**

शरीर- क्रोध से पाचन बिगड़ जाता है

तेज क्रोध से बीपी व भय से हार्ट बीट बढ़ जाती है। चिंता से पाचन बिगड़ जाता है। अनिद्रा घेर लेती है। समाधानः *प्रेम, आनंद व शांति की भावनाएं शरीर में स्फूर्ति बढ़ाती हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं।*

मन- नकारात्मकता से निराशा आती है

नकारात्मक भावनाएं जैसे घृणा, ईर्ष्या, प्रतिशोध मन में निरंतर अवसाद, अशांति और निराशा को जन्म देती हैं। समाधानः *सकारात्मक भावनाएं जैसे संतोष, कृतज्ञता, उत्साह मन को प्रसन्न, शांत और ऊर्जावान बनाती हैं।*

वाणी- अपमानजनक शब्द निकलते हैं

अंतर्मन में जैसी भावना होगी, वैसे ही शब्द निकलते हैं। जैसे क्रोध में अपमानजनक शब्द निकलते हैं। समाधानः *प्रेम में मधुर और प्रिय शब्द। जबकि सरलता और सत्य की भावना वाणी को पवित्र बनाती है।*

व्यवहार- अहंकार से रिश्ते टूटते हैं

भावनाएं ही हमारे पारस्परिक संबंधों की नींव रखती हैं। जैसे घृणा-अहंकार से रिश्ते टूटते, अशांति फैलती है। समाधानः *प्रेम और मैत्री की भावना सौहार्द को जन्म देती है, जिससे परिवार, समाज में मधुरता आती है।*

कर्म- भावकर्म ही मूलकारण होता है

भावना से प्रेरित एक सूक्ष्म मानसिक कर्म होता है। यही भावकर्म आत्मा के साथ कर्म का मूल कारण होता है। समाधानः *शुभ भावनाएं पुण्य कर्मों का बंध कराती हैं। ये भविष्य में सुख के रूप में फल देती हैं।*

आप अपने ऐसे अनुभव, जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनें, srcitizen@dbcorp.in पर भेज सकते हैं। चुनिंदा अनुभव हम प्रकाशित करेंगे।

आपकी योजना

डोरस्टेप बैंकिंगः घर बैठे नकदी व चेक जमा करें

70 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए कुछ बैंक डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। डोरस्टेप बैंकिंग, वह सेवा है जिसके तहत बैंक के ग्राहक घर बैठे ही नकदी और चेक जमा या नकद निकासी का लाभ उठा सकते हैं। बैंक से जुड़े एजेंट आपकी ओर से आपके बैंक खाते में नकदी और चेक जमा करते हैं। आप स्व-आहरणीय चेक के बदले अपने घर के पते पर नकदी मंगवाने का अनुरोध भी कर सकते हैं। साथ ही चेक पिक-अप सेवाएं भी प्राप्त कर सकते हैं।

लाभ लेने के लिए ऐसे करें आवेदन

आवेदन करने के लिए अपनी शाखा के कर्मचारियों से बात करें या अपने बैंक के फोन नंबर पर कॉल करें। इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पांस (आईवीआर) आपको ग्राहक सेवा अधिकारी से बात कराएगा। इसके बाद आप डोरस्टेप बैंकिंग के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। हालांकि डोरस्टेप बैंकिंग सेवा सभी बैंकों में उपलब्ध नहीं होती है। अपनी बैंक से इस बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। इस सुविधा के लिए आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर से भी संपर्क कर सकते हैं।

ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड

समाज से जो लिया 91 की उम्र में उसे लौटा रहीं

मुस्कराते चेहरे के साथ दिल पर हाथ रखकर बैठीं ये हैं 91 वर्षीय केरल की सेवानिवृत्त शिक्षिका थंकम्मा। इन्होंने पति के निधन के बाद अपने 200 साल पुराने पैतृक घर में डेकेयर की स्थापना की। इस डेकेयर में 30 महिलाएं रोजाना साथ की तलाश में आती हैं और अपने मन व शरीर को स्वस्थ रखने वाली दिलचस्प गतिविधियों में व्यस्त रहती हैं। थंकम्मा कहती हैं, 'मैंने हमेशा उस समाज को कुछ वापस देने की जिम्मेदारी महसूस की है जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। इन महिलाओं के साथ समय बिताने से मुझे बेजोड़ खुशी और मानसिक शांति मिलती है।

टेक्नोलॉजी गाइड **जीवन** आसान बनेगा

ये बातें आपको ऑनलाइन जिंदगी में रखेंगी सुरक्षित, धोखे से बचाएंगी

देशभर में स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने वाले बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। एक ओर तो स्मार्टफोन के कारण बुजुर्गों के काम आसान हो रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर फ्रॉड करने वाले बुजुर्गों को शिकार बना रहे हैं। आए दिन अलग-अलग किस्म के साइबर फ्रॉड की खबरें आती रहती हैं।

इन धोखाधड़ियों से बचने का सबसे आसान तरीका है जागरूकता। आपको मोबाइल, सोशल मीडिया, इंटरनेट के उपयोग के दौरान कुछ बातें ध्यान रखने की खास जरूरत है। जैसे कि कोशिश करें कि अपनी निजी जानकारी इंटरनेट पर साझा करने से बचें। ओटीपी या किसी भी तरह का पासवर्ड भी इंटरनेट, कॉल आदि पर किसी से साझा न करें।

किसी को ऑनलाइन पेमेंट करें तो दो मर्तबा डिटेल्स चेक कर लें। फोन व इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए कुछ बातों को ध्यान में रख लेंगे तो आपकी डिजिटल सुरक्षा पुख्ता हो जाएगी।

ये चार बातें कभी न भूलें

1. अपने फोन व ईमेल का पासवर्ड थोड़े दिनों में बदलते रहना चाहिए। साथ ही इंटरनेट पर पासवर्ड सेव करने की परमिशन न दें। हर बार पासवर्ड डालकर लॉगइन करें।
2. सार्वजनिक व अनजान जगहों पर लगे वाईफाई का इस्तेमाल न करें। ऐसा करने से आपकी डिवाइस में संदिग्ध लिंक्स व वायरस आदि आ सकते हैं।
3. गूगल पर दिखाए गए किसी तरह के हेल्पलाइन नंबर्स पर भरोसा न करें। यूपीआई पेमेंट की लिमिट सेट कर लें। ताकि 24 घंटे में एक निश्चित राशि ही ट्रांसफर कर सकें।
4. अपनी निजी जानकारियों को इंटरनेट पर जितना हो सके कम से कम डालें। ऐसा करने से आपकी डिजिटल सुरक्षा मजबूत होगी।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

पायनियर
नई दिल्ली, सोमवार, 15 सितंबर 2025

भारत-मॉरीशस संबंध

नातेदारी से रणनीतिक साझेदारी तक

भारत और मॉरीशस के बीच एक ऐसा गहरा नाभि-संबंध है जिसे अक्सर नाभि-संबंधी कहा जाता है, एक ऐसा बंधन जो कूटनीति और अर्थशास्त्र से कहीं आगे तक जाता है। इस रिश्ते के मूल में एक गहरा सभ्यतागत और सांस्कृतिक जुड़ाव है, जो सदियों से प्रवास, साझा विरासत और समान मूल्यों के माध्यम से पोषित हुआ है। मॉरीशस की अधिकांश आबादी भारत से जुड़ी है, जो अपनी भाषाओं, परंपराओं, खानपान, त्योहारों और आध्यात्मिक प्रथाओं को आगे बढ़ाती है जो आज भी इस द्वीप पर जीवंत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में मॉरीशस के लिए 680 मिलियन डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा, पोर्ट लुई बंदरगाह के पुनर्विकास और चागोस समुद्री संरक्षित क्षेत्र की निगरानी के लिए सैद्धांतिक समझौतों के साथ, इस प्रगति में एक और मील का पत्थर है।

इस पैकेज की रूपरेखा भारत द्वारा मॉरीशस को केवल एक भागीदार के बजाय एक परिवार के रूप में मान्यता देने को दशार्ती है। इसमें अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, राजमार्गों और रिंग रोड का विस्तार और बेहतर स्वास्थ्य सेवा जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल हैं। ये विकास मॉरीशस की अपनी जरूरतों और प्राथमिकताओं के साथ सावधानीपूर्वक संरेखित हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि नई दिल्ली का समर्थन दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता को पोषित करे।

चागोस समुद्री संरक्षित क्षेत्र के विकास में सहयोग करने और जल विज्ञान पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की प्रतिबद्धता जताकर, भारत ने मॉरीशस

को अपनी हिंद महासागर रणनीति के केंद्र में रखा है। चागोस पर ब्रिटेन के साथ संप्रभुता समझौते के बाद, मॉरीशस के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के विस्तार ने अवसरों और ज़िम्मेदारियों, दोनों को बढ़ा दिया है। भारत द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण, नेविगेशन चार्ट और जल विज्ञान संबंधी डेटा संग्रह की पेशकश, मॉरीशस को अपने जल क्षेत्र पर संप्रभुता का प्रयोग करने और साथ ही क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने का प्रत्यक्ष अधिकार देती है। यह इसलिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन हिंद महासागर में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है और भारतीय प्रभाव को घेरना चाहता है। इसके अलावा, पश्चिमी देशों की उपस्थिति पहले से ही वहाँ मौजूद है। रणनीतिक रूप से, यह सहयोग महत्वपूर्ण है। चागोस द्वीपसमूह में डिएगो गार्सिया स्थित है, जो अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा है। भारत ने मॉरीशस की संप्रभुता के लिए इस क्षेत्र पर स्पष्ट समर्थन व्यक्त किया है और साथ ही नाजुक भू-राजनीतिक जलक्षेत्रों में पोर्ट लुई की स्थिति को मजबूत किया है।

भारत के लिए, मॉरीशस उसकी ₹पड़ोसी पहले₹ नीति और हिंद महासागर के लिए उसके व्यापक ₹विजन महासागर₹ का एक स्तंभ है। मॉरीशस की समुद्री क्षमता को पोषित करके और उसकी संप्रभुता को सुदृढ़ करके, नई दिल्ली इस क्षेत्र में एक व्यापक सुरक्षा प्रदाता और प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करता है। प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम की यह टिप्पणी कि मॉरीशस ने चागोस की यात्रा के लिए ब्रिटिश पोत की बजाय भारतीय पोत को प्राथमिकता दी, कृतज्ञता और विश्वास दोनों को दशार्ती है। जैसे-जैसे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में वैश्विक शक्ति गतिशीलता तीव्र होती जा रही है, भारत और मॉरीशस के बीच बढ़ता तालमेल सम्मान, साझा इतिहास और पारस्परिक आकांक्षाओं पर आधारित कूटनीति का प्रमाण है।

भारत में डिजिटल क्रांति

जो प्रक्रिया लक्षित प्रौद्योगिकीय अंतःक्षेपों की एक श्रृंखला के रूप में शुरू हुई थी ,वह अब एक व्यापक परिवर्तन के रूप में विकसित हो चुकी है, जो भारतीय जीवन के लगभग हर पहलू जैसे अर्थव्यवस्था, शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, वाणिज्य, और देश के कोने-कोने में बसे किसानों और छोटे उद्यमियों के जीवन को भी प्रभावित कर रही है।

राव इंद्रजीत सिंह
लेखक, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं।

पिछले एक दशक में भारत में एक ऐसी डिजिटल क्रांति आई है जो असाधारण है। जो प्रक्रिया लक्षित प्रौद्योगिकीय अंतःक्षेपों की एक श्रृंखला के रूप में शुरू हुई थी ,वह अब एक व्यापक परिवर्तन के रूप में विकसित हो चुकी है, जो भारतीय जीवन के लगभग हर पहलू जैसे अर्थव्यवस्था, शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, वाणिज्य, और देश के कोने-कोने में बसे किसानों और छोटे उद्यमियों के जीवन को भी प्रभावित कर रही है।

यह यात्रा आकस्मिक नहीं थी। इसे भारत सरकार द्वारा ठोस नीति निर्धारण, अंतरमंत्रालयी सहयोग, और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से सावधानीपूर्वक प्रबंधित किया गया है। जब संबद्ध मंत्रालयों जैसेइलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), वित्त मंत्रालय (एमओएफ), कृषि मंत्रालय, और अन्य मंत्रालयोंने बड़े पैमाने में जमीनी स्तर पर परियोजनाओं को पूरा किया, तो दूसरी ओर नीति आयोग ने अभिसरण को बढ़ावा देकर, विचारों को नेतृत्व देकर, और स्केलेबल, नागरिक-प्रमुखतावाले नवाचारों की ओर प्रणाली को प्रेरित कर नीति इंजन का काम किया है।

जन धन-आधार-मोबाइल (जेएएम) ट्रिनिटी की शुरूआत के साथ इसमें एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है। लगभग 55 करोड़ बैंक खातों के खोलने के साथ-साथ, करोड़ों लोगों को, जो पहले वित्तीय प्रणाली की पहुंच से बाहर थे, उन्हें अकस्मात बैंकिंग व्यवस्था और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तक पहुंच प्राप्त हुई है। ओडिशा के एक छोटे से गांव में पहली बार बिना बिचौलिए की सहायता से एक सिंगल मदरको कल्याणकारी लाभ सीधे उनके खाते में प्राप्त करने में सक्षम बनाया गया। उनकी कहानी भारत भर के करोड़ों लोगों की कहानी बन गई है। यह वृहद वित्तीय समावेशन आंदोलन वित्त मंत्रालय के समर्थन और आधार तथा मोबाइल पैठ कीसक्षम सहायता सेअगला कदमः एक वित्तीय-प्रौद्योगिकी विस्फोट का आधार बना।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शन में विकसित एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) ने भारतीयों के लेन-देन के तरीके में क्रांति ला दी है। किसी मित्र को पैसे भेजने के एक अनूठे तरीके के रूप में शुरू किया गया यह तरीका शीघ्र ही छोटे व्यवसायों, सब्जी विक्रेताओं और गिग वर्कर्स की जीवनरेखा बन गया। आज, भारत में प्रति माह 17 बिलियन से अधिक यूपीआई के माध्यम से लेनदेन होते हैं, और यहाँ तक कि सड़क किनारे के विक्रेता वाले भी एक साधारण क्यूआर कोड के जरिए डिजिटल भुगतान स्वीकार कर रहे हैं।

इसी दौरान, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत भारत के डिजिटल अवसंरचना के मुख्य तंत्र को धीरे-धीरे और निरंतरता से तैयार किया जा रहा है। भारतनेट जैसी परियोजनाओं ने दो लाख से अधिक ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुंचाया है, जबकि इंडिया स्टैक ने कागज-रहित, उपस्थिति-रहित और नकदी-रहित सेवाओं का ढाँचा तैयार किया। डिजी-लॉकर ने छात्रों को अपने प्रमाणपत्र डिजिटल रूप में रखने, और ई-हस्ताक्षर ने महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लिए दूरस्थ प्रमाणीकरण प्रदान किया। डिजी-यात्रा एक अग्रणी पहल है जो चेहरे के पहचान की तकनीक का उपयोग करके निर्बाध, कागज-रहित और संपर्क-रहित

इसी दौरान, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत भारत के डिजिटल अवसंरचना के मुख्य तंत्र को धीरे-धीरे और निरंतरता से तैयार किया जा रहा है। भारतनेट जैसी परियोजनाओं ने दो लाख से अधिक ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुंचाया है।

हवाई यात्रा को संभव बनाती है। यह त्वरित चेक-इन, बेहतर यात्री अनुभव और बेहतर हवाई अड्डे की क्षमता में सुधार सुनिश्चित करती है, साथ ही विकेंद्रीकृत पहचान प्रबंधन के माध्यम से डेटा गोपनीयता की सुरक्षा भी करती है।यह भारतीय विमानन के भविष्य की तैयारी और यात्री-अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।ये मात्र ऐप ही नहीं हैं - ये एक डिजिटल गणराज्य की आधारशिला हैं।

डिजिटल गवर्नेंस ने भी गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) के शुभारंभ के साथ बड़ी उछाल लगाई है। सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए डिजाइन किए गए, जेमने 1.6 लाख से अधिक सरकारी क्रेताओं को 22 लाख से अधिक विक्रेताओं से जोड़ा है - जिसमें महिला उद्यमियों और एमएसएमई की बढ़ती संख्या शामिल है। राजस्थान के एक छोटे हस्तशिल्प विक्रेता के लिए, इसका अभिप्राय सरकारी संविदाओं तक पहुंच प्रदान करना था जो पहले अकल्पनीय था।

कृषि क्षेत्र, जिसे प्रायः परिवर्तन के प्रतिरोधी के रूप में देखा जाता है, ने भी डिजिटल साधनों को अपनाना शुरू कर दिया है। पीएम-किसान जैसे प्लेटफॉर्म ने यह सुनिश्चित किया कि आय सहायता किसानों तक सीधे पहुँचे। ई-नैम ने राज्यों की कृषि मंडियों को जोड़ा, जिससे किसानों को अपनी उपज के बेहतर दाम मिल सके। डिजिटल मृदा स्वास्थ्य कार्ड ने उन्हें यह समझने में मदद की कि उन्हें कौन सी फसलें उगानी चाहिए और अपनी भूमि में कौन से पोषक तत्वों का प्रयोग करना चाहिए। झारखंड के ग्रामीण-क्षेत्रों में, स्थानीय उद्यमियों द्वारा संचालित सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) उनके लिए एक प्रकार से डिजिटल जीवन रेखा बन गए, जो टेली-मेडिसिन से लेकर बैंकिंग और कौशल विकास कार्यक्रमों तक, हर चीज की पेशकश करते हैं।

महामारी भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे के लिए एक कठिन परीक्षा थी जिसमें हम बखूबी सफलहुए। स्कूल बंद होने के बावजूद, दीक्षा और स्वयं जैसे प्लेटफॉर्मों ने यह सुनिश्चित किया कि पढ़ाई अनवरत चलती रहे। लद्दाख और केरल के छात्र भी भारत भर के शिक्षकों द्वारा तैयार की गई शिक्षण सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने अपना आकार लिया, जिससे नागरिकों को एक डिजिटल आईडी के माध्यम से अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुँच प्राप्त हुई और अस्पतालों एवं राज्यों में एक सहज वातावरण बन सका।

वाणिज्य में भी एक शांत क्रांति देखी गई। डीपीआईआईटी की एक पहल, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) अब छोटी किराना दुकानों और हथकरघा बुनकरों को बड़ी ई-कामर्स कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बना रही है। डिजिटल कॉमर्स के कार्यों को एकीकृत करके, ओएनडीसी प्रतिस्पर्धा के मैदान को समतल कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छोटे व्यवसाय आसानी से लॉजिस्टिक्स, भुगतान और ग्राहक प्रतिक्रिया प्रणालियों तक पहुँच सकें।

नीति आयोग की अभिसरण भूमिका–मंत्रालयों, राज्यों, स्टार्टअप्स और उद्योग जगत को एकजुट करना है–जो सुनिश्चित करता है कि डिजिटल सार्वजनिक वस्तुएँ अंतर-संचालनीय, समावेशी और स्केलेबल हों। जैसे-जैसे भारत अपने 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, नए आयाम उभर रहे हैंः एआई-सक्षम शासन, विकेन्द्रीकृत वाणिज्य, और बहुभाषी, मोबाइल-प्रथम डिजिटल सेवाएँ जो देश के सबसे गरीब व्यक्ति तक पहुँच सकती हैं। लेकिन यह सिर्फ.एक सरकारी सफलता से जुड़ी कहानी नहीं है। यह एक राष्ट्र की कहानी है–करोड़ों नागरिकों की कहानी है जिन्होंने बदलाव को अपनाया, उद्यमियों की कहानी है जो डिजिटल रेल पर आगे बढ़े, और स्थानीय लीडरों की कहानी है जिन्होंने सेवा वितरण की नई कल्पना की।

भारत का डिजिटल दशक सिर्फ.तकनीक का नहीं है–यह बदलाव का दशक भी है और यह कहानी का अभी प्रारंभिक चरण ही है।

राजस्व चक्रों को बदलती कृत्रिम बुद्धि

वित्तीय प्रभाव दक्षता लाभ से कहीं आगे तक फैला हुआ है। स्वचालित राजस्व पहचान मासिक अंत में होने वाली देरी को समाप्त करती है जो पारंपरिक रूप से वित्तीय प्रदर्शन को अस्पष्ट करती थी।

हेमंत सोनी
लेखक, प्रौद्योगिकी के शिक्षक हैं।

दूरसंचार उद्योग एक निर्णायक मोड़ पर है। राजस्व दबाव, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और ग्राहकों की बदलती अपेक्षाओं ने पारंपरिक ऑर्डर-टू-कैश प्रक्रियाओं में गंभीर अक्षमताओं को उजागर किया है। जो प्रक्रियाएं कभी सरल बाजार परिस्थितियों में ठीक से काम करती थीं, अब विकास और ग्राहक संतुष्टि के लिए एक बड़ी बाधा बन रही हैं।

पारंपरिक दूरसंचार ऑर्डर-टू-कैश चक्र आमतौर पर प्रारंभिक ग्राहक पूछताछ से लेकर राजस्व निर्धारण तक 30-45 दिनों का होता है। इस लंबी प्रक्रिया में बिक्री, प्रावधान, बिलिंग और ग्राहक सेवा टीमों के बीच कई बार स्थानांतरण शामिल होता है। प्रत्येक संक्रमण बिंदु देरी, त्रुटियों और ग्राहकों की निराशा के अवसर पैदा करता है। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि ये मैन्युअल प्रक्रियाएँ पाइपलाइन की स्थिति और राजस्व पूवार्नुमान की सटीकता की वास्तविक समय की दृश्यता को अस्पष्ट कर देती हैं।

नई कनेक्टिविटी सेवाओं की तलाश कर रहे एक सामान्य उद्यम ग्राहक पर विचार करें। बिक्री प्रतिनिधि कई डिस्कवरी कॉल के माध्यम से आवश्यकताओं को पूरा करता है, स्प्रेडशीट का उपयोग करके मैन्युअल रूप से कोटेशन तैयार करता है, और आईटी सत्यापन की आवश्यकता वाले लीगेसी सिस्टम के माध्यम से ऑर्डर सबमिट करता है। सेवा प्रावधान टीमें फिर इन आवश्यकताओं की व्याख्या करती हैं, और अक्सर ऐसी जानकारी की कमी का पता लगा लेती हैं जिससे अतिरिक्त ग्राहक संपर्क की आवश्यकता होती है। इस बीच, बिलिंग प्रणालियाँ मैन्युअल कॉन्फिगरेशन का इंतजार कर रही हैं, और ग्राहकों की ऑनबोर्डिंग विभागों में बिखरी हुई है। यह बिखरा हुआ दृष्टिकोण कई गंभीर कमजोरियाँ पैदा करता है। जब अपेक्षाएँ सभी टचपॉइंट्स पर एक समान नहीं होतीं, तो ग्राहक अनुभव प्रभावित होता है।

एआई-संचालित स्वचालन राजस्व चक्र के प्रत्येक चरण में बुद्धिमान निर्णय लेने की प्रक्रिया को लागू करके इन प्रक्रियाओं का मौलिक रूप से पुनर्गठन कर रहा है। आधुनिक दूरसंचार ऑपरेटर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लागू कर रहे हैं जो ग्राहकों की आवश्यकताओं का विश्लेषण करते हैं, इष्टतम सेवा कॉन्फिगरेशन का अनुमान लगाते हैं, और स्वचालित रूप से उपयुक्त प्रावधान वर्कफ़्लो शुरू करते हैं।

पूवार्नुमानित विश्लेषण अब बिक्री टीमों को औपचारिक मूल्यांकन प्रक्रियाओं में प्रवेश करने से पहले उच्च-प्रवृत्ति वाले ग्राहकों की पहचान करने में सक्षम बनाता है। प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण तकनीकी आवश्यकताओं को स्वचालित रूप से निकालने के लिए ग्राहक संचार का विश्लेषण करता है, जिससे खोज चक्र का समय हफ़्तों से घटकर दिनों में आ जाता है। गतिशील मूल्य निर्धारण एल्गोरिदम वास्तविक समय में प्रस्ताव की लाभप्रदता को अनुकूलित करने के लिए प्रतिस्पर्धी स्थिति, ग्राहक इतिहास और बाजार स्थितियों पर विचार करते हैं। जब कोई ग्राहक किसी प्रस्ताव को स्वीकार करता है, तो स्वचालित वर्कफ़्लो एक साथ सेवा प्रावधान शुरू करते हैं, बिलिंग मापदंडों को कॉन्फिगर करते हैं, इन्वेंट्री सिस्टम को अपडेट करते हैं, और इंस्टॉलेशन गतिविधियों को शेड्यूल करते हैं। यह समानांतर प्रसंस्करण दृष्टिकोण सटीकता में सुधार करते हुए ऑर्डर-टू-कैश चक्र समय को 60-70 प्रतिशत तक कम कर देता है। दूरदर्शी दूरसंचार प्रदाता एआई कार्यान्वयन के बाद मापनीय सुधार प्रदर्शित करते हैं। क्षेत्रीय वाहक बिक्री चक्र समय में उल्लेखनीय कमी की रिपोर्ट करते हैं जबकि उद्धरण सटीकता में पर्याप्त सुधार प्राप्त करते हैं।

वित्तीय प्रभाव दक्षता लाभ से कहीं आगे तक फैला हुआ है। स्वचालित राजस्व पहचान मासिक अंत में होने वाली देरी को समाप्त करती है जो पारंपरिक रूप से वित्तीय प्रदर्शन को अस्पष्ट करती थी। पूवार्नुमानित विश्लेषण ग्राहक संबंधों में पहले ही अप-सेलिंग के अवसरों की पहचान कर लेता है, जिससे प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बेहतर ग्राहक अनुभव ऐसे उद्योग में वफादारी को बढ़ावा देता है जहाँ स्विचिंग लागत में लगातार गिरावट जारी है।

सफल परिवर्तन के लिए तकनीकी क्षमताओं के साथ-साथ संगठनात्मक तत्परता पर भी सावधानीपूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जब पारंपरिक विभागीय सीमाएँ समाप्त हो जाती हैं, तो अंतर-कार्यात्मक सहयोग आवश्यक हो जाता है। कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में तकनीकी कौशल और प्रक्रिया परिवर्तन, दोनों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। परिवर्तन प्रबंधन पहलों को केवल दक्षता के बजाय ग्राहक-केंद्रित परिणामों पर जोर देना चाहिए। डेटा की गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण सफलता कारक के रूप में उभर रही है। संगठनों को ऐसे डेटा शासन ढाँचों में निवेश करना चाहिए जो बहु-स्रोत प्रणालियों में सटीकता सुनिश्चित करें। ग्राहक जानकारी स्वचालित प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रवाहित होने के कारण गोपनीयता सुरक्षा सर्वोपरि बनी हुई है।

पूरी तरह से स्वचालित ऑर्डर-टू-कैश प्रक्रियाओं की ओर विकास तेजी से बढ़ रहा है। संवादात्मक एआई जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ ग्राहकों को प्राकृतिक भाषा इंटरैक्शन के माध्यम से जटिल सेवाओं को कॉन्फिगर करने में सक्षम बनाएँगी। ब्लॉकचेन-आधारित स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिलिंग और भुगतान प्रक्रियाओं को पूरी तरह से स्वचालित कर सकते हैं। हालाँकि, सबसे सफल कार्यान्वयन स्वचालन और मानवीय विशेषज्ञता के बीच संतुलन बनाए रखेंगे। मानक लेनदेन को संसाधित करने और पैटर्न की पहचान करने में अकउत्कृष्ट है, लेकिन जटिल उद्यम संबंधों के लिए अभी भी मानवीय निर्णय और रचनात्मकता की आवश्यकता होती है। भविष्य उन संगठनों का है जो ग्राहक निष्ठा को बढ़ावा देने वाले परामर्शात्मक संबंधों को बनाए रखते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमताओं को सोच-समझकर एकीकृत करते हैं।

दूरसंचार ऑर्डर-टू-कैश प्रक्रियाओं का परिवर्तन केवल परिचालन सुधार से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करता है; यह ग्राहक-केंद्रित व्यावसायिक मॉडलों की ओर एक मौलिक बदलाव है जो वास्तविक समय में बाजार के अवसरों पर प्रतिक्रिया देते हैं। जो संगठन इस विकास को अपनाते हैं, उन्हें ऐसे प्रतिस्पर्धी लाभ मिलेंगे जो राजस्व चक्र दक्षता से कहीं आगे तक फैले हुए हैं।

आप की बात

प्रदूषण नीति पूरे देश के लिए हो

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों पर प्रतिबन्ध केवल दिल्ली एनसीआर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ही होना चाहिए. उनका तर्क सही है. क्योंकि प्रदूषण की समस्या सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही नहीं है पूरे देश में ही है. अतः जो भी नियम/योजनाएं बनें वे देशभर के लिए ही होना चाहिए. एक बात और है पटाखों से प्रदूषण सिर्फ दिवाली पर ही होता है. जबकि प्रदूषण अनेक कारणों जैसे उद्योगों, वाहनों, धूल,ध्वनि,धुएं,-साफ- सफाई के अभाव आदि के फैलने से भी रोजाना होता है. इसके प्रति सरकार की नीति/नियम बने ही नहीं बल्कि प्रभावी रूप कारगर भी होने चाहिए। खाने-पीने के मिलावटी सामान व दवाइयों पर भी सख्त निगरानी की व्यवस्था होनी चाहिए. क्योंकि जैसे पटाखों के प्रदूषण से बीमारी फैल सकती है तब पूरे वर्ष इनसे फैलने वाली बीमारियों का डर तो और भी ज्यादा बना रहता है. सबसे अधिक बीमारी की जड़ तो "आर्थिक भ्रष्टाचार" है। जिसमें राजनीतिक चन्दा,भाई-भतीजावाद, सरकारी मशीनरी में आम काम "रोको-टोको और पाओ" आदि. जिसे ईडी, सीबीआई व अन्य सरकारी/गैरसरकारी भ्रष्टाचार उन्मूलन संस्थानों द्वारा जड़ से मिटाने/काटने से संभव है. जिससे सभी तरह की प्रदूषण का समूल नाश करना संभव है. साथ ही अनेक तरह की बीमारियों का इलाज भी संभावित हो सकेगा।

– **शंकुतला महेश नेनावा**, इंदौर

भारत को नेपाल से उम्मीदें

नेपाल मे संसद भंग कर पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की जी ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप मे शपथ ले ली है ! नेपाल के इतिहास मे पहली प्रधानमंत्री महिला बनी ! जनता जनार्दन ने पूर्व सरकार को नेस्तनाबूत कर दिया और जता दिया की नेपाल की जनता जनार्दन भ्रष्टाचार, और अवरुद्ध विकास , बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और मोनोपाली के सख्त खिलाफ है ! इतिहास गवाह है की नेपाल भारत के संबंधो की बात करे तो दोनों देशों के संबंध मैत्री भाव और सहयोगी रहे , नेपाल मे भी हिंदुस्तान की झलक और संस्कृति सभ्यता और परम्परा इत्यादि पुराने समय से प्रचलित है ! अंतरिम प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति सदभाव और सम्मान रखती हैं ! भारत को नेपाल से उम्मीदे हैं दोनों देशों मे शांति, सौहार्द और सामाजिक, राजनैतिक संबंध अनवरत मजबूत रहे ! विगत वर्षो की सरकारों मे भारत और नेपाल के संबंधो मे थोड़ी किरकिरी बनी हुई थी ! नेपाल सरकार ने भारत से समजस्य और सहयोगकी भावनाओं से खरा उतरना चाहिए ! और मोदीजी और भारत को आपने मैत्री भाव से मजबूत करना चाहिए ! हालांकि चीन , पाकिस्तान, अमेरिका, रूस जैसे देशों की नजर भी नेपाल पर होती है ! और चीन की संगत का कु असर नेपाल मे विगत वर्षो नजर भी आया ! अच्छा तो यही होगा नेपाल आत्म निर्भर मोदीजी के भारत का सच्चा और अच्छा मित्र बनने की मिशाल देश दुनियां को दिखाए !

– **योगेश जोशी**, बड़वाह, मप्र

गृह मंत्री की हुंकार

पिछले दो-तीन सालों से विशेष करके मोदी सरकार के इस तीसरे कार्यकाल की शुरूआत से हि हमारे ग्रह मंत्री अपनी इसी एक बात पर हर तरह से कायम है एवं उसे वह पूरी तरह से लागू करने पर प्रयत्न शील भी है ।वह है देश के ग्रह मंत्री अमीत शाह का हमारे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का कमीटमेंट। अतः हम हमारे ग्रह मंत्री अमीत शाह की इसी कारण दिल से सराहना भी करना चाहते हैं। उनका अपने काम के प्रति जो जूनून है वह काबिले तारीफ है, कहना न होगा कि वे देश की दो बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए काफी समय से प्रयत्नशील है। एक जम्मू कश्मीर,विशेष करके कश्मीर घाटी से आतंकवाद को समाप्त करना एवं दूसरा देश से नक्सलवाद को भी खत्म करना। और इन दोनों की समाप्ति का उनका कमीटमेंट काबिले-तारीफ है। कारण उनका अपने काम के प्रति जो जूनून है हम उसके लिए उन्हें धन्यवाद कहना चाहते है। कारण आज कश्मीर घाटी में हर तरह से शान्ती स्थापित हो चुकी है एवं वहां आज एक लोकतांत्रिक सरकार भी कार्य कर रही है। इसी तरह से देश के महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं कर्नाटक के कुछ जिलों में व्याप्त नक्सलवाद को भी समाप्त करने के लिए हमारी सेना हर तरह से प्रयत्नशील है। हम ग्रह मंत्री अमीत शाह के इन प्रयासों की सराहना करते हैं। इस इक्कीसवीं सदी में आम आदमी अपने देश को आज तरक्की राह पर निरन्तर आगे बढ़ते देखना चाहता है।

– **मनमोहन राजावत राज**, शाजापुर

भारत की धैर्यपूर्ण कूटनीति

भारत और अमेरिका के संबंधों का विश्लेषण यह बताता है कि दोनों देशों की नीतियाँ केवल तात्कालिक लाभ तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दीर्घकालीन वैश्विक शक्ति संतुलन पर आधारित हैं। जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन यह कहते हैं कि ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत पर शुल्क लगाना अनुचित था और भारत ने धैर्यपूर्वक प्रतिक्रिया दी, तो यह भारत की परिपक्व कूटनीति का प्रमाण है। भारत ने प्रतिघात की जल्दबाजी नहीं दिखाई, बल्कि अपनी नीतियों को व्यापक अंतरराष्ट्रीय समीकरणों और भविष्य की साझेदारियों के अनुरूप साधा। तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो शुल्क और व्यापारिक प्रतिबंध केवल अस्थायी आर्थिक दबाव उत्पन्न करते हैं, लेकिन दीर्घकाल में ये वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, निवेश प्रवाह और नवाचार आधारित उद्योगों को गहरा प्रभावित करते हैं। यदि भारत आक्रामक प्रतिक्रिया करता तो न केवल द्विपक्षीय व्यापार प्रभावित होता, बल्कि अंतरराष्ट्रीय निवेशकों में अस्थिरता का संदेश जाता। विवेकपूर्ण और संतुलित नीति ने भारत को एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थापित किया है, जिससे उसकी वैश्विक छवि और मजबूत हुई है। दीर्घकालिक प्रभाव यह है कि भारत अब न केवल अमेरिका बल्कि यूरोपीय संघ, आसियान और अफ्रीकी देशों के लिए भी स्थिर और भरोसेमंद शक्ति बनता जा रहा है।

– **अवनीश कुमार गुप्ता**, आजमगढ़

https://t.me/AllNewsPaperPaid

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 179

एथनॉल की अनिवार्यता

इस वर्ष मोटर वाहनों के ईंधन में 20 फीसदी एथनॉल मिलाने (ई20 ईंधन) का लक्ष्य निर्धारित समय से पांच साल पहले हासिल करने की घोषणा की गई है। इसे आगे बढ़ाकर ई27 तक ले जाने का इरादा जाहिर किया गया है जो स्वागतयोग्य है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब भारत के ताप बिजली घरों के कारण ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन तेजी से बढ़ रहा है और शहरों में प्रदूषण की समस्या एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकट में तब्दील होती जा रही है। ई20 ईंधन देश की 2070 तक विशुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने तथा आयातित कच्चे तेल पर देश की निर्भरता कम करने की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के अनुरूप है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि एथनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2014-15 में जब एथनॉल मिश्रण केवल 1.5 फीसदी था, से लेकर 2024-25 तक सरकारी तेल कंपनियों ने 1,44,087 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा बचाई है। यह करीब 2,45,000 टन कच्चे तेल के बराबर हैऔर इससे अनुमानतः इतने कार्बन डाईऑक्साइड की बचत हुई जो शायद 30 करोड़ वृक्ष लगाने से बचता। नीति आयोग के एक अध्ययन के अनुसार, जीवन-चक्र उत्सर्जन के आधार पर गन्ना और मक्के से बने एथनॉल से होने वाला ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पेट्रोल की तुलना में क्रमशः 65 फीसदी और 50 फीसदी कम हैं। एथनॉल उत्पादन किसानों के लिए भी लाभकारी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यह मक्का, गन्ना और धान की पराली के लिए एक स्थायी बाजार उपलब्ध कराता है। इस उपलब्धि के साथ भारत अब ब्राजील, अमेरिका और यूरोप जैसे विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है, जो पेट्रोल में एथनॉल का मिश्रण करते हैं।

उपभोक्ताओं के नजरिये से देखें तो इस बदलाव का बेहतर प्रबंधन किया जाना चाहिए था। हालांकि ई20 चुनिंदा पंपों पर ही उपलब्ध था लेकिन अब यह देश के करीब 90,000 पंपों पर इकलौता विकल्प है। आश्चर्य नहीं है कि माइलेज और एक्सिलरेशन पर ई20 के प्रभाव को लेकर बहुत बड़े पैमाने पर असमंजस के हालात बन गए हैं। यूरोप और अमेरिका में वाहन चालकों को यह विकल्प दिया गया है कि वे अपने वाहन की उम्र के मुताबिक ई10, ई15 या ई20 ईंधन डलवाएं। 2020 में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने कहा कि ई20 के साथ ई10 ईंधन का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि वाहनों का बेहतरीन प्रदर्शन सुनिश्चित हो सके। उसने कहा कि रबर के हिस्से या गास्केट आदि को बदलना एक बड़ा काम होगा। भारत में अधिकांश कार इंजनों को ई10 ईंधन के लिए तैयार किया जाता है। केवल एक अप्रैल 2025 के बाद बने इंजन ही ई20 ईंधन के लिए बने हैं। वाहन निर्माताओं ने पहले यह संकेत दिया था कि वाहनों के प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है। अब लगता है कि उन्होंने सरकार के नजरिये को स्वीकार कर लिया है और वे उपभोक्ताओं को आवश्स्त कर रही हैं कि वाहनों के प्रदर्शन पर पड़ने वाला असर बहुत मामूली है। उद्योग जगत के विचारों में यह भिन्नता शायद ही चिंताओं को दूर कर सके।

लंबी अवधि में भले ही हवा की गुणवत्ता या किसानों की आय के रूप में जैव ईंधन के व्यापक लाभ तात्कालिक परिवर्तन की कीमत पर भारी पड़ें लेकिन इस नीति से अनचाहे परिणाम भी जुड़े हुए हैं। इनमें से एक है खाद्यान्न बनाम ईंधन की बहस क्योंकि किसानों को जैव ईंधन संबंधी फसलें उगाने पर खाद्यान्न फसलों की तुलना में बेहतर आय हासिल हो रही है। उदाहरणके लिए मक्के की कीमतें जैव ईंधन की मांग बढ़ने के साथ ही दो सालों में 1,800 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,500 रुपये प्रति क्विंटल हो गई हैं। इससे किसानों की आय तो बढ़ी है लेकिन पोल्ट्री और पालतु पशुओं के खाद्यान्न पर इसका विपरीत असर हुआ है। मक्के के उत्पादन का 70 फीसदी इसी पशु आहार में जाता है। इसके अलावा मोटे अनाज तथा तिलहन की खेती की जमीन में अब मक्का उगाया जा रहा है।

इसके अलावा अन्य जैव ईंधन वाली फसलों यानी चावल और गन्ने की खेती मौसम के लिहाज से बहुत संवेदनशील होती है। पंजाब, हरियाणा तथा महाराष्ट्र में उनका रकबा बढ़ने का देश की जल सुरक्षा पर बुरा असर हो सकता है। इन प्रतिस्पर्धी मांगों का प्रबंधन करना होगा तथा सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि खाद्य और जल सुरक्षा की कीमत पर ईंधन सुरक्षा न हो।

आखिर क्यों होता है सत्ता प्रतिष्ठान का पतन?

सक्रिय और टिकाऊ और यहां तक कि शाश्वत होने के लिए राज्य को किसी नेता, पार्टी या विचारधारा की आवश्यकता नहीं होती है। उसके लिए जरूरत होती है गतिशील और मजबूत संस्थाओं की।

राष्ट्र की बात

शेखर गुप्ता

क्या सख्त या नरम सत्ता जैसा कुछ होता है? अगर हम कहें कि सत्ता केवल सत्ता होती है तो? उसमें यह कुव्वत होनी चाहिए कि वह एकजुट, स्थिर और व्यवस्थित बनी रहे। यह अंतिम पंक्ति मेरी नहीं है। किसकी है यह मैं आगे बताऊंगा।

नेपाल को ही देख लें। जेनजी (युवाओं) ने राजधानी काठमांडू में एक दिन प्रदर्शन किया और संवैधानिक ढंग से चुनी सरकार अगले दिन गिर गई। उपमहाद्वीप में तीन साल में ऐसा तीसरा उदाहरण दिखा है। इससे पहले श्रीलंका (कोलंबो जुलाई 2022) और बांग्लादेश (ढाका अगस्त 2024) में हम ऐसा होते देख चुके हैं। जैसा हम पत्रकारिता में कहते हैं, यह तीन उदाहरणों वाले नियम को साबित करता है। सोशल मीडिया पर तमाम लोग जिनमें अधिकांश भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध हैं, लिख रहे हैं कि कुछ ताकतें भारत में मोदी सरकार के साथ ऐसा ही करना चाहती हैं।

हमें अपवादों पर भी नजर रखनी चाहिए। हर सरकार का पतन जनता के विरोध प्रदर्शन के कारण ही नहीं होता। यह उदाहरण भड़काऊ हो सकता है लेकिन क्या आपको याद है कि पाकिस्तान में 9 मई, 2023 को क्या हुआ था?

इमरान खान के समर्थकों ने एक शहर में नहीं बल्कि कई शहरों में दंगा किया था। वे लाहौर के जिन्ना हाउस तक में घुस गए थे जो कोर कमांडर का घर था। वहां के हालात कोलंबो, ढाका या काठमांडू की तुलना में सत्ता को उखाड़ फेंकने के अधिक करीब थे। सेना की कठपुतली बनी और बहुत नापसंद की जा रही सरकार ने सबसे लोकप्रिय नेता को जेल में बंद कर दिया था।

परंतु वह 'क्रांति' 48 घंटे में ही खत्म हो गई। इमरान खान अब भी जेल में हैं और अब तो उन्हें 14 वर्ष की सजा सुना दी गई है। चुनावों में छेड़खानी से दोबारा सत्ता हासिल कर वही गठबंधन अब भी शासन में है और देश के सामाजिक-आर्थिक तथा लोकतांत्रिक कष्ट जस के तस हैं। 250 से अधिक प्रदर्शनकारी नेताओं पर सैन्य अदालतों में मुकदमा चल रहा है। सत्ता कहीं अधिक मजबूत नजर आ रही है।

क्या पाकिस्तान में शासन इसलिए बचा रहा क्योंकि वह सख्त है जबकि श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की सरकारें सख्त नहीं थीं? यह तो आसिम मुनीर भी नहीं मानते होंगे। वरना वह 16 अप्रैल के अपने कुख्यात भाषण में यह न कहते कि 'हमें एक सख्त राज्य बनना होगा।'

सच तो यह है कि पाकिस्तान में सरकार बची रही क्योंकि वह अब भी क्रियाशील देश है। क्रियाशील देश का मूल है कानून-व्यवस्था। यहां सक्रियता अहम है न कि सख्त या नरम होना। जब किसी देश में कानून-व्यवस्था विफल होते हैं तो कोलंबो, ढाका और अब काठमांडू जैसे हालात बनते हैं।

सत्ता परिवर्तन केवल लोकतांत्रिक आकांक्षा हो सकती है परंतु इसे हासिल करने के लिए कुछ दिनों के विरोध प्रदर्शन, दंगे और आगजनी से ही बात नहीं बनेगी। इसके लिए सालों का नहीं तो भी महीनों का संघर्ष जरूरी है ताकि राजनीतिक प्रतिरोध खड़ा किया जा सके। इसके लिए लोगों तक पहुंचना होगा और आपको जो क्रांति चाहिए उसकी तैयारी करनी होगी। यह चुनावों या व्यापक जनांदोलन के जरिये संभव होगा। काठमांडू में एक झटके में जो हुआ वह हमें बताता है कि क्रियाहीन राज्य कैसा होता है। वहां चुनी हुई सरकार थी लेकिन उसके नेता शासन संबंधी पहली शर्त ही नहीं निभा पा रहे थेः लोकतांत्रिक धैर्य।

आधी उम्र तक छापामार हमले सीखने और करने वाले नेता सत्ता में आने के बाद दलबदल और नित नए गठजोड़ बनाने में ही फंसे रहे और इन निर्वाचित नेताओं को पास 'दूसरे' नाराज लोगों से निपटना ही नहीं आता था। माओवादी एक समय परिवर्तन के वाहक थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्हें लगा ही नहीं कि वे ही लोग उनसे नाराज भी हो सकते हैं। जब लोग नाराज हुए तो भरोसा और विश्वसनीयता लौटाने के लिए उन्हें बातचीत की जरूरत थी गोलियों की नहीं।

बंदूकें लोकप्रियता और सत्ता हासिल करने का उपाय थीं। इन नेताओं ने 2008 में राजतंत्र समाप्त होने के बाद विगत 17 सालों में लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए कुछ नहीं किया। ऐसा किया होता तो उन्हीं संस्थाओं ने उनकी रक्षा की होती। अगर प्रदर्शनकारी केवल सेना पर विश्वास कर रहे हैं तो पता चल जाता है कि नेपाल में क्रांतिकारी राजनीतिक खेमा किस कदर नाकाम रहा। उन्होंने कभी क्रियाशील राज्य बनाया ही नहीं।

सख्त राज्य बड़ा नाजुक हो सकता है। मैं जॉर्जिया की बात करता हूं, जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा था। इतिहास में सोवियत संघ से सख्त राज्य शायद ही कोई रहा हो। परंतु 1988-89 में जॉर्जिया में पहला विरोध प्रदर्शन शुरू होते ही वहां घबराहट फैल गई। उसने विशेष बलों और हथियारों से लेस केजीबी वाली रेड आर्मी भेजी, जिसने गोलियां चलाईं और जहरीली गैस का भी इस्तेमाल किया। अंततः यह बिखर गया। अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता थी और पार्टी को पता नहीं था कि असहमतियों को कैसे संभाला जाए। असंतुष्ट लोगों को तो मारा जा सकता था या कहीं दूर भेजा जा सकता था मगर व्यापक जनप्रदर्शन से निपटना इसे नहीं आता था।

हमें जल्द ही यह बात समझ आई जब मेरे तत्कालीन संपादक अरुण पुरी के साथ बूटा सिंह ने हमें खाने पर बुलाया। बूटा राजीव गांधी सरकार में गृह मंत्री थे। उन्होंने बताया कि हाल में उन्होंने रूस के विदेश मंत्री एदुआर्द शेवर्नदेज (जॉर्जिया मूल के) को आमंत्रित किया था और शेवर्नदेज ने 'मुझसे पूछा कि हम लोग लाखों लोगों के प्रदर्शनों से कैसे निबटते हैं, जबकि उनकी सेना ने तिबिलिसी में छोटी सी भीड़ पर ही जहरीली गैस छोड़ दी'।

बूटा सिंह ने हमें बताया, 'मैंने कहा, मान्यवर मैं आपको सीआरपीएफ की कुछ कंपनियां उधार दे सकता हूं।' सबक यह था कि हुकूमत को कानून-व्यवस्था बनाकर रखनी ही होगी। इसकी तीन शर्तें हैं- सही प्रशिक्षण वाली पर्याप्त पुलिस, वार्ता का कौशल और लोकतांत्रिक धैर्य हो, या जिम्मेदारियां बदलने की तैयारी हो।

आज सख्त राज्य के लिए विपक्ष की गैरमौजूदगी को जरूरी मानने की गलती की जाती है। हकीकत इसके उलट है। विपक्ष दबाव कम करने वाला वॉल्व होता है। लोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोर कमांडर के घरों को निशाना बनाने के बजाय विपक्ष के जरिये अपनी भड़ास निकाल लेते हैं। हमारे चारों पड़ोसी देशों ने अपने विपक्षियों को अलग-अलग स्तर पर ठिकाने लगाने का काम किया।

क्या ऐसा भारत में 'टूल-किट' के जरिये सत्ता परिवर्तन हो सकता है? हमारे यहां ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि संवैधानिक लोकतांत्रिक देशों में 'हुकूमत' नहीं होतीं। भारत में हर समय दर्जनों विरोध हो रहे होते हैं मगर बीते 50 साल में दो ऐसे मौके आए जब सड़क से सत्ता को गंभीर चुनौती मिली। पहला था जयप्रकाश नारायण (जेपी) का नवनिर्माण आंदोलन जो 1974 में आरंभ हुआ और जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे हड़ताल ने जिसे और मजबूत कर भारत को एक तरह से थाम दिया। इसके बावजूद वे इंदिरा गांधी को नहीं हटा सके। इसके लिए चुनाव की मदद लेनी पड़ी।

दूसरा आंदोलन था अन्ना हजारे का कथित भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, जिसे टेलीविजन और विपक्ष के कद्दावरों का समर्थन हासिल था, खास तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, जिसने जेपी का भी साथ दिया था। परंतु संप्रग-2 जैसी कमजोर सरकार भी उससे निपटने में कामयाब रही।

जन लोकपाल विधेयक पर आधी रात के बाद तक बहस चली और मामला निपट गया। संसद और निर्वाचित नेताओं पर स्वयंभू गांधी अन्ना हजारे के तीखे तानों के जवाब में दिवंगत शरद यादव ने फॉरबिसगंज से चुने गए समाजवादी पार्टी के सांसद पकौड़ी लाल की ओर इशारा किया और कहा, 'जरा पकौड़ी लाल नाम के किसी हिंदुस्तानी की बारे में सोचिए। इस व्यवस्था के कारण ही इनके जैसा साधारण आदमी यहां तक पहुंच पाया है। आप इस व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं?' अन्ना आंदोलन उसी समय समाप्त हो गया। सत्ता को बचाने के लिए संसद खड़ी हो गई थी।

आखिर में मैं आपको बताता हूं कि 'राज्य को एकजुट बने रहने के लिए अपने भीतर से ताकत की जरूरत होती है' वाली टिप्पणी किसने की थी। 2010 में जब घाटी में पत्थरबाजी और आतंक चरम पर था तब मुख्य धारा की कई आवाजें उठ रही थीं और कह रही थीं, 'अगर कश्मीरी इतने असंतुष्ट हैं तो उन्हें जाने क्यों न दें?' उस समय के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एमके नारायणन ने बातचीत के दौरान अपने पेट की ओर मुट्ठी तानते हुए यह बात कही थी। यह बात 15 साल पुरानी है और मुझे उम्मीद है कि इसे दोहराने पर वह मुझे माफ कर देंगे। अब देखिए घाटी कहां से कहां पहुंच चुकी है। यह वही संप्रग-2 सरकार थी जिसे आम तौर पर 'नरम राज्य' कहा जाता था।

बिजली उत्पादन में कोयले से जुड़े अहम सवाल

जमीनी हकीकत

सुनीता नारायण

जलवायु परिवर्तन और दुनिया के विकासशील देशों की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने की चुनौती के बीच एक बड़ा अहम सवाल यह है कि हम कोयले और उससे बनने वाली बिजली का क्या करें? तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियससे नीचे रखने के लिए दुनिया का कार्बन बजट तेजी से खत्म हो रहा है, जो एक ऐसा सुरक्षा उपाय है जो हमें पूरी तरह तबाही की स्थिति से बचाएगा।

दरअसल अब हमें ऐसे समाधान चाहिए जो सभी के हित में काम करें। यहीं पर कोयले का सवाल पेचीदा हो जाता है। यह कहना आसान है कि 'कोयले को जमीन में ही रहने दिया जाए' यानी बिजली बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल न करें क्योंकि यह हमारे वातावरण को ग्रीनहाउस गैसों से भर देता है। लेकिन सवाल यह है कि ऊर्जा की कमी वाली दुनिया में यह कैसे कारगर होगा?

यह भी सच है कि कई वर्षों से कार्बन उत्सर्जन कम करने का उपदेश देने वाले देश बिजली के लिए कोयले का इस्तेमाल करते रहे हैं। इन देशों की वजह से जो उत्सर्जन हुआ, वह अभी भी हमारे वातावरण में मौजूद है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल है। हालांकि अब ये देश अधिकांशतः दूसरे जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस को अपना रहे हैं जो थोड़ा बहुत ही स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है और इससे भी छोटे पैमाने पर ही सही ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है।

यूरोपीय संघ (ईयू) ने अमेरिका के साथ एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत उसने तीन साल के लिए हर साल 250 अरब डॉलर के ऊर्जा उत्पाद यानी प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल और कोयला आयात करने का वादा किया है। मुमकिन है कि यह एक हवाई वादा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि यूरोपीय संघ ने अब जीवाश्म ईंधन से जुड़े रहने के लिए सहमति जता दी है जो उसकी हरित ऊर्जा योजनाओं के विपरीत है।

ऐसे में भारत जैसे देशों को क्या करना चाहिए, जहां ऊर्जा की कमी का समाधान निकालने के साथ ही किफायती तरीके से विकास करने की सख्त जरूरत है और देश को तरह की कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ रहा है? ऐसे में सवाल यह है कि अगर हम स्वच्छ ऊर्जा के बलबूते विकास करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो क्या हमें कोयले पर निर्भरता छोड़ देनी चाहिए, या हमें पुरानी और नई ऊर्जा के स्रोतों को संतुलित करने के तरीके खोजने चाहिए?

मैं हमेशा से यह कहती रही हूं कि भारत सरकार की ऊर्जा बदलाव की योजना हमारे लिए सही रास्ता है जो कोयले को पूरी तरह हटाने के बजाय सिर्फ कम करने पर आधारित है। तथ्य यह है कि वर्ष 2030 तक हमारी ऊर्जा की मांग दोगुनी हो जाएगी, और यह बढ़ोतरी स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों, खासकर पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा से पूरी होगी। वर्ष 2030 तक, बिजली की मांग का 70-75 फीसदी पूरा करने के बजाय कोयला सिर्फ 50 फीसदी मांग ही पूरा कर पाएगा।

हमें इस बारे में भी बात करनी चाहिए कि इसका क्या अर्थ है और कोयले पर आधारित बिजली क्षेत्र से ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। मैं जानती हूं कि यह एक वर्जित विषय है क्योंकि यह मानना बेहतर है कि कोयला जल्द ही इतिहास का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन अब हम थोड़ा व्यावहारिक होते हैं। हमें किसी भी कीमत पर सभी क्षेत्रों में उत्सर्जन कम करना होगा। हमें स्थानीय हवा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी ऐसा करना चाहिए, ताकि हवा में मौजूद उन जहरीले प्रदूषक तत्त्वों को कम किया जा सके जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बढ़ाते हैं। हमें वैश्विक स्तर पर जलवायु की स्थिति बेहतर करने के लिए भी ऐसा करना चाहिए। अगर हम ऐसी रणनीतियां बना पाते हैं जो दोनों ही स्तर पर काम करे तब यह हमारे लिए सफलता वाली स्थिति होगी।

मेरे सहयोगियों ने 'भारत में कोयला-आधारित ताप विद्युत क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने से जुड़े रोडमैप' शीर्ष वाली रिपोर्ट में भी यही बात की है। हमारे विश्लेषण से पता चलता है कि, अगर देश ताप विद्युत संयंत्र को कार्बन मुक्त करने की रणनीति अपनाता है तब इसके कारण उत्सर्जन दो अन्य क्षेत्रों, लोहा और इस्पात एवं सीमेंट से भी कम हो सकता है।

रोडमैप में पहला कदम यह है कि मौजूदा संयंत्र को अपनी श्रेणी के सबसे अच्छे संयंत्र जैसी मानक कुशलता हासिल करने की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर अहम तकनीक पर आधारित विद्युत संयंत्र जो मौजूदा कुल संयंत्र का लगभग 85 फीसदी हैं उन्हें कम से कम अपनी श्रेणी में शीर्ष स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले संयंत्रों (जैसे टाटा पावर की 40 साल पुरानी ट्रॉम्बे इकाई, तेलंगाना राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा संचालित कोतागुडम ताप विद्युत स्टेशन या जेएसडब्ल्यू का तोरनगल्लू संयंत्र) के उत्सर्जन मानक तक पहुंचना चाहिए। इससे कुल उत्सर्जन में काफी सुधार होगा।

दूसरा कदम है कच्चे माल के तौर पर कोयले की जगह दूसरे विकल्प का इस्तेमाल करना। कई बिजली संयंत्र पहले से ही जैविक उत्पादों के अवशेष (बायोमास) का इस्तेमाल, कोयले के साथ मिलाकर कर रहे हैं। हमारा सुझाव 20 फीसदी बायोमास का इस्तेमाल अनिवार्य करना है, जिससे बड़े पैमाने पर कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी। लेकिन इन सबके लिए उत्सर्जन लक्ष्यों और स्पष्ट निर्देशों के साथ एक बेहतर योजना की दरकार है। उदाहरण के तौर पर अभी सरकार की योजना उन्नत ताप विद्युत संयंत्र बनाने की है, जो निस्संदेह पुरानी परंपरागत तकनीक से अधिक कुशल और स्वच्छ होगी।

हालांकि सही नीतिगत प्रोत्साहन के बिना, इनमें से 40 फीसदी नई पीढ़ी की इकाइयां 50 फीसदी प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) से कम पर काम करती हैं, जिसका मतलब है कि उनका उत्सर्जन, पुरानी तकनीक वाले संयंत्र से ज्यादा है। इसकी असल वजह यह है कि मौजूदा मेरिट ऑर्डर डिस्पैच सिस्टम यानी बिजली कंपनियों को सबसे सस्ती बिजली पहले बेचने के नियम तय करने वाली प्रणाली, उत्पादन की लागत पर आधारित है।

पुराने बिजली संयंत्र से बिजली बनाना सस्ता होता है, क्योंकि उनकी पूंजीगत लागत कम हो चुकी है, या ऐसी इकाइयों से भी बिजली बनाना सस्ता होता है जिनमें तकनीक या रखरखाव में कम निवेश हुआ है। यही सबसे बड़ी खामी है जो अब भी भी कोयले को बादशाहत की स्थिति में बनाए हुए है। इसे वास्तव में खत्म करने की जरूरत है और ऐसा करना संभव हो सकता है।

(लेखिका सेंटर फॉर साइंस ऐंड एन्वायरनमेंट से जुड़ी हैं)

आपका पक्ष

नेपाल के पुनर्निर्माण में भारत का दायित्व

लेख 'संकट के मुहाने पर नेपाल' में भारी उपद्रव, हिंसा और विनाशलीला की धरातल की स्थिति, पूर्व सरकारों के पतन और उसके बाद नेपाल की राजनीति में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के लिए चुनौतियों पर सार्थक चर्चा करता है। नेपाल में शांति बहाल हो रही है। पिछले दो दशकों में नेपाल की राजनीति पर दृष्टि डालें तो प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली, शेर बहादुर देउबा और पुष्प कमल दहल प्रचंड के बीच ही सत्ता की भागीदारी हो रही थी। यह सभी वामपंथी रहे हैं और चीन के नजदीकी रहे हैं। इस सत्ता चक्र ने देश को भ्रष्टाचार में झोंक दिया था, जिसके कारण नेपाल में सत्ता के विरुद्ध आक्रोश सिमर रहा था जो असंगठित रूप से फूट पड़ा। यह बहुत आश्चर्यजनक है कि युवा वर्ग जेनजी के आक्रोश ने देश को बुरी तरह तहस नहस कर डाला और संभवतः नेपाल को पुनर्निर्माण के लिए भविष्य की सरकार का एक कार्यकाल भी कम होगा। अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने 5 मार्च, 2026 को आम चुनाव घोषित करके अपनी सीमाएं तय कर दी हैं। इसलिए अचानक कौन से उपद्रवी तत्त्व देश को बरबाद करने पर तुले थे, उनकी जांच पड़ताल संभवतः उनकी प्राथमिकता न हो, परंतु भविष्य की सरकार की यह जिम्मेदारी है कि आंदोलनकारियों के बीच इन उपद्रवियों की तह तक जांच हो। यह तो निश्चित है कि आंदोलन में अगर विदेशी हाथ था तो वह विफल हो गया। नेपाल में सुशीला कार्की की अंतरिम सरकार गठित होते ही, शांति स्थापित होने लगी। ऐसी स्थिति में भारत की नेपाल के पुनर्निर्माण में भागीदारी का दायित्व है। भारत को पड़ोसी देशों में अधिक सक्रियता के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है।

विनोद जौहरी, दिल्ली

नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने रविवार को काठमांडू में नवनिर्मित गृह मंत्रालय भवन में पदभार ग्रहण किया

भारत की धैर्यपूर्ण कूटनीति

भारत और अमेरिका के संबंधों का विश्लेषण यह बताता है कि दोनों देशों की नीतियां केवल तात्कालिक लाभ तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दीर्घकालीन वैश्विक शक्ति संतुलन पर आधारित हैं। जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन यह कहते हैं कि ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत पर शुल्क लगाना अनुचित था और भारत ने धैर्यपूर्वक प्रतिक्रिया दी तो यह भारत की परिपक्व कूटनीति का प्रमाण है। भारत ने प्रतिघात की जल्दबाजी नहीं दिखाई, बल्कि अपनी नीतियों को व्यापक अंतरराष्ट्रीय समीकरणों और भविष्य की साझेदारियों के अनुरूप साधा। अगर भारत आक्रामक प्रतिक्रिया करता तो न केवल द्विपक्षीय व्यापार प्रभावित होता, बल्कि अंतरराष्ट्रीय निवेशकों में अस्थिरता का संदेश जाता। दीर्घकालिक प्रभाव यह है कि भारत अब न केवल अमेरिका बल्कि यूरोपीय संघ, आसियान और अफ्रीकी देशों के लिए भी स्थिर और भरोसेमंद शक्ति बनता जा रहा है। संरक्षणवाद और व्यापार युद्धों की प्रवृत्तियों के बीच भारत का धैर्यपूर्ण रुख उसे वैश्विक व्यवस्था में एक स्थिरकारी शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। यही संतुलन और कूटनीतिक भविष्य में भारत को वैश्विक आर्थिक नेतृत्व और नैतिक मार्गदर्शन दोनों की केंद्रीय भूमिका में स्थापित कर सकती है।

अवनीश कुमार गुप्ता, प्रयागराज

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

इजरायल ने रविवार को उत्तरी गाजा पर हमले तेज कर दिए जिससे एक और ऊंची इमारत ध्वस्त हो गई तथा कम से कम 12 फिलिस्तीनी मारे गए। इस बीच, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो रविवार को इजरायल पहुंचे।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

Join The Official Private Channel

I have opened entry to my private channel.

Support me by joining my private channel

AND GET EARLIEST AND RELIABLE SOURCE TO READ NEWSPAPERS DAILY.

Click below to

Join

1) Times of India
2) Hindustan Times
3) Business line
4) The Indian Express
5) Economic Times
6) The Hindu
7) Live Mint
8) Financial Express
9) Business standard
+All Editorial PDFs

नवभारत टाइम्स • विचार

नवभारत टाइम्स | मुंबई | सोमवार, 15 सितंबर 2025

> इतिहास में अनेक छोटे और बड़े आंदोलनों ने यह साबित किया है कि नैतिक ब्रह्मांड का चाप (आर्क) भले ही लंबा हो, वह अंततः न्याय की ओर ही झुकता है। – *मार्टिन लूथर किंग जूनियर*

संतुलन की उम्मीद

करीब हफ्तेभर की उथलपुथल के बाद नेपाल का फिर से शांति की ओर बढ़ना अच्छी खबर है। नवनियुक्त अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बेदाग छवि और संतुलित नजरिये के लिए जानी जाती हैं। उनके नेतृत्व में वहां जल्द चुनाव होने और हालात के सामान्य होने की उम्मीद है।

बेदाग छवि । सुशीला कार्की नेपाल की मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। उनके पास राजनीतिक अनुभव बेहद कम है। इसके बावजूद Gen-Z ने उनके नाम पर सहमति जताई, क्योंकि बाकी राजनेताओं से उसका भरोसा उठ चुका है। कार्की भ्रष्टाचार विरोधी सख्त रुख के लिए जानी जाती हैं।

नेपाल में अंतरिम सरकार

चुनाव का ऐलान । सुशीला कार्की के लिए इन अपेक्षाओं पर खरा उतरना आसान नहीं। अच्छी बात यह है कि अंतरिम सरकार के गठन के साथ ही अगले साल मार्च में चुनाव कराने का भी ऐलान कर दिया गया। नेपाल ने इस मामले में बांग्लादेश से सबक लिया। ढाका में भी जन आंदोलन ने चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका था। हालांकि एक साल से ज्यादा वक्त बाद भी तय नहीं हो सका है कि चुनाव कब होंगे।

भारत के हक में स्थायित्व। नेपाल का जल्द से जल्द सामान्य होना भारत के लिए भी अच्छा होगा। दोनों देश आपस में इस कदर जुड़े हैं कि काठमांडू की कोई भी हलचल नई दिल्ली में महसूस हुए बिना नहीं रह सकती। फिर पड़ोस में स्थायित्व इसलिए भी जरूरी है, ताकि दूसरे तत्वों को फायदा उठाने का मौका न मिले। बांग्लादेश की अस्थिरता का उदाहरण सामने है, जहां पाकिस्तान अब भारत विरोधी नैरेटिव बनाने में लगा हुआ है।

रिश्तों में बैलेंस। भारत-नेपाल की सीमाएं ही नहीं जुड़तीं, दोनों की संस्कृति, रहन-सहन, खानपान भी बहुत हद तक साझा है। लेकिन, केपीएस ओली के दौर में दूरी साफ महसूस की जा सकती थी। वह नेपाल को धीरे-धीरे चीन की तरफ शिफ्ट कर रहे थे। यहां तक कि लिपुलेख का मुद्दा भी उन्होंने चीन के सामने उठाया। इससे नेपाल में ही वह वर्ग बहुत नाराज था, जो पेइचिंग को संशय की नजरों से देखता है। सुशीला कार्की से द्विपक्षीय रिश्तों में ज्यादा बैलेंस की उम्मीद है। मणिपुर से पीएम नरेंद्र मोदी का नेपाल को संदेश देना इस रिश्ते की अहमियत बताता है।

नश्तर

बिन पेंदी नैतिकता

खबरिया चैनल पर सत्ता और विपक्ष के नेताओं की मुट्ठियां तन ही गई थीं कि ऐंकर ने एक प्रफेसरनुमा राजनीतिक विश्लेषक से सवाल पूछ लिया- राजनीतिक बहस में इतनी गिरावट क्यों आ रही है? उन्होंने ओशोनुमा पोज बनाया और माथे पर लकीरें लाते हुए बोले-समाज की नैतिकता गिरी है। मेरी चेतना का पॉइंटर इसी वाक्य पर अटक गया, इसके बाद उन्होंने जो भी कहा वह अपन के लिए शोर था। सोचने लगा आखिर नैतिकता कितनी ऊंचाई पर थी कि लगातार गिरते हुए भी पूरी तरह गिर नहीं पा रही है। मेरा चिंतन मोड ऑन होने ही वाला था कि बेटे की आवाज सुनाई दी- पापा आपके पैर के पास मेरी नैतिक शिक्षा की किताब गिर गई है। उठा दीजिए। मैंने किताब उठाकर उसे दी, फिर सोचा इससे थोड़ी तो नैतिकता उठी ही होगी। इस तरह तो मैं रुपया भी उठा सकता हूं। अगर फर्श पर पड़ा रुपया उठाने से बाजार में रुपया उठ जाता तो मैं खुद को कितना निर्मल महसूस करता, पर ऐसा होना नहीं था तो नहीं ही हुआ।

सौरभ श्रीवास्तव

मैं नैतिकता से चला था, पर रुपये पर पहुंच गया। यह भी नैतिकता में गिरावट ही है। नैतिकता कब से गिरनी शुरू हुई इसका ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं मिलता, पर इतना याद है वह उठी कभी नहीं। किसी ने ऐसा नहीं लिखा कि फलां साब के इस काम से नैतिकता उठी है। प्रेमचंद अपने आलोचनात्मक निबंधों में समाज में नैतिकता के गिरने का जिक्र करते थे। उन्हें गए आज 89 साल हो गए, नैतिकता है कि गिरे ही जा रही है। वर्तमान के तमाम समाजशास्त्री, आलोचक और प्रवचन देने वाले नैतिकता के गिरने की बात करते हैं। विपक्ष पीएम से कहता है कि वह नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दें। सत्ता पक्ष के लोग विपक्षियों से कहते हैं कि जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं, वहां के मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दें, लेकिन कोई इस्तीफा नहीं देता। मेरी मानिए तो देना भी नहीं चाहिए, जिस चीज का कोई भरोसा ही नहीं कि वह कहां तक और कब तक गिरेगी, उसे आधार क्यों बनाया जाए? जिस रोज कोई ज्ञानी यह कहेगा कि अब नैतिकता सतह को लग गई है और नहीं गिरेगी, उस दिन नेता सोचेंगे कि इस्तीफा देना है या नहीं। फिलहाल तो वे मस्त हैं और हम गिरती नैतिकता की चिंता करते हुए सेहत गिरा रहे हैं।

एकदा

संकलन : दीनदयाल मुरारका

आमजन के प्रति सम्मान

लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बनने से पहले केंद्रीय गृहमंत्री थे। उनका निवास स्थान दो रास्तों से जुड़ा था- एक जनपथ की ओर, दूसरा अकबर मार्ग की ओर। एक दिन दो श्रमिक महिलाएं सिर पर घास का गट्ठर लिए अकबर मार्ग की ओर वाले रास्ते से निकल रही थीं। चौकीदार ने उन्हें रोककर डांटना शुरू कर दिया, क्योंकि यह रास्ता शास्त्री जी के निवास से होकर जाता था। तभी बरामदे में बैठे शास्त्री जी ने यह सब देखा और बाहर आकर चौकीदार से पूरी बात पूछी। चौकीदार ने बताया कि वह उन्हें इस रास्ते से जाने से मना कर रहा है, क्योंकि यह सरकारी निवास का हिस्सा है। शास्त्री जी ने शांति से कहा, 'क्या तुम नहीं देख रहे हो कि उनके सिर पर भारी बोझ है? यदि यह रास्ता उनके लिए छोटा और सुविधाजनक है, तो इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए?' यह घटना दर्शाती है कि सच्चे नेता वही होते हैं, जो छोटे-छोटे कार्यों में भी अपने कर्तव्य, सहानुभूति और सेवा की भावना को नहीं भूलते।

Subrata Dhar
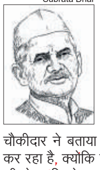

भारत-चीन सीमा विवाद पर बातचीत में प्रगति तो है, लेकिन उलझन भी कम नहीं

बॉर्डर पर कैसे बदलेंगे हालात

भारत और चीन के बीच संबंध सुधारने वाली पहल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का SCO समिट में हिस्सा लेने चीन जाना और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मिलना अहम रहा। इसने सबका ध्यान खींचा। क्या इसके आधार पर यह मान लिया जाए कि अब धीरे-धीरे भारत और चीन के बीच सब ठीक हो जाएगा? इस सवाल का जवाब सीधा और स्पष्ट हां में नहीं हो सकता क्योंकि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद जब तक कायम है, तब तक भारत के लिए यह कठिन चुनौती बना हुआ है।

पूनम पाण्डे

CDS का बयान। भारत और चीन के बीच विशेष प्रतिनिधियों की बैठक हुई। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा भी हो गई। इसका मतलब यह नहीं कि चुनौती कम हो गई है। प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के तुरंत बाद ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने एक कार्यक्रम में कहा कि कई चुनौतियां हैं, जिनका सामना भारत आज कर रहा है, भविष्य में भी करता रहेगा। इस सिलसिले में उन्होंने सीमा विवाद का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चीन के साथ यह मुख्य चुनौती है। CDS जनरल अनिल चौहान ने यह भी कहा कि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर है। दरअसल, पाकिस्तान और चीन की जुगलबंदी का जिक्र हमेशा होता आया है और ये आर्म्ड फोर्सेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है भी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी चीन ने पाकिस्तान को मदद पहुंचाई थी और भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ने खुद उसका जिक्र किया था।

बैठक-दर-बैठक
- बैठकों के लंबे दौर के बाद डिसइंगेजमेंट पर बात बनी
- अब होगी डी-एस्केलेशन पर सहमति बनाने की कवायद
- सीमा पर इन्फ्रास्ट्रक्चर, हथियारों की रेंज का भी है सवाल

कोर कमांडर मीटिंग। भारत और चीन WMCC (वर्किंग मेकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन) मीटिंग से लेकर कोर कमांडर मीटिंग्स तक में कहते रहे हैं कि दोनों देशों के बीच जो विवाद हैं, उनका समाधान बातचीत से ही निकलेगा। कोर कमांडर स्तर की मीटिंग की अहमियत दोनों देश मानते हैं। इसका सबूत यह भी है कि अब दोनों देशों के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव (SR) के बीच वेस्टर्न सेक्टर की तरह ईस्टर्न सेक्टर और सेंट्रल सेक्टर में भी जनरल लेवल मेकेनिज्म बनाने को लेकर सहमति बन गई है। जनरल लेवल मेकेनिज्म का मतलब है, ऐसी व्यवस्था जिसमें भारत और चीन की सेना के बीच कोर कमांडर स्तर की मीटिंग होती है। LAC पर तनाव शुरू होने से पहले कोर कमांडर स्तर पर मीटिंग का कोई सिस्टम नहीं था।

डी-एस्केलेशन पर ध्यान। भारत और चीन की सेना के बीच ईस्टर्न लद्दाख में डिसइंगेजमेंट तो पूरा हो चुका है। यानी दोनों देशों की सेनाएं इस कदर आमने-सामने किसी भी पॉइंट पर नहीं हैं जहां एकदम झड़प की नौबत आ सकती है। अब डी-एस्केलेशन की बात हो रही है। इसका मतलब है कि जो बड़े हथियार और सैन्य साजोसामान हैं जैसे- टैंक, आर्टिलरी गन उन्हें पीछे करना। दोनों देशों की तरफ से डिप्लोमेटिक लेवल पर कहा गया है कि डी-एस्केलेशन के लिए बातचीत की जाएगी। लेकिन मिलिट्री स्तर पर इसका ध्यान भी रखना होगा कि डी-एस्केलेशन किस तरह हो।

कौन कितना पीछे जाए। मिलिट्री एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सिर्फ पीछे जाने को राजी होना ही समाधान नहीं है क्योंकि असल पेच यह है कि कौन कितना पीछे जाएगा। मान लीजिए ये तय किया जाता है कि दोनों सेनाएं अपने हथियारों को 100-100 किलोमीटर पीछे कर दें। लेकिन यह भारतीय सेना को मंजूर नहीं होगा क्योंकि जरूरत पड़ने पर उस दूरी से आगे आने में चीनी सैनिकों को कम समय लगेगा। भारत के सैनिकों को हो सकता है कि उनसे कई गुना ज्यादा वक्त लगे क्योंकि चीन ने LAC के पास तक पहुंचने के लिए जैसा इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाया है, वैसा अभी भारत में नहीं है। यह भी देखना होगा कि जिन हथियारों को पीछे करने की बात की जाएगी उनकी रेंज कितनी है। हो सकता है, 100 किलोमीटर पीछे जाकर भी चीन के हथियारों की जद में LAC रहे। ऐसे में भारत के पास मौजूद हथियारों की रेंज कितनी है वह भी ध्यान में रखना होगा।

लगेगा वक्त । LAC पर डिसइंगेजमेंट पूरा होने से पहले कोर कमांडर स्तर की 22 मीटिंग हुई। कुछ मीटिंग दो-दो दिन चली और 22 वीं मीटिंग तो कई हफ्तों तक चली, तब जाकर सहमति बनी। अब जब कोर कमांडर स्तर की मीटिंग होगी तो उसमें भी किसी सहमति तक पहुंचने में हो सकता है कि लंबा वक्त लगे। साथ ही अभी ये भी तय करना होगा कि डी-एस्केलेशन पर बातचीत होनी है या फिर पहले उन चार पॉइंट्स पर जहां नो-पेट्रोलिंग जोन बने हैं, जहां डिसइंगेजमेंट के बाद न तो भारतीय सैनिक पेट्रोलिंग कर रहे हैं ना ही चीनी सैनिक।

जिसके हर कौर में है सेहत की ख़ूबसूरती

AI Image

जीवन आनंद
शैलेंद्र पांडेय

कभी मसाले दुनिया की सबसे कीमती चीज थे और तनख्वाह मिलती थी नमक में। संस्कृतियों से होकर इतिहास के पन्नों तक, हर जगह दखल रहा खाने-पीने की चीजों का। यही खानपान फिर से बदल रहा है इंसानों को। हाल में यूनिसेफ का एक सर्वे आया, जिसके मुताबिक अब दुनिया में कुपोषण से ज्यादा बड़ी समस्या मोटापे की है। 5 से 19 साल की 20% आबादी जूझ रही है अधिक वजन की समस्या से। और इसकी वजह है खानपान, जिसमें घुसपैठ हो चुकी है अल्ट्रा-प्रॉसेस्ड फूड और सॉफ्ट-कोल्ड ड्रिंक्स की। यह सर्वे सेहत के प्रति चिंता तो जगाता ही है, साथ में याद दिलाता है सादे और स्वास्थ्यकर भोजन की जरूरत व इसके आनंद की।

'सादा जीवन उच्च विचार' - यह दर्शन रहा है भारतीय जीवन का। सात्विक आहार को जोड़ा गया है शुद्ध विचार और संतुलित मन से। कहा गया है - जैसा अन्न जाता है, वैसा मन हो जाता है। सादगी में जीवन की मिठास है और पोषण से भरपूर खाने में जीवन की ऊर्जा। ऐसा भोजन हमें याद दिलाता है कि जिंदगी का असली सुख जटिलता में नहीं, बल्कि सरलता में छुपा है। अक्सर चटपटे स्वादों और तैलीय व्यंजनों की भीड़ हमें भुला देती है कि सादगी में भी सुंदरता होती है।

भोजन हमारे मूड और सेहत - दोनों पर असर डालता है। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने समझाया है कि हमारे पेट और दिमाग के बीच गहरा संबंध है, जिसे gut-brain axis कहा जाता है। आसान शब्दों में समझें तो यह दोतरफा संवाद है दिमाग और पेट के बीच का। हमारे पेट में मौजूद खरबों छोटे-छोटे जीवाणु, जिन्हें हम gut microbiome कहते हैं, लगातार मेसेजबाजी करते रहते हैं हमारे दिमाग से। जब हम स्वास्थ्यकर भोजन करते हैं, तो ये जीवाणु हमें अच्छा महसूस कराते हैं, मूड हल्का हो जाता है, चिंता कम होती है और मन में संतुलन का भाव आता है। घर में बने खाने का पहला निवाला मन को जो तृप्त कर जाता है, उसके पीछे यही संदेश है। इस समय शरीर में serotonin और dopamine जैसे खुशी देने वाले हार्मोन निकलते हैं, जो हमें भीतर से प्रसन्न करते हैं।

अच्छा खाना किसी परिभाषा में नहीं बंधा। उम्र बढ़ती है, जगह बदलती है, तो जरूरतें भी बदल जाती हैं। खुद को ढालना पड़ता है हालात के हिसाब से। खाना भी ऐसा ही है, हमारे नजरिये जैसा - परिस्थितियों के अनुसार बदलता हुआ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है विविधता और संतुलन।

यह कहना नाइंसाफी होगी कि भोजन केवल पेट का मसला है। यह पहचान है संस्कृतियों की। रोटी का हर कौर, चावल का हर दाना जोड़ता है हमें उन खेतों से, जहां से उनकी शुरुआत हुई। जड़ों से यह जुड़ाव तभी बना रहता है, जब हम किसी को उसके मूल स्वरूप में अपनाएं। जो प्रॉसेस्ड हुआ, वह तो बदल गया।

सादा और स्वास्थ्यकर खाना उत्सव है। न तो दिखावा है, न ही आडंबर।

कांटे की बात

> मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, वे सब आसिम मुनीर के आदेश पर हो रहे हैं। हमारा देश इस समय 'आसिम लॉ' के तहत चल रहा है। मुनीर ने नैतिकता को खत्म कर दिया है और देश को 'डकैत और डफर्स अलायंस' के तहत चला रहे हैं।

इमरान खान -पूर्व प्रधानमंत्री, पाकिस्तान

डेटा Window

पिज्जा बर्गर का दिखने लगा असर दुनिया में तीन गुना बढ़े मोटे लोग

यूनिसेफ ने 190 से अधिक देशों में बच्चों व किशोरों में मोटापे और कुपोषण का हिसाब लगाया है। उसके मुताबिक, इस सदी की शुरुआत से लेकर अब तक दुनिया में तीन गुना ज्यादा लोग मोटे हो चुके हैं :

बढ़ता मोटापा

वर्ष 2000	वर्ष 2025
3% मोटापे की दर	9.4% मोटापे की दर

2000 से अब तक मोटापा 3 गुना से ज्यादा बढ़ा

20% दुनिया में मोटापे से शिकार बच्चे व किशोर

अंडरवेट

9.2% 5–19 साल के बच्चों/युवाओं में कम वजन की दर

13% 25 साल पहले (वर्ष 2000 के आसपास)

Adobe Stock

सूरत-ए-हाल

चिली	जर्मनी	अमेरिका
27%	25%	21%

UAE	नीयू
21%	38%
कुक द्वीप समूह	नाउरू
37%	33%

वजह

फास्टफूड, तला-भुना, कोल्ड ड्रिंक, अल्ट्रा-प्रॉसेस्ड फूड। उदाहरण- मेक्सिको में बच्चों की दैनिक कैलरी का 40% हिस्सा इन्हीं से।

'टिफिन बैठक' पहल कैसे बन गई यादगार

'संगठन की शक्ति वहीं खिलती है, जहां कार्यकर्ता तपस्वी बनकर खड़े होते हैं'– यही दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवन यात्रा और उनके सामाजिक-सांगठनिक दृष्टिकोण का मूल मंत्र रहा है। नरेंद्र मोदी ने हमेशा कार्यकर्ताओं को संगठन का हृदय माना। उन्हें तैयार करना, प्रशिक्षित करना और सशक्त बनाना अपने प्राथमिक कार्यों में रखा।

बी एल संतोष

हर गांव में शाखा हो । नरेंद्र मोदी RSS के प्रचारक बने 1970 के शुरुआती दौर में। 1977 में आपातकाल के बाद, जब वे विभाग प्रचारक के रूप में एक कुशल संगठनकर्ता बनकर उभरे, तब उनकी कार्यशैली का मुख्य आधार कार्यकर्ता निर्माण रहा। 1980 के दशक में गुजरात में संगठन का विस्तार बहुत सीमित था। उस समय किसी एक तालुका में शाखा स्थापित करना भी बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। लेकिन मोदी की दृष्टि अलग थी। उनका मानना था, 'हर गांव में शाखा होनी चाहिए।'

गणवेश पर जोर । संघ के 60 वर्ष पूरे होने पर 1985 में कर्णावती (अहमदाबाद) में एक विशाल शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में लगभग 5000 कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। शिविर की पूर्व तैयारी में मोदी गांव-गांव जाकर युवाओं से संपर्क करते और उन्हें गणवेश खरीदने हेतु प्रेरित करते। परिणामस्वरूप, सैकड़ों नए युवा न केवल शिविर में पहुंचे बल्कि संगठन से स्थायी रूप से जुड़ भी गए।

योजनाबद्ध सोच का संदेश । मोदी कार्यकर्ताओं को योजनाबद्ध और व्यवस्थित रूप से काम करना सिखाते थे। उदाहरण के लिए, 1980 के दशक की शुरुआत में राजकोट के पी.डी. मालवीय कॉलेज में आयोजित संघ शिक्षा वर्ग में भाग लेने वाले कार्यकर्ता याद करते हैं कि उन्होंने स्थानीय लोगों से सर्वे कर परिणामों को सांख्यिकीय विधियों के माध्यम से प्रस्तुत करने का नया प्रयोग कराया।

कॉमनरूम

कार्यकर्ताओं की खोज-खबर । नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को आचरण और शिष्टाचार के व्यावहारिक उदाहरणों से प्रेरित करते थे। मोदी कठिन परिस्थितियों एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के समय कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत नैतिक सहयोग दिया करते थे।

टिफिन बैठक । 1987 में BJP की गुजरात इकाई के संगठन मंत्री बनकर उन्होंने कार्यकर्ता निर्माण का यही काम राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए भी करना शुरू किया। मोदी व्यक्तिगत आचरण के माध्यम से भी कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास और क्षमता बढ़ाते थे। BJP में संगठन मंत्री रहते हुए उन्होंने 'टिफिन बैठक' जैसी पहल से कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को संगठन से भावनात्मक रूप से जोड़ा। संगठन निर्माण में वह केवल ढांचे और रणनीति तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संवेदनशील और दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता बनने की शिक्षा दी।

जड़ों की सिंचाई । नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण स्पष्ट था - संगठन की असली ताकत कार्यकर्ताओं में है। अनुशासन, समर्पण और सेवा की भावना से भरे ऐसे कार्यकर्ता किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हैं। यही कारण है कि आज संगठन जीवंत सांस्कृतिक चेतना बन चुका है। मोदी की कार्यकर्ता-निर्माण की यात्रा आने वाली पीढ़ियों के लिए यह संदेश देती है कि यदि जड़ों को सींचा जाए, तो शाखाएं अपने आप फलती-फूलती हैं।

(लेखक BJP के राष्ट्रीय महासचिव हैं)

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें www.speakingtree.nbt.in

जीवन एक मिशन है, निजी स्वार्थ में खपाने की चीज़ नहीं

श्री श्री आनंदमूर्ति

आज की दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। विज्ञान, तकनीक, शिक्षा और विचार - हर क्षेत्र में लगातार बदलाव हो रहा है। यदि कोई व्यक्ति कहे कि 'बस, मैं अब और आगे नहीं बढ़ूंगा', तो उसका ठहर जाना वास्तव में ठहरना नहीं, बल्कि पीछे खिसकना होगा। जब पूरी दुनिया आगे बढ़ रही हो और आप अपनी जगह खड़े रह जाएं, तो धीरे-धीरे आप दूसरों से पिछड़ जाते हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई नाव नदी के बहाव में खड़ी रहे। वह आगे नहीं बढ़ेगी तो पानी का बहाव उसे पीछे ले जाएगा।

इसीलिए कहा गया है कि जीवन एक मिशन है। यह केवल दिन काटने या रोजमर्रा की भागदौड़ के लिए नहीं। जीवन का सही उद्देश्य है - 'आत्ममोक्षार्थ जगद्धिताय च', यानी अपने आत्मिक उत्थान के लिए और समाज की भलाई के लिए जीना। आज जब दुनिया जलवायु परिवर्तन, युद्ध, असमानता और गरीबी जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, तब यह सिद्धांत और भी प्रासंगिक हो जाता है।

AI Image

अगर हम केवल अपनी मुक्ति, अपनी सफलता और अपने सुख-सुविधा की ही सोचेंगे, तो यह स्वार्थ होगा। हमें अपनी साधना और आत्मिक प्रगति के साथ-साथ समाज की समस्याओं की ओर भी देखना होगा। जब कोई भूखा हो, तो उसके सामने जाकर उपदेश या सलाह देने से पहले उसे भोजन देना जरूरी है। जब कोई युद्ध या हिंसा से पीड़ित हो, तो उसकी सुरक्षा और मदद करना सेवा है। और जब लोग शिक्षा और नैतिक मार्गदर्शन से वंचित हों, तो उन्हें सच्चाई और आदर्शों का रास्ता दिखाना भी महत्वपूर्ण है।

सेवा के अलग-अलग रूप हैं - शारीरिक मदद, सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और आध्यात्मिक मार्गदर्शन। इनमें से हर सेवा का अपना महत्व है। कोई भी सेवा छोटी नहीं होती। हां, कुछ का असर तुरंत दिखता है और कुछ का असर स्थायी होता है। भूखे को भोजन तुरंत राहत देता है, पर शिक्षा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन जीवनभर का सहारा बन जाते हैं। इसलिए आज के दौर में हमें यह समझना होगा कि जीवन ठहरने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए है।

प्रस्तुति : दिव्यचेतनानंद अवधूत

मीम बहार

ये भाई नेपाल में शांति खोजने आया था फिर जो हुआ, वो इतिहास है

UK के ट्रैवल ब्लॉगर हैरी बाइक से जब काठमांडू पहुंचे, तो Gen Z ने विद्रोह कर दिया। उनकी पूरी कवरेज को यूट्यूब पर 20M व्यूज मिले हैं।

रीडर्स मेल
www.edit.nbt.in

हिंदी से आत्मीयता

13 सितंबर के लेख 'सिनेमा ने साहित्य से क्या लिया' स्पष्ट करता है कि विदेशों में हिंदी की लोकप्रियता बढ़ाने में हिंदी फिल्मों की अहम भूमिका रही है। राज कपूर से लेकर शाहरुख खान तक, भारतीय सिनेमा ने वैश्विक दर्शकों को हिंदी से जोड़ा है। किंतु दुख की बात है कि हिंदी सिनेमा से जुड़े अधिकांश लोग हिंदी भाषा से आत्मीय जुड़ाव नहीं रखते। स्क्रिप्ट और संवाद रोमन लिपि में लिखे जाते हैं, जिससे भाषा की गहराई प्रभावित होती है। लेख यह भी दर्शाता है कि जब सिनेमा साहित्य से जुड़ता है, तो वह अधिक अर्थपूर्ण बनता है।

वीणा सिन्हा, ईमेल से

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

आर.एन.आई. पंजीयन नंबर 1613/1957 स्वत्वाधिकारी बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के लिए आर. कृष्णमूर्ति द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 से प्रकाशित और उनके द्वारा (1) टाइम्स ऑफ इंडिया सबर्बन प्रेस, आकुर्ली रोड, निकट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, कांदिवली (पू.) मुंबई 400101 एवं (2) टाइम्स ऑफ इंडिया प्रिंट सिटी, प्लॉट नं. 4, टी.टी.सी. इंडस्ट्रियल एरिया, ठाणे बेलापुर रोड, ऐरोली, नवी मुंबई-400708. फोन नं. (022) 2760 9999 ; फैक्स:(022) 2760 5275। फोन मुंबई: (022) 66353535, 22733535 रेस्पांस: (022) 66353636, 22733636 फैक्स: (022) 22731889, 22731144, कांदिवली (022) 28872324 से मुद्रित। स्थानीय संपादक (मुंबई) : सुंदर चंद ठाकुर (पी. आर. बी. अधिनियम के अंतर्गत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी) सर्वाधिकार सुरक्षित। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। सड़क व रेल परिवहन सेवा शुल्क: मुंबई, ठाणे व रायगढ़ जिलों के बाहर 1.00 रुपया। विमान सेवा शुल्क: रायपुर, नागपुर, गोवा एवं वाया 2.00 रुपये, इंदौर, चेन्नै एवं वाया 3.00 रुपये, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोचीन, कोयम्बतूर, एरनाकुलम, हैदराबाद, कोझीकोड, मंगलूर, त्रिवेंद्रम, उदयपुर, वाइजग एवं वाया 4.00 रुपये, दिल्ली, कोलकाता, एवं वाया 5.00 रुपये।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

मैक्रोज़ में सुधार

भारत कम मुद्रास्फीति और अपेक्षाकृत उच्च विकास की अवधि के लिए तैयार प्रतीत होता है

एन अगस्त 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति में वृद्धि से न तो सरकार और न ही आरबीआई चिंतित होंगे, भले ही यह अनुमान लगाया जा रहा हो कि यह वृद्धि दर अगस्त 2025 में 1.5 प्रतिशत से अधिक होगी। मुद्रास्फीति दर में गिरावट का नौ महीने का सिलसिला टूट गया। 2.1% पर, यह RBI के 2%-6% के आरामदायक बैंड के भीतर मामूली रूप से है, जिसमें कोई वास्तविक मैक्रोइकॉनॉमिक जोखिम नहीं है। सरकार को शहरी और ग्रामीण स्तरों पर खाद्य मुद्रास्फीति को कम होते हुए देखकर खुशी होगी। विशेष रूप से सब्जियों और दालों की कीमतों में क्रमशः 15.9% और 14.5% की कमी उत्साहजनक होती। जब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त खाद्यान्न प्रावधान के साथ जोड़ा जाता है, तो खाद्य कीमतों में यह गिरावट इन आवश्यकताओं की सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित करती है। अन्य आवश्यकताएं, जैसे कपड़े और जूते, आवास, और ईंधन और प्रकाश, सभी में मुद्रास्फीति कम बनी हुई है, और जुलाई की तुलना में अगस्त में कम है। जैसा कि चीजें हैं, भारत का मैक्रोइकॉनॉमिक दृष्टिकोण पिछले साल के बिल्कुल विपरीत दिखता है। अपेक्षाकृत कम विकास, उच्च मुद्रास्फीति परिदृश्य से, भारत अब उच्च विकास और कम मुद्रास्फीति देख रहा है।

दूसरे शब्दों में, पिछले साल इसी समय विकास और मुद्रास्फीति के बीच का अंतर लगभग 2.1 प्रतिशत अंक था। इस साल, यह लगभग 5.5 प्रतिशत अंक है, जो एक स्वागत योग्य और बड़ा अंतर है। बेशक, जीडीपी और मुद्रास्फीति के आंकड़ों के बारे में पूछे जाने वाले सवाल जायज़ हैं, लेकिन ये सवाल पिछले साल भी जायज़ थे, इसलिए इनसे दोनों वर्षों की तुलना कम नहीं होती।

भविष्य की ओर देखते हुए, निवेश का समग्र दृष्टिकोण अभी भी अनुकूल प्रतीत होता है। यदि भारत अमेरिका की माँगों को स्वीकार कर लेता है और रूसी तेल की खरीद बंद कर देता है, तब भी आर्थिक प्रभाव सीमित रहने की संभावना है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें अपेक्षाकृत कम हैं, इसलिए रूस द्वारा दी जा रही छूट 2022 जितनी आकर्षक नहीं है। इसलिए, तेल के लिए अन्य देशों का रुख करने से होने वाली लागत वृद्धि सीमित रहने की संभावना है।

परिणामस्वरूप, यदि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है, तो भारत के भीतर अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव सीमित रहने की संभावना है। दूसरी ओर, नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।

ब्याज दरों में कटौती के कारण अधिकांश कीमतों में गिरावट आने की संभावना है, इसलिए ब्याज दरों पर भी इसका प्रभाव उसी दिशा में होगा। पहली तिमाही में कम ब्याज दर और उच्च वृद्धि दर ने उम्मीदें बढ़ा दी हैं कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति सितंबर के अंत में अपनी अगली बैठक में ब्याज दरों में और कटौती करेगी। हालाँकि, मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए, यह कदम जल्दबाज़ी भरा हो सकता है। भारत और अमेरिका के बीच नए सिरे से बने सौहार्दपूर्ण संबंधों की प्रगति के आधार पर, दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती की संभावना अधिक है।

आशा की किरण

संरक्षण का एक समावेशी दृष्टिकोण अधिक आवासों की रक्षा कर सकता है । सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में खारे पानी के मगरमच्छों

टी का हालिया सर्वेक्षण भारत में संरक्षण के लिए एक उल्लेखनीय प्रगति है। जनगणना कुल संख्या और जनसांख्यिकीय विविधता में वृद्धि दर्शाती है, जो एक पारिस्थितिक सफलता का संकेत देती है जो इस बात का भी सूचक है कि कैसे वन्यजीव कानून और संरक्षण नीति धीरे-धीरे बाघ और हाथी सहित मुट्ठी भर करिश्माई प्रजातियों तक ही सीमित रह गई है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के शुरुआती वर्षों में, संरक्षण अनुपातहीन रूप से मेगाफौना पर केंद्रित था, जिसकी अपील जनमत को प्रेरित कर सकती थी। खारे पानी के मगरमच्छों पर ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए उनकी पुनर्प्राप्ति दर्शाती है कि कैसे वैधानिक ढांचा, भगबतपुर मगरमच्छ परियोजना जैसे लक्षित हस्तक्षेपों के साथ मिलकर, कम प्रमुख प्रजातियों के लिए भी स्थायी लाभ प्रदान कर सकता है। सुंदरबन में मगरमच्छों की संख्या में वृद्धि दर्शाती है कि भारत का व्यापक कानूनी संरक्षण और स्थान-विशिष्ट बंदी प्रजनन एवं रिहाई कार्यक्रमों को संयोजित करने का मॉडल प्रभावी रहा है। लेकिन समग्र रूप से, इस कानून में अभी भी खामियाँ हैं: यह जलवायु परिवर्तन, बढ़ती लवणता या आवास विखंडन से जुड़े उभरते खतरों का पर्याप्त रूप से पूर्वानुमान नहीं लगाता है।

संरक्षण भी प्रतिक्रियात्मक रहा है।

अतिमांसाहारी शीर्ष शिकारियों के रूप में, मगरमच्छ शिकार की आबादी को नियंत्रित करते हैं और जलमार्गों से शवों को हटाते हैं, जिससे मैंग्रोव के स्वास्थ्य में योगदान मिलता है। इस प्रकार, उनकी उपस्थिति संकेत देती है कि खाड़ियाँ और नदियाँ मानव बस्तियों, चक्रवातों और समुद्र-स्तर में वृद्धि के भारी दबाव के बावजूद अभी भी एक कार्यशील खाद्य जाल बनाए हुए हैं। बेहतर किशोर उत्तरजीविता यह भी दर्शाती है कि प्रजनन आवास पर्याप्त गुणवत्ता बनाए रखता है। यह डेल्टा के लिए एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक चिह्नक है, जहाँ बढ़ती लवणता और कटाव वन्यजीवों के लिए उपलब्ध आवासों को कम कर रहे हैं। यदि मगरमच्छों की आबादी एक स्थिर आयु संरचना स्थापित कर सकती है, तो यह सुंदरबन के मानव-ग्रोव नेटवर्क की लचीलापन को मजबूत कर सकती है।

अधिनियम के अंतर्गत वर्तमान अनुसूचियों के साथ सक्रिय, सु-वित्तपोषित पुनर्प्राप्ति योजनाएँ भी होनी चाहिए, और जनसंचार रणनीतियों को पुनर्संयोजित करने की आवश्यकता है। मगरमच्छों की संख्या इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि वे प्रिय हो गए, बल्कि इसलिए बढ़ी क्योंकि संरक्षण एजेंसियों ने उनके संरक्षण में निवेश किया। इसी तरह का ध्यान अन्य प्रजातियों को भी लाभ पहुँचा सकता है। जलवायु परिवर्तन एकीकरण भी आवश्यक है। खारे पानी के मगरमच्छ व्यापक लवणता सीमा को सहन कर लेते हैं, लेकिन कई उभयचर या मीठे पानी के सरीसृप ऐसा नहीं कर पाते। इसलिए, जलवायु शरणस्थलों की पहचान और सहायक प्रजनन को सक्षम बनाने जैसे पूर्वानुमानित उपाय आवश्यक हैं। यह पुनर्प्राप्ति दर्शाती है कि गैर-करिश्माई प्रजातियाँ निरंतर ध्यान देने पर कानून और नीति से लाभान्वित हो सकती हैं। भारत के लिए, यह सबक है कि संरक्षण का एक अधिक समृद्ध, अधिक समावेशी दृष्टिकोण संभव और आवश्यक है।

अनियंत्रित विश्व में भारत की स्थिति

एमके नारायणन

एक पूर्व निदेशक हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एक पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, और एक पूर्व के राज्यपाल पश्चिम बंगाल

फॉरेन एयर्स में एक लेख , जिसका शीर्षक था "भारत की महाशक्ति होने का भ्रम - नई दिल्ली की भव्य रणनीति उसकी भव्य महत्वाकांक्षाओं को कैसे विफल करती है" (जुलाई/अगस्त 2025), एक कहावत के अनुसार, चाय के प्याले में तूफान खड़ा कर रहा है। लेख का मुख्य बिंदु यह है कि भारत को भव्यता और महाशक्ति बनने का 'भ्रम' था, और इसमें कोई ठोस आधार नहीं था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लेख में भारत के बारे में अपमानजनक बातें कही गई हैं, जिसमें कहा गया है कि जहाँ तक महाशक्ति बनने की होड़ का सवाल है, चीन और अमेरिका के बीच भारत कहीं नहीं ठहरता।

अप्रत्याशित रूप से, इस बात ने लोगों को परेशान किया है, ऐसे समय में जब भारत यह मानने लगा था कि वह 'मध्यम आय के जाल' से बाहर निकलने और एक बड़ी शक्ति की श्रेणी में उभरने के कगार पर है। कुछ लोग इसे भ्रम कह सकते हैं, लेकिन भारत का अपने भविष्य के प्रति यह विश्वास नया नहीं है और इसकी नींव मज़बूत है। लेखक का यह तर्क गलत हो सकता है कि भारत और चीन एक संघर्ष के कगार पर हैं, और चीनी आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता की आवश्यकता होगी। भारत और चीन दोनों ही सभ्यतागत शक्तियाँ हैं, हालाँकि उन्होंने प्रगति के लिए अलग-अलग रास्ते अपनाए हैं। हालाँकि, दोनों देशों के बीच कुछ सीमा संबंधी मुद्दों के बावजूद, कोई भी देश संघर्ष के दौर के लिए तैयार नहीं है।

हालांकि, 1962 और 1971 के भारत के अनुभव को देखते हुए, जब अमेरिका ने भारत के समर्थन के बारे में किसी भी संदेह को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया था, भारत भविष्य में किसी भी संघर्ष में उसकी सहायता की उम्मीद नहीं कर रहा है।

इस लेख का सार यही है कि अमेरिका इस समय यह सोच रहा है कि वह 'तारी युद्ध' का बड़ा हथियार चलाकर भारत को अपनी बात मनवाने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन, यह बात समझ से परे है कि डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि पूर्व की ज़्यादा उन्नत सभ्यताएँ, जैसे भारत और चीन, इस समय युद्ध या टकराव के बारे में नहीं सोच रही हैं।

हाल की घटनाएं और तियानजिन में हुई बैठकें इसकी पुष्टि करती हैं, तथा यह भी दर्शाती हैं कि भारत और चीन, रूस के साथ मिलकर, वर्तमान विश्व व्यवस्था को बाधित करने के इच्छुक लोगों के विरुद्ध एक मजबूत मोर्चा बनाते हैं - कम से कम जहां तक एशिया का संबंध है।

भारत की कहानी पर एक करीबी नज़र फिर भी, यह विश्लेषण करना ज़रूरी है कि क्या भारत की महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षाएँ वाकई वास्तविकता से मेल नहीं खातीं। साथ ही, क्या भारत का यह मानना ग़लत है कि महाशक्ति का दर्जा हासिल करना उसकी पहुँच में है। आलोचकों द्वारा की गई पहली ग़लती यह है कि भारत ने कभी यह दावा नहीं किया कि वह निकट भविष्य में चीन से आगे निकल जाएगा।

या यह कि यह अमेरिका के हमले की सीमा के भीतर था

भारत पर सबसे बुरा आरोप यह लगाया जा सकता है कि उसने यह मान लिया है कि वह उन देशों से काफी आगे निकल गया है, जिन्होंने ऐसी ही उम्मीदें लेकर शुरुआत की थी, और भारत 'मध्यम आय के जाल' से बाहर निकलने में सफल हो गया है - अपने मुख्य उद्देश्य से बहुत दूर पहुंच गया है।

भारत का अपने भविष्य के प्रति विश्वास नया नहीं है और यह हमेशा से रहा है। मजबूत नींव, जिसे पश्चिम को समझना चाहिए

लेख के लेखक द्वारा अपनाया गया उपहासपूर्ण लहजा भारत के प्रगति के दावों पर आक्रोश का एक तत्व प्रतीत होता है। हालाँकि, भारत की विकास गाथा के पक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता है, और उससे भी ज़्यादा, जिस तरह से यह हासिल किया गया है, वह चीन जैसे देशों के बिल्कुल विपरीत है।

अमेरिकियों को इतिहास न पढ़ने या न समझने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि यह उनके डीएनए में ही नहीं है। लेकिन भारत का एक 'अकालग्रस्त' राष्ट्र से हरित क्रांति के माध्यम से खाद्यान्न निर्यातक बनने तक का शानदार परिवर्तन, शायद आधुनिक या प्राचीन काल के इतिहास में भी बेजोड़ है।

स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में सैन्य शक्ति संचय करने की अपेक्षा आर्थिक प्रगति भारत के अस्तित्व की अनिवार्य शर्त थी, तथा इसने भविष्य की प्रगति के लिए आधार प्रदान किया।

बंदूक से पहले मक्खन ही आदर्श वाक्य था।

फिर भी, और इस पूरी अवधि के दौरान, भारत ने एक हद तक नैतिक अधिकार का प्रयोग किया है—जिसे अमेरिका समेत अधिकांश देशों ने शायद ही कभी प्रयोग किया हो—अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक संतुलनकारी कारक के रूप में उभरने के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति में इसकी बराबरी करने वाले बहुत कम, यदि कोई हैं, तो हैं। यह भारत ही है जिसने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक नए दर्शन, अर्थात गुटनिरपेक्षता की अवधारणा को गढ़ा और प्रचारित किया, वह भी ऐसे समय में जब दुनिया दो प्रतिद्वंद्वी और परस्पर विरोधी रूढ़िवादियों में विभाजित थी; इसने 1945 के बाद नए राष्ट्रों की पहचान और उम्मीदों की रक्षा करने में मदद की, जो क्रमशः अमेरिका और रूस के नेतृत्व वाले दो प्रतिद्वंद्वी गुटों में से किसी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहते थे। भारत ने अक्सर उस समय संघर्षों (जैसे 1950 के दशक में कोरियाई युद्ध) में मध्यस्थ की भूमिका निभाई,

पश्चिम की नज़र में 1970 के दशक में अमेरिका-चीन 'भाईचारा' - जो तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर की मंत्रमुग्ध कर देने वाली कूटनीति और चीन के देंग शियाओपिंग के साथ उनकी दोस्ती के माध्यम से हासिल हुआ - जिसने एक बाजार के रूप में चीन की क्षमता के प्रति अमेरिका और पश्चिम के दृष्टिकोण को बदल दिया, इसका पश्चिमी देशों, विशेष रूप से अमेरिका की नज़र में भारत के महत्व को कम करने वाला प्रभाव पड़ा।

इसके साथ ही, रूस के साथ भारत की घनिष्ठ मित्रता भी एक समस्या साबित हुई, जो 1971 की भारत-सोवियत संधि पर हस्ताक्षर के साथ और भी मजबूत हो गई।

1974 में पोखरण रेगिस्तान में हुए परमाणु परीक्षण - 'बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं' - ने इस स्थिति को और भी बदतर बना दिया।

फॉरेन एयर्स के लेख का दबंग लहजा हर तरह के विरोधाभासों को संभालने की भारत की क्षमता की समझ की कमी को दर्शाता है। सदी की शुरुआत के बाद से अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में काफी सुधार हुआ है, और 2008 में भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते के बाद ये अपने चरम पर पहुँच गए। लेकिन यह तब हुआ जब भारत-अमेरिका संबंध अभी भी गर्मजोशी से भरे नहीं थे।

कई परेशान करने वाली बातें अभी भी बनी हुई हैं, जिनमें सबसे अधिक परेशान करने वाली बात है भारत की रूसी हथियारों पर निर्भरता, और,

हाल ही में, अमेरिकी विरोध के बावजूद, रूसी तेल पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

ऐसा तब है जब भारत ने क्वाड (ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका) में शामिल होकर इसकी भरपाई कर ली है। विरोधाभासों का प्रबंधन करना इस देश की उन प्रमुख शक्तियों में से एक है जो इसे अपने सभ्यतागत अतीत से प्राप्त हुई है, जिसे पश्चिम के देश, विशेष रूप से सुदूर पश्चिम के देश जैसे अमेरिका, बहुत कम समझते हैं। इसलिए, अमेरिका के दिग्गज यह समझने में असमर्थ हैं कि सीमा विवाद में उलझे होने के बावजूद भारत और चीन कैसे दोस्त भी हो सकते हैं, जैसा कि हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के दौरान स्पष्ट हुआ। पश्चिम के लिए इससे भी अधिक भ्रमित करने वाली बात चीन, भारत और रूस के बीच 'सौहार्दपूर्ण समझौता' है, जैसा कि इस अवसर पर प्रदर्शित हुआ।

तकनीकी श्रेष्ठता ही प्रेरक शक्ति है। हालाँकि, जो बात वास्तव में भ्रामक है, वह यह है कि पश्चिम आज विश्व अर्थव्यवस्थाओं में वास्तविक प्रेरणा को पहचानने में विफल रहा है, जो 'मन के साम्राज्यों' से उपजी है। इस लिहाज से, आज अमेरिका के पास निपटने के लिए बहुत कम पत्ते हैं। यह 'साइबरनेटेड पीढ़ी' का युग है और आज चीन, भारत, जापान और वियतनाम जैसे विकसित सभ्यता वाले देश डिजिटल किले को भेद रहे हैं।

डेटा संग्रहण आज मुख्य हथियार बन गया है — और यह 'लेज़र हथियारों' के इस्तेमाल से बिल्कुल अलग है। तकनीकी श्रेष्ठता नए डिजिटल उपनिवेशों का निर्माण कर रही है, और अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा, और अभी तक, भारत जैसे देशों पर मामूली बढ़त का दावा कर सकता है। इस बीच, इस क्षेत्र में भारत की अंतर्निहित क्षमता में मज़बूत और स्थिर वृद्धि देखी जा रही है। इसलिए, विदेशी हवाई हमलों वाले लेख के लेखक जैसे लोग, जो भारत की ताकत पर नज़र रखते हैं, उन्हें शायद बाद में पछताना पड़े।

भारत पर पत्थर फेंकने के बजाय, अमेरिका और पश्चिम को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या महत्वपूर्ण तकनीकों में उनकी वर्तमान बढ़त जल्द ही भ्रामक साबित हो सकती है। जैसे-जैसे तकनीक के 'विशेषज्ञों' की एक नई लहर अतीत के किलों को ध्वस्त कर एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत करेगी, यह एक वास्तविक संभावना है। पश्चिम को यह भी समझना चाहिए कि आज सिलिकॉन वैली पर हावी 'शेरपा' मुख्यतः भारतीय और एशियाई मूल के हैं।

इस प्रकार, आज अमेरिका की बढ़त, ज़्यादा से ज़्यादा, क्षणिक है। भारत, अपनी ओर से, भविष्य की तकनीकों के मामले में इसी विश्वास की छलांग पर दांव लगा रहा है, और पश्चिमी देशों के लिए बेहतर होगा कि वे अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका से मदद लेने वाले देशों की घिसी-पिटी बातों पर निर्भर रहने के बजाय, उन्हें समझें। अमेरिका का सूरज शायद अस्त हो जाए, और उसे अंदाज़ा होने से बहुत पहले, जबकि एक प्राचीन सभ्यता के गुणों में डूबा और सदियों के सभ्यतागत अस्तित्व से प्राप्त ज्ञान पर आधारित भारत, अपनी स्थिति मज़बूत कर रहा है। आज अस्पष्ट बातों में उलझने के बजाय बेहतर स्थिति बनाना ज़्यादा ज़रूरी है।

चिंताएं.

ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध की कैंची से वार

एमवी राजीव गौड़ा

के पूर्व सदस्य हैं संसद (कांग्रेस)

में एक गुप्त ऑपरेशन के समान तरीके से, भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 को आगे बढ़ाया

संसद का मानसून सत्र समाप्त होने के साथ ही यह विधेयक पारित हो गया। इस विधेयक का उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स के विकास को बढ़ावा देना था, जबकि इस विधेयक को बिना किसी बहस के दोनों सदनों से जल्दबाजी में पारित कर दिया गया। इस विधेयक पर न तो संबंधित उद्योग और न ही राज्यों, जिनके पास इस विषय के प्रमुख पहलुओं पर अधिकार क्षेत्र है, के साथ कोई परामर्श किया गया।

ऑनलाइन गेमिंग भारत में एक उभरता हुआ क्षेत्र था और इसमें उल्लेखनीय विदेशी निवेश देखा गया था। इस अचानक प्रतिबंध का सभी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जब नियम रातोंरात लागू हो जाते हैं और सरकार उन कुछ डिजिटल उद्योगों में से एक को खत्म कर देती है जहाँ भारत वैश्विक स्तर पर अग्रणी हो सकता है, तो वैश्विक निवेशक भारत पर भरोसा क्यों करेंगे?

ऑनलाइन गेमिंग

तकनीक, भुगतान और डिजिटल सामग्री के संगम पर स्थित है—ये वही क्षेत्र हैं जिनका भारत डिजिटल इंडिया के नाम पर नेतृत्व करने का दावा करता है। इस उद्योग का गला घोंटने का मतलब है हज़ारों कुशल नौकरियों के दरवाज़े बंद करना, नवाचार को धीमा करना और ऐसे समय में उद्यमिता को हतोत्साहित करना जब अर्थव्यवस्था को इन सबकी सख़्त ज़रूरत है।

ऐसे समय में जब भारत में रोज़गार सृजन बेहद धीमा है और दुनिया अगले डिजिटल क्षेत्र के रूप में गेमिंग में निवेश कर रही है, इस विधेयक के परिणामस्वरूप नौकरियों में भारी कमी आई है। गेमिंग क्षेत्र 2025 तक विकास, डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग, ग्राहक सहायता और एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में 1.5 लाख लोगों को रोज़गार देने की राह पर था।

ये बिल्कुल वैसी ही अत्याधुनिक, गुणवत्तापूर्ण तकनीकी नौकरियाँ हैं जिनकी भारत को अपनी डिजिटल अर्थव्यवस्था में ज़रूरत है। इनमें से कुछ तो प्रतिबंध के बाद भी बची रहेंगी।

ऑनलाइन असली पैसे वाले खेलों से यह उम्मीद की जा रही थी कि माल और सेवा कर में लगभग ₹17,000 करोड़ का उत्पादन संघ के लिए सेवा कर (जीएसटी) राजस्व

ऑनलाइन का प्रचार और विनियमन गेमिंग बिल 2025 एक उभरते क्षेत्र की संभावनाओं को ही समाप्त कर देगा

सरकार और राज्यों के बीच। राजस्व के इस स्रोत को बंद करके, केंद्र ने एकतरफ़ा तौर पर राज्यों के लिए भी एक महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत में कटौती की है, और साथ ही एक बड़ा त्याग भी किया है। क्यों?

प्रतिबंध के समर्थन में सरकार की मुख्य दलील यह है कि ऑनलाइन असली पैसे वाले खेलों के कारण खिलाड़ियों को आर्थिक नुकसान हुआ है और उनमें नशे की लत जैसी स्थिति पैदा हो गई है।

यह स्पष्ट रूप से एक सामाजिक क्षति है जिसका तत्काल समाधान आवश्यक है। लेकिन, क्या प्रतिबंध से कोई समाधान निकलेगा? या, तमिलनाडु जैसे राज्यों में विकसित किए जा रहे सावधानीपूर्वक नियमन से, क्या कोई अधिक संतुलित समाधान निकलेगा? क्या ऑनलाइन असली पैसे वाले खेलों के नकारात्मक दुष्प्रभावों को कम करने के और भी, संभवतः बेहतर, तरीके थे?

ज़िम्मेदार गेमिंग को नज़रअंदाज़ करना ऑनलाइन गेमिंग कंपनियाँ समस्याग्रस्त गेमिंग की पहचान करने और उसे रोकने के लिए तकनीकी पहलों पर काम कर रही थीं। ज़िम्मेदार गेमिंग के तरीके पहले से ही मौजूद हैं और दुनिया भर में सिद्ध भी हैं। इनमें नाबालिगों की पहुँच को प्रतिबंधित करने के लिए आयु-सीमा, स्व-बहिष्करण तंत्र, जमा और समय सीमा, बॉट-डिटेक्शन सिस्टम, अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) और धन-शोधन-रोधी (एएमएल) जाँच, और नैतिक विज्ञापन मानक शामिल हैं।

ऐसे सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के बजाय, प्रतिबंध उन्हें अचानक नष्ट कर देता है, जिससे खिलाड़ी पहले से भी अधिक असुरक्षित हो जाते हैं।

अगर कर और नियमन का पालन करने वाले ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म को बाहर कर दिया जाता है, तो मजबूर खिलाड़ी अनिवार्य रूप से बाहरी या भूमिगत नेटवर्क द्वारा होस्ट किए गए अवैध ऐप्स की ओर रुख़ कर लेंगे। ऐसे प्लेटफ़ॉर्म भारतीय अधिकारियों की पहुँच से बाहर काम करते हैं, कोई कर नहीं देते, और उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी और असुरक्षित गतिविधियों के लिए उजागर करते हैं। सरकार न केवल राजस्व खोएगी, बल्कि अनजाने में उन अवैध जुआ रैकेटों को भी बढ़ावा देगी जिन पर वह अंकुश लगाना चाहती है।

यह प्रतिबंध सिर्फ़ जवाबदेही को ख़त्म कर देगा। यहाँ असली मुद्दा नियामक क्षमता का है। मज़बूत निगरानी ढाँचे बनाने के बजाय,

सार्वजनिक हित और निजी हित के बीच संतुलन बनाने के लिए भारत ने शराबबंदी के कुंद हथियार का सहारा लिया है।

यह प्रतिबंध संवैधानिक प्रावधानों और न्यायिक सिद्धांतों का भी उल्लंघन करता है और संघवाद पर कुठाराघात करता है। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g) प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी पेशा या व्यवसाय करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। यह प्रतिबंध इस अधिकार के मूल आधार पर ही प्रहार करता है। एक कानून के ज़रिए, एक फलते-फूलते उद्योग को करारा झटका दिया गया है। अगर चिंता जुए को बढ़ावा देने की थी, तो केंद्र सरकार को राज्यों से परामर्श करना चाहिए था क्योंकि सट्टेबाजी और जुए का नियमन राज्य के विषय हैं। नए कानून को पहले ही अदालतों में चुनौती दी जा चुकी है क्योंकि यह संवैधानिक औचित्य पर कई सवाल उठाता है।

ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा एक अस्पष्ट क्षेत्र यह रहा है कि यह 'कौशल का खेल' है या 'संयोग का खेल'। न्यायिक निर्णयों ने कौशल के खेलों की वैधता को लगातार बरकरार रखा है। राज्यों को संयोग के खेलों या जुए को विनियमित या प्रतिबंधित करने का अधिकार है। अच्छे नियमन से इस विषय से जुड़ी शंकाएँ दूर हो जाएँगी।

एक मध्यम मार्ग मौजूद है। आदर्श रूप से, ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जो खिलाड़ियों की सुरक्षा करे, व्यसन और शोषण को रोके, और विभिन्न हितधारकों व राज्यों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखे। विकल्प निषेध और सभी के लिए खुली छूट के बीच नहीं है। एक मध्यम मार्ग मौजूद है: एक स्पष्ट लाइसेंसिंग ढाँचा, सख्त अनुपालन मानक, और एक निष्पक्ष लेकिन पूर्वानुमानित कराधान व्यवस्था।

दूसरी ओर, ऑनलाइन असली पैसे वाले गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने से यह सुनिश्चित होता है कि राजस्व और अवसर दोनों ही भूमिगत अर्थव्यवस्था में लुप्त हो जाएँगे, और खिलाड़ी असुरक्षित और असुरक्षित रह जाएँगे। समय ही बताएगा कि इस प्रतिबंध के ज़रिए भारत अपने नागरिकों की रक्षा कर पाया है या उन्हें निराश किया है।

व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं

द टटर्सटूदएडिटर

आशा, शांति और मणिपुर जातीय संघर्षों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मणिपुर यात्रा, हिंसा और विस्थापन से त्रस्त राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री मोदी का संवाद पर ज़ोर आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता दर्शाता है—जो आपसी सम्मान और समझ पर आधारित है।

हालाँकि, सच्चा मेल-मिलाप इसके लिए वित्तीय सहायता या बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं से कहीं अधिक की आवश्यकता है। इसके लिए विश्वास निर्माण, कमजोर समुदायों की सुरक्षा और विभाजन को पाटने में नागरिक समाज की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा न केवल प्रतीकात्मक होनी चाहिए, बल्कि राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ भी होनी चाहिए।

रुक्मा शर्मा, जालंधर, पंजाब

एसआईआर

आयोजित करना कोई भी संस्था, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अनन्य और पूर्ण शक्ति का दावा नहीं कर सकती ("चुनाव आयोग ने एसआईआर आयोजित करने का तरीका और समय तय करने का 'अनन्य' अधिकार होने का दावा किया है", 14 सितंबर)। वे दिन गए जब शक्तिशाली संस्थाओं पर सवाल नहीं उठाए जा सकते थे। यह एक ऐसा युग है जहाँ

आम आदमी हैं

दक्षिणपंथ से मजबूत सूचना अधिनियम, याचिकाओं और जनहित याचिकाओं के प्रति। हालाँकि भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को अपार शक्तियाँ प्रदान की गई हैं और निष्पक्ष चुनाव कराने की बड़ी ज़िम्मेदारी भी उसी पर है, फिर भी उसे यह समझना होगा कि उसकी नीतियाँ पूरी तरह दोषरहित नहीं हैं।

लोगों को जानने का अधिकार है और ईसीआई को जांच के लिए खुला होना चाहिए।

बालासुब्रमण्यम पावनी, सिकंदराबाद

महान निकोबार परियोजना अब निकोबार द्वीप समूह में मेगा-इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना को 'रणनीतिक, रक्षा और राष्ट्रीय महत्व' का बताकर इसे उचित ठहराने का प्रयास किया जा रहा है।

आदिवासी कल्याण समिति का गठन, वनरोपण, वन्यजीव गलियारों का निर्माण, शोम्पेन लोगों की "जियो-फेंसिंग" और अन्य

"शमन उपाय" नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएँगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पूर्वी तट पर अपनी पूरी समृद्धि के साथ फैले हुए 'खजाने' द्वीप हैं। कारण देखें और परियोजना को रद्द कर दें।

जी. डेविड मिल्टन, मारुथनकोड, तमिलनाडु

letters@thehindu.co.in पर भेजे गए पत्रों में पूरा डाक पता अवश्य होना चाहिए।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

राष्ट्रीय
सहारा
नई दिल्ली • सोमवार • 15 सितम्बर • 2025
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

पिता की सेवा करना जिस प्रकार कल्याणकारी माना गया है, वैसा प्रबल साधन न सत्य है, न दान है, और न यज्ञ है।
-वाल्मीकि

कांटों भरी राह

नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रहीं सुशीला कार्की को पहली अंतरिम महिला प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई गई है। उन्होंने केपी शर्मा ओली की जगह ली है जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों और सोशल मीडिया को प्रतिबंधित करने के खिलाफ युवाओं के भारी आक्रोश के चलते इस्तीफा देना पड़ा। कार्की की ईमानदार छवि के चलते जेन-जी प्रदर्शनकारियों समेत राष्ट्रपति और कानूनी विशेषज्ञों की सहमति से चुना गया। कार्की ने कहा कि युवाओं का उन पर विश्वास है, जो चाहते हैं चुनाव कराए जाएं और देश को अराजकता से निकाला जाए। ताजा साक्षात्कार में उन्होंने आंदोलन के दौरान मारे गए छात्रों के दुखी परिवारों के लिए कुछ करने की बात की। पचास से ज्यादा

लड़के-लड़कियां इस उपद्रव के दौरान मारे जाने की खबर है। भ्रष्टाचार हटाने के सवाल पर कार्की ने स्पष्ट किया कि यह मांग तभी पूरी हो सकेगी जब सरकार बनेगी। नेपाल में जन्मी कार्की ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर करके त्रिभुवन विवि से कानून की डिग्री ली। वकालत और अध्यापन के बाद वे न्यायाधीश बनीं और 2016 में नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद संभाला। भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई करने के लिए मशहूर कार्की को महाभियोग का सामना भी करना पड़ा जिसके चलते उन्हें निलंबित कर दिया गया था। पक्षपात और सरकार के काम में दखल देने के आरोपों का उन्होंने सख्ती से सामना किया। इस दरम्यान जनता ने न्यायपालिका की आजादी के लिए आवाज बुलंद की तो सुप्रीम कोर्ट ने संसद की आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी। संसद के प्रस्ताव वापस लेने से जनता के बीच कार्की की छवि सत्ता के दबाव में न आने वाली दबंग शख्सियत की बन गई। भारत को लेकर उनके भीतर विशेष लगाव है। गंगा, वाराणसी और बीएचयू की यादों को समेटे वह अच्छी हिन्दी बोलती हैं। उनके ढेरों रिश्तेदार और परिचित भारत में रहते हैं। वह छोटे-मोटे मतभेदों के बावजूद भारत-नेपाल के रिश्तों को लेकर आशान्वित हैं। निःसंदेह उनके समक्ष भ्रष्टाचार से जूझने की चुनौती है। जेन-जी के आक्रोश से जूझना और देश की सरकार से जेन-जी की उम्मीदों पर खरा उतरने के प्रयासों में उन्हें तेजी लानी होगी। युवाओं में जिन नेपो किड्स की वैभवशाली जीवनशैली के प्रति जबरदस्त गुस्सा है, उसे भी शांत करते नजर आना होगा। बेशक, यह सब आसान नहीं हैं। कार्की के लिए खांटी राजनीतिक दलों व नेताओं के सामने राह में ढेरों रोड़े हैं, और कांटे भी कम नहीं।

शांत मणिपुर की कामना

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मणिपुर में विभिन्न संगठनों से हिंसा छोड़ने का आग्रह करते हुए कहा है कि उनकी सरकार राज्य के लोगों के साथ दृढ़ता से खड़ी है, और इस हिंसाग्रस्त प्रांत को शांति और समृद्धि का प्रतीक बनाने की दिशा में काम कर रही है। मई, 2023 में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा भड़कने के बाद राज्य की अपनी पहली यात्रा के दौरान कुकी बहुल चूड़ाचांपुर जिले में शनिवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर को आशा और आकांक्षा की भूमि बताया। मई,

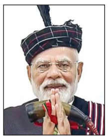

2023 में जातीय हिंसा शुरू होने के बाद से 260 लोग मारे गए और हजारों लोग बेघर हो गए। लंबे समय से जारी जातीय हिंसा के बावजूद राज्य का दौरा न करने को लेकर विपक्ष की तीखी आलोचना झेलते रहे प्रधानमंत्री मोदी ने प्रांत के विकास के लिए अपनी सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले दिल्ली में लिए गए फैसलों को यहां तक पहुंचने में दशकों लग जाते थे लेकिन अब मणिपुर देश के बाकी हिस्सों के साथ-साथ प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने मणिपुर की राजधानी इंफाल के ऐतिहासिक कांगला किला परिसर में जातीय हिंसा के कारण विस्थापित लोगों के एक वर्ग से भी मुलाकात की। जनसभा से पहले चूड़ाचांदपुर के पीस ग्राउंड में राहत शिविर में विस्थापित परिवारों का हालचाल जाना। विस्थापितों से मिलने के बाद विश्वास जताया कि यकीन के साथ कहा जा सकता है कि मणिपुर में आशा और विश्वास के एक नये सवेरे का उदय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने राज्य में 1200 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इससे उम्मीद बंधती है कि राज्य में विकास के नये दौर का आगाज होगा। इसलिए भी कि राज्य में 11 सालों पूर्वोत्तर में जारी कई संघर्ष और विवाद सुलझ गए हैं। शांति और सहमति का माहौल बना है, जो विकास की जड़ें जमाने की बुनियादी शर्त है। पूर्वोत्तर में विकास की अकूत संभावनाएं हैं। खासकर मणिपुर में सामाजिक तानाबाना सौहार्दपूर्ण बने रहने पर विकास और समृद्धि की नई राह खुल सकती है। लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि पहाड़ी पर कुकी बहुल और घाटी में मैतेई बहुल इलाकों में स्थायी शांति, सुरक्षा और अपनेपन की भावना को प्रगाढ़ करने के लिए राजनीतिक पहलू से भी प्रयास और पहल किया जाना जरूरी है।

परिधि/ राजीव मंडल

सामान्य भी 'कुलीन' हैं

पहली बार देश की किसी शीर्ष संस्था ने प्रदूषण की भयावहता और उससे उपजे दर्द को संजीदगी से समझा है। पटाखों पर रोक के लिए सिर्फ दिल्ली-एनसीआर में ही नीति क्यों बने? प्रदूषण का जहर तो अब छोटे शहरों को भी अपने आगोश में ले लिया है। इस बात की तस्दीक वहां से मिले प्रदूषण के आंकड़े और वहां के बाशिंदों की जुबानी महसूस की जा सकती है।

दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, प्रदूषण रोकने की नीति सिर्फ दिल्ली के लोगों के लिए नहीं हो सकती। कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि दिल्ली के लोग देश के खास नागरिक हैं इसलिए सिर्फ उनके लिए नियम बने। कोर्ट की यह टिप्पणी उस याचिका पर आई है, जिसमें दिल्ली में पटाखों पर बैन लाने वाले आदेश को चुनौती दी गई है। आमतौर पर जब भी प्रदूषण की चर्चा होती है, दिल्ली और उसके आसपास के शहरों पर जार-जार आंसू तो बहाये जाते हैं मगर छोटे शहरों के दर्द बिसरा दिए जाते हैं। यहां तक कि छोटे शहरों (द्वितीय और तृतीय श्रेणी) में न तो प्रदूषण मापने के आधुनिक यंत्र स्थापित किए गए हैं और न वहां प्रदूषण की रोकथाम से जुड़ी कोई सरकारी संस्था है। स्वाभाविक है, जब प्राथमिक स्तर पर इन सब बातों पर नजर रखने वाली कोई संस्था नहीं होगी तो वहां के हालात को बखूबी समझा जा सकता है।

मुख्य न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई में एक शब्द 'एलीट' कुलीन का जिक्र किया। सीजेआई बीआर गवई ने बिना लाग-लपेट के कहा कि 'अगर स्वच्छ हवा राष्ट्रीय राजधानी के एलीट निवासियों का अधिकार है तो वह पूरे देश को मिलना चाहिए। अब समय आ गया है कि प्रदूषण के मामले को सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों तक सीमित नहीं रखा जाए। प्रदूषण की मार जितनी दिल्ली-एनसीआर की जनता झेल रही है, उतनी कमोबेश देश के बाकी शहरों की जनता भी झेलती है। इसलिए इस मसले को राष्ट्रीय स्तर पर समझने और निदान तलाशने की जरूरत है। अच्छी बात है कि अब साफ हवा, प्रदूषण और इससे पैदा दुश्वारियों को लेकर जागरूकता और चिंता-फिकर सतह पर आने लगा है। लेकिन सिर्फ चिंता जताने भर से कुछ नहीं होगा। सर्वोच्च अदालत को बहुत ज्यादा अख्तियार है। इस नाते वह इस बेहद गंभीर समस्या को लेकर केंद्र सरकार को एक राष्ट्रीय नीति बनाने को कहे। हां, छोटे शहरों में लोगों को प्रदूषण के नुकसान को समझाना जरूर दुष्कर काज होगा।

टीवी बहसों का गिरता स्तर

शुचिता की बात

विनीत नारायण

भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां संवाद और विमर्श लोकतंत्र की रीढ़ माने जाते हैं। वहां आज टीवी बहसें ऐसा मंच बन चुकी हैं जहां तर्क की जगह एक दूसरे का अपमान, चीख-पुकार और राजनीतिक दुष्प्रचार हावी हो गया है। प्राइम टाइम के इन शो में राजनीतिक दलों के प्रवक्ता एक-दूसरे पर व्यक्तिगत हमले करते नजर आते हैं, जिससे बहसें निष्कर्षहीन हो जाती हैं। प्रवक्ताओं द्वारा इस्तेमाल अपमानजनक भाषा ने टीवी डिबेट्स को सर्कस का रूप दे दिया है। चैनल और एंकर ऐसी निरर्थक बहसों को क्यों बढ़ावा देते हैं? क्या यह टीआरपी की होड़ है, या राजनीतिक दबाव?

टीवी बहसों का इतिहास भारत में 1990 के दशक से जुड़ा है, जब निजी चैनलों का आगमन हुआ। शुरू में बहसें मुद्दों पर तथ्यपरक चर्चा का माध्यम थीं, लेकिन आज शोरगुल भरी जंग बन चुकी हैं। एक शोध के अनुसार, बहसों में एंकरों द्वारा आक्रामक लहजे का इस्तेमाल 80 प्रतिशत से अधिक होता है, जो दर्शकों पर नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है। ये आंकड़े बताते हैं कि बहसें अब सूचना का स्रोत नहीं रह गई हैं, बल्कि प्रचार का हथियार बन चुकी हैं। राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं द्वारा अपमानजनक भाषा का उपयोग इस समस्या का केंद्रीय बिंदु है। एक बहस के दौरान एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता को दूसरी पार्टी के प्रवक्ता द्वारा 'जयचंद' और 'गद्दार' कहा गया, जिसे सुन कर उस प्रवक्ता को हार्ट अटैक हुआ और उनकी मृत्यु हो गई।

यह घटना टीवी डिबेट्स की विषाक्तता का जीता-जागता उदाहरण है। इसी तरह एक अन्य प्रवक्ता एक दूसरे प्रवक्ता को 'नाली का कीड़ा', 'दादी मां', 'वैंप' कहा या 'उल्टा टांग दूंगा' जैसे शब्दों का प्रयोग करते पाए गए हैं। एक प्रवक्ता ने तो बहस के दौरान दूसरे प्रवक्ता पर हाथ भी उठा दिया। यह समस्या बढ़ रही है, कम नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक टीवी बहस के दौरान एक नेता पर कुर्सी फेंकी गई, जिसके बाद एफआईआर भी दर्ज हुई। नवम्बर, 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक टीवी चैनल को एक प्रवक्ता के खिलाफ अपमानजनक क्लिप हटाने का आदेश दिया था। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि अपमान अब शारीरिक हिंसा तक पहुंच गया है। राजनीतिक दलों द्वारा ऐसे प्रवक्ताओं को चुना जाना भी चिंता की बात है। अधिकांश प्रवक्ता राजनीतिक अनुभव की कमी रखते हैं, और केवल टीवी पर चिल्लाने के लिए नियुक्त होते हैं। यदि राजनैतिक दलों द्वारा योग्य प्रवक्ताओं को चुना गया होता तो बहसें अधिक शालीन और उत्पादक होतीं। लेकिन वर्तमान में ये प्रवक्ता दलों के चेहरे बन चुके हैं, जो विचारधारा की बजाय व्यक्तिगत हमलों पर निर्भर

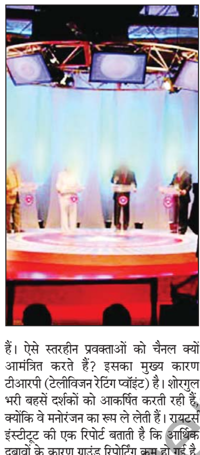

हैं। ऐसे स्तरहीन प्रवक्ताओं को चैनल क्यों आमंत्रित करते हैं? इसका मुख्य कारण टीआरपी (टेलीविजन रेटिंग प्वॉइंट) है। शोरगुल भरी बहसें दर्शकों को आकर्षित करती रही हैं, क्योंकि वे मनोरंजन का रूप ले लेती हैं। रायटर्स इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट बताती है कि आर्थिक दबावों के कारण ग्राउंड रिपोर्टिंग कम हो गई है, और स्टूडियो डिबेट्स ही मुख्य सामग्री बन गई हैं। चैनल जानते हैं कि तर्कपूर्ण चर्चा से दर्शक भागते हैं, लेकिन चीख-पुकार उन्हें बांधे रखती है। दूसरा कारण राजनीतिक दबाव का उदय है।

टाइम मैगजीन के अनुसार, राज्य और पार्टी के विज्ञापन बजट चैनलों को नियंत्रित करते हैं। परिणामस्वरूप, बहसें सत्ता पक्ष को लाभ पहुंचाने वाली बन जाती हैं। विपक्षी प्रवक्ताओं को अपमानित किया जाता है, जबकि सत्ताधारी प्रवक्ताओं को खुली छूट मिलती है। 2022 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने चैनलों को सलाह दी कि उत्तेजक भाषा वाली बहसें न दिखाएं। लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। चैनल जान-बूझ कर ऐसे प्रवक्ताओं को बुलाते हैं जो विवाद पैदा करें क्योंकि यह सोशल मीडिया पर वायरल होता है, और चैनल की पहुंच बढ़ाता है। ऐसी बहसों के सामाजिक प्रभाव गंभीर हैं। वे समाज को ध्रुवित करती हैं, विशेषकर हिन्दू-मुस्लिम मुद्दों पर। एक शोध के अनुसार, बहसें 'फिक्स्ड मैच' की तरह होती हैं, जहां अपमान और झगड़े पूर्वनियोजित होते हैं। मुस्लिम पैनलिस्टों को एंटी-नेशनल' तक कहा जाता है, जो सांप्रदायिक हिंसा को भड़काता है। 'गल्फ न्यूज' की एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के चैनल मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैला रहे हैं। युवाओं का एक वर्ग, जो रोजगार और शिक्षा चाहता है, इन बहसों से प्रभावित होकर हिंसक हो रहा है। लोकतंत्र में संवाद बहुत आवश्यक है, लेकिन अब विषाक्त हो चला संवाद समाज को कमजोर कर रहा है।

चैनल और एंकरों की जिम्मेदारी यहां महत्त्वपूर्ण है। वे मोडरेटर हैं, न कि भागीदार। लेकिन अधिकांश एंकर खुद अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। रेडिफ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बहसें 'विषैली' हो चुकी हैं। एंकर विपक्ष को बोलने न देकर मात्र समय काटते हैं। यदि चैनल सख्त कोड ऑफ कंडक्ट लागू करें तो स्थिति सुधर सकती है। लेकिन टीआरपी और राजनीतिक लाभ के लालच में वे इसकी अनदेखी करते हैं। समाधान के लिए बहुआयामी प्रयास जरूरी हैं। सबसे पहले तो राजनैतिक दलों को अपने प्रवक्ताओं के चयन में सुधार करना चाहिए। केवल अनुभवी और शालीन व्यक्तियों को ही टीवी पर भेजा जाए। दूसरा, 'ट्राई' और सूचना मंत्रालय को सख्त नियम लागू करने चाहिए जैसे अपमानजनक भाषा पर तत्काल जुर्माना लगे। तीसरा, दर्शकों को जागरूक होना चाहिए; वे ऐसे चैनलों का बहिष्कार करें जो सनसनी फैलाते हैं।

चौथा, स्वतंत्र मीडिया वॉचडॉग को मजबूत बनाना चाहिए। अंत में, डिजिटल प्लेटफर्म्स जैसे यूट्यूब पर तथ्यपरक बहसें बढ़ावा दें जहां सोशल मीडिया इंगेजमेंट सकारात्मक हो। भारत की टीवी बहसें लोकतंत्र का मजाक बन चुकी हैं। अपमानजनक प्रवक्ताओं का बोलबाला न केवल बहसों को निरर्थक बनाता है, बल्कि समाज को भी विभाजित करता है। चैनल और एंकरों को यदि वास्तव में पत्रकारिता का सम्मान करना है, तो टीआरपी के पीछे भागना छोड़कर जिम्मेदार संवाद को प्राथमिकता देनी चाहिए। अन्यथा, ये बहसें लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करती रहेंगी। समय आ गया है कि हम एक ऐसे मीडिया की मांग करें जहां तर्क जीते, न कि अपमान। तभी भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा।

(लेख में विचार निजी हैं)

टीवी बहसें लोकतंत्र का मजाक बन चुकी हैं। अपमानजनक प्रवक्ताओं का बोलबाला न केवल बहसों को निरर्थक बनाता है, बल्कि समाज को भी विभाजित करता है। एंकरों को पत्रकारिता का सम्मान करना है, तो जिम्मेदार संवाद को प्राथमिकता देनी चाहिए। अन्यथा ये बहसें लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करती रहेंगी। समय आ गया है कि हम ऐसे मीडिया की मांग करें जहां तर्क जीते, न कि अपमान। तभी अपना लोकतंत्र मजबूत होगा

सेहत के लिए नेमत हैं सूरजमुखी के बीज

- सूरजमुखी के बीज सेहत के लिए किसी नेमत से कम नहीं हैं। अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, इनमें प्रोटीन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, हेल्दी फैट्स और विटामिन्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं
- सूरजमुखी के बीजों में पाया जाने वाला ओमेगा-6 फैटी एसिड और विटामिन ई दिल की धड़कन को सही रखने में मदद करता है। सूरजमुखी के बीज कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करते हैं, और धमनियों में खून के थक्के नहीं जमने देते
- सूरजमुखी के बीजों में इम्यूनिटी बढ़ाने वाले तत्व भी होते हैं। इनमें कैल्शियम, आयरन, जिंक, फॉस्फोरस, पोटेशियम और सेलेनियम जैसे तत्व भी पाए जाते हैं, जो हड्डियों, खून और मांसपेशियों की मजबूती के लिए बेहद जरूरी हैं

(स्रोत : मीडिया इन्पुट्स)

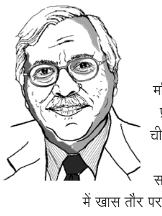

नेपाल ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया हैः प्रथम महिला न्यायाधीश के बाद अब प्रथम महिला प्रधानमंत्री। कुछ चीजें तो हैं जिन्हें हम अपने इस पड़ोसी छोटे-से देश से सीख सकते हैं। संवैधानिक संस्थानों में खास तौर पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में।

डॉ. एस.वाई. कुरैशी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त
@DrSYQuraishi

आपदा का घर बना हिमालय

मुद्दा

सुरेश भाई

हिमालय ऋषि-मुनियों और संत-महात्माओं की तपस्थली रहा है। उन्होंने यहां वेद, पुराण और उपनिषदों की रचना की। इसलिए कर पाए कि उन्हें यहां शांति की अनुभूति होती थी। हिमालय की जैव-विविधता के कारण प्राकृतिक आपदा यहां से सिर झुका कर चली जाती थी। लेकिन समय बदल गया है। मनुष्य ने प्रकृति के साथ जीने के जो संयमित नियम-कायदे बनाए थे उनका उल्लंघन करना शुरू कर दिया है। इसके चलते प्रकृति का रौद्र रूप इतना विकराल हो चुका है कि आगे किसी भी प्राणी के लिए हिमालय में रहना मुश्किल होता जा रहा है, जो मैदानी क्षेत्रों में भी भीषण आपदा पैदा कर रहा है। मनुष्य पछतावे के रूप में चालाकी से अपनी करतूत को जलवायु परिवर्तन से जोड़ रहा है। लेकिन समस्या का सामना करने के लिए जरूरी शर्तों को लागू नहीं कर पाता। यही कारण है कि भारतीय हिमालय क्षेत्र भीषण आपदा की चपेट में आ गया है।

इस बरसात में जिस तरह से जल प्रलय का सामना हुआ है, उससे प्राकृतिक और मानवीय, दोनों पहुलओं से चर्चा फिर से शुरू हो गई है। इस संदर्भ में देश की सुप्रीम अदालत के निर्णय काबिलेतारीफ हैं। सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरणविद्, वैज्ञानिक कहते रहे हैं कि विकास परियोजनाओं की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति होनी चाहिए जिसके द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर परियोजनाओं के संदर्भ में सही पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन हो। हिमाचल में बाढ़ के दौरान रावी नदी में बह कर आई अंधाधुंध लकड़ी का संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को कहा कि बड़े पैमाने पर वनों का कटान हो रहा है। वन माफिया ने जंगल काट कर छुपा रखे हैं, जो बरसात में बह कर नदियों में आ रहे हैं। यह अतिश्योक्ति नहीं है कि हिमालय के ऊंचे से ऊंचे स्थान पर वनों का व्यावसायिक दोहन हो रहा है। लाखों पेड़ों को राजस्व के लिए काटा जा रहा है। बड़े पेड़ों को काटने से चट्टानें अस्थिर हो जाती हैं, जो बरसात में भूस्खलन का रूप लेता है।

हर साल जंगलों में भीषण आग भी भूस्खलन को न्योता दे रही है। इसके अलावा नदियों के किनारे बन रही सड़कों के चौड़ीकरण में अंधाधुंध पेड़ों का कटान हो रहा है। चारधाम में ऑल वेदर रोड के निर्माण के दौरान लाखों पेड़

काटे गए। भागीरथी जैसे संवेदनशील जोन में भी अमूल्य वन प्रजाति देवदार के पेड़ों पर संकट मंडरा रहा है। भागीरथी इको सेंसेटिव जोन 2012 में बन गया था जिसकी शर्तों को लागू करने में लापरवाही बरती गई है जबकि भागीरथी यमुना का क्षेत्र मेंन सेंट्रल थ्रस्ट जोन में आता है। यदि पिछले 13-14 वर्षों में इसको नियमानुसार क्रियान्वित किया जाता तो बार-बार आ रही आपदाओं को कम किया जा सकता था।

मानवीय आपदा की सच्चाई यह भी है कि 5 सितम्बर तक हिमाचल में 1115, उत्तराखंड में 520, जम्मू कश्मीर में दर्जनों सड़कें बंद पड़ी थीं। इसका कारण है कि चौड़ी सड़कों के निर्माण के दौरान विस्फोटों और जेसीबी मशीनों के उपयोग से पहाड़ की रीढ़ के ऊपर थमी हुई मिट्टी बरसात के समय नदियों की तरफ बहने के लिए मजबूर हो गई है। पहाड़ों पर भूकंप से भी दरारें आ रखी हैं। जंगल कटने से भी गांव के ऊपर से भूस्खलन होता है।

कारण स्पष्ट है कि तीर्थाटन को भूल कर पर्यटन संस्कृति के विकास के लिए नदी-नालों के मुहाने पर उग आईं बस्तियों के नियंत्रण पर सोचा ही नहीं गया और उसे विकास की संज्ञा दी गई है। बाजारीकरण और पर्यटन स्थलों के समीप आकर रोजगार के लिए लोग अपना गांव छोड़ रहे हैं। जहां पर ग्लेशियरों और झीलों से आ रहे गाड़-गदेरों और नदियों के मुहाने पर बन रहीं इमारतों के भूस्खलन की चपेट में आकर भारी जन-धन की हानि हो रही है। पुराने समय में भी नदियों में आज की तरह ही जल प्रलय होता था लेकिन तब लोगों के घर, होटल नदी के किनारे नहीं होते थे।

हिमालय के ऊंचे पर्वत शिखरों से बर्फीली झीलें कहर बरपा रही हैं। इस बार 2013 की केदारनाथ आपदा से अधिक नुकसान हुआ है। यमुनोत्री में भी स्याना चट्टी के पास तीसरी बार झील बनी है जिसके कारण आसपास के दर्जन भर गांवों पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। आपदा राहत और पुनर्वास के लिए केंद्र से अकेले उत्तराखंड ने ही 5 हजार करोड़ रुपये की मांग की है। इस तरह से बजट की मांग कब तक होती रहेगी। अच्छा हो कि हिमालय क्षेत्र के विकास का मॉडल मैदानी मानकों से अलग हो। जहां पर हिमालय की भौगोलिक संरचना को ध्यान में रख कर निर्माण हो जिससे यहां के छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका बची रहे। निचले क्षेत्रों को भी बचाया जा सके। तीर्थयात्रियों को भी सुरक्षा मिले। सुरंग आधारित परियोजनाओं पर रोक लगे। जल, वन, ग्लेशियर, बुग्याल, जैव-विविधता संरक्षण, सूक्ष्म जल विद्युत की दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता है जिसके लिए हिमालय की अलग नीति हो।

(लेख में विचार निजी हैं)

मुस्कान | श्रीराम शर्मा आचार्य

स्वादिष्ट व्यंजन की कल्पना मात्र से मुंह में पानी भर आता है। शोक समाचार पाकर उदासी छा जाती है। अदृश्य होते हुए भी मन की हलचलों का भला-बुरा प्रभाव जीवन में पग-पग पर अनुभव होता है। मनुष्य अपने मानस का प्रतिबिंब है। मानसिक दशा का स्वास्थ्य के साथ घनिष्ठ संबंध है। शोधों के आधार पर तो यह भी कहा जाने लगा है कि रोग शरीर में नहीं, बल्कि मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। यही कारण है कि उत्तम और समग्र स्वास्थ्य के लिए मन का स्वस्थ होना जरूरी है। रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन ने अंग्रेजी में कई साहसिक उपन्यास लिखे हैं, उन्हें पढ़ने वाले सोचते थे कि लेखक भी योद्धा जैसा दिखने वाला कोई भारी-भरकम कद्दावर होगा जबकि वास्तविकता यह थी कि उनने अपनी अधिकांश प्रसिद्ध कृतियां रुग्णावस्था में चारपाई पर पड़े हुए लिखीं। शंकराचार्य अपने जीवन के उत्तरार्ध में भगंदर के मरीज रहे, वैद्य ने उनकी स्थिति को देखते हुए शारीरिक श्रम तथा चलने-फिरने की मनाही की थी परंतु उस जर्जर काया को लेकर ही उनने चारों धामों की स्थापना, शास्त्रार्थ द्वारा दिग्विजय तथा पातंजलि के भाष्य आदि का गुरुत्तर कार्य भी संपन्न किया। यहां शारीरिक स्वास्थ्य के नियमों की अवहेलना करने अथवा उन्हें नगण्य बताने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। कहने का आशय इतना भर है कि स्वस्थ शरीर का सदुपयोग जिस मनस्विता के आधार पर संभव होता है-उसके विकास पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए, मनःस्थिति हल्की-फुल्की रहनी चाहिए। प्रसन्न चित्त रहना मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। उदासीन रहने वालों की अपेक्षा खुशमिजाज लोग अक्सर अधिक स्वस्थ, उत्साही और स्फूर्तिवान पाए जाते हैं। गीताकार ने प्रसन्नता को महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक सुण माना है, और कहा है कि प्रसन्न चित्त लोगों को उद्विग्नता एवं दुःख नहीं सताते। अकारण भय, आशंका, क्रोध, दुश्चिंता आदि की गणना मानसिक रोगों में की जाती है। जिस प्रकार शारीरिक रुग्णता का लक्षण मुख-मंडल पर दृष्टिगोचर होता है, उसी प्रकार मन की रुग्णता भी चेहरे पर झलकती है। मनोविज्ञानी डॉ. लिली एलन के अनुसार 'मुस्कान वह दवा है, जो इन रोगों के निशान आपके चेहरे से ही नहीं उड़ा देगी वरन इन रोगों की जड़ भी आपके अन्तः से निकाल देगी।'

रीडर्स मेल

पेंशन पर न हो राजनीति

आजकल एक खबर सुर्खियों में है कि केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारी पेंशन योजना के तहत प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन में वृद्धि कर सकती है। अभी न्यूनतम पेंशन लगभग 1,000 हजार रुपये है। अगर सरकार ऐसा कर देती है तो करोड़ों लोगों को खुशी होगी। उनकी बुढ़ापे में अपने खर्चे की टेंशन कुछ कम होगी। देश के हर कर्मचारी, चाहे वो सरकारी नौकरी का हो या निजी संस्थान का, को पेंशन महंगाई के हिसाब से मिलनी चाहिए। 60 वर्ष के बाद किसी भी व्यक्ति में इतनी एनर्जी रह नहीं जाती कि अपने खर्चे पूरे करने के लिए और कोई नौकरी या काम-धंधा कर ले। इसलिए कर्मचारियों की पेंशन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार से अनुरोध है कि प्राइवेट सेक्टर में काम, रोजगार करने वाले लोगों का बुढ़ापा सुरक्षित करने के लिए भी कोई अच्छी सी पेंशन योजना अमल में लाए। देश में सरकारी क्षेत्र से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में लोग कार्यरत हैं। केंद्र सरकार ने कौशल विकास को बढ़ावा देने और युवाओं की प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को दी हरी झंडी देकर अच्छा प्रयास किया है क्योंकि देश में बेरोजगारी ज्यादा है, और सभी बेरोजगारों को सरकारी नौकरी मुहैया करना नामुमकिन सी बात है। इसलिए प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने और युवाओं को इस क्षेत्र में नौकरी करने के लिए प्रेरित करना जरूरी है। सरकार का कौशल विकास मिशन भी तभी कामयाब होगा और युवा वर्ग की इसमें रुचि बढ़ेगी। वह तब बढ़ेगी जब सरकार प्राइवेट सेक्टर में उचित पेंशन का भी इंतजाम करे।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

नेपाल में शांति की कामना

नेपाल में युवा विद्रोह के बाद अशांति, अराजकता और अफरातफरी का माहौल बना हुआ था। इस बीच नई प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने पद की शपथ ले ली है, और संसद भवन को भंग करते हुए मार्च में आम चुनाव कराने का फैसला किया है। नेपाल के युवाओं ने जिस तेजी के साथ सत्ता पलट किया ऐसी मिसाल दुनिया में कम मिलती है। अब अपेक्षा कर सकते हैं कि नेपाल में शांति का माहौल होगा। बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था ठीक होगी। जनता में विश्वास बहाली का माहौल बनेगा। भारत के लिए चिंता का विषय है कि नेपाल, जिसके साथ भारत के सांस्कृतिक संबंध हैं, अभी त्रासदी से गुजर रहा है।

वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

साफ-सफाई अनुशासन से होगी

देश में स्वच्छता अभियान के सफर को गुटखा-पान की पिचकारी और पाउच बदनाम कर रहे हैं। सड़कों, दीवारों और सार्वजनिक स्थलों पर थूक के दाग और बिखरे पाउच हमारी लापरवाही का आईना हैं। यह सिर्फ गंदगी नहीं, बल्कि बीमारियों का भी बड़ा कारण है। हैरानी की बात है कि जो लोग अपने घर को साफ रखते हैं, वही बाहर बेधड़क गंदगी फैलाने से नहीं चूकते। गुटखा-पान की लत न केवल स्वास्थ्यनाशक है, बल्कि समाज को गंदगी और कुरूपता का उपहार भी दे रही है। सख्त जुर्माना और कानूनी कार्रवाई से ही इस समस्या से निजात मिलेगी। गुटखा-पान थूकने की आदत पर नकेल नहीं कसी जाएगी तो स्वच्छ भारत का सपना अधूरा रहेगा। असल सफाई झाड़ू से नहीं, अनुशासन और जिम्मेदारी से शुरू होती है।

अमृतलाल मारू 'रवि', इंदौर

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

राष्ट्रीय सहारा
• राष्ट्रीयता • कर्त्तव्य • समर्पण
वर्ष-35, अंक 32

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3, 4 सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा तथा 1209-1210, बारहवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग नई दिल्ली से प्रकाशित।
। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 011-23352369, 011-23352372, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

पंजाब केसरी संपादकीय

संस्थापक: शहीद शिरोमणि लाला जगतनारायण जी, अमर शहीद रमेश चन्द्र जी एवं कलम के योद्धा अश्विनी कुमार जी

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता फिर से पटरी पर लौट आई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भी वार्ता के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत भेजने को राजी हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रम्प और उनके सलाहकार पीटर नवारो द्वारा भारत के खिलाफ दिए गए कड़वे बयानों के बाद अब ऐसा लगता है कि अमेरिका हालात सम्भालने की कोशिश कर रहा है। व्यापार वार्ता के लिए कूटनीतिक चैनलों से वार्ता जारी है। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कई प्रमुख अमेरिकी सांसदों के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंधों पर चर्चा की और कूटनीति के माध्यम से यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के प्रति जानकारी दी। केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी व्यापार वार्ता को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने भी यह स्वीकार किया है कि रूस से तेल की खरीद के लिए भारत पर भारी शुल्क लगाने से दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। ऐसा लगता है कि ट्रम्प भारत को लेकर दुविधा में फंस गए हैं। उनकी नीतियों में साफ विरोधाभास दिखाई देता है लेकिन वे अपने ही बुने जाल में फंसते जा रहे हैं। अब उन्हें लगता है कि कुछ न कुछ किया जाना चाहिए।

डोनाल्ड ट्रम्प और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापारिक संबंधों में सुधार के संकेत दिए। राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि वॉशिंगटन और दिल्ली के बीच चल रही बातचीत जल्दी किसी बेहतर नतीजे पर पहुंचेगी। ट्रम्प ने यह भी कहा कि वे सभी तरह की बाधाएं खत्म करने के लिए आने वाले हफ्तों में प्रधानमंत्री मोदी से बात करेंगे। ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, 'मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार बाधा को दूर करने के लिए बातचीत जारी है। आने वाले हफ्तों में मैं अपने बहुत अच्छे दोस्त, पीएम मोदी से बात के लिए उत्सुक हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों महान देशों के लिए एक सफल नतीजे पर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी'। राष्ट्रपति ट्रम्प की इस पोस्ट के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'भारत और अमेरिका अच्छे दोस्त और नैसर्गिक सहयोगी हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी व्यापार वार्ता भारत-अमेरिका साझेदारी के असीमित संभावनाओं को खोलने का रास्ता बना देगी। हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए मेहनत कर रही हैं।

> डोनाल्ड ट्रम्प और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापारिक संबंधों में सुधार के संकेत दिए। राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि वॉशिंगटन और दिल्ली के बीच चल रही बातचीत जल्दी किसी बेहतर नतीजे पर पहुंचेगी। ट्रम्प ने यह भी कहा कि वे सभी तरह की बाधाएं खत्म करने के लिए आने वाले हफ्तों में प्रधानमंत्री मोदी से बात करेंगे। ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, 'मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार बाधा को दूर करने के लिए बातचीत जारी है। आने वाले हफ्तों में मैं अपने बहुत अच्छे दोस्त, पीएम मोदी से बात के लिए उत्सुक हूं।

भारत और चीन ने जिस तरह से समूचे विश्व को अमेरिका के जाल से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया है, उसके बाद से ट्रम्प भारत को पुचकारने में लगे हैं। एक तरफ ट्रम्प भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं तो दूसरी तरफ यूरोपीय देशों को भारत और चीन पर 100 प्रतिशत टैक्स लगाने को कहते हैं। ट्रम्प के भारत विरोधी बयानों का बड़ा कारण वहां की घरेलू राजनीति भी है। ट्रम्प का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा भी सबसे बड़ा कारण है। ट्रम्प देश के लोगों को यह दिखाना चाहते हैं कि वह अमेरिका में उद्योगों और नौकरियों को बचाने के लिए यह सब कर रहे हैं। ट्रम्प की टैरिफ नीति के विरोध में अमेरिका के भीतर भी आवाज बुलंद होने लगी है। ट्रम्प यह भी जानते हैं कि चीन को संतुलित करने के लिए भारत को पूरी तरह से अलग-थलग नहीं किया जा सकता। भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि उसकी विदेश नीति स्वतंत्र है और वह किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। भारत ने किसी भी दबाव के आगे झुकने से साफ इंकार करते हुए रूस से तेल और हथियार खरीदना जारी रखा हुआ है। यद्यपि मोदी सरकार ने पूर्व में अमेरिकी चेतावनियों के चलते ईरान और वेनेजुएला से तेल आयात को रोक दिया था लेकिन इस वर्ष रूस के साथ यह मामला काफी जटिल हो गया। रूस से हमारी मित्रता और भारत की घरेलू जरूरतों को देखते हुए तेल की खरीद बहुत जरूरी है। इससे भारत के हितों की रक्षा होती है। दूसरा भारत कृषि और डेयरी उत्पादों को लेकर अमेरिका के साथ ऐसा समझौता नहीं कर सकता जिससे भारत के किसानों को नुक्सान पहुंचे।

भारत किसानों की सुरक्षा के लिए कृषि क्षेत्र को आयात के लिए खोलने के खिलाफ दृढ़ है। अमेरिका इस बात के लिए दबाव डाल रहा है कि कृषि और डेयरी उत्पादों का क्षेत्र खोला जाए क्योंकि ऐसा समझौता यूरोपीय संघ और जापान के साथ भविष्य में समझौतों के लिए एक मिसाल कायम करेगा। ट्रम्प भारत पर इसलिए ज्यादा दबाव बना रहे हैं क्योंकि यह कदम व्यापार से ज्यादा भू-राजनीतिक दबाव बनाने के लिए भी हैं। हो सकता है कि व्यापार वार्ता में अमेरिका कुछ नए प्रस्ताव पेश करे जिसमें हथियारों की डील भी शामिल हो। भारत को बहुत ही फूंक-फूंक कर कदम रखना होगा, क्योंकि ट्रम्प पर अब ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। देखना होगा कि आने वाले दिनों में वार्ता का क्या नतीजा निकलता है। टैरिफ कटौती के अलावा बोइंग विमान, हैलीकॉप्टर और परमाणु रिएक्टर तक बड़े पैमाने पर कमर्शियल खरीद के लिए दबाव डाल सकता है। ट्रम्प और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की होने वाली बातचीत में कोई न कोई समाधान निकलेगा। अमेरिका उन निर्मित वस्तुओं पर ध्यान केन्द्रित करेगा जो पूंजी प्रधान हैं, जबकि भारत उन वस्तुओं पर ध्यान केन्द्रित करेगा जो श्रम प्रधान हों। ट्रम्प अंततः तोल-मोल करके भारत से व्यापार करने पर सहमत हो सकते हैं। अब गेंद भारत के पाले में नहीं अमेरिका के पाले में है।

धैर्य और अहिंसा के बल पर...

गीता पाढा

शांति और सद्भाव बिना, कभी राष्ट्र एक सूत्र में नहीं बंध पाते हैं,
जो आपस में ही संग्राम करें वह इतिहास में मूर्ख कहलाते हैं,
बुद्धिहीन राजा के राज्य में उन्नति के मार्ग बंद हो जाते हैं,
धैर्य और अहिंसा के बल पर कुछ लोग विश्व को दिशा दिखाते हैं!

जरूरत पड़ी तो हम अकेले 50-100 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव

गयाजी, (पंजाब केसरी): बिहार में अगले कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि आवश्यकता पड़ी तो हम अकेले 50 से 100 सीट पर चुनाव लड़ेंगे।

उन्होंने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी पहले से हारे हुए हैं, इसीलिए 243 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बात नहीं बन पा रही है। मंत्री ने कहा कि हमारी पार्टी छोटी-मोटी पार्टी नहीं है 10 वर्ष पार्टी के हो गए हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो। इसके लिए दो क्राइटेरिया होते हैं, एक विधानसभा में 60 प्रतिशत सीट जीतकर जाना होता है।

इस हवेली में आती है हर वर्ष एक आत्मा

डा. चन्द्र त्रिखा
chandertrikha@gmail.com

हरियाणा के जिला झज्जर के एक गांव गुड़ियानी में एक हवेली है, जहां इस समय सिवाय कबूतरों के, और कोई नहीं रहता। कुछेक कोनों में कुछ पुरानी पांडुलिपियां लाल कपड़ों में बंधी रखी थीं, अब शायद नहीं होंगी या वे गठरियां होंगी भी तो उनका रंग भी बदल चुका होगा। इन्हीं दिनों एक आत्मा भी वहां आती है और पूरे जनपद में चक्कर लगाकर लौट जाती है। यह दिव्य-आत्मा उस शख्स की है जो इसी हवेली की ओर, 'कोलकाता' से एक सेवादार के साथ रेल द्वारा चला था। यह संभवत: 13-14 सितम्बर, 1907 की घटना है। उसके साथ उसकी एक संदूकची थी, जिसमें कुछ किताबें, कुछ कोरे कागज, कुछ अखबारों की कतरनें, दो टोपियां, दो-तीन जोड़ी कुर्ते-पायजामे व एक छोटी सी सरस्वती प्रतिमा व एक जोड़े तौलिया-मौजे व एक जोड़ी चप्पल थीं। साथ ही दैनिक पूजा-अर्चना के लिए तांबे की एक प्लेट, घंटी व धूपदान भी था।

जब वह शख्स कलकत्ता से चला था तब से उसे तेज बुखार था। सांस उखड़ी हुई थी, उस पर लम्बी यात्रा। एक ही तड़प थी कि किसी तरह अपनी जन्मस्थली पहुंच जाए और वहां पुरखों की हवेली में ही अंतिम दिन कुछ लिखते-लिखाते कटे। मगर रेल पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देर से पहुंची। उस समय गांव की ओर जाने का कोई साधन नहीं था। सेवक उसे किसी तरह रेलवे स्टेशन के सामने स्थित एक धर्मशाला तक ले आया। मगर मैनेजर ने जब देखा कि रात बिताने के लिए आने वाले शख्स की सांसें उखड़ रही हैं, फतेहपुरी में तो उसने धर्मशाला में कमरा देने से भी इन्कार कर दिया। तब तक सर्दी का मौसम भी दस्तकें दे चुका था। सेवक ने मुश्किल से अपने स्वामी को उसी धर्मशाला के बाहरी बरामदे में लिटा दिया। एक कम्बल उढ़ा दिया और उसी रात किसी क्षण उस दिव्य पुरुष ने 'हरि ओम' कहते हुए अंतिम सांस ली। अधखुली आंखों में उस पुश्तैनी हवेली का चित्र था, जहां वह दिव्य पुरुष पहुंच नहीं पाया।

अगले दिन पौ फटने से पहले ही उस सेवक ने एक पुराने जमाने की जीप का सहारा लिया। जीप-ड्राइवर को अपनी जेब की सारी राशि दी और कम्बल में लिपटे उस दिव्य शव को डालकर गांव तक ले आए। वहां गांव वाले एक आवाज पर 'बाबू जी, बाबू जी' कहते एकत्र हो गए। पंचायती निर्णय हुआ कि अंतिम-क्रिया विधिपूर्वक हो। उस समय परिजन भी आ पाए या नहीं, यह तो पता नहीं चला लेकिन उस दिव्य पुरुष, जिसकी कलम से लार्ड कर्जन सरीखा वायसराय भी कांपता था, की अंतिम-क्रिया हुई।

उस शख्स ने लगभग 16 कृतियां दी थीं, 'हिन्दुस्तान' (कालाकांकर) का सम्पादन किया था। कलकत्ता में उस समय के सबसे बड़े दैनिक 'भारतमित्र' का भी सम्पादन किया था। लाहौर से छपने वाले 'कोहेनूर' (उर्दू पत्र) व 'अखबारे चुनार' (उर्दू) का भी सम्पादन किया था। उनकी चर्चित रचनाओं में 'शिवशम्भू के चिट्ठे' के इलावा उर्दू बीबी के नाम चिट्ठी भी शामिल थी। उसके प्रशंसकों के हिंदी के महान विद्वान आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, पत्रकार महाशय कृष्ण, उर्दू के अदीब मंटो, शायर अहमद नदीम कासमी व फैज़ भी शामिल थे।

42 वर्ष की अल्पायु में ही अंतिम सांस लेने वाले इस दिव्य लेखक बाबू बाल मुकन्द गुप्त की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने वालों में उनकी स्मृति में एडवोकेट नरेश चौहान के नेतृत्व में दर्जनभर दीवानों कर एक शोध संस्थान भी स्थापित किया। वर्ष में दो बार समारोहों की परंपरा आरंभ की। यहां प्रदेश के लगभग सभी मुख्यमंत्रियों ने यहां आने व इस हवेली को एक राष्ट्रीय स्मारक का रूप देने की घोषणाएं की। मगर एक मुख्यमंत्री के इलावा शेष कोई भी नहीं आ पाया। ऐसी दिव्य आत्माएं अभिशाप तो नहीं देती, मगर श्राद्धों के दिनों अपनी जन्मस्थली तक आती तो हैं। उनकी इतनी अपेक्षा कभी-कभी कचोटती अवश्य है।

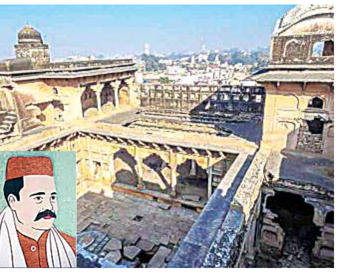

इस दिव्य आत्मा का नाम था, प्रख्यात साहित्यकार व पत्रकार 'बाबू बाल मुकुन्द गुप्त'। परिजन अब भी कलकत्ता में रहते हैं। बाबू जी का श्राद्ध कर्म होता होगा मगर शेष भटकाव अभी जारी है। श्राद्धों के दिनों में यदि पितर धरती पर उतरते हैं तो यह मान कर चलना चाहिए कि रेवाड़ी के समीप गांव गुडियानी में भारत के हिंदी पत्रकारिता के महानायक बाबू बाल मुकुंद गुप्त की आत्मा भी अपनी धीरे-धीरे ध्वस्त हो रही हवेली के आसपास होगी। इसी हवेली में बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने पहली बार आंखें खोली थी। यहीं से पंडित मदन मोहन मालवीय, उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें पहले कालाकांकर और फिर लाहौर व कलकत्ता (अब कोलकाता) ले गए थे।

इसी गांव के परिवेश में व जनपद में अपनी शुरुआती शिक्षा-प्राप्ति के दौरान ही गुप्त जी ने लिखना शुरू कर दिया था। कुछ लेख छपे तो लेखनी की सुगंध आसपास फैलने लगी। कालाकांकर में उन्हें वहां से प्रकाशित होने वाले 'हिन्दोस्तान' का सम्पादन-कार्यभार मिला और जब ख्याति फैली तो 'कोहेनूर' में चले गए। लेखों की धूम का सिलसिला शुरू हो चुका था। वहां से कलकत्ता में 'भारत-मित्र' और बंगबंधु के सम्पादक पद की पेशकश आई तो वहां चले गए। वहां सम्पादन कार्य चुनौतीपूर्ण भी था और ढेरों उम्मीदें भी लगाई जाती थीं एक सम्पादक से। उन दिनों ऐसा पहली बार हुआ था कि तत्कालीन वायसराय लार्ड कर्जन ने अपने स्टाफ को, बाबू बाल मुकुंद गुप्त के सम्पादकीय लेखों और उनके नियमित स्तम्भ 'शिव शम्भू के चिट्ठे' का अंग्रेजी अनुवाद दैनिक आधार पर उन्हें भेजने का आदेश दिया था। कलकत्ता-प्रवास के मध्य हिंदी के महान विद्वान महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी बाबू बाल मुकुंद गुप्त का टकराव हो जाया करता था लेकिन अधिकांश अवसरों पर द्विवेदी जी को ही झुकना पड़ता था। कहां गुड़ियानी का ग्रामीण युवा पत्रकार और कहां भाषा-मर्मज्ञ आचार्य द्विवेदी। बहरहाल, खूब चर्चा होती गुप्त जी की। इसी बीच उन्होंने बंगला की कृतियों के हिंदी अनुवाद का सिलसिला भी शुरू कर दिया।

काम के बोझ से शरीर शीघ्र ही हारने लगा था। एक बार उनको लगा कि अब लम्बी पारी नहीं खेल पाएंगे तो उन्होंने अपने गांव गुड़ियानी लौटने का मन बना दिया। कोलकाता से तो यही कहकर अवकाश लिया था कि वापिस लौट आएंगे लेकिन मन में यही आशंका थी कि शायद शरीर इतना श्रम झेल नहीं पाएगा। पिछले कुछ दशकों से बाबू जी के दीवाने हर वर्ष उसी हवेली में हवन करते हैं और फिर शहर में एक समारोह। मगरअब धीरे-धीरे हवेली की हालत खराब होने लगी हैं और जहां बैठकर बाबू जी कलम-क्रांति करते थे वह स्थल भी ध्वस्त होने लगा है। वंशज कोलकाता में रहते हैं। एक प्रपौत्र विमल गुप्त सरकार को बार-बार आग्रह कर रहे हैं कि यह हवेली सरकार ले ले और कोई स्मारक बन जाए। कुछ दीवाने लोग हैं एडवोकेट नरेश चौहान, रोहित यादव, ऋषि सिंहल, सत्यवीर नाहड़िया और प्रवीण खुराना जैसे जो अब भी अपने दायित्व और लगाव से बंधे हुए हैं।

ढेरों प्रश्न हैं जो अभी भी उत्तर के मोहताज हैं। पहला यह कि इस हवेली का अधिग्रहण क्यों नहीं हो पा रहा? दूसरा यह कि क्या युवा पीढ़ी अभी भी इस महान युगपुरुष के साथ भावनात्मक या विचारात्मक रूप से जुड़ी हुई है? तीसरा यह कि बाबू जी पर ग्रंथावलियां तो छपीं लेकिन क्या इस जनपद के शिक्षा संस्थानों तक पहुंच पाई? चौथा उन परिस्थितियों पर शोध, जिनमें बाबू जी मात्र चार दशक (42 वर्ष) ही जी पाए। उनके महाप्रयाण के बारे में कोई पुख्ता विशेष विवरण अभी भी नहीं मिलता।

टीवी बहसों का गिरता स्तर चिंतनीय

विनीत नारायण
www.vineetnarain.net

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां संवाद और विमर्श लोकतंत्र की रीढ़ माने जाते हैं, वहां आज टीवी बहसें एक ऐसा मंच बन चुकी हैं जहां तर्क की जगह एक दूसरे का अपमान, चीख-पुकार और राजनीतिक दुष्प्रचार हावी हो गया है। प्राइम टाइम के इन शो में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रवक्ता एक-दूसरे पर व्यक्तिगत हमले करते नजर आते हैं जिससे बहसें निष्कर्षहीन हो जाती हैं। यह न केवल दर्शकों के समय की बर्बादी है, बल्कि समाज में ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने वाला एक खतरनाक माध्यम भी बन गया है। प्रवक्ताओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अपमानजनक भाषा ने टीवी डिबेट्स को एक सर्कस का रूप दे दिया है। चैनल और एंकर ऐसे निरर्थक बहसों को क्यों बढ़ावा देते हैं? क्या यह टीआरपी की होड़ है या राजनीतिक दबाव?

टीवी बहसों का इतिहास भारत में 1990 के दशक से जुड़ा है, जब निजी चैनलों का आगमन हुआ। शुरू में ये बहसें मुद्दों पर तथ्यपरक चर्चा का माध्यम थीं लेकिन आज वे एक शोरगुल भरी जंग बन चुकी हैं। विभिन्न अध्ययनों और रिपोर्टों से स्पष्ट है कि भारतीय टीवी डिबेट्स में आक्रामकता और विषाक्त भाषा का स्तर चिंताजनक रूप से बढ़ा है। एक शोध के अनुसार, बहसों में एंकरों द्वारा आक्रामक लहजे का इस्तेमाल 80 प्रतिशत से अधिक होता है जो दर्शकों पर नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है। ये आंकड़े बताते हैं कि बहसें अब सूचना का स्रोत नहीं, बल्कि प्रचार का हथियार बन चुकी हैं।

राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं द्वारा अपमानजनक भाषा का उपयोग इस समस्या का केंद्रीय बिंदु है। एक बहस के दौरान एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता को दूसरी पार्टी के प्रवक्ता द्वारा 'जयचंद' और 'गद्दार' कहा गया, जिसे सुनकर उस प्रवक्ता को हार्टअटैक हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना टीवी डिबेट्स की विषाक्तता का जीता-जागता उदाहरण है। इसी तरह अन्य प्रवक्ता ने एक दूसरे प्रवक्ता को 'नाली का कीड़ा','दादी मां', 'वैंप' कहा या 'उल्टा टांग दूंगा' जैसे शब्दों का प्रयोग करते पाए गए हैं। एक प्रवक्ता ने तो बहस के दौरान दूसरे प्रवक्ता पर हाथ भी उठा दिया।

यह समस्या बढ़ रही है, कम नहीं हुई। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक टीवी बहस के दौरान एक नेता पर कुर्सी फेंकी गई, जिसके बाद एफआईआर भी दर्ज हुई। नवंबर 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक टीवी चैनल को एक प्रवक्ता के खिलाफ अपमानजनक क्लिप हटाने का आदेश दिया। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि अपमान अब शारीरिक हिंसा तक पहुंच गया है। राजनीतिक दलों द्वारा ऐसे प्रवक्ताओं को चुना जाना भी एक चिंताजनक बात है। अधिकांश प्रवक्ता राजनीतिक अनुभव की कमी रखते हैं और केवल टीवी पर चिल्लाने के लिए नियुक्त होते हैं। यदि राजनैतिक दल द्वारा योग्य प्रवक्ताओं को चुना गया होता तो बहसें अधिक सभ्य और उत्पादक होतीं लेकिन वर्तमान में ये प्रवक्ता दलों के चेहरे बन चुके हैं, जो विचारधारा के बजाय व्यक्तिगत हमलों पर निर्भर हैं।

ऐसे स्तरहीन प्रवक्ताओं को चैनल क्यों आमंत्रित करते हैं? इसका मुख्य कारण टीआरपी (टेलीविजन रेटिंग पॉइंट) है। शोरगुल भरी बहसें दर्शकों को आकर्षित करती रही हैं, क्योंकि वे मनोरंजन का रूप ले लेती हैं। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बताती है कि आर्थिक दबावों के कारण ग्राउंड रिपोर्टिंग कम हो गई है और स्टूडियो डिबेट्स ही मुख्य सामग्री बन गई हैं। चैनल जानते हैं कि तर्कपूर्ण चर्चा से दर्शक भागते हैं लेकिन चीख-पुकार उन्हें बांधे रखती है। चैनल और एंकरों की जिम्मेदारी यहां महत्वपूर्ण है। वे मॉडरेटर हैं, न कि भागीदार लेकिन अधिकांश एंकर, खुद अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। रेडिफ की एक रिपोर्ट में कहा गया कि बहसें 'विषैली' हो चुकी हैं। एंकर विपक्ष को बोलने न देकर, मात्र समय काटते हैं। यदि चैनल सख्त कोड ऑफ कंडक्ट लागू करें तो स्थिति सुधर सकती है लेकिन टीआरपी और राजनीतिक लाभ के लालच में वे अनदेखी करते हैं।

समाधान के लिए बहुआयामी प्रयास जरूरी हैं। सबसे पहले राजनैतिक दलों को प्रवक्ताओं के चयन में सुधार करना चाहिए। केवल अनुभवी और सभ्य व्यक्तियों को ही टीवी पर भेजा जाए। दूसरा, 'ट्राई' और सूचना मंत्रालय को सख्त नियम लागू करने चाहिए, जैसे अपमानजनक भाषा पर तत्काल जुर्माना लगे। तीसरा, दर्शकों को जागरूक होना चाहिए। वे ऐसे चैनलों का बहिष्कार करें जो सनसनी फैलाते हैं। चौथा, स्वतंत्र मीडिया वॉचडॉग को मजबूत बनाना चाहिए। अंत में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब पर तथ्यपरक बहसें बढ़ावा दें, जहां सोशल मीडिया इंगेजमेंट सकारात्मक हो। भारत की टीवी बहसें लोकतंत्र का मजाक बन चुकी हैं। अपमानजनक प्रवक्ताओं का बोलबाला न केवल बहसों को निरर्थक बनाता है, बल्कि समाज को विभाजित करता है। चैनल और एंकरों को यदि वास्तव में पत्रकारिता का सम्मान करना है तो उन्हें टीआरपी के पीछे भागना छोड़कर जिम्मेदार संवाद को प्राथमिकता देनी चाहिए। अन्यथा, ये बहसें लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करती रहेंगी। समय आ गया है कि हम एक ऐसे मीडिया की मांग करें जहां तर्क जीते, न कि अपमान। केवल तभी भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा।

खादी : विकसित भारत की स्वदेशी पहचान

मनोज कुमार
अध्यक्ष (खादी और ग्रामोद्योग आयोग)

पूरी दुनिया इन दिनों 'टैरिफ वॉर के चक्रव्यूह' में उलझी है। हर देश अपने-अपने हितों को साधने के लिए आयात-निर्यात पर शुल्क की दीवारें खड़ी कर रहा है। वैश्विक कूटनीति के इस दौर में आर्थिक प्रतिस्पर्धा ने नए तनाव पैदा किए हैं और वैश्विक व्यापार का संतुलन डगमगा रहा है। प्रत्येक देश इस चक्रव्यूह को भेदने के रास्ते खोज रहा है, लेकिन इससे निकलने के लिए भारत के पास पूर्व में आजमाया हुआ एक शाश्वत समाधान है- स्वदेशी।

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दक्षिण अफ्रीका से लौटकर पूज्य बापू ने चरखे के माध्यम से स्वदेशी से स्वावलंबन का बिगुल फूंका था। आज वही चरखा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प से 'स्वदेशी क्रांति' का आधार बन गया है। हाल ही में गुजरात की धरती से प्रधानमंत्री जी ने कहा था- "गुजरात की ये धरती दो मोहन की है- एक सुदर्शन-चक्रधारी द्वारकाधीश श्रीकृष्ण और दूसरे चरखाधारी मोहन, साबरमती के संत पूज्य बापू।" इन दोनों के मार्गदर्शन पर भारत निरंतर सशक्त हो रहा है। सच्चे अर्थों में मैं कहूं तो खादी के माध्यम से 'स्वदेशी क्रांति का ये मोदी युग है'। आज जब गांवों में चरखे-करघे की घरघराहट गूंजती है, तो उसमें केवल सूत नहीं, बल्कि विकसित भारत की आत्मा का ताना-बाना बुनता है। जिस चरखे को महात्मा गांधी ने 'आजादी का अस्त्र' बनाया था, उसी चरखे को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'विकसित भारत का आधार' बना दिया है। खादी अब केवल वस्त्र नहीं, बल्कि 'स्वदेशी क्रांति की ध्वजवाहक' बन चुकी है।

स्वदेशी क्रांति के अगुवा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विभिन्न मंचों से लगातार देशवासियों से खादी और स्वदेशी उत्पाद अपनाने का आह्वान करते रहे हैं। 31 अगस्त, 2025 को 'मन की बात' में उन्होंने कहा-आने वाले दिनों में त्यौहारों की रौनक होगी। इन त्यौहारों में स्वदेशी को कभी न भूलें- उपहार वही जो भारत में बना हो, पहनावा वही जो भारत में बुना हो, सजावट वही जो भारत में बने सामानों से हो, रोशनी वही जो भारत में बनी झालरों से हो। जीवन की हर जरूरत में स्वदेशी हो और गर्व से कहो- ये स्वदेशी है। इसी तरह से उन्होंने 15 अगस्त, 2025 को लाल किले से संबोधन के दौरान सभी दुकानदारों व व्यापारियों से अपील की कि वे अपनी दुकानों पर बोर्ड लगाएं जिसमें लिखा हो, 'यहां स्वदेशी माल बिकता है'। हाल ही में दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा-जब भी हमने संकल्प लिया है, तब-तब उसे सिद्ध कर दिखाया है। खादी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। खादी विलुप्त होने के कगार पर थी, कोई पूछने वाला नहीं था। जब मुझे सेवा का अवसर मिला, मैंने देश से आह्वान किया और लोगों ने संकल्प लिया। नतीजा यह हुआ कि एक दशक में खादी की बिक्री लगभग सात गुना बढ़ी है। देशवासियों ने 'वोकल फॉर लोकल' के मंत्र के साथ खादी को अपनाया है।

भारत में यह समय तीज और त्यौहारों का है। प्रधानमंत्री की अपील है कि यह त्यौहारों का मौसम केवल संस्कृति का उत्सव न होकर आत्मनिर्भरता का उत्सव भी बने। उनका मंत्र साफ है- "हम जो भी खरीदेंगे, वह मेड इन इंडिया होगा, स्वदेशी होगा और जो भी बेचेंगे वो भी स्वदेशी होगा।" आइए हम सभी आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने जैसे संदेशों के साथ अमृतकाल का विकसित और समृद्ध भारत बनाने का संकल्प लें। ध्यान रहे कि, विकसित भारत की नींव हमें, अपनी-अपनी इकाई से ही रखनी होगी। हम 144 करोड़ भारतवासी संकल्प लें कि हम स्वदेशी वस्तुएं ही खरीदेंगे और बेचेंगे, जो एक स्वावलंबी, समृद्धि-शाली राष्ट्र बनाने में सहायक होगा।

बीते 11 वर्षों में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। कारोबार पहली बार पौने दो लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा है। खादी की बिक्री में सात गुना तक की वृद्धि हुई है। आज देशभर में लगभग 2 करोड़ लोग खादी और ग्रामोद्योग से जुड़कर रोजगार पा रहे हैं। यह केवल आंकड़े नहीं, बल्कि 'स्वदेशी क्रांति' का जीवंत प्रमाण है। मोदी के नेतृत्व में खादी और ग्रामोद्योग न केवल 'वोकल फॉर लोकल' का अगुवा है, बल्कि 'मेक इन इंडिया', 'मेक फॉर द वर्ल्ड' की जीवंत मिसाल भी बन चुका है।

प्रधानमंत्री ने 'मन की बात' से लेकर संसद और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक हर जगह खादी का गौरवगान किया है। उन्होंने कहा है- "जब आप खादी खरीदते हैं, तो यह सिर्फ वस्त्र नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन को संबल देने वाला कदम होता है।" यही खादी आज 'विकसित भारत @2047' अभियान का आधार बन गई है।

राष्ट्र प्रथम की नीति और वंचितों के हितों की भावना से प्रेरित हमारे प्रधानसेवक सदैव लघु उद्यमियों, पशुपालकों, किसानों और श्रमजीवी भाइयों-बहनों की चिंता करते रहे हैं। अपने निजी अनुभव से कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी दुनिया के ऐसे विलक्षण नेता हैं, जो अपने छोटे कारोबारियों और हस्तशिल्पियों के उत्पादों को स्वयं प्रोत्साहित और प्रचारित करते हैं। इतना सशक्त और स्पष्ट संदेश केवल वही दे सकते हैं कि 'देश के उत्पादन में देशवासियों का पसीना झलके।' यही भावना 'वोकल फॉर लोकल' और 'स्वदेशी' के संकल्प को जीवंत बनाती है। आज हम सबका एक ही मंत्र होना चाहिए- 'एक ही संकल्प, स्वदेशी विकल्प'- 'हर त्यौहार, सिर्फ स्वदेशी उपहार'

अभी भारत के धैर्य की परीक्षा का समय है लेकिन समय बदलते समय नहीं लगता। चरखे का पहिया निरंतर गति से घूम रहा है। भारतीय जनमानस का खून-पसीना पूरे उत्साह और सामर्थ्य से अर्थव्यवस्था को सींच रहा है। यही सामर्थ्य विकसित भारत की गाड़ी को उस मंजिल तक पहुंचाएगा, जहां विश्व की महाशक्तियां भी भारत की विराट शक्ति को स्वीकारेंगी। आज नहीं तो कल, भारत को 'विश्व गुरु' के रूप में मान्यता मिलकर रहेगी।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

प्रवाह

77 साल बेमिसाल
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना : 18 अप्रैल 1948 • आगरा

हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है।
- सुमित्रानंदन पंत

प्रधानमंत्री की पूर्वोत्तर के तीन राज्यों की यात्रा के दौरान जो घोषणाएं हुईं, वे महत्वपूर्ण होने के साथ ऐतिहासिक भी हैं। घुसपैठ व विश्वास बहाली की चुनौतियां बेशक हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने शांति के साथ विकास का जो पैगाम दिया है, वह जमीनी स्तर पर दिखे भी, तो यह सबसे बड़ी कामयाबी होगी।

पूर्वोत्तर में मोदी

प्रधानमंत्री मोदी की तीन पूर्वोत्तर राज्यों- मिजोरम, मणिपुर और असम की यात्रा के दौरान जो घोषणाएं हुईं, वे महत्वपूर्ण तो हैं ही, इन्हें ऐतिहासिक भी कहा जाए, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि मई, 2023 में इंफाल घाटी में रहने वाले मैतेई समुदाय और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले कुकी-जो समुदाय के बीच शुरू हुए जातीय संघर्ष में अब तक 260 लोग मारे गए और तकरीबन 60 हजार लोग विस्थापित हुए हैं। करीब दो वर्ष पहले भड़की जातीय हिंसा के बाद राज्य के अपने पहले दौरे में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिया गया शांति का संदेश महत्वपूर्ण है। उनका यह कहना कि मणिपुर ही वह भूमि थी, जहां पहली बार भारतीय राष्ट्रीय सेना ने राष्ट्र ध्वज फहराया था, राज्य के गौरवपूर्ण अतीत और स्वतंत्रता संग्राम में इसकी भूमिका को रेखांकित करता है। राज्य को भारत माता के मुकुट का रत्न बताते हुए कुकी बहुल हिंसा से सर्वाधिक प्रभावित चुराचांदपुर के लिए 7,300 करोड़ रुपये से अधिक और मैतेई बहुल इंफाल के लिए करीब 1,200 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की घोषणा कर प्रधानमंत्री ने पीड़ितों को यह संदेश देने की कोशिश की है कि सरकार और समूचा देश उनके साथ है। राजनीति में कई फैसले रणनीतिक आधारों पर लिए जाते हैं। पिछले दो वर्षों में मणिपुर का मुद्दा देश के भीतर और बाहर जिस तरह से उठाया गया, वह किसी से छिपा नहीं है। यह भी नहीं भूला जा सकता कि किस तरह यूरोपीय संघ की संसद में मणिपुर को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ, जिसे सरकार ने देश का आंतरिक मामला बताते हुए उचित ही खारिज कर दिया था। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मणिपुर में शांति बनी रहे और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे ने जो उम्मीदें जगाई हैं, वे पूरी हों। अपनी मिजोरम यात्रा में प्रधानमंत्री ने आठ हजार करोड़ रुपये ,से भी अधिक की सैरांग-बैरवी रेल लाइन का शुभारंभ किया है, जो इस मायने में ऐतिहासिक है कि यह पहली बार मिजोरम की राजधानी को भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। जाहिर है कि इससे मिजोरम के किसान और व्यवसायी देश भर के बाजारों तक आसानी से पहुंच सकेंगे; कई क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेंगे, सो अलग। असम यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य को करीब बारह हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात दी है, जो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को यकीनन सहारा देंगी। कुल मिलाकर देखें, तो प्रधानमंत्री का पूर्वोत्तर दौरा केवल परियोजनाओं तक सीमित नहीं, यह एक दृष्टि का प्रतिबिंब है। म्यांमार से हो रही घुसपैठ समेत विभिन्न समूहों के बीच विश्वास बहाली की चुनौतियां बेशक हैं, लेकिन पूर्वोत्तर में प्रधानमंत्री ने शांति के साथ विकास का जो पैगाम दिया है, वह जमीनी स्तर पर दिखे भी, तो यह सबसे बड़ी कामयाबी होगी।

पखवाड़े से हिंदी को बाहर निकालिए

हिंदी को जब पखवाड़े की मर्यादा से बाहर निकाला जाएगा, तभी वह सही मायने में अपना स्थान ग्रहण कर पाएगी। तभी वह नीतियों की बुनियाद होगी, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय लोक की आत्मा गहरे तक समाहित होगी।

उमेश चतुर्वेदी
मीडिया एवं राजनीतिक टिप्पणीकार

पितरों को समर्पित सनातन परंपरा का श्राद्ध पक्ष हिंदू मान्यता के अनुसार, शुभ कार्यों के लिए वर्जित है। लेकिन संविधान सभा में श्राद्ध पक्ष में भी बहसें हुईं और फैसले भी हुए। वर्ष 1949 में आठ सितंबर से 22 सितंबर के बीच श्राद्ध पक्ष था। इसी पखवाड़े में महज ढाई दिनों की बहस के बाद हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया। लगता है कि शुभ कार्यों के लिए वर्जित श्राद्ध पक्ष में हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने का जो शुभ कार्य हुआ, उस पर अशुभ छाया पड़ गई। वास्तविकता के धरातल पर वैधानिक दर्जे के लिए जूझती हिंदी को देखकर ऐसी सोच विकसित होना स्वाभाविक है।

जिस तरह श्राद्ध पक्ष में हर बार पितरों को याद किया जाता है, उसी तरह हिंदी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। श्राद्ध पक्ष के साथ ही तकरीबन हर साल हिंदी पखवाड़ा आता है। हिंदी को लेकर सरकारी दफ्तरों में नव उत्साह का संचार हो जाता है। वाद-विवाद, टाइपिंग, निबंध लेखन, आशु लेखन, भाषण आदि की प्रतियोगिताओं के चलते सरकारी दफ्तर हिंदीयाना रौनक से भर जाते हैं। कुछ लोगों को पुरस्कार मिलता है और कार्यालय के हर व्यक्ति के लिए चाय-नाश्ते का इंतजाम हो जाता है। इस तरह पखवाड़े भर तक हिंदी का एक तरह से तर्पण होता है और फिर दफ्तरी दुनिया अपने पुराने ढर्रे पर फिर से लौट आती है, जिसकी कल्पना 1835 में मैकाले ने की थी।

हिंदी का भविष्य कैसा होगा, इसे समझने के लिए 14-15 अगस्त, 1947 की दरम्यानी रात को हुए कार्यक्रम को देखना होगा। 'ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी' भाषण ने ही तय कर दिया कि भारत में हिंदी का भविष्य क्या होने वाला है। तर्क हो सकता है कि नेहरू का मशहूर भाषण अंग्रेजी में इसलिए हुआ, क्योंकि दुनिया को बताना था कि हजार साल से चली आ रही गुलामी की बेड़ियों को भारत ने काट डाला है। यह ठीक है कि तब दुनिया की निगाह भारत पर थी, लेकिन दुनिया हिंदी में दिए भाषण का अनुवाद करा सकती थी। नियति के साथ समझौते का सीधा प्रभाव भारत और भारतीयों पर पड़ना था, दुनिया पर नहीं। बेशक नियति के साथ भारत के समझौते की विलायती परत को भारतीय रंग देने की कोशिश अगले दिन गांधी ने जरूर की, जब उन्होंने एक विदेशी संवाददाता को भाषा को लेकर स्पष्ट संदेश दिया। तब उन्होंने कहा था, 'पूरी दुनिया को बता दो कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता।' गांधी की तमाम बातों के साथ उनके इस संदेश को भी भुला दिया गया।

तभी से सितंबर के पहले पखवाड़े या कुछ दफ्तरों में पूरे सितंबर हिंदी का तर्पण करने की परंपरा शुरू हो गई। हिंदी को किनारे रखने में द्रविड़ राजनीति की बड़ी भूमिका रही है। हालांकि हिंदी को लेकर बेहतर रूख बाकी दलों का भी नहीं रहा। भारतीय राजसत्ता के इतिहास में हिंदी को लेकर जमीनी स्तर तक प्रभाव डालने वाले कदम उठाने की कोशिश शायद ही नजर आती है। हिंदी को लेकर ज्यादातर रस्मी अंदाज में कदम उठाए गए। ठोस बदलाव लाने की कोशिश नहीं दिखती है। हिंदी को लेकर सरकारी दफ्तरों में एक निश्चित अवधि के लिए कार्यशालाओं का विधान है, जिनमें कुछेक कर्मचारियों के अलावा किसी की भागीदारी नहीं होती। अधिकारी तो हिंदी को लेकर होने वाली ऐसी बैठकों में जाना भी अपनी तौहीन समझते हैं। हिंदी के बढ़ते प्रसार को लेकर हिंदी प्रेमी आए दिन खुश होते रहते हैं, लेकिन वह प्रसार राजकीय कम, लोकपक्षीय ज्यादा है। कॉरपोरेट जगत ने बाजार तक अपनी सीधी पहुंच बनाने के लिए हिंदी समेत भारतीय भाषाओं को अपना हथियार बना लिया है। लेकिन नीतियों, प्रशासन और ऐसे ही दूसरे कार्यों के लिए कॉरपोरेट जगत में हिंदी उतनी ही बेगानी है, जितनी संविधान के तहत कार्य करने वाली संस्थाओं और सरकारी दफ्तरों की दीवारों के पीछे है। इस तरह कह सकते हैं कि हिंदी कमाई की भाषा तो है, लेकिन उसे नियंत्रित करने वाली सोच की भाषा अंग्रेजी ही है। लोहिया के अंग्रेजी हटाओ आंदोलन को समाजवादी खेमा बहुत शानदार मानता है, लेकिन लगता है कि इस आंदोलन ने हिंदी विरोधियों की कुंठा को अभिव्यक्त होने का जोरदार मौका दिया। इसी कुंठा की उपज है कि गैर-हिंदीभाषी राज्यों में हिंदी को लेकर तिरस्कार और अंग्रेजी के प्रति सम्मान दिखता है। लोहिया के आंदोलन ने द्रविड़ दलों में गहरे तक हिंदी को लेकर प्रतिक्रिया बोध को स्थापित किया। यह विडंबना ही है कि आज लोहिया के अनुयायी समाजवादी धारा के दल उन द्रविड़ दलों के साथ खड़े हैं, जो हिंदी को लेकर जहर उगलते हैं और वे चुप्पी साधे रखते हैं। आजादी के बाद की कांग्रेस न तो हिंदी समर्थक रही और न ही विरोधी। परिस्थिति और जगह के हिसाब से उसकी हिंदी नीति चलती रही। जबकि भाजपा ने मोदी-शाह के दौर में हिंदी को प्रतिष्ठित करने की कोशिश की, लेकिन नौकरशाही का रूख नहीं बदला। नौकरशाही का रवैया अब भी अंग्रेजी समर्थक ज्यादा है।

बहरहाल राजकाज की नीतिगत भाषा अब भी हिंदी ही है। संसदीय हिंदी समिति की सिफारिशें हों या फिर राजभाषा कानून के दूसरे प्रावधान, अब भी हिंदी के कथित उत्थान और विकास के लिए रस्म ही पूरी की जाती है। नीतियां अब भी अंग्रेजी में ही बनती हैं, और हिंदी या भारतीय भाषाओं में उनका अनुवाद परोसा जा रहा है। अनुवाद वाली भाषा के जरिये राजकाज को जमीनी हकीकत बनाया तो जा सकता है, लेकिन उस राजकाज में लोक की आत्मा नहीं रहती।

गांधी ने जब *हिंद स्वराज* में भावी स्वाधीन भारत के लिए हिंदी की कल्पना की थी, तो उसका उद्देश्य था, राजकाज और उसकी नीतियों में भारत की आत्मा को सहजता से शामिल करना। आज अगर राजकाज की नीतियां जमीनी हकीकत से दूर दिखती हैं, तो इसकी एक बड़ी वजह नीति निर्माण में लोक भाषाओं की अनुपस्थिति भी है।

ऐसे माहौल में हिंदी सिर्फ सालाना दफ्तरी रस्मों में सिमट कर रह जाती है। कार्यालय की हिंदी वह तब होगी, जब रोजाना उसके जरिये दफ्तरी कामकाज निबटाए जाएंगे। जब हिंदी में सोचा जाएगा, और उस सोच के आधार पर नीतियां बनेंगी, तभी उन नीतियों में राष्ट्रीय लोक की आत्मा होगी। यहां ध्यान रखना होगा कि हिंदी का मतलब सिर्फ हिंदी से नहीं है, बल्कि दूसरी भारतीय भाषाओं से भी है। भारतीय भाषाएं सहोदरी हैं। हिंदी को जब पखवाड़े की मर्यादा से बाहर निकाला जाएगा, तभी वह सही मायने में अपना स्थान ग्रहण कर पाएगी। तभी वह नीतियों की बुनियाद होगी, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय लोक की आत्मा गहरे तक समाहित होगी।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

लुईस हे

अगर मैं यह मानने को तैयार हूं कि प्रेम सर्वत्र है, और मैं प्रेमयोग्य हूं, तो यह एक दिन सच हो जाएगा। हमें समस्याओं का नहीं, बल्कि अपनी सोच का समाधान करना चाहिए।

अपनी सोच से जीवन को आनंदमय बनाएं

जीवन वास्तव में बहुत ही सरल है। हम जो देते हैं, वही हमें वापस मिलता है। हम अपने बारे में जो सोचते हैं, वही हमारे लिए सच्चाई बन जाती है। मेरा मानना है कि हर कोई, जिसमें मैं भी शामिल हूं, हमारे जीवन की सबसे अच्छी और सबसे बुरी चीज के लिए जिम्मेदार है। हर विचार, जो हम सोचते हैं, हमारे भविष्य को बना रहा है। हममें से हर कोई अपने विचारों और भावनाओं से अपने अनुभव रचता है। हम जो सोचते हैं और जो शब्द बोलते हैं, वे हमारे अनुभवों का निर्माण करते हैं। हम परिस्थितियां खुद बनाते हैं, और फिर अपनी हताशा के लिए दूसरे को दोषी ठहराकर अपनी शक्ति खो देते हैं। किसी भी व्यक्ति, स्थान और वस्तु का हम पर कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि 'हम' ही इसके एकमात्र विचारक हैं। जब हम अपने मन में शांति, सद्भाव और संतुलन पैदा करते हैं, तो हम इसे अपने जीवन में पा लेते हैं। इनमें से कौन-सा कथन आपको पसंद आता है? 'लोग मुझे पकड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं।' दूसरा, 'हर कोई हमेशा मददगार होता है।' इनमें से हर एक विश्वास बिल्कुल अलग अनुभव पैदा करेगा। हम अपने बारे में और जीवन के बारे में जो विश्वास करते हैं, वही हमारे लिए सच हो जाता है। ब्रह्मांड हमारे हर विचार में, जिसे हम सोचना और मानना चुनते हैं, हमारा पूरा साथ देता है। दूसरे शब्दों में, हमारा अवचेतन मन, हम जो भी विश्वास करना चुनते हैं, उसे स्वीकार कर लेता है। इन दोनों का मतलब है कि मैं अपने बारे में और जीवन के बारे में जो विश्वास करती हूं, वही मेरे लिए सच हो जाता है। आप अपने बारे में और जीवन के बारे में जो सोचना चुनते हैं, वही आपके लिए सच हो जाता है। हमारे पास सोचने के असीमित विकल्प होते हैं। चुनना समझदारी भरा होता है। जीवन में सब कुछ हमारे या किसी दूसरे के अनुसार नहीं चलता है। लेकिन जीवन में हम क्या सोचते हैं और किस पर सबसे ज्यादा विश्वास रखते हैं, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सार्वभौमिक शक्ति कभी हमारी आलोचना नहीं करती। वह हमें केवल हमारे मूल्य पर ही स्वीकार करती है। फिर यह जीवन में हमारे विश्वासों को प्रतिबिंबित करती है। अगर मैं यह मानना चाहती हूं कि मैं जीवन में अकेली हूं और कोई मुझसे प्यार नहीं करता, तो मुझे अपनी दुनिया में यही मिलेगा। अगर मैं इस विश्वास को छोड़ने और यह मानने को तैयार हूं कि प्रेम सर्वत्र है, और मैं प्रेमपूर्ण और प्रेमयोग्य हूं, तो यह एक दिन सच हो जाएगा।

हमें समस्याओं का नहीं, बल्कि अपनी सोच का समाधान करना चाहिए। फिर समस्याएं अपने आप ठीक हो जाएंगी। हमें सबसे अद्भुत उपहार मिला है, हमारा मन। हम सोच सकते हैं और विचारों से अपनी दुनिया को आकार दे सकते हैं। शक्ति का केंद्र हमेशा वर्तमान क्षण में होता है। अतीत से सीखें और वर्तमान में जिएं। हम विश्वासों से अपनी वास्तविकता का निर्माण कर सकते हैं। आनंद, प्रेम और लोगों की भलाई करना चुनें।

खुद पर विश्वास रखें

सूत्र

जीवन में सब कुछ हमारे या किसी दूसरे के अनुसार नहीं चलता है। लेकिन जीवन में हम क्या सोचते हैं और किस पर सबसे ज्यादा विश्वास रखते हैं, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो हम सोचते हैं, एक समय बाद वही बन जाते हैं। आपको किसी मंजिल पर पहुंचना हो, तो खुद पर विश्वास रखें और हमेशा अच्छा सोचें।

दूसरा पहलू

मानव सभ्यता की शुरुआत से लेकर एक सदी पहले तक पृथ्वी की सतह का तापमान संतुलित था, अब असंतुलित क्यों हो गया है?

पृथ्वी का ऊर्जा बजट बैंक खाते की तरह है

जलवायु परिवर्तन को मापने का एक तरीका है लंबी अवधि में अलग-अलग जगहों पर तापमान को रिकॉर्ड करना। यह अच्छी तरह से काम करता है, लेकिन प्राकृतिक भिन्नता की वजह से लंबी अवधि के रुझान को देखना मुश्किल हो सकता है। लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी गर्मी आ रही है व कितनी बाहर जा रही है, इसका पता लगाने से लंबी अवधि के रुझान को स्पष्ट समझा जा सकता है।

बेनोइट मेसिग्नैक

2000 के दशक के मध्य में, ऊर्जा असंतुलन औसतन 0.6 वाट प्रति वर्ग मीटर था। अब यह औसतन 1.3 वाट प्रति वर्ग मीटर हो गया है।

यह पृथ्वी का ऊर्जा बजट है, जो अब असंतुलित हो चुका है। हाल के शोध बताते हैं कि पिछले 20 सालों में पृथ्वी का तापमान दोगुने से भी ज्यादा हो गया है। यह असंतुलन जलवायु मॉडलों द्वारा सुझाए गए स्तर से कहीं अधिक है। 2000 के दशक के मध्य में, ऊर्जा असंतुलन औसतन 0.6 वाट प्रति वर्ग मीटर था। हाल के वर्षों में, यह औसतन 1.3 वाट प्रति वर्ग मीटर हो गया है। यानी ग्रह की सतह के पास ऊर्जा संचय की दर दोगुनी हो गई है। ये नतीजे बताते हैं कि आने वाले वर्षों में जलवायु परिवर्तन और तेज हो सकता है। पृथ्वी का ऊर्जा बजट कुछ हद तक बैंक खाते की तरह काम करता है, जहां पैसा आता और जाता है। अगर आप अपने खर्च कम करते हैं, तो आपके खाते में नकदी जमा हो जाएगी। यहां, ऊर्जा ही मुद्रा है। पृथ्वी पर जीवन सूर्य से आने और जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन पर निर्भर करता है। यह संतुलन एक तरफ झुक रहा है। वायुमंडल में 20 खरब टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसें जमा हो चुकी हैं, जो गर्मी को बाहर जाने से रोक रही हैं। इस तापमान का कुछ हिस्सा जमीन को गर्म कर रहा है, तो कुछ ग्लेशियर को पिघला रहा है।

वायुमंडल में 20 खरब टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसें जमा हो चुकी हैं, जो गर्मी को बाहर जाने से रोक रही हैं। इस तापमान का कुछ हिस्सा ग्लेशियर को पिघला रहा है।

पृथ्वी प्राकृतिक रूप से कई तरीकों से गर्मी छोड़ती है। मानव सभ्यता की शुरुआत से लेकर एक सदी पहले तक पृथ्वी की सतह का औसत तापमान लगभग 14 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन बढ़ते ऊर्जा असंतुलन के कारण औसत तापमान 1.3-1.5 डिग्री तक बढ़ गया है। ऊर्जा असंतुलन तेजी से बढ़ रहा है। नए शोध बताते हैं कि बादलों में बदलाव इसका एक बड़ा कारण है। अत्यधिक परावर्तक सफेद बादलों से ढका क्षेत्र सिकुड़ गया है, जबकि अव्यवस्थित, कम परावर्तक बादलों का क्षेत्र बढ़ गया है। अगर उत्सर्जन को जल्दी कम नहीं किया गया, तो अगले कुछ दशकों में और गंभीर स्थिति होगी। हमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग बंद करना होगा। यदि हमें अप्रत्याशित परिवर्तनों को पहचानना है, तो लंबे समय तक सटीक रिकॉर्ड रखना जरूरी है। सैटेलाइट्स हमारे अग्रिम चेतावनी सिस्टम हैं, जो हमें गर्मी भंडारण में बदलाव के बारे में लगभग एक दशक पहले सूचना देते हैं।

-साथ में स्टीवन शेरवुड व थोरस्टन मॉरिट्सन (द कन्वर्सेशन से)

आंकड़े

भारत की ऊर्जा

नवीकरणीय ऊर्जा और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स के प्रति उपभोक्ताओं की रुचि सबसे अधिक भारत में है, जो जलवायु परिवर्तन के लिए बेहतर है।

भारत	39%
चीन	33%
मेक्सिको	32%
ब्राजील	29%
अमेरिका	20%

आंकड़े प्रतिशत में हैं। | स्रोत : statista

सामतसिंह शिकार खेलने गए, तो जल पी रहे एक मृग को उन्होंने बाण से मार डाला। बाद में पश्चाताप होने पर उन्होंने दीक्षा ले ली।

भक्ति में जीवन समर्पित

अंतर्यात्रा
संकलित

सालावाड़ प्रांत में योगिराज श्री षट्प्रज्ञ का जन्म हुआ था। उनके पिता श्री योगिराज सिंह झिंझुवाड़ा के महाराज थे। श्रीषट्प्रज्ञ जी के बचपन का नाम सामतसिंह था। एक दिन सामतसिंह झिंझुवाड़ा नगर के निकट सरस्वती झील के तट पर शिकार खेलने गए। वहीं पास में योगींद्र श्रीयादव स्वामी जी का आश्रम था। आश्रम के समीप जल पी रहे एक मृग को सामतसिंह ने अपने बाण से मार डाला।

स्वामी मृग को मृत देखकर उसके पास गए और भगवान का स्मरण करते हुए मंत्र पढ़ा। भगवान की कृपा से मृग जीवित हो गया। सामतसिंह को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। वह श्रीस्वामी जी के चरणों में गिर पड़े और प्रार्थना करते हुए बोले, 'हे भगवन! मैंने कितना बड़ा अपराध किया है! कृपया मुझे दीक्षा प्रदान कर अपनी शरण में स्वीकार करें।' श्रीस्वामी जी बोले, 'राजकुमार! सत्पुरुषों की मर्यादा का रक्षण तो क्षत्रिय ही करते हैं, और राक्षसों का नाश भी। किंतु तुमने भगवान नलेश्वर के आश्रम के निकट मृग का वध करके महान पाप किया है। तथापि, तुम्हारे पश्चाताप को देखकर मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। सामतसिंह बोले, 'गुरुदेव! आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं अब भगवान की भक्ति में जीवन समर्पित करना चाहता हूं।' राजकुमार की ऐसी प्रबल उत्कंठा देखकर श्री स्वामी जी ने उन्हें दीक्षा प्रदान की और उनका नाम श्री षट्प्रज्ञ रखा। इसके बाद श्रीषट्प्रज्ञ आश्रम में रहकर भगवान की भक्ति में लीन हो गए।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 15 सितंबर, 1955

विश्व शांति के लिए भारत व ब्रिटेन का सहयोग जरूरी

विश्वशांति के लिये भारत व ब्रिटेन का सहयोग जरूरी
ब्रिटेन के हाईकमिश्नर श्री मैकडोनेल्ड का बयान
पचास डूबे

ब्रिटेन के नए हाई कमिश्नर मालकन मैकडोनाल्ड ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विश्व शांति के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि भारत व ब्रिटेन के बीच सहयोग बना रहे।

बाढ़ के बाद पंजाब की दोहरी चुनौती

पंजाब में बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण का एजेंडा दो भागों में विभाजित होना चाहिए-नागरिक पुनर्वास और सुरक्षा पुनर्वास।

चंद्रशेखर बेंजवाल

मुद्दा

पंजाब में बाढ़ से फौरी राहत का मोर्चा तो पंजाबियों ने अपने जज्बे, हिम्मत और हौसले से फतह कर लिया। इसमें हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसान बिरादरी की मदद और सरकारी एजेंसियों के सहयोग का भी बड़ा योगदान रहा। अब जब बाढ़ का पानी उतरने लगेगा, तो पुनर्निर्माण का कार्य तेजी पकड़ेगा। 1988 के बाद आई इस भयानक बाढ़ में सूबे के सभी 23 जिले बाढ़ग्रस्त हो गए और 55 लोगों की मौत हो गई। साढ़े तीन लाख से अधिक लोग इससे प्रभावित हुए। 4.32 लाख एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि में खड़ी फसलें नष्ट हो गईं।

आगे का काम बहुत बड़ा है। बाढ़ के पानी में डूबी लाखों एकड़ जमीन में पानी के साथ आए रेत-पत्थर को निकालकर उसे फिर से खेती योग्य बनाना है। सैकड़ों निजी घर, सरकारी इमारतें ढह गईं, ग्रामीण सड़कें टूट गई हैं, इन सबका पुनर्निर्माण होना है। रावी, ब्यास व सतलुज नदियों के ध्वस्त हो चुके तटबंधों को फिर से खड़ा करना होगा। इसके अलावा, जो सबसे बड़ी चुनौती है, वह

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है।

पंजाब के पश्चिम में भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग 553 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जिसमें से थोड़ा-सा हिस्सा नदियों से बनाई गई सीमा का है और शेष 462 किलोमीटर जमीनी सरहद है, जिसे रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है। पंजाब में आतंकवाद के चरम दौर में पाकिस्तान से घुसपैठ और हथियारों की आवाजाही रोकने के लिए 1988 से 1993 के बीच इस पूरी सीमा पर आठ से 12 फीट ऊंची कंटीली तार की फेंसिंग खड़ी की गई। साथ ही इनका विद्युतीकरण किया गया। रात में घुसपैठियों पर निगाह रखने के लिए फ्लडलाइट्स लगाई गई। निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए इसमें मोशन सेंसर, थर्मल इमेजिंग डिवाइस, नाइट विजन कैमरे एवं अलार्म भी लगाए गए। नदी वाले क्षेत्रों में लेजर बाड़ लगाई गई है, जो इन्फ्रारेड और लेजर बीम से घुसपैठ का पता लगाती है और सैटेलाइट-आधारित सिग्नल सिस्टम से जुड़ी होती है। इस सरहद पर सीमा सुरक्षा बल की सख्त निगरानी और गश्त जारी रहती है। इसी प्रकार सीमा के उस पार पाक रेंजर्स भी चौकस रहते हैं। बाढ़ ने जन-धन की व्यापक हानि तो की ही, सीमा पर की गई सुरक्षा व्यवस्था को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। कंटीली बाड़ क्षतिग्रस्त हो गई, सीमा सुरक्षा बल के कई पोस्ट जलमग्न हो गए। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 30 किलोमीटर बाड़ क्षतिग्रस्त हुई है। यह आंकड़ा अधिक भी हो सकता है। अभी सेना व सुरक्षा बलों का भी ध्यान लोगों की मदद करने पर है। स्वाभाविक है कि जब बाड़ क्षतिग्रस्त हुई है, तो इससे जुड़े निगरानी तंत्र के दूसरे उपकरणों को भी उसी पैमाने पर नुकसान पहुंचा होगा।

यह नुकसान ऐसे समय हुआ है, जब पाकिस्तान के साथ हालिया युद्ध के बाद घुसपैठ की आशंकाएं अधिक प्रबल हैं। हालांकि, बाढ़ ने पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन उसकी फितरत अपने घर को ठीक करने से ज्यादा, भारत को नुकसान पहुंचाने की रही है। पाकिस्तान की रणनीति हमेशा से दो स्तरों पर चलती रही है। एक ओर औपचारिक युद्ध, तो दूसरी ओर 'प्रॉक्सी वॉर'। सीमा पार से आतंकियों को भेजना, हथियारों की तस्करी करना, नशे की खेप पहुंचा कर पंजाब के युवाओं को अस्थिरता के रास्ते पर धकेलना इस रणनीति के अहम हिस्से हैं। युद्ध में हार या दबाव झेलने के बाद पाकिस्तान अक्सर ऐसे रास्ते अपनाता है, ताकि भारत के भीतर असंतोष, हिंसा और अराजकता का वातावरण बने।

ऐसे में पंजाब का पुनर्निर्माण केवल नागरिक जीवन तक सीमित नहीं है। खेतों को फिर आबाद करना, टूटे हुए घरों, दफ्तरों और स्कूलों को बनाना, सड़क नेटवर्क को दुरुस्त करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि सीमा पर सुरक्षा व्यवस्थाओं की बहाली और सुदृढ़ीकरण फौरन किया जाना। इसलिए पुनर्निर्माण का एजेंडा दो भागों में विभाजित होना चाहिए-नागरिक पुनर्वास और सुरक्षा पुनर्वास। इन दोनों के लिए केंद्र व राज्य के बीच बेहतर तालमेल होना चाहिए। यह दोहरा दायित्व न केवल पंजाब की बहादुरी का इम्तिहान है, बल्कि पूरे देश की एकजुटता और दृढ़ संकल्प की भी परीक्षा है।

पंजाब की चुनौती केवल एक सूबे की नहीं है, यह पूरे भारत की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। अगर पंजाब की सीमा कमजोर पड़ती है, तो उसकी गूंज शेष देश तक सुनाई देती है। इसलिए जरूरी है कि केंद्र और राज्य सरकारें पुनर्निर्माण में धन और संसाधनों की कोई कमी न करें। पंजाब के पुनर्निर्माण का अर्थ है खेतों में हरियाली लौटाना, गांवों में मुस्कान लौटाना और साथ ही सीमा पर सुरक्षा के तंत्र को फिर से अभेद्य बनाना। लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है और न ही यह परस्पर राजनीतिक दोषारोपण का समय है।

पंजाब की मिट्टी ने बार-बार आपदाओं का सामना किया है। यही आत्मबल अब फिर से जरूरी है। उम्मीद है, पंजाब की धरती इस चुनौती को भी पार कर फिर से समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक बनेगी।

हिन्दुस्तान
1936 सत्य • सार्थक • सदैव

मौसम से सावधान

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और देश के अनेक इलाकों में जिस तेजी से मौसमी रोगों और भांति-भांति के वायरल बुखार का प्रकोप बढ़ रहा है, उसे देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता की जरूरत है। ज्यादातर मामले इन्फ्लूएंजा-ए (एच3एन2) संक्रमण के सामने आ रहे हैं, जिसमें आम मौसमी फ्लू की तरह तेज बुखार, गले में संक्रमण, सिर और बदन में दर्द व कमजोरी जैसे लक्षण दिखते हैं। कुछ मामलों में यह संक्रमण गंभीर रूप ले लेता है और मरीजों को अस्पताल में भर्ती तक करवाना पड़ रहा है। बेशक, दो से पांच प्रतिशत रोगियों को ही सघन निगरानी की जरूरत पड़ रही है, मगर यह भी छोटी संख्या नहीं है। दिल्ली से सटे नोएडा के अस्पतालों की आपातकालीन सेवाओं में लग रही मरीजों की कतारें और बेड कम पड़ने की खबरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। चिंता की बात यह भी है कि कुछ रोगियों ने पैरासिटामोल जैसी बुखार की आम दवा के बेअसर होने की शिकायत की है। यह एच3एन2 संक्रमण है, जो ठीक होने में एक सप्ताह से भी ज्यादा समय ले रहा है। चिकित्सकों ने आगाह किया है कि इस समय अनेक लोगों में फैल रहा फ्लू वास्तव में सामान्य नहीं है। बड़ी संख्या में लोग इसी शिकायत के साथ अस्पताल आ रहे हैं कि वे ठीक नहीं हो पा रहे हैं।

इसके क्या वैज्ञानिक कारण हैं, इसकी पड़ताल जारी है। आम तौर पर मानसून का समय जब कुछ लंबा खिंच जाता है या बारिश ज्यादा समय तक होती रहती है, तब वायरल बुखार का रूप भी बदल जाता है। व्यक्ति से व्यक्ति संक्रमण तेजी से होता है। इस बार जब देश के अनेक इलाकों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है, तो ऐसे तमाम इलाकों में स्वास्थ्य एजेंसियों को ज्यादा सतर्कता का परिचय देना चाहिए। कठिनाई की बात यह है कि मौसमी बीमारियों को वायरल, डेंगू और मलेरिया का साथ मिल रहा है। टाइफाइड, यानी मियादी बुखार के मामले भी बढ़े हैं। बीते गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अगुवाई में हुई बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने तमाम राज्यों की सरकारों को निर्देश जारी किए हैं कि वे आगामी महीनों में सतर्कता बरतें और अपने-अपने सूबे में डेंगू व मलेरिया पर प्रभावी नियंत्रण के लिए निवारक उपाय अपनाएं। ताजा दिशा-निर्देश में जन-जागरूकता बढ़ाने का आग्रह भी शामिल है, ताकि लोग अपने तईं मच्छरों को पनपने न दें। इसीलिए व्यक्तिगत साफ-सफाई के साथ आस-पास की स्वच्छता बढ़ाने की जरूरत बढ़ गई है। चिकित्सा एजेंसियों को देखना चाहिए कि किसी भी इलाके में जरूरी दवाओं का अभाव न होने पाए। विशेष रूप से बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा सजग होने की जरूरत है। सावधानी के अभाव में स्कूलों से भी वायरल संक्रमण को बढ़ावा मिल रहा है।

आजकल एच3एन2 नामक फ्लू या वायरल संक्रमण फैल रहा है, जो ठीक होने में एक सप्ताह से भी ज्यादा समय ले रहा है। यह मौसमी रोगों से भी बचने का समय है।

हमें डेंगू के प्रति भी सजग होना चाहिए। इस संदर्भ में अमेरिका के स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड विश्वविद्यालयों के शोधार्थियों का यह दावा शोचनीय है कि एशिया व अमेरिका के 21 देशों में 1995 से 2014 के बीच सालाना औसतन 46 लाख डेंगू के नए मामले जलवायु परिवर्तन के चलते पैदा हुए हैं। इस अवधि में डेंगू में 18 प्रतिशत की बढ़त हुई है और आगामी 25 वर्षों में डेंगू मरीजों की संख्या में तीन गुना से ज्यादा इजाफे की आशंका है। मतलब, डेंगू और मच्छर जनित बीमारियों के खिलाफ भी युद्ध स्तर पर काम करना पड़ेगा। ध्यान रहे, विश्व स्वास्थ्य संगठन हर साल 'फ्लू वैक्सीन' लेने की सलाह देता है। जब हर साल दुनिया के 6.5 लाख लोगों की सांसें इन्फ्लूएंजा की वजह से थम जाती है, तब लोगों का सतर्क होना समय की सबसे बड़ी मांग है।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 15 सितंबर, 1950

उत्थापितों की क्षतिपूर्ति

देश-विभाजन के साथ हुए उपद्रवों और नरसंहार के फलस्वरूप पाकिस्तान (पश्चिम) से उत्थापित होकर आये व्यक्तियों के कष्टों को कौन नहीं जानता? प्राण संकट से निकलने के बाद कहीं बसने का सवाल आता है और साथ ही भागते हुए छोड़ी हुई अपनी सम्पत्ति का भी। जब तक कहीं बस न जायें और जीविका का समुचित प्रबन्ध न हो जाये, तब तक ही छोड़ी सम्पत्ति की टीस मन में नहीं रहती, जम जाने और निबाह की व्यवस्था हो जाने पर भी उसे हड़प किये रहने वालों के प्रति दुर्भावना दूर करना सम्भव नहीं होता।

अपनी सरकार के प्रति भी, चाहे वह शरण देने वाली ही क्यों न हो, इस बात की झुंझलाहट रहती ही है कि वह क्यों नहीं उत्थापित करने वाले से वहां रही सम्पत्ति की वसूली कराती या फिर स्वयं क्षतिपूर्ति क्यों नहीं करती। इस बारे में कुछ होना न केवल शरणार्थियों के हित में, बल्कि सरकार की दृष्टि से भी आवश्यक है। अतः भारत सरकार की ओर से अधिकृत रूप में दिये गये इस आश्वासन का स्वागत किया जायेगा कि पश्चिमी पाकिस्तान से आये उत्थापितों की क्षति की यथासम्भव पूर्ति की जायेगी। क्षतिपूर्ति किस प्रकार की जायेगी, यह, यह स्पष्ट नहीं किया गया है; परन्तु विज्ञप्ति की भाषा से कुछ ऐसा भासित होता है कि पाकिस्तान सरकार से यदि रकम न मिली, तो यहां से पाकिस्तान जाने वालों की छोड़ी हुई सम्पत्ति को वहां से आये हुओं की क्षतिपूर्ति का साधन बनाया जायेगा। विज्ञप्ति के शब्द ये हैं: भारत-सरकार तमाम सम्बद्ध व्यक्तियों को यह आश्वासन देना चाहती है कि उत्थापित व्यक्तियों की यथासम्भव क्षतिपूर्ति की जायेगी, किंतु यह इस बात पर निर्भर है कि सरकार को बांटने के लिए कितनी सम्पत्ति मिलती है।' इसमें 'यथासम्भव' और 'इस बात पर निर्भर है कि सरकार को बांटने के लिए कितनी सम्पत्ति मिलती है' शब्द इसके सिवा किसी अन्य कल्पना को जन्म नहीं देते।

भारतीय कोष से क्षतिपूर्ति की मांग भी बीच-बीच में सामने आती रही है, यह अप्रकट नहीं है; परन्तु सरकार ने कभी उसे स्वीकार किया हो, ऐसा याद नहीं पड़ता। इसके अलावा यह भी सोचने की बात है कि उत्थापितों के लिए अभी जितना व्यय सरकार कर चुकी है, उसी का योग जब 75 करोड़ रुपये के लगभग हो जाता है, तो क्षतिपूर्ति का भार भी वह कैसे बर्दाश्त कर सकती है?

अपनी ताकत के भरोसे बढ़े भारत

देश के आर्थिक हालात के बिगड़ने की आशंका कम और सुधरने के आसार ज्यादा दिख रहे हैं। रेटिंग एजेंसी 'फिच' का भारत के प्रति बदला हुआ रवैया इसका पहला संकेत है।

यहां स्कैन करें

आलोक जोशी | वरिष्ठ पत्रकार

वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व जैसी बातें शायद अब पुरानी पड़ गई हैं। पिछले करीब पचास वर्षों से 'कनेक्टेड वर्ल्ड, ओपेन इकोनॉमी, फ्री मार्केट' और 'ग्लोबल विलेज' जैसे जो नारे उछल रहे थे, लगता है कि वे यकायक धराशायी हो गए हैं। खासकर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से जिस अंदाज में अमेरिका को फिर से 'महान' बनाने का नारा उछाला गया, उसने अंतरराष्ट्रीय व्यापार, कारोबार, राजनीति व कूटनीति की पूरी इबारत ही बदलकर रख दी है।

भारत और अमेरिका के रिश्ते तो कुछ यूं हो गए हैं कि जैसे- *खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं।* व्यापार-समझौते पर लंबी बातचीत के बाद बात टूट गई और राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर न सिर्फ 50 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाने का एलान कर दिया, बल्कि उनकी तरफ से तरह-तरह के आरोप, कटाक्ष और धमकियों का सिलसिला भी रुक-रुक कर जारी रहा। यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूरोपीय संघ को भी कहा है कि रूस से तेल खरीदने का बदला लेने के लिए वह भारत पर सौ फीसदी शुल्क लगाए।

हालांकि, इस बात की संभावना बहुत कम है, क्योंकि यूरोप ऐसे टैरिफ लगाता नहीं है। मगर यूरोपीय संघ रूस पर दबाव बनाने या उसे आर्थिक रूप से पंगु बनाने के लिए अमेरिका के साथ खड़ा हो सकता है और इसके लिए वह आर्थिक प्रतिबंध लगाने का फैसला कर सकता है, न सिर्फ रूस पर, बल्कि उन देशों पर भी, जो रूस से व्यापार कर रहे हैं। इरादा यही है कि रूस को पैसा मिलना बंद हो जाए। इसके लिए वह इन देशों से बैंकिंग लेन-देन पर रोक लगा सकता है। उनकी संपत्ति फ्रीज कर सकता है। और यह भी कर सकता है कि रूस से तेल लेकर जाने वाले टैंकरों को कोई भी यूरोपीय कंपनी री-इंश्योरेंस न दे।

हालांकि, अभी तक यूरोपीय संघ के सदस्य 27 देश इस मामले पर बंटे हुए हैं, मगर अमेरिका का दबाव बना हुआ है और कई यूरोपीय देश भी मानते हैं कि अगर ये दोनों मिलकर प्रतिबंध लगाएंगे, तो रूस को घुटनों पर आते देर नहीं लगेगी। रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुए साढ़े तीन साल बीत चुके हैं। ऐसे में, इसे रोकना सभी को जरूरी लग रहा है और यही वजह है कि यूरोपीय संघ इस मसले पर कड़े फैसलों की तैयारी कर रहा है।

हमारे लिए यह चिंता की बात इसलिए है, क्योंकि भारत रूस के कच्चे तेल के सबसे बड़े और अहम खरीदारों में है। अगर यूरोपीय संघ की तरफ से किसी भी तरह के प्रतिबंध लगे, तो इसके दो नुकसान हो सकते हैं। एक, अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश की साख में कमी और दूसरा, भारतीय कारोबारियों के लिए यूरोप में कई तरह की नई परेशानियां। मगर दूसरी तरफ यूरोपीय संघ की नजर भी भारत के विशाल बाजार पर है, साथ ही वह बदलती दुनिया में भारत की बढ़ती हैसियत को भी नजरंदाज नहीं कर सकता है। इसीलिए, वह बात को इस हद तक नहीं खींचना चाहता कि भारत के साथ व्यापार मुश्किल में पड़ जाए। यूरोपीय संघ और भारत के बीच व्यापार-समझौते पर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है, और दोनों में से कोई भी नहीं चाहेगा कि अब वह खटाई में पड़ जाए।

उधर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खुद भी दुविधा में दिख रहे हैं। एक तरफ तो वह यूरोपीय संघ पर दबाव बना रहे हैं कि भारत और चीन पर सख्त कार्रवाई हो, मगर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की भी बाट जोह रहे हैं। काफी खींचतान के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार-वार्ता फिर से शुरू हो चुकी है। हो सकता है, जल्द ही अमेरिका और भारत के बीच व्यापार-समझौते की खबर भी आने लगे।

इस चिंता के बीच अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी 'फिच' ने भारत को एक खुशखबरी भी सुना दी है। उसने कहा है कि भारत में मजबूत घरेलू मांग को देखते हुए उसे चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी विकास दर 6.9 प्रतिशत होने की उम्मीद है। इससे पहले उसे यह दर 6.5 फीसदी पर रहने की संभावना दिख रही थी। फिच का कहना है कि अमेरिका के टैरिफ का असर कुछ समय तक तो दिख सकता है, लेकिन दोनों देशों के बीच व्यापार-समझौता हो ही जाएगा, जिससे यह परेशानी भी खत्म हो जाएगी।

फिच की इस खुशखबरी से पहले ही जीएसटी दरों में कटौती की खबर आ चुकी थी और उसका असर होना भी स्वाभाविक है। उधर महंगाई दर भी आठ साल में सबसे नीचे पहुंच चुकी है और नई जीएसटी व्यवस्था लागू होने पर जो चीजें सस्ती होंगी, उनसे अर्थव्यवस्था को जबर्दस्त सहारा मिलने की उम्मीद है। अभी तो अनुमान ही लगाए जा रहे हैं, लेकिन कार के शोरूम में ग्राहकों की गिनती बढ़ने लगी है।

जाहिर है, उपभोक्ता की जेब में रकम बचेगी, तो वे कुछ और चीजें खरीदने की भी सोच सकते हैं या इन पैसे का कोई और बेहतर इस्तेमाल वे कर सकते हैं। दोनों ही सूरत में स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए सुखद रहेगी। कुलजमा बात यही है कि अब यहां से हालात बिगड़ने की आशंका बहुत कम और सुधरने के आसार ज्यादा दिख रहे हैं। फिच का बदला रवैया इसका पहला संकेत है। उम्मीद करनी चाहिए कि इसके और भी संकेत जल्दी ही सामने आने लगेंगे।

हालांकि, यहां भारत के सामने एक बड़ी सच्चाई भी उजागर हुई है कि हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, विकट समय पर दुनिया का कोई देश आपको अचानक मंझधार में छोड़ सकता है। वहां से आगे निकलने में आपकी अपनी ताकत और हुनर ही काम आएंगे। भारत ने इस संकट में दिखाया भी है कि रूस और चीन से हाथ मिलाने की तस्वीर भर ने कैसे अमेरिका पर असर डाला। इससे पहले भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत अमेरिका जैसे देश को सामने से चुनौती देकर दिखा चुका है। हो सकता है कि टैरिफ का विवाद बहुत ही आसानी से सुलझ जाए। अमेरिका, यूरोप और दूसरे पश्चिमी देशों के साथ समझौते भी हो जाएं।

मगर यह एक आत्मचिंतन का क्षण भी है। आजादी के वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस 'ट्रिस्ट विद डेस्टिनी' का आह्वान किया था, भारत भी इस वक्त वैसा ही एक बहुत बड़ा दांव लगाने के लिए खुद को तैयार करे। वह दांव, जो साल 2047 के सपनों को जल्दी से जल्दी साकार करने में एक निर्णायक भूमिका निभाए। पिछली घटनाएं गवाह हैं कि इसके लिए जमीन तैयार है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

माओ से जिनपिंग तक काले बालों की असली कहानी

यहां स्कैन करें

विवेक शुक्ला | वरिष्ठ पत्रकार

चीन की राजधानी बीजिंग में इस महीने की शुरुआत में आयोजित विक्ट्री डे परेड ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इसमें चीनी सेना ने अपनी शक्ति, अनुशासन और एकता का शानदार प्रदर्शन किया। परेड में हजारों सैनिकों, नेताओं ने हिस्सा लिया, पर आपने गौर किया कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग से लेकर किसी भी अन्य नेता या सैनिक के चेहरे पर दाढ़ी या मूंछ नहीं थी। टीवी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कुछ वयोवृद्ध नेताओं से भी मिलते हुए दिखाया। उन सबकी उम्र 90 या इससे अधिक थी। उनके सबके सिर के बाल काले थे। इसका मुख्य कारण है कि चीन के नेता और अधिकारी अपने बालों को काला डाई करते हैं। यह एक लंबी परंपरा है, जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) के शीर्ष नेतृत्व में प्रचलित है। बालों को रंगने की यह रवायत माओत्से-तुंग के जमाने से चली आ रही है। लेकिन 1990 के दशक से यह चलन और गाढ़ा हो गया है।

चीनी नेताओं के काले बालों का राज हमेशा से लोगों के लिए कौतूहल का विषय रहा है। दरअसल, चीनी संस्कृति में काले बाल जवानी, ताकत और ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। सफेद या भूरे बालों को कमजोरी का संकेत माना जाता है, और कोई भी नेता नहीं चाहता कि जनता उसे बूढ़ा या कमजोर समझे। इसलिए बालों को काला रखना एक तरह से अपनी मजबूत और युवा छवि को बनाए रखने का तरीका है।

चीन में गिरफ्तार अधिकारियों को बाल काले करने की अनुमति नहीं दी जाती। इसी तरह, चीनी सेना में दाढ़ी रखने पर सख्त प्रतिबंध है।

चीनी नेताओं के काले बाल एक सोची-समझी रणनीति है। यह जनता की नजरों में अपनी मजबूत छवि बनाने का खेल है। शी जिनपिंग की उम्र 72 साल है। गौर से देखने पर उनके बालों में कुछ सफेद लकीरें देखी जा सकती हैं। विक्ट्री डे परेड से पहले तियानजिन शहर में एससीओ की बैठक में जिनपिंग की भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक भी हुई थी। उसमें दोनों नेताओं के साथ उनके सहयोगी भी थे। जिनपिंग को छोड़कर बाकी सब नेताओं के बाल काले नजर आ रहे थे। हालांकि, अधिकतर 60 की उम्र पार कर चुके हैं। माओ से लेकर देंग शियाओपिंग तक, सभी ने अपने बाल काले रखे। हालांकि, एक तथ्य यह भी है कि उम्रदराज होने के बाद भी ज्यादातर चीनियों के बाल प्राकृतिक रूप से काले रहते हैं।

बहरहाल, चीन में गिरफ्तार या दंडित अधिकारियों को बाल काले करने की अनुमति नहीं दी जाती। इसी तरह, चीनी सेना में दाढ़ी रखने पर भी सख्त प्रतिबंध है, जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के 'ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स' का हिस्सा है। पीएलए के नियमों के अनुसार, सैनिकों को हमेशा साफ-सुथरा और एक समान दिखना चाहिए। इस बारे में किसी किस्म का तर्क नामंजूर होता है। दुनिया की कई सेनाओं में ऐसे नियम एक स्तर तक हैं, लेकिन चीनी सेना में यह बेहद कठोर है। उदाहरण के लिए, पीएलए के नियमों में स्पष्ट है कि चेहरे पर बाल केवल मूंछ तक सीमित रह सकते हैं और वह भी नियंत्रित लंबाई में। दाढ़ी को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। परेड में कोई सैनिक या नेता मूंछों वाला नहीं दिखाई दिया।

माओत्से तुंग के समय से ही सेना को एक जैसे दिखने का आदेश है। चीन में दाढ़ी रखने को पश्चिमी या धार्मिक अतिवाद से जोड़ा जाता है, खासकर उइगर मुसलमानों वाले शिनजियांग सूबे में, जहां दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध है। विक्ट्री डे परेड में सैनिकों की दाढ़ी न होना भी प्रतीकात्मक है। जेएनयू में लंबे समय तक चीनी विभाग के अध्यक्ष रहे प्रो. तान चुंग ने एक बार कहा था, चीन में दाढ़ी को कभी-कभी विद्रोह या अल्पसंख्यक पहचान से जोड़ा जाता है। इसलिए, राष्ट्रीय परेड में इसे पूरी से तरह हटा दिया जाता है, ताकि चीनी एकता का संदेश मजबूत हो।

कुल मिलाकर, चीन में दाढ़ी और मूंछें न होना सैन्य अनुशासन, सुरक्षा और सांस्कृतिक एकता से जुड़ा है, जबकि बाल काले होना राजनीतिक प्रतीकवाद और युवा छवि का मामला है। विक्ट्री डे परेड जैसे आयोजन इन मूल्यों को मजबूत बनाते हैं। हालांकि, आधुनिक चीन में बदलाव आ रहे हैं, जैसे शी के कुछ सफेद बाल दिखते हैं, लेकिन परंपरा बनी हुई है। समझना होगा कि सतह पर दिखने वाली सादगी के पीछे गहरे सांस्कृतिक और राजनीतिक कारण होते हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

मुनि अशांतिनाथ

आदमी का मन ऐसा है कि एक अति से दूसरी पर डोल सकता है, लेकिन मध्य में ठहर नहीं सकता। चूंकि मन की ऊर्जा निरंतर बदलती रहती है, इसलिए मन को चंचल कहा जाता है। अक्सर ऐसे किस्से सुनाई देते हैं, जहां हिंसक आदमी पछतावे में आकर अचानक अहिंसक बन जाता है। क्रोधी आदमी सब कुछ छोड़कर शांत बन जाता है। यह बदलाव अगर गहरी समझ से हुआ है, तब तो टिकाऊ हो सकता है, लेकिन ऊपरी हो, तो उसे संयम साधना मुश्किल होता है। ऐसे लोग जज्बाती होते हैं, इसलिए जल्दबाजी में एक अति से दूसरी अति पर जाने का फैसला लेते हैं, फिर जरा सी चुनौती मिलते ही इनकी कलई आसानी से खुल जाती है।

ओशो एक कहानी कहते हैं मुनि शांतिनाथ की। एक गांव में एक बहुत क्रोधी आदमी था। धीरे-धीरे उसे अपने क्रोध का बोझ भारी लगने लगा; हर किसी के साथ झगड़ा, मारपीट! उसने तैश में आकर दीक्षा ले ली और साधु शांतिनाथ बन गया। शांतिनाथ एक पहाड़ पर बैठकर ध्यान-साधना करने लगा। धीरे-धीरे उसकी ख्याति फैलने लगी। एक दिन उसका कोई पुराना मित्र दर्शन करने आया। शांतिनाथ ने उस मित्र को पहचान भी लिया, लेकिन अब एक महातपस्वी मुनि किसी साधारण आदमी को कैसे पहचाने? मित्र को लगा कि क्या यह सचमुच इतना बदल गया है या शांतिनाथ होने का नाटक चल रहा है? इतनी जल्दी इसका क्रोध कैसे चला गया? उस मित्र ने मुनि शांतिनाथ को आजमाने के ख्याल से पूछा- महाराज! बड़ी दूर से दर्शन को आया हूं, आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा, 'शांतिनाथ! आप अखबार नहीं पढ़ते? टेलीविजन नहीं देखते? पूरी दुनिया जानती है।'

मित्र ने कहा, 'महाराज, गांव का गंवार हूं, कुछ ज्यादा जानता-करता नहीं, पढ़ा-लिखा भी ज्यादा नहीं हूं।' थोड़ी देर ऐसी और बातें चलती रहीं, उस आदमी ने फिर पूछा कि महाराज, माफ करें, नाम भूल गया आपका! महाराज तो भन्ना गए। कहा, 'कह दिया एक दफे कि शांतिनाथ, समझ में नहीं आया? बहरे हो?'

वह आदमी बोला कि नहीं महाराज, मेरी बुद्धि जरा कमजोर है। मगर शांतिनाथ का असली रूप प्रगट होने लगा। मित्र को तो उसे उघाड़ना ही था, सो वह थोड़ी देर बैठा रहा और फिर उसने पूछा कि महाराज, आपका नाम भूल गया। फिर तो महाराज सब कुछ भूल गए और साथ में जो डंडा रखा था, वह उठा लिया। उसे उसके सिर पर मारने वाले थे; बोले, हजार दफे समझा दिया। तू ऐसे नहीं समझेगा! शांतिनाथ नाम है मेरा! उसने कहा, 'महाराज, अब समझ गया, अब कभी नहीं भूलेगा। इतना ही हम जानना चाहते थे कि आपमें कुछ फर्क आया है कि नहीं? कोई फर्क नहीं, आप बिल्कुल वही हैं, बस नाम गलत रख लिया! अशांतिनाथ रखें, तो सही होगा।'

अक्सर ऐसे किस्से सुनाई देते हैं, जब हिंसक आदमी पछतावे में आकर अचानक अहिंसक बन जाता है। यह बदलाव अगर गहरी समझ से हुआ हो, तभी टिकाऊ हो सकता है।

अमृत साधना

एंटोनियो गुटेरस | संयुक्त राष्ट्र महासचिव

सशस्त्र संघर्षों में बाल हिंसा अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ती जा रही है। हमें हर बच्चे की सुरक्षा और शांति से पढ़ने के मौलिक अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। किसी भी बच्चे की जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए।

अनुलोम-विलोम

शिक्षक परीक्षा

अयोग्य शिक्षकों को खुद हट जाना चाहिए

अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो सोशल मीडिया में बेहद वायरल हुआ था, जो छत्तीसगढ़ के किसी सरकारी स्कूल का था। इसमें शिक्षक गण 'इलेवन' और 'नाइन्टीन' अंग्रेजी में सही-सही नहीं लिख पा रहे थे, जबकि उन पर नौनिहालों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी है। यह किसी एक स्कूल या खास क्षेत्र की कहानी नहीं है। वक्त-वक्त पर ऐसी खबरें आती रहती हैं कि सरकारी स्कूलों के कुछ शिक्षक अपनी अयोग्यता बच्चों पर लाद रहे हैं। खुद सरकार का मानना है कि पहली से पांचवीं तक की कक्षा लेने वाले शिक्षकों में करीब 10 फीसदी ऐसे हैं, जो अयोग्य हैं। साफ है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे शिक्षकों को ही व्यवस्था से बाहर करने से जुड़ा है, बल्कि उन्हें खुद ही बाहर हो जाना चाहिए। उनके हाथों में बच्चों का भविष्य भला कैसे सुरक्षित रह सकता है?

यह फैसला शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। सर्वोच्च न्यायालय का साफ कहना है कि जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में पांच साल से कम का समय बचा है, उन्हें तो इस नियम से राहत दी जाएगी, लेकिन अगर वे बिना टीईटी पास किए अपनी सेवा जारी रखना चाहते हैं, तो उनको पदोन्नति से वंचित होना पड़ेगा। हां, जिनकी नौकरी पांच साल से ज्यादा बची है, उनको दो साल के अंदर यह परीक्षा पास करनी ही होगी, अन्यथा उनकी नौकरी चली जाएगी। यह सब करना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि आंकड़े यही बताते हैं कि कक्षा छह से आठ तक को पढ़ाने वाले 11 फीसदी, नौवीं और 10वीं की कक्षा लेने वाले 9.3 प्रतिशत और 11वीं व 12वीं पढ़ाने वाले 11 प्रतिशत शिक्षकों के पास जरूरी न्यूनतम योग्यता नहीं है। इस तरह देखा जाए, तो हर 10 शिक्षकों में से एक पढ़ाने के योग्य नहीं है। जब सरकारी स्कूलों की यह कहानी है, तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से भला किसे नाराजगी होगी! इससे तो भारत की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आ सकता है।

फिर भी यदि शिक्षकों को कोई दिक्कत हो रही है, तो उनको राहत देने के लिए सरकार अपने स्तर पर कुछ प्रयास कर सकती है। जैसे, टीईटी परीक्षा की तैयारी के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। शिक्षकों के लिए कुछ ऑनलाइन कोर्स और मॉक टेस्ट भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ऐसे कदमों से उनको टीईटी परीक्षा के पैटर्न को समझने में आसानी होगी और वे जान सकेंगे कि किस तरह से उन्हें तैयारी करनी है। मगर इसके साथ-साथ नए शिक्षकों की नियुक्ति का भी प्रयास होना चाहिए और ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए कि योग्य शिक्षक ही व्यवस्था का हिस्सा बनें।

सुमित कुमार, टिप्पणीकार

फैसले पर दोबारा गौर करने की जरूरत

हाल ही में कक्षा एक से आठ तक को पढ़ाने वाले शिक्षकों के सेवा में बने रहने और पदोन्नति के लिए टीईटी परीक्षा पास करने की अनिवार्यता का फैसला शीर्ष अदालत से हुआ है। शैक्षिक अर्हता के तहत नियुक्ति पाए शिक्षकों की लंबे सेवाकाल के बाद दक्षता की परीक्षा उचित नहीं जान पड़ती। सवाल यह भी है कि यदि दो बार के प्रयासों में भी कोई शिक्षक इस परीक्षा को पास नहीं कर सका, तो इससे उस पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा और समाज में उसकी छवि को नुकसान होगा। नौकरी जाने का डर किसी अनहोनी का कारण भी बन सकता है। इसलिए माननीय अदालत को अपने फैसले पर दोबारा गौर करना चाहिए।

सत्यपाल सिंह, टिप्पणीकार

अभी कुछ ही दिनों पहले राजस्थान से यह खबर आई थी कि जिला जज की पदोन्नति-परीक्षा में सम्मिलित सभी जज फेल हो गए, यानी किसी को पदोन्नति के लायक नहीं समझा गया। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे काबिल नहीं हैं? नहीं, मैं इसको नहीं मानता। जज काबिल हैं, तभी वे इस पद पर हैं। अब बात करते हैं शिक्षकों की। कुछ लोगों का कहना है कि शिक्षक हैं, तो परीक्षा से कैसा डर? बिल्कुल, हम शिक्षक किसी परीक्षा से नहीं डरते। एक साथी शिक्षक ने जब जूनियर टीईटी के पुराने पेपर मंगवाए, तो मैंने भी एक नजर उस पर दौड़ा ली। मैंने गणित के कुछ सवाल देखे, जो अवकलन और समाकलन, यानी कैलकुलस द्वारा हल होते। मुझे पढ़ाते हुए 10 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। आप बेसिक विभाग की गणित का कोई भी प्रश्न दें, मैं उसको हल कर सकता हूं, मगर क्या मैं कैलकुलस को सॉल्व कर सकता हूं? यह समझना होगा कि टीईटी एक पात्रता परीक्षा है। इसको पास करके समाज जान सकता है कि विद्यालय में पढ़ाने वाला शिक्षक बच्चों के लायक हैं या नहीं, लेकिन इस पात्रता परीक्षा की भी शर्तें हैं। यदि आप मुझसे वे प्रश्न पूछेंगे, जो मैं रोज पढ़ाता हूं, और अगर उसका जवाब न दे सकूं, तो बेशक मैं इस नौकरी के काबिल नहीं। मगर अदालती आदेश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यहां दो सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूं। पहला, बिना टीईटी वाले शिक्षक के पढ़ाए बच्चे अगर आज सरकारी नौकरी में हैं, तो क्या इसमें उस शिक्षक की मेहनत शामिल नहीं है और क्या वह काबिल नहीं था? दूसरा, जिन अध्यापकों की याचिका से यह फैसला आया है, उनको दोबारा टीईटी पास करने को बोला जाए, तो क्या सभी पास करके दिखा देंगे? इस मुद्दे पर दोबारा विचार करने की जरूरत है।

शाकुल गुप्ता, टिप्पणीकार

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दैनिक जागरण
तर्क मानव जीवन को प्रगति के शिखरों तक पहुंचाता है

देशव्यापी एसआइआर

यह अच्छा है कि चुनाव आयोग बिहार के बाद देश भर में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात एसआइआर के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त कर रहा है। चुनाव आयोग की ओर से मिले संकेतों के अनुसार वह अगले माह से मतदाता सूचियों के सत्यापन का देशव्यापी अभियान चला सकता है। जो भी हो, आवश्यकता इस बात की है कि यह अभियान प्रभावी ढंग से चलाया जाए, भले ही इसमें कुछ विलंब हो। बिहार के अनुभव ने इस आवश्यकता पर और अधिक बल दिया है कि पूरे देश में मतदाता सूचियों का सत्यापन होना चाहिए। सच तो यह है कि यह कार्य एक निश्चित अंतराल के बाद होते ही रहना चाहिए। यह ठीक नहीं कि बिहार में 2003 के बाद अब जाकर मतदाता सूची के सत्यापन करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकी। चुनाव आयोग को देशव्यापी एसआइआर करते समय इसके लिए भी तैयार रहना होगा कि उसे विपक्षी दलों और साथ ही स्वयं को लोकतंत्र का स्वयंभू पैरोकार बताने वाले लोगों के विरोध और दुष्प्रचार का सामना करना पड़ सकता है। इसका अंदेशा इसलिए है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से बिहार में मतदाता सूची के सत्यापन की प्रक्रिया को हरी झंडी दिखाए जाने के बावजूद विपक्षी दल अपने बेजा विरोध से बाज नहीं आ रहे हैं। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मतदाता सूची के सत्यापन की संभावित प्रक्रिया के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। इस राज्य में चुनाव आयोग को एसआइआर की प्रक्रिया आगे बढ़ाने में सत्तारूढ़ दल के असहयोग के साथ अन्य चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। एक बड़ी चुनौती उन दस्तावेजों के सत्यापन की हो सकती है, जिनके आधार पर कोई अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा तय किए गए दस्तावेजों में आधार को भी शामिल कर लिया है और यह किसी से छिपा नहीं कि बंगाल में सर्वाधिक नकली अथवा फर्जी दस्तावेजों के सहारे आधार से लैस लोगों की संख्या सबसे अधिक होने की आशंका है।

यह कोई हैरानी की बात नहीं कि बांग्लादेश से अवैध तरीके से आए लोगों ने मतदाता पहचान पत्र के साथ आधार और अन्य अनेक वे दस्तावेज हासिल कर लिए हैं, जिनसे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है और साथ ही खुद को भारतीय नागरिक बताया जा सकता है। यह कोई अच्छी स्थिति नहीं कि अभारतीय नागरिक फर्जी प्रमाण पत्रों अथवा गलत जानकारी के आधार पर भारतीय नागरिक होने के पहचान पत्र हासिल कर लें और अंततः मतदाता भी बन जाएं। ऐसे लोग केवल भारतीय लोकतंत्र के साथ छल करने वाले ही नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा भी हो सकते हैं। कोई भी चुनाव हो, उसमें मतदान करने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही मिलना चाहिए।

ई-बसों का दौर

हरित राज्य हिमाचल में नवंबर से ई-बसों की राह खुल रही है। यह सूचना न केवल पर्यावरण सरोकारों के लिए आश्वस्तिकारक है, अपितु परंपरागत ईंधन पर निर्भर न होने की ओर कदम भी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश को ग्रीन राज्य बनाने की बात करते रहे हैं और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए परिवहन विभाग का दायित्व संभाले उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी प्रयासरत हैं। राज्य सरकार ने तय यह भी किया था कि हर सरकारी विभाग में ई वाहन ही होंगे। कुछ हद तक सफलता मिली भी है, किंतु अब बात बसों की हो रही है। तीन सौ के करीब बसों में से 80 से 100 बसें नवंबर में आएंगी। इनके लिए 40 चार्जिंग स्टेशन भी खोले जाएंगे। 2024 के आंकड़े बताते हैं कि इलेक्ट्रिक 2,423 बसों के पंजीकरण के साथ महाराष्ट्र सबसे आगे, जबकि उसके बाद 2,361 बसों के साथ दिल्ली और 1,473 बसों के साथ कर्नाटक है। अधिक से अधिक राज्य परिवहन इकाइयां अब ई-बसों के लिए टेंडर जारी कर रही हैं, जिससे आने वाले समय में देश भर में ई-बसों की पैठ बढ़ेगी। भारत में प्रति दस लाख लोगों पर केवल छह इलेक्ट्रिक बसें हैं, जबकि वैश्विक औसत 85 है। अच्छी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश जिन बसों को खरीद रहा है, उनकी मरम्मत 12 वर्ष तक कंपनी ही करेगी। वही बैटरी निस्तारण की चुनौती को देखेगी। वर्तमान युग के साथ कदमताल समय की आवश्यकता है।

ई-बसों से परंपरागत ईंधन से छुटकारे के साथ ही पर्यावरण संरक्षण भी बढ़ेगा

एक ओर कुआं तो दूसरी तरफ खाई

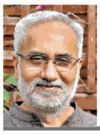

शिवकांत शर्मा

ट्रंप जिस वैश्विक व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे हैं उसकी भरपाई का चीनी प्रस्ताव बेहतर तो दिखता है, पर उसके लिए चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता

इन दिनों संयुक्त राष्ट्र महासभा का वार्षिक अधिवेशन चल रहा है। यूएन की स्थापना विश्व में शांति और सुरक्षा कायम रखने, आर्थिक, सामाजिक और मानवीय चुनौतियों का बहुपक्षीय सहयोग से समाधान और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए की गई थी। पश्चिमी देश इसे नियमबद्ध व्यवस्था कहते हैं जिसका प्रवर्तक एवं संरक्षक अमेरिका था। यूएन ने अपने 80 वर्षों में उपनिवेशवाद को समाप्त करने, शांति कायम रखने, महामारियों पर नियंत्रण रखने, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने और समुद्रों में व्यवस्था कायम रखने जैसे कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। हालांकि देशों की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा वह अमेरिका के दम पर ही करा पाया और शीतयुद्ध के दिनों में वह भी नहीं हो पाया। अमेरिका की दिलचस्पी न रहने के कारण ही न भारत को पाकिस्तान और चीन के द्वारा कब्जा किया हुआ कश्मीर मिल सका और न फलस्तीनियों को उनका देश। अमेरिका ने वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान में अपनी मनमानी जरूर की, लेकिन हकीकत यह है कि उसके दम के बिना संयुक्त राष्ट्र के लिए उतना हासिल करना भी मुमकिन न होता, जितना उसने हासिल किया।

अपनी मनमानी के बावजूद यूएन की नियमबद्ध व्यवस्था का संरक्षण करने अमेरिका को प्रतिष्ठा और वर्चस्व का अकूत लाभ मिला जिसकी वजह से पिछली सदी को अमेरिका की सदी कहा जाता है। फिर भी राष्ट्रपति ट्रंप ने आते ही एक-एक करके संयुक्त राष्ट्र की पेरिस जलवायु संधि, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जैसी संस्थाओं से हाथ खींच लिए और अमेरिकी राहत संस्था यूएस एड को भी रोक दिया। विश्व की 26 प्रतिशत अर्थव्यवस्था होने के कारण अमेरिका इन सभी संस्थाओं में सबसे अधिक योगदान करता है। उसके निकल जाने से विश्व में जलवायु संकट और महामारियों के प्रकोप का सामना करने की क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई है। स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी और असमानता के उन्मूलन के लक्ष्यों को पाना भी कठिन हो गया है।

ट्रंप की नीतियों से सबसे बड़ा धक्का विश्व व्यापार व्यवस्था को लगा है। पिछले पचास वर्षों में मुक्त व्यापार और वैश्वीकरण की वजह से जो आपूर्ति मार्ग बने और आर्थिक प्रगति हुई जिसके सहारे करोड़ों लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, वह सारी व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई है। ट्रंप जिस गति से मनमाने फरमान जारी कर रहे हैं और अपने ही बयानों से पलट रहे हैं, उन्हें देखकर अमेरिका के गठबंधन मित्र यूरोप की आयोग अध्यक्ष अर्सुला वान डर लेन को अपनी रिपोर्ट में लिखना पड़ा है, 'विश्व व्यवस्था अब सुधारातीत हो चुकी है, इसलिए यूरोप को जंगलराज के लिए तैयार हो जाना चाहिए।' इस निष्कर्ष पर पहुंचने की वजह वे घटनाएं हैं, जिनकी एक साल पहले तक कोई कल्पना भी नहीं करता था। यूएन के संरक्षक अमेरिका ने अपने मित्र देश डेनमार्क से कहा ग्रीनलैंड हमें सौंप दें, वर्ना हम छीन लेंगे। विश्व व्यापार संगठन को अमेरिका ने ही मनमानी टैरिफ नीतियों से अप्रासंगिक बना दिया है। सुरक्षा परिषद यूक्रेन और गाजा के युद्ध रुकवाने के लिए कोई प्रस्ताव पारित नहीं कर पा रही है। गाजा में मानवीय राहत पहुंचाने के लिए भी प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन पा रही है। अमेरिका यूएन के मतदान में रूस का साथ दे रहा है। रूसी हमले के लिए रूस पर या फिर उससे सबसे अधिक तेल खरीदने वाले चीन पर कोई कार्रवाई करने की जगह भारत पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं और यूक्रेन की लड़ाई को मोदी युद्ध की संज्ञा दी जा रही है। यूरोप से कहा जा रहा है कि वह भारत और चीन पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगा दे।

ट्रंप के आलोचक भी स्तब्ध हैं और कह रहे हैं कि विदेश नीति के इतिहास में उन्होंने किसी नेता को इस तरह अपने देश के हितों की होली खेलते नहीं देखा। अमेरिका के ही वरदान से बलशाली हुए चीन ने अवसर भांपते हुए महासभा के अधिवेशन से ठीक पहले शंघाई सहयोग संगठन के इतिहास की सबसे बड़ी शिखर बैठक का आयोजन किया। इसमें रूस और भारत समेत 24 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के समक्ष उसने अपनी नई 'वैश्विक प्रशासन पहल' की घोषणा की। इसकी बुनियाद पांच सिद्धांतों पर टिकी है। प्रभुसत्ता में बराबरी, अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन, बहुपक्षीय आचरण, जनोन्मुखी दृष्टिकोण और ठोस कार्यों पर ध्यान। ट्रंप जनित अस्थिरता के दौर में चीन को स्थिरता, सहयोग और शांति के चैंपियन के रूप में पेश करने के लिए सिद्धांततः तो ये सभी बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन तिब्बत में भारतीय सीमा पर ताइवान को लेकर और दक्षिणी चीन सागर में चीन की विस्तारवादी हरकतें इन सिद्धांतों के विपरीत रही हैं। ठीक वैसे जैसे एससीओ का बुनियादी लक्ष्य तो आतंकवाद पर अंकुश लगाना है, मगर पाकिस्तानी आतंकियों और उनके संगठनों को आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर चीन ने हमेशा टांग अड़ाई है।

विश्व में कैसी व्यवस्था हो इसे लेकर दो धुरियां बन गई हैं। एक ओर अमेरिका है जिसके नेता ट्रंप अपने ही देश के बनाए नियमों को खारिज कर रहे हैं। दूसरी ओर चीन है, जो बातें तो नियमबद्ध और न्यायसंगत व्यवस्था की करता है, लेकिन आचरण में उलटा है। जिस व्यवस्था को ट्रंप ने तोड़ा वह बराबरी और न्याय पर आधारित नहीं थी, इसलिए भारत बदलाव चाहता था। जिसका प्रस्ताव चीन ने रखा है वह व्यवस्था बेहतर तो है, पर उसे अमल में लाने के लिए चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए भारत को चीन से सतर्क रहते हुए विषय आधारित संबंध बनाकर चलना होगा और अमेरिका से संबंध सुधारने के प्रयास करने होंगे। चूंकि अब पड़ोसी बहुत प्रबल हो गया है, इसलिए अपनी सैनिक और आर्थिक शक्ति पर भी लगकर काम करना होगा भारत को एक ऐसी बहुध्रुवीय व्यवस्था के निर्माण पर काम करना होगा जो बराबरी और न्याय पर आधारित हो और पर्यावरण और जनकल्याण को ध्यान में रखते हुए मुक्त व्यापार के अवसर खोले। इसके लिए भारत को ब्रिक्स, आसियान, पश्चिमी एशिया और अफ्रीकी देशों के साथ अपने संबंध और प्रगाढ़ करने होंगे।

(लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं)
response@jagran.com

अवधेश राजपूत

कर प्रणाली को सरल बनाने की पहल

प्रो. गौरव वल्लभ

जीएसटी 2.0 भारत में एक सरलीकृत और विकासोन्मुखी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का सफर परिवर्तनकारी रहा है। 2017 में शुरू हुई इस व्यवस्था को आलोचकों ने 'गब्बर सिंह टैक्स' कहकर खारिज करने का भी प्रयास किया और इस पर नागरिकों तथा व्यवसायों, दोनों पर बोझ डालने का आरोप लगाया। वास्तव में असली 'गब्बर सिंह टैक्स' जीएसटी से पहले की अव्यवस्थित व्यवस्था थी। उत्पाद शुल्क, वैट और सेवा करों के एक खंडित जाल ने अकुशलता और बढ़ी हुई लागतों को जन्म दिया था। जीएसटी लागू होने के पहले ट्रक राज्य की सीमाओं पर खड़े रहते थे, छोटी कंपनियां कई फाइलिंग में ही उलझी रहती थीं और उपभोक्ताओं को इसकी कीमत चुकानी पड़ती थी। जीएसटी ने इसकी जगह देश में एक एकीकृत कर प्रणाली को संभव बनाया, जिससे आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स कम हुए और एक अधिक तर्कसंगत ढांचा तैयार हुआ। अब जीएसटी 2.0 के साथ भारत ने एक निर्णायक कदम आगे बढ़ाया है, टैक्स स्लैब को सुव्यवस्थित किया है और दरों में कटौती की है। शुरुआत में जीएसटी में चार स्लैब (5, 12, 18, 28 प्रतिशत) थे। ऐसा उन राज्यों के बीच आम सहमति बनाने के लिए किया गया था, जो नई व्यवस्था के तहत होने वाले संभावित राजस्व नुकसान को वहन करने के लिए तैयार नहीं थे। इस समझौते ने भारत को जीएसटी युग में प्रवेश करने में मदद की, लेकिन इसने जटिलता और विवादों को भी जन्म दिया, जो जीएसटी की सरलता के मूल दर्शन के विपरीत थे। जीएसटी 2.0 एक स्वाभाविक सुधार का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें दो मुख्य स्लैब (5 और 18 प्रतिशत) और विलासिता तथा अहितकर वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत की कर दर की व्यवस्था की गई है।

यह सुधार भी सही समय पर किया गया है। वैश्विक अनिश्चितताएं और टैरिफ युद्ध व्यवसायों के लिए बाधाएं पैदा कर रहे हैं। अनुपालन बोझ एवं कार्यशील पूंजी की रुकावटों को कम करके और बड़े पैमाने पर उपभोग तथा श्रम-प्रधान क्षेत्रों में टैक्स दरों को आसान बनाकर जीएसटी 2.0 आपूर्ति-पक्ष को ठीक उसी समय सहायता प्रदान करता है जब फर्मों को इसकी आवश्यकता है।

जीएसटी में सुधार से सस्ती हुईं जरूरी चीजें। फाइल

अन्य संरचनात्मक सुधारों के साथ जीएसटी 2.0 वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत को एक प्रतिस्पर्धी और स्थिर उत्पादन आधार के रूप में स्थापित करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं और बड़े पैमाने पर उपभोग की जाने वाली वस्तुएं पांच प्रतिशत, जबकि प्रमुख औद्योगिक इनपुट 18 प्रतिशत कर के दायरे में आ गई हैं, जिससे घरों और फर्मों, दोनों की लागत कम होगी। दूध, पनीर और चपाती जैसी मुख्य वस्तुओं के साथ-साथ 33 से अधिक जीवनरक्षक दवाओं को पूरी तरह से कर मुक्त कर दिया गया है। आटोमोबाइल, सीमेंट और इलेक्ट्रानिक्स पर करों में भारी कटौती की गई, जिससे क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। त्योहारी सीजन से पहले इसे लागू करने से घरेलू खर्च पर भी अधिकतम प्रभाव सुनिश्चित होता है। एसबीआइ रिसर्च का अनुमान है कि औसत प्रभावी जीएसटी दर अब शुरुआत के 14.4 प्रतिशत से घटकर लगभग 9.5 प्रतिशत हो गई है। जीएसटी 2.0 के तहत जिन 453 वस्तुओं की दरों में बदलाव किया गया है, उनमें से 413 (91 प्रतिशत) वस्तुओं के कर में कमी आई है, और लगभग 295 वस्तुओं पर कर दर पहले के 12 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत या शून्य हो गई है, जो परिवारों को राहत देने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। जीएसटी सुधारों के कारण कुल अतिरिक्त सकल मांग 1.98 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। समवर्ती आयकर सुधारों के साथ कुल अतिरिक्त मांग 5.31 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है, जो जीडीपी में लगभग 1.6 प्रतिशत की वृद्धि करेगी। इससे संभावित रूप से वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी वृद्धि 6.5 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2026-27 में 7 प्रतिशत तक पहुंच सकती है।

दरों में कटौती के अलावा जीएसटी 2.0 कर प्रणाली के काम करने के तरीके को बेहतर बनाने पर भी केंद्रित है। पंजीकरण को स्वचालित बना दिया गया है, रिफंड की प्रक्रिया तेज हो गई है और अस्थायी इनपुट क्रेडिट की अनुमति दी गई है, जिससे उद्यमों के लिए कार्यशील पूंजी पर दबाव घटा है। उल्टे शुल्क ढांचे जैसे लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों का भी समाधान किया गया है, जिससे उन क्षेत्रों को राहत मिली है, जो पहले लागत संबंधी नुकसान झेल रहे थे। एमएसएमई के लिए कागजी कार्रवाई का बोझ घटा है।

सुधार एक सतत प्रक्रिया है। जीएसटी स्वयं 2017 से पहले की खंडित प्रणाली की तुलना में एक सुधार था और जीएसटी 2.0 सरलता तथा निष्पक्षता की ओर एक और कदम है। जैसे-जैसे इसका अनुपालन होगा, नीतिगत सुधार और भी बेहतर हो सकेंगे। जीएसटी 2.0 भारत में एक सरलीकृत, अधिक निष्पक्ष और विकासोन्मुखी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। कर दरों को सोच-समझकर युक्तिसंगत बनाकर और व्यापक संरचनात्मक एवं प्रक्रियागत सुधारों के माध्यम से घरेलू क्रय शक्ति बढ़ाकर जीएसटी 2.0 उपभोग, औद्योगिक विकास और समग्र आर्थिकी को मजबूती से बढ़ावा देगा। यह समावेशी और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक निर्णायक उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करेगा, जो वर्तमान भू-राजनीतिक परिवेश में आर्थिक गति को बढ़ावा देने में सहायक है।

(लेखक प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य और वित्त के प्रोफेसर हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

मोक्ष

मनुष्य का जीवन केवल जन्म लेना, भोजन करना और मृत्यु तक संघर्ष करना नहीं है। यदि हम जीवन को इसी दृष्टिकोण से देखें, तो मनुष्य और अन्य जीवों में कोई विशेष अंतर नहीं रह जाता। इंसान को उसकी चेतना और उसकी खोज विशेष बनाती है-मैं कौन हूं? मैं क्यों आया हूं? मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है?' इस खोज का उत्तर है-मोक्ष। मोक्ष का सामान्य अर्थ है बंधनों से मुक्ति। हम जीवनभर इच्छाओं, भय, दुख और सुख, सफलता और असफलता के विभिन्न बंधनों में जकड़े रहते हैं। इन बंधनों में फंसकर मनुष्य बार-बार जन्म-मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। मोक्ष का अर्थ है इस चक्र से निकलकर परम स्वतंत्रता को पाना।

मोक्ष की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि कोई भी असली सुख स्थायी नहीं होता। धन, यश, पद या संबंध, सब बदलते रहते हैं। जब तक हम इन पर निर्भर रहते हैं, हमें शांति नहीं मिलती। मोक्ष वह अवस्था है जब मनुष्य बाहरी सहारे पर नहीं, बल्कि अपने भीतर के सत्य और परमात्मा पर आश्रित होता है। यह शांति, आनंद और स्वतंत्रता की चरम स्थिति है। वास्तव में मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के बाद किसी लोक में जाना नहीं है। यह तो जीवन में ही प्राप्त होने वाली अवस्था है। जब मनुष्य अपने भीतर की सीमाओं को तोड़ देता है, जब वह 'मैं' और 'मेरा' से ऊपर उठकर पूरे ब्रह्मांड से एकात्म हो जाता है, तभी मोक्ष की अनुभूति होती है। यह वही स्थिति है जब भय समाप्त हो जाता है, जब किसी प्रकार की कमी या असुरक्षा नहीं रहती। इसलिए कहा गया है कि जीवन का लक्ष्य केवल जीना नहीं, बल्कि मोक्ष की ओर बढ़ना है। मोक्ष ही वह बिंदु है जहां आत्मा पूर्ण स्वतंत्रता और अनंत शांति का अनुभव करता है। मोक्ष की इस खोज में ध्यान और साधना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं, तब हमें अपने अस्तित्व का अर्थ समझ में आता है।

श्रीश्री आनंदमूर्ति

भोजन की बर्बादी चिंताजनक

देवेंद्रराज सुथार

दुनिया के बड़े उत्पादक देशों में शामिल होने के बावजूद भारत में हर साल करीब 6.7 करोड़ टन खाद्यान्न बर्बाद होता है

हाल में यूरोपीय संघ ने एक कानून पारित किया, जिसके तहत सभी सदस्य देशों को 2030 तक खाद्यान्न बर्बादी में 30 प्रतिशत कमी लाना अनिवार्य है। यह कदम न केवल भोजन बचाने के लिए है, बल्कि पानी, ऊर्जा, भूमि और श्रम जैसे संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन की दिशा में भी अहम है। इससे पहले भी यूरोप के कई देशों ने अलग-अलग स्तर पर इस दिशा में पहल की थी। फ्रांस ने सुपरमार्केट को अनिवार्य किया कि वे खाने योग्य भोजन फेंकने के बजाय दान करें। इटली ने कर छूट और प्रोत्साहन योजनाएं शुरू कीं, ताकि बचा हुआ भोजन जरूरतमंदों तक पहुंचे। जर्मनी, स्पेन और डेनमार्क में फूड-शेयरिंग प्लेटफार्म और मोबाइल एप बनाए गए, जिनसे सीधे लोगों तक भोजन पहुंचाया जा रहा है।

भारत की स्थिति पर नजर डालें तो तस्वीर चिंताजनक है। खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर होने और दुनिया के बड़े उत्पादक देशों में शामिल होने के बावजूद यहां हर साल करीब 6.7 करोड़ टन भोजन बर्बाद होता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, यह मात्रा ब्रिटेन जैसे पूरे देश की वार्षिक खपत के बराबर है। इस बर्बादी की आर्थिक कीमत लगभग 92 हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष आंकी गई है। भारत में खाद्य अपव्यय दो स्तरों पर होता है। उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला में भंडारण और परिवहन की कमी के कारण बड़ी मात्रा में अनाज और सब्जियां खराब हो जाती हैं। कृषि मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि हर साल करीब 40 प्रतिशत फल और सब्जियां उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाती हैं। दूसरी ओर, उपभोक्ता स्तर पर होटलों, रेस्तरांओं और विवाह समारोहों में जरूरत से ज्यादा पकाया गया भोजन बर्बाद होता है।

इस परिप्रेक्ष्य में भारत के लिए यूरोपीय संघ का कानून प्रेरणादायी हो सकता है। यदि भारत सरकार भी आने वाले 10 वर्षों में खाद्यान्न की बर्बादी को निश्चित प्रतिशत तक कम करने का कानूनी लक्ष्य तय करे, तो व्यापक बदलाव संभव होंगे। सुपरमार्केट और होटल उद्योग को यह बाध्य किया जा सकता है कि वे बचा हुआ भोजन चैरिटी संगठनों, अनाथालयों और जरूरतमंदों तक पहुंचाएं। बड़े आयोजनों में भोजन की बर्बादी रोकने के लिए स्पष्ट नियम बनाए जा सकते हैं। सामाजिक दृष्टि से भी यह बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत की लगभग 14 प्रतिशत आबादी भूख और कुपोषण से जूझ रही है। ऐसे में भोजन की बर्बादी केवल आर्थिक हानि नहीं, बल्कि विडंबना भी है। भोजन की बर्बादी पर्यावरणीय संकट से भी जुड़ी है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार, वैश्विक खाद्य अपव्यय से हर साल 8 से 10 प्रतिशत ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन होता है। भारत जैसे देश के लिए इस दिशा में ठोस कानूनी कदम उठाना और भी आवश्यक हो जाता है, जो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से सर्वाधिक प्रभावित है।

(लेखक लोकनीति विश्लेषक हैं)

मणिपुर को चाहिए शांति और विकास

'मणिपुर में मोदी' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय पढ़ा। यह निर्विवाद सत्य है कि मणिपुर ने पिछले ढाई वर्षों में हिंसा और अस्थिरता की लंबी त्रासदी झेली है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री का प्रदेश दौरा शांति और विकास की राह में एक महत्वपूर्ण संदेश है। यह यात्रा न केवल मणिपुर के लोगों, बल्कि पूरे देश को यह भरोसा दिलाती है कि इस आग में झुलसे प्रदेश को फिर से सामान्य जीवन की ओर ले जाना केंद्र की प्राथमिकता है। मणिपुर की आवश्यकता अब स्थायी शांति है। जब तक समाज में सौहार्द और आपसी विश्वास बहाल नहीं होगा, तब तक कोई भी विकास-परियोजना सार्थक नहीं हो पाएगी। प्रधानमंत्री की उपस्थिति से जनता को यह आश्वासन अवश्य मिला है कि राज्य की पीड़ा और चुनौतियों के प्रति केंद्र सरकार संवेदनशील है तथा संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। दूसरी ओर, विपक्ष विशेषकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का यह कहना कि प्रधानमंत्री मणिपुर में केवल 'वोट चोरी' करने आए हैं, नितांत बचकाना प्रतीत होता है। ऐसे आरोप न तो राज्य के हालात सुधारने में सहायक हैं और न ही जनता की पीड़ा के प्रति संवेदनशीलता के परिचायक। आवश्यकता है कि सभी राजनीतिक दल स्थिति की गंभीरता को समझते हुए एकजुट होकर शांति बहाली में योगदान दें। आज मणिपुर को राष्ट्रीय सरोकार की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। तभी यह प्रदेश हिंसा की छाया से निकलकर स्थायी शांति और प्रगति की ओर अग्रसर हो पाएगा।

सुरेश गोयल धूप वाला, हिसार, हरियाणा

मेलबाक्स

भाषा का सम्मान ही राष्ट्र का स्वाभिमान

'देश की अभिव्यक्ति का सबल माध्यम हिंदी'' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में गिरीश्वर मिश्र ने शत प्रतिशत उपयुक्त और व्यावहारिक बात कही है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं न केवल संवाद और ज्ञान का माध्यम हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति और एकता का मूल आधार भी हैं। शिक्षा, प्रशासन और रोजगार में इन्हें बढ़ावा देना राष्ट्रीय स्वाभिमान और प्रगति के लिए आवश्यक है। भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्र का आत्मा है। भारत की अधिकांश जनता हिंदी समझती और बोलती है, फिर भी शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में हिंदी को वह स्थान नहीं मिल पाया जिसकी वह हकदार है। अंग्रेजी की अनिवार्यता ने प्रतिभा को भाषा की दीवारों में कैद कर दिया है। यही कारण है कि लाखों विद्यार्थी योग्य होते हुए भी केवल भाषा के कारण अवसरों से वंचित रह जाते हैं। समाधान स्पष्ट है। विद्यालयों से लेकर उच्च शिक्षा संस्थानों तक हिंदी सहित भारतीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण पाठ्यपुस्तकें और शोध सामग्री उपलब्ध कराई जाए। प्रतियोगी परीक्षाएं मातृभाषा में देने का पूरा अवसर मिले। विश्वविद्यालयों में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा हिंदी माध्यम से संचालित हो, ताकि भाषा प्रतिभा के मार्ग में बाधा न बने। रोजगार और सरकारी कार्यालयों में भी हिंदी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि दफ्तरों में फाइलें, पत्राचार और सेवाएं हिंदी में हों तो आम नागरिक सहजता से जुड़ पाएगा। निजी संस्थानों को भी भर्ती और प्रशिक्षण में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना होगा।

अमन सिंह गौर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश

असुरक्षित प्रसव की चिंता

देशभर में 2.5 प्रतिशत यानी लगभग छह लाख महिलाओं की प्रसव डिलीवरी बिना किसी प्रशिक्षण वाली महिलाओं या बिना किसी चिकित्सकीय सहायता के हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिना प्रशिक्षण वाली महिलाओं या अन्य व्यक्तियों से प्रसव कराने का प्रतिशत 2.3 प्रतिशत है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 1.1 प्रतिशत है। इसका अर्थ है कि ग्रामीण महिलाएं सरकारी अस्पतालों पर अधिक भरोसा करती हैं, जबकि शहरी महिलाएं निजी अस्पतालों को प्राथमिकता देती हैं। देश में बिना चिकित्सकीय सहायता या बिना प्रशिक्षित महिलाओं की मदद से प्रसव के मामले बने हुए हैं, जिससे मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु का खतरा बढ़ने की आशंका व्यक्त की गई है। इन असुरक्षित प्रसवों को रोकने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है।

दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुंबई

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संपादकीय जागरण

(10) सोमवार, 15 सितंबर, 2025 : आश्विन कृष्ण - 9 वि. 2082

तर्क मानव जीवन को प्रगति के शिखरों तक पहुंचाता है

देशव्यापी एसआइआर

यह अच्छा है कि चुनाव आयोग बिहार के बाद देश भर में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात एसआइआर के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त कर रहा है। चुनाव आयोग की ओर से मिले संकेतों के अनुसार वह अगले माह से मतदाता सूचियों के सत्यापन का देशव्यापी अभियान चला सकता है। जो भी हो, आवश्यकता इस बात की है कि यह अभियान प्रभावी ढंग से चलाया जाए, भले ही इसमें कुछ विलंब हो। बिहार के अनुभव ने इस आवश्यकता पर और अधिक बल दिया है कि पूरे देश में मतदाता सूचियों का सत्यापन होना चाहिए। सच तो यह है कि यह कार्य एक निश्चित अंतराल के बाद होते ही रहना चाहिए। यह ठीक नहीं कि बिहार में 2003 के बाद अब जाकर मतदाता सूची के सत्यापन करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकी। चुनाव आयोग को देशव्यापी एसआइआर करते समय इसके लिए भी तैयार रहना होगा कि उसे विपक्षी दलों और साथ ही स्वयं को लोकतंत्र का स्वयंभू पैरोकार बताने वाले लोगों के विरोध और दुष्प्रचार का सामना करना पड़ सकता है। इसका अंदेशा इसलिए है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से बिहार में मतदाता सूची के सत्यापन की प्रक्रिया को हरी झंडी दिखाए जाने के बावजूद विपक्षी दल अपने बेजा विरोध से बाज नहीं आ रहे हैं। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मतदाता सूची के सत्यापन की संभावित प्रक्रिया के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। इस राज्य में चुनाव आयोग को एसआइआर की प्रक्रिया आगे बढ़ाने में सत्तारूढ़ दल के असहयोग के साथ अन्य चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। एक बड़ी चुनौती उन दस्तावेजों के सत्यापन की हो सकती है, जिनके आधार पर कोई अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा तय किए गए दस्तावेजों में आधार को भी शामिल कर लिया है और यह किसी से छिपा नहीं कि बंगाल में सर्वाधिक नकली अथवा फर्जी दस्तावेजों के सहारे आधार से लैस लोगों की संख्या सबसे अधिक होने की आशंका है। यह कोई हैरानी की बात नहीं कि बांग्लादेश से अवैध तरीके से आए लोगों ने मतदाता पहचान पत्र के साथ आधार और अन्य अनेक वे दस्तावेज हासिल कर लिए हैं, जिनसे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है और साथ ही खुद को भारतीय नागरिक बताया जा सकता है। यह कोई अच्छी स्थिति नहीं कि अभारतीय नागरिक फर्जी प्रमाण पत्रों अथवा गलत जानकारी के आधार पर भारतीय नागरिक होने के पहचान पत्र हासिल कर लें और अंततः मतदाता भी बन जाएं। ऐसे लोग केवल भारतीय लोकतंत्र के साथ छल करने वाले ही नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा भी हो सकते हैं। कोई भी चुनाव हो, उसमें मतदान करने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही मिलना चाहिए।

बेहतर होती स्वास्थ्य सेवा

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए सरकारी प्रयास चल रहे हैं। राजधानी पटना से लेकर जिला अस्पतालों तक में विशेषज्ञ चिकित्सकों के अलावा जांच व आवश्यक दवाओं की उपलब्धता इस बात का द्योतक है कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं। इसी का फलाफल है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवाएं मुहैया कराने में बिहार लगातार 11 महीने से अव्वल रहा। सरकारी अस्पतालों में गंभीर बीमारियों के साथ-साथ सामान्य बीमारियों की दवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। राज्य के मेडिकल कालेज और अस्पतालों में कुल 611 प्रकार की दवाएं मरीजों को दी जाती हैं। वहीं, जिला अस्पताल की ओपीडी में 287 और आइपीडी में 169 प्रकार की दवाएं मिल रही हैं। यहां तक कि अनुमंडलीय अस्पताल की ओपीडी में भी 212 प्रकार की दवाएं दी जा रही हैं। इसके बावजूद अक्सर यह सुनने को मिलता है कि अस्पताल में दवा नहीं मिलने के कारण मरीज या तीमारदार को बाहर से खरीदनी पड़ रही है। ऐसी शिकायतों की जांच के लिए विभाग को बीच-बीच में पड़ताल करानी चाहिए कि क्या अस्पताल में उपलब्ध दवा के लिए मरीजों को भटकना तो नहीं पड़ रहा। इसके अलावा मेडिकल कालेज, जिला, अनुमंडल अस्पतालों में औचक निरीक्षण की व्यवस्था हो, ताकि पता चल सके कि जो सुविधाएं सरकार की ओर से मुहैया कराई जा रही हैं, उसका लाभ मरीजों को मिल रहा है या नहीं।

> स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है, लेकिन समय-समय पर औचक निरीक्षण से व्यवस्था और बेहतर होगी।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या नेपाल में अंतरिम सरकार स्थायित्व प्रदान करने में सक्षम दिख रही है?

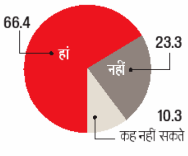

आज का सवाल

क्या पूरे देश में मतदाता सत्यापन पुनरीक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाना समय की आवश्यकता है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

एक ओर कुआं तो दूसरी तरफ खाई

शिवकांत शर्मा

ट्रंप जिस वैश्विक व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे हैं उसकी भरपाई का चीनी प्रस्ताव बेहतर तो दिखता है, पर उसके लिए चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता

इन दिनों संयुक्त राष्ट्र महासभा का वार्षिक अधिवेशन चल रहा है। यूएन की स्थापना विश्व में शांति और सुरक्षा कायम रखने, आर्थिक, सामाजिक और मानवीय चुनौतियों का बहुपक्षीय सहयोग से समाधान और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए की गई थी। पश्चिमी देश इसे नियमबद्ध व्यवस्था कहते हैं जिसका प्रवर्तक एवं संरक्षक अमेरिका था। यूएन ने अपने 80 वर्षों में उपनिवेशवाद को समाप्त करने, शांति कायम रखने, महामारियों पर नियंत्रण रखने, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने और समुद्रों में व्यवस्था कायम रखने जैसे कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। हालांकि देशों की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा वह अमेरिका के दम पर ही करा पाया और शीतयुद्ध के दिनों में वह भी नहीं हो पाया। अमेरिका की दिलचस्पी न रहने के कारण ही न भारत को पाकिस्तान और चीन के द्वारा कब्जा किया हुआ कश्मीर मिल सका और न फलस्तीनियों को उनका देश। अमेरिका ने वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान में अपनी मनमानी जरूर की, लेकिन हकीकत यह है कि उसके दम के बिना संयुक्त राष्ट्र के लिए उतना हासिल करना भी मुमकिन न होता, जितना उसने हासिल किया।

अपनी मनमानी के बावजूद यूएन की नियमबद्ध व्यवस्था का संरक्षण करने अमेरिका को प्रतिष्ठा और वर्चस्व का अकूत लाभ मिला जिसकी वजह से पिछली सदी को अमेरिका की सदी कहा जाता है। फिर भी राष्ट्रपति ट्रंप ने आते ही एक-एक करके संयुक्त राष्ट्र की पेरिस जलवायु संधि, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जैसी संस्थाओं से हाथ खींच लिए और अमेरिकी राहत संस्था यूएस एड को भी रोक दिया। विश्व की 26 प्रतिशत अर्थव्यवस्था होने के कारण अमेरिका इन सभी संस्थाओं में सबसे अधिक योगदान करता है। उसके निकल जाने से विश्व में जलवायु संकट और महामारियों के प्रकोप का सामना करने की क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई है। स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी और असमानता के उन्मूलन के लक्ष्यों को पाना भी कठिन हो गया है।

ट्रंप की नीतियों से सबसे बड़ा धक्का विश्व व्यापार व्यवस्था को लगा है। पिछले पचास वर्षों में मुक्त व्यापार और वैश्वीकरण की वजह से जो आपूर्ति मार्ग बने और आर्थिक प्रगति हुई जिसके सहारे करोड़ों लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, वह सारी व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई है। ट्रंप जिस गति से मनमाने फरमान जारी कर रहे हैं और अपने ही बयानों से पलट रहे हैं, उन्हें देखकर अमेरिका के गठबंधन मित्र यूरोप की आयोग अध्यक्ष

अवधेश राजपूत

अर्सुला वान डर लेन को अपनी रिपोर्ट में लिखना पड़ा है, 'विश्व व्यवस्था अब सुधारातीत हो चुकी है, इसलिए यूरोप को जंगलराज के लिए तैयार हो जाना चाहिए।' इस निष्कर्ष पर पहुंचने की वजह वे घटनाएं हैं, जिनकी एक साल पहले तक कोई कल्पना भी नहीं करता था। यूएन के संरक्षक अमेरिका ने अपने मित्र देश डेनमार्क से कहा ग्रीनलैंड हमें सौंप दें, वर्ना हम छीन लेंगे। विश्व व्यापार संगठन को अमेरिका ने ही मनमानी टैरिफ नीतियों से अप्रासंगिक बना दिया है। सुरक्षा परिषद यूक्रेन और गाजा के युद्ध रुकवाने के लिए कोई प्रस्ताव पारित नहीं कर पा रही है। गाजा में मानवीय राहत पहुंचाने के लिए भी प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन पा रही है। अमेरिका यूएन के मतदान में रूस का साथ दे रहा है। रूसी हमले के लिए रूस पर या फिर उससे सबसे अधिक तेल खरीदने वाले चीन पर कोई कार्रवाई करने की जगह भारत पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं और यूक्रेन की लड़ाई को मोदी युद्ध की संज्ञा दी जा रही है। यूरोप से कहा जा रहा है कि वह भारत और चीन पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगा दे। स्पष्ट है कि नियमबद्ध मानी जाने वाली व्यवस्था नियमहीन होकर टूट चुकी है।

ट्रंप के आलोचक भी स्तब्ध हैं और कह रहे हैं कि विदेश नीति के इतिहास में उन्होंने किसी नेता को इस तरह अपने देश के हितों की होली खेलते नहीं देखा। अमेरिका के ही वरदान से बलशाली हुए चीन ने अवसर भांपते हुए महासभा के अधिवेशन से ठीक पहले शंघाई सहयोग संगठन के इतिहास की सबसे बड़ी शिखर बैठक का आयोजन किया। इसमें रूस और भारत समेत 24 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के समक्ष उसने अपनी नई 'वैश्विक प्रशासन पहल' की घोषणा की। इसकी बुनियाद पांच सिद्धांतों पर टिकी है। प्रभुसत्ता में बराबरी, अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन, बहुपक्षीय आचरण, जनोन्मुखी दृष्टिकोण और ठोस कार्यों पर ध्यान। ट्रंप जनित अस्थिरता के दौर में चीन को स्थिरता, सहयोग और शांति के चैंपियन के रूप में पेश करने के लिए सिद्धांततः तो ये सभी बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन तिब्बत में भारतीय सीमा पर ताइवान को लेकर और दक्षिणी चीन सागर में चीन की विस्तारवादी हरकतें इन सिद्धांतों के विपरीत रही हैं। ठीक वैसे जैसे एससीओ का बुनियादी लक्ष्य तो आतंकवाद पर अंकुश लगाना है, मगर पाकिस्तानी आतंकियों और उनके संगठनों को आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर चीन ने हमेशा टांग अड़ाई है।

विश्व में कैसी व्यवस्था हो इसे लेकर दो धुरियां बन गई हैं। एक ओर अमेरिका है जिसके नेता ट्रंप अपने ही देश के बनाए नियमों को खारिज कर रहे हैं। दूसरी ओर चीन है, जो बातें तो नियमबद्ध और न्यायसंगत व्यवस्था की करता है, लेकिन आचरण में उलटा है। जिस व्यवस्था को ट्रंप ने तोड़ा वह बराबरी और न्याय पर आधारित नहीं थी, इसलिए भारत बदलाव चाहता था। जिसका प्रस्ताव चीन ने रखा है वह व्यवस्था बेहतर तो है, पर उसे अमल में लाने के लिए चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए भारत को चीन से सतर्क रहते हुए विषय आधारित संबंध बनाकर चलना होगा और अमेरिका से संबंध सुधारने के प्रयास करने होंगे। चूंकि अब पड़ोसी बहुत प्रबल हो गया है, इसलिए अपनी सैनिक और आर्थिक शक्ति पर भी लगकर काम करना होगा भारत को एक ऐसी बहुध्रुवीय व्यवस्था के निर्माण पर काम करना होगा जो बराबरी और न्याय पर आधारित हो और पर्यावरण और जनकल्याण को ध्यान में रखते हुए मुक्त व्यापार के अवसर खोले। इसके लिए भारत को ब्रिक्स, आसियान, पश्चिमी एशिया और अफ्रीकी देशों के साथ अपने संबंध और प्रगाढ़ करने होंगे।

(लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं)
response@jagran.com

कर प्रणाली को सरल बनाने की पहल

प्रो. गौरव वल्लभ

जीएसटी 2.0 भारत में एक सरलीकृत और विकासोन्मुखी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का सफर परिवर्तनकारी रहा है। 2017 में शुरू हुई इस व्यवस्था को आलोचकों ने 'गब्बर सिंह टैक्स' कहकर खारिज करने का भी प्रयास किया और इस पर नागरिकों तथा व्यवसायों, दोनों पर बोझ डालने का आरोप लगाया। वास्तव में असली 'गब्बर सिंह टैक्स' जीएसटी से पहले की अव्यवस्थित व्यवस्था थी। उत्पाद शुल्क, वैट और सेवा करों के एक खंडित जाल ने अकुशलता और बढ़ी हुई लागतों को जन्म दिया था। जीएसटी लागू होने के पहले ट्रक राज्य की सीमाओं पर खड़े रहते थे, छोटी कंपनियां कई फाइलिंग में ही उलझी रहती थीं और उपभोक्ताओं को इसकी कीमत चुकानी पड़ती थी। जीएसटी ने इसकी जगह देश में एक एकीकृत कर प्रणाली को संभव बनाया, जिससे आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स कम हुए और एक अधिक तर्कसंगत ढांचा तैयार हुआ। अब जीएसटी 2.0 के साथ भारत ने एक निर्णायक कदम आगे बढ़ाया है, टैक्स स्लैब को सुव्यवस्थित किया है और दरों में कटौती की है। शुरुआत में जीएसटी में चार स्लैब (5, 12, 18, 28 प्रतिशत) थे। ऐसा उन राज्यों के बीच आम सहमति बनाने के लिए किया गया था, जो नई व्यवस्था के तहत होने वाले संभावित राजस्व नुकसान को वहन करने के लिए तैयार नहीं थे। इस समझौते ने भारत को जीएसटी युग में प्रवेश करने में मदद की, लेकिन इसने जटिलता और विवादों को भी जन्म दिया, जो जीएसटी की सरलता के मूल दर्शन के विपरीत थे। जीएसटी 2.0 एक स्वाभाविक सुधार का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें दो मुख्य स्लैब (5 और 18 प्रतिशत) और विलासिता तथा अहितकर वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत की कर दर की व्यवस्था की गई है।

यह सुधार भी सही समय पर किया गया है। वैश्विक अनिश्चितताएं और टैरिफ युद्ध व्यवसायों के लिए बाधाएं पैदा कर रहे हैं। अनुपालन बोझ एवं कार्यशील पूंजी की रुकावटों को कम करके और बड़े पैमाने पर उपभोग तथा श्रम-प्रधान क्षेत्रों में टैक्स दरों को आसान बनाकर जीएसटी 2.0 आपूर्ति-पक्ष को ठीक उसी समय सहायता प्रदान करता है जब फर्मों को इसकी आवश्यकता है। अन्य संरचनात्मक सुधारों के साथ जीएसटी 2.0 वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत को एक प्रतिस्पर्धी और स्थिर उत्पादन आधार के रूप में स्थापित करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं और बड़े पैमाने पर उपभोग की जाने वाली वस्तुएं पांच प्रतिशत, जबकि प्रमुख औद्योगिक इनपुट 18 प्रतिशत कर के दायरे में आ गई हैं, जिससे घरों और फर्मों, दोनों की लागत कम होगी। दूध, पनीर और चपाती जैसी मुख्य वस्तुओं के साथ-साथ 33 से अधिक जीवनरक्षक दवाओं को पूरी तरह से कर मुक्त कर दिया गया है। आटोमोबाइल, सीमेंट और इलेक्ट्रानिक्स पर करों में भारी कटौती की गई, जिससे क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। त्योहारी सीजन से पहले इसे लागू करने से घरेलू खर्च पर भी अधिकतम प्रभाव सुनिश्चित होता है। एसबीआइ रिसर्च का अनुमान है कि औसत प्रभावी जीएसटी दर अब शुरुआत के 14.4 प्रतिशत से घटकर लगभग 9.5 प्रतिशत हो गई है। जीएसटी 2.0 के तहत जिन 453 वस्तुओं की दरों में बदलाव किया गया है, उनमें से 413 (91 प्रतिशत) वस्तुओं के कर में कमी आई है, और लगभग 295 वस्तुओं पर कर दर पहले के 12 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत या शून्य हो गई है, जो परिवारों को राहत देने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। जीएसटी सुधारों के कारण कुल अतिरिक्त सकल मांग 1.98 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। समवर्ती आयकर सुधारों के साथ कुल अतिरिक्त मांग 5.31 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है, जो सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 1.6 प्रतिशत की वृद्धि करेगी। इससे संभावित रूप से वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी वृद्धि 6.5 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2026-27 में 7 प्रतिशत तक पहुंच सकती है।

जीएसटी में सुधार से सस्ती हुईं जरूरी चीजें ● फाइल

दरों में कटौती के अलावा जीएसटी 2.0 कर प्रणाली के काम करने के तरीके को बेहतर बनाने पर भी केंद्रित है। पंजीकरण को स्वचालित बना दिया गया है, रिफंड की प्रक्रिया तेज हो गई है और अस्थायी इनपुट क्रेडिट की अनुमति दी गई है, जिससे उद्यमों के लिए कार्यशील पूंजी पर दबाव घटा है। उल्टे शुल्क ढांचे जैसे लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों का भी समाधान किया गया है, जिससे उन क्षेत्रों को राहत मिली है, जो पहले लागत संबंधी नुकसान झेल रहे थे। एमएसएमई के लिए कागजी कार्रवाई का बोझ घटा है।

सुधार एक सतत प्रक्रिया है। जीएसटी स्वयं 2017 से पहले की खंडित प्रणाली की तुलना में एक सुधार था और जीएसटी 2.0 सरलता तथा निष्पक्षता की ओर एक और कदम है। जैसे-जैसे इसका अनुपालन होगा, नीतिगत सुधार और भी बेहतर हो सकेंगे। जीएसटी 2.0 भारत में एक सरलीकृत, अधिक निष्पक्ष और विकासोन्मुखी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। कर दरों को सोच-समझकर युक्तिसंगत बनाकर और व्यापक संरचनात्मक एवं प्रक्रियागत सुधारों के माध्यम से घरेलू क्रय शक्ति बढ़ाकर जीएसटी 2.0 उपभोग, औद्योगिक विकास और समग्र आर्थिकी को मजबूती से बढ़ावा देगा। यह समावेशी और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक निर्णायक उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करेगा, जो वर्तमान भू-राजनीतिक परिवेश में आर्थिक गति को बढ़ावा देने में सहायक है।

(लेखक प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य और वित्त के प्रोफेसर हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

मोक्ष

मनुष्य का जीवन केवल जन्म लेना, भोजन करना और मृत्यु तक संघर्ष करना नहीं है। यदि हम जीवन को इसी दृष्टिकोण से देखें, तो मनुष्य और अन्य जीवों में कोई विशेष अंतर नहीं रह जाता। इंसान को उसकी चेतना और उसकी खोज विशेष बनाती है-मैं कौन हूं? मैं क्यों आया हूं? मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है?' इस खोज का उत्तर है-मोक्ष। मोक्ष का सामान्य अर्थ है बंधनों से मुक्ति। हम जीवनभर इच्छाओं, भय, दुख और सुख, सफलता और असफलता के विभिन्न बंधनों में जकड़े रहते हैं। इन बंधनों में फंसकर मनुष्य बार-बार जन्म-मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। मोक्ष का अर्थ है इस चक्र से निकलकर परम स्वतंत्रता को पाना।

मोक्ष की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि कोई भी असली सुख स्थायी नहीं होता। धन, यश, पद या संबंध, सब बदलते रहते हैं। जब तक हम इन पर निर्भर रहते हैं, हमें शांति नहीं मिलती। मोक्ष वह अवस्था है जब मनुष्य बाहरी सहारे पर नहीं, बल्कि अपने भीतर के सत्य और परमात्मा पर आश्रित होता है। यह शांति, आनंद और स्वतंत्रता की चरम स्थिति है। वास्तव में मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के बाद किसी लोक में जाना नहीं है। यह तो जीवन में ही प्राप्त होने वाली अवस्था है। जब मनुष्य अपने भीतर की सीमाओं को तोड़ देता है, जब वह 'मैं' और 'मेरा' से ऊपर उठकर पूरे ब्रह्मांड से एकात्म हो जाता है, तभी मोक्ष की अनुभूति होती है। यह वही स्थिति है जब भय समाप्त हो जाता है, जब किसी प्रकार की कमी या असुरक्षा नहीं रहती। इसलिए कहा गया है कि जीवन का लक्ष्य केवल जीना नहीं, बल्कि मोक्ष की ओर बढ़ना है। मोक्ष ही वह बिंदु है जहां आत्मा पूर्ण स्वतंत्रता और अनंत शांति का अनुभव करता है। मोक्ष की इस खोज में ध्यान और साधना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं, तब हमें अपने अस्तित्व का अर्थ समझ में आता है।

श्रीश्री आनंदमूर्ति

पाठकनामा

pathaknama@pat .jagran.com

मणिपुर को चाहिए शांति और विकास

'मणिपुर में मोदी' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय पढ़ा। यह निर्विवाद सत्य है कि मणिपुर ने पिछले ढाई वर्षों में हिंसा और अस्थिरता की लंबी त्रासदी झेली है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री का प्रदेश दौरा केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि शांति और विकास की राह में एक महत्वपूर्ण संदेश है। यह यात्रा न केवल मणिपुर के लोगों, बल्कि पूरे देश को यह भरोसा दिलाती है कि इस आग में झुलसे प्रदेश को फिर से सामान्य जीवन की ओर ले जाना केंद्र की प्राथमिकता है। मणिपुर की सबसे बड़ी आवश्यकता अब स्थायी शांति है। जब तक समाज में सौहार्द और आपसी विश्वास बहाल नहीं होगा, तब तक कोई भी विकास-परियोजना सार्थक नहीं हो पाएगी। प्रधानमंत्री की उपस्थिति से जनता को यह आश्वासन अवश्य मिला है कि राज्य की पीड़ा और चुनौतियों के प्रति केंद्र सरकार संवेदनशील है तथा संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। दूसरी ओर, विपक्ष विशेषकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का यह कहना कि प्रधानमंत्री मणिपुर में केवल 'वोट चोरी' करने आए हैं, नितांत बचकाना प्रतीत होता है। ऐसे आरोप न तो राज्य के हालात सुधारने में सहायक हैं और न ही जनता की पीड़ा के प्रति संवेदनशीलता के परिचायक। आवश्यकता है कि सभी राजनीतिक दल स्थिति की गंभीरता को समझते हुए एकजुट होकर शांति बहाली में योगदान दें। आज मणिपुर को राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय सरोकार की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। तभी यह प्रदेश हिंसा की छाया से निकलकर स्थायी शांति और प्रगति की ओर अग्रसर हो पाएगा।

सुरेश गोयल धूप वाला, हिसार, हरियाणा

एक सूत्र में बांधती हिंदी

गिरीश्वर मिश्र द्वारा लिखित आलेख 'देश की अभिव्यक्ति का सबल माध्यम हिंदी' पढ़ा। हिंदी की महत्ता को स्थापित करने एवं इसकी लोकप्रियता को जन-जन तक बढ़ाने के लिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। हिंदी दुनिया की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। विश्व भर की वेबसाइट हिंदी को महत्व दे रही है। ईमेल, ई कामर्स, ई बुक, इंटरनेट, एसएमएस, वेब जगत और इंटरनेट मीडिया में हिंदी को बड़ी सहजता से अपनाया जा रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी ने देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया था, लेकिन आज भारत में ही हिंदी दोयम दर्जे की भाषा हो चुकी है। कई क्षेत्रीय दल भाषा के नाम पर लोगों में कटुता पैदा कर रहे है। हिंदी से किसी भी क्षेत्रीय भाषा को कोई खतरा नहीं है, लेकिन अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव की वजह से कई क्षेत्रीय भाषा और बोलियां विलुप्त होने की कगार पर आ चुकी हैं। समाज में आज भी अंग्रेजी बोलने वाले को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। लोगों को सोच बदलने की आवश्यकता है। सरकार को उच्च शिक्षा में हिंदी को प्राथमिकता देनी चाहिए, न्यायालय सहित हर विभाग का कार्यकलाप हिंदी में करना चाहिए।

ई हिमांशु शेखर, केसपा, गयाजी।

इथेनाल का लाभ नहीं

केंद्र सरकार ने देश में पेट्रोल में इथेनाल मिलाने की पहल इसलिए की थी, ताकि देश की पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम हो, किसानों को गन्ना व अन्य फसलों से उचित दाम मिल सके और आम उपभोक्ताओं को सस्ता ईंधन उपलब्ध हो। इथेनाल, गन्ने के रस या अन्य कृषि उत्पादों से तैयार होने वाला जैव-ईंधन है, जो पेट्रोल से अपेक्षाकृत सस्ता होता है। सरकार ने लक्ष्य रखा कि पेट्रोल में 20 प्रतिशत तक इथेनाल मिलाकर बेचा जाए। इससे न केवल प्रदूषण घटेगा, बल्कि पेट्रोल की कीमतों में भी राहत मिलेगी। वास्तविक स्थिति आज भी उम्मीदों से भिन्न है। पेट्रोल में इथेनाल मिलाने के बावजूद आम जनता को इसका आर्थिक लाभ नहीं मिल पा रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें और टैक्स संरचना इतनी अधिक है कि इथेनाल मिश्रण का फायदा उपभोक्ता तक नहीं पहुंचता। किसानों को कभी-कभी गन्ने का बकाया पाने में संघर्ष करना पड़ता है और उपभोक्ता को पेट्रोल की ऊंची कीमतें चुकानी पड़ती हैं। यदि सरकार सचमुच इस योजना का उद्देश्य सफल बनाना चाहती है, तो उसे इथेनल उत्पादन बढ़ाने के साथ कर व्यवस्था में भी बदलाव करना होगा। पारदर्शिता और लागत का सही आकलन करके पेट्रोल में इथेनाल मिश्रण का फायदा आम जनता तक पहुंचाना ज़रूरी है। तभी इस पहल का सही उद्देश्य पूरा होगा।

डा. संजीव कुमार, स्मृति, राजेंद्र पथ, गया।

पोस्ट

नेपाल में कुछ दिन बिताने के बाद वहां के हालात को लेकर कुछ अंदाजा लगा है। राजशाही की वापसी की संभावना नगण्य है। पूरा देश वास्तविक परिवर्तन को बेचैन है। लोग भ्रष्टाचार से तंग आ गए हैं। राजनीतिक तंत्र से निराशा और अवसरों के अभाव ने उन्हें कुंठा से भर दिया है। नेपाली लोग पूरी गरिमा के साथ अपने देश को तरक्की के पथ पर आगे बढ़ता देखना चाहते हैं।

आदित्य राज कौल@AdityaRajKaul

अमेरिका के डलास में एक भारतीय की उनकी पत्नी और बेटे के सामने निर्मम हत्या कर दी गई। पूरी कोशिश के बाद भी वे उन्हें बचा नहीं पाए। मदद को कोई आगे नहीं आया, लेकिन इस हत्या से वहां पर वैसा तूफान नहीं दिखा जैसा फर्स्ट वर्ल्ड, लोकतंत्र, बराबरी, मानवाधिकार के झंडे बुलंद करने वाले सभ्य समाज में दिखना चाहिए।

कादंबिनी शर्मा@SharmaKadambini

शानदार साझा प्रयासों से भारतीय टीम ने डेविस कप में जीत हासिल की। यूरोप की धरती पर 32 साल बाद मिली यह जीत इतनी खास है कि उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। सुमित नागल@nagalsumit

जनपथ

मणिपुर में हो शांती जन्नत बने प्रदेश,
रहें सभी गुट साथ में सुंदर हो परिवेश।
सुंदर हो परिवेश तनिक भी हो ना हिंसा,
कर दें मिलकर फेल दुश्मनों की सब मंसा।
पूर्वोत्तर को स्वर्ग बनाने को हम आतुर,
क्यों पीछे रह जाय दौड़ में अपना मणिपुर!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त

जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073

E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 26 अंक 155

****

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

6 | संपादकीय
जनसत्ता | 15 सितंबर, 2025

कल्पमेधा

एक सफल व्यक्ति वह है जो अपने ऊपर फेंके गए पत्थरों से अपना आधार बनाता है।

– डेविड ब्रिंकले

प्रदूषण का दायरा

देश के विभिन्न शहरों में बढ़ता प्रदूषण एक गंभीर और जटिल समस्या बनता जा रहा है। हवा, पानी और जमीन में प्रदूषण के जहरीले तत्त्वों के घुलने से मानव जीवन तथा पर्यावरण के लिए खतरा लगातार बढ़ रहा है। इसका असर सांस एवं अन्य तरह की बीमारियों में वृद्धि और कृषि उत्पादन में कमी के रूप में भी देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रदूषण जलवायु परिवर्तन में तेजी का कारण भी बन रहा है, जिससे बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति बढ़ रही है। प्रदूषण बढ़ने के कई कारण हैं, जिनमें पटाखे भी शामिल हैं। देश की राजधानी दिल्ली प्रदूषण को लेकर हमेशा चर्चा में रहती है, जबकि ऐसा नहीं है कि देश के अन्य शहरों में प्रदूषण कम है। दिवाली और दशहरे के मौके पर पटाखे चलाए जाने से दिल्ली समेत देश के कई शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर काफी नीचे गिर जाता है। ऐसे में दिल्ली-एनसीआर में पटाखों के विनियमन की मांग पर सर्वोच्च न्यायालय ने दो टूक कहा कि अगर स्वच्छ हवा राष्ट्रीय राजधानी के 'कुलीन' निवासियों का अधिकार है, तो यह पूरे देश के नागरिकों को भी मिलना चाहिए।

दरअसल, पटाखों से होने वाला प्रदूषण बहुआयामी है। इसमें वायु और ध्वनि प्रदूषण के अलावा मिट्टी और जल प्रदूषण भी शामिल है। पटाखों से होने वाला वायु प्रदूषण विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि इससे निकलने वाले महीन कण (पीएम 2.5 और पीएम 10) फेफड़ों और रक्तप्रवाह में गहराई तक प्रवेश कर जाते हैं, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। पटाखे चलाने के दौरान जहरीली गैसों के अलावा प्लास्टिक के सूक्ष्म कण और कई खतरनाक धातुओं के कण भी निकलते हैं, जो वातावरण और पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही कार्बन डाइआक्साइड जैसी ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन वैश्विक ताप और जलवायु परिवर्तन की गति को बढ़ाने का काम करता है। हमारी सामाजिक सोच अब ऐसी हो गई है कि त्योहार हो, विवाह समारोह हो या कोई अन्य विशेष कार्यक्रम, पटाखों के बिना उसे अधूरा माना जाता है। खुशी और उत्साह में हम यह भूल जाते हैं कि पर्यावरण में जो जहर में हम घोल रहे हैं, वह हमारे जीवन के लिए कितना खतरनाक है।

स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी आइक्यूएअर की हालिया वैश्विक रपट के मुताबिक, भारत विश्व स्तर पर पांचवां सबसे प्रदूषित देश है। दुनिया के बीस सबसे प्रदूषित शहरों में से तेरह भारत में हैं। इनमें असम-मेघालय सीमा पर स्थित बर्नीहाट को विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित शहर के रूप में चिह्नित किया गया है। इसके अलावा, इस सूची में दिल्ली, पंजाब का मुल्लांपुर, राजस्थान का भिवाड़ी और गंगनगर भी शामिल है। इससे साफ है कि प्रदूषण का मसला सिर्फ दिल्ली से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि देश के अन्य शहरों में भी स्थिति गंभीर होती जा रही है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ा कि स्वच्छ हवा का अधिकार पूरे देश के नागरिकों को मिलना चाहिए। इसमें दोराय नहीं कि पटाखों पर चुनिंदा तरीके से प्रतिबंध लगाने से व्यापक रूप ले चुकी इस समस्या से निजात मिलना संभव नहीं है। दिल्ली जैसे शहरों की स्थिति किसी अन्य शहर में पैदा होने का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए इस बात पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि प्रदूषण से निपटने के लिए पटाखों पर प्रतिबंध की अगर कोई नीति बने, तो वह देश भर में लागू होनी चाहिए।

नया अध्याय

एक व्यापक उथल-पुथल और अराजकता के बाद नेपाल अब धीरे-धीरे पटरी पर लौटता दिखने लगा है। 'जेन-जी' कहे वाले युवाओं के हिंसक प्रदर्शनों का सिलसिला अब रुक गया है और पूर्व सरकार के इस्तीफे के बाद नए शासन ने आकार लेना शुरू कर दिया है। मगर इस बीच सबसे ज्यादा फिक्र इस बात को लेकर जताई जा रही है कि क्या नेपाल में लोकतंत्र अपने ठोस रूप में मजबूत हो पाएगा। फिलहाल नेपाल की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश रहीं सुशीला कार्की को वहां की पहली अंतरिम महिला प्रधानमंत्री बनाया गया है। चूंकि नई सरकार का नेतृत्व करने के लिए सुशीला कार्की के नाम पर प्रदर्शनकारी समूहों के बीच आम सहमति बन सकी, इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि जिन मुद्दों पर नेपाल में इतना बड़ा विरोध खड़ा हुआ, सबसे पहले उनके मद्देनजर ही नई सरकार समस्याओं के हल की तलाश करेगी। दरअसल, नेपाल में राजशाही के खात्मे के बाद लोकतंत्र की जो बयार आई थी, उसमें जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के बजाय शासन में भ्रष्टाचार और अन्य वंचनाओं को दूर करने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया गया, जिससे लोगों के भीतर भरोसा पैदा हो पाता। राजनीतिक अस्थिरता में एक तरह की निरंतरता कायम रहने के बीच यह बेवजह नहीं है कि धीरे-धीरे जनता के बीच असंतोष ने जड़ें जमाना शुरू कर दिया।

अब नेपाल एक बार फिर नए दौर से गुजर रहा है और यह देखने की बात होगी कि जिन उम्मीदों के साथ वहां की जनता ने बदलाव की राह तैयार करने के लिए सुशीला कार्की के हाथ में कमान दी है, वे कितनी पूरी हो पाती हैं। एक बड़ी चुनौती भारत के सामने होगी कि पिछले कुछ वर्षों में नेपाल का जैसा रवैया रहा, नाहक प्रतिद्वंद्विता पालने की कोशिश की गई, उसमें वहां नई सरकार के आने के बाद क्या बदलाव आता है। यों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा हासिल करने वाली सुशीला कार्की ने भारत को लेकर जैसी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, उससे नेपाल के साथ भारत के संबंधों के एक नए अध्याय की शुरुआत की उम्मीद की जा सकती है। मगर भारत के लिए यह एक संवेदनशील अवसर है कि वह नेपाल से संबंधों के मामले में अपने हित में नई रणनीति बनाए और उसी लिहाज से कूटनीतिक पहल करे।

सुधारों की राह और चुनौतियां

सरकार अपने प्रयासों से महंगाई पर नियंत्रण पा लेगी और बाजारों में वस्तुओं का सस्ता दौर आ जाएगा, यह उम्मीद अभी विरोधाभास से भरी हुई लगती है। हालांकि सरकार पूंजीगत निवेश के साथ एक ऐसा नया ढांचा बनाने की कोशिश में है, जिससे आत्मनिर्भरता के प्रयासों को बल मिलेगा।

सुरेश सेठ

इस समय यह उम्मीद विरोधाभास से भरी हुई लगती है कि सरकार अपने प्रयासों से महंगाई पर नियंत्रण पा लेगी और बाजारों में वस्तुओं का सस्ता दौर आ जाएगा। विरोधाभास इसलिए कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में बरसात और बाढ़ के कारण जानमाल का व्यापक नुकसान हुआ है और उत्पादित वस्तुएं उचित परिवहन के अभाव में नष्ट हो रही हैं। ऐसे में यह उम्मीद कैसे की जा सकती है कि सरकार की महंगाई नियंत्रण और सस्ते दिन ले आने की परिकल्पना सही साबित होगी। मगर देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार यह कहते हैं कि अमेरिका की ओर से भारत के निर्यात पर भारी शुल्क लगा देने के बावजूद देश में आर्थिक विकास की गति धीमी नहीं होगी या उसी तरह बनी रहेगी। यह भी कहा जाता है कि इस वर्ष की पहली तिमाही में देश के आर्थिक विकास की गति 7.8 फीसद से आठ फीसद तक रही, तो यह एक उम्मीद और राहत भरी बात है। जिस तरह घरेलू निवेशकों का रुख देश के उत्पादन और निवेश को निरुत्साह न होने देने का है, इसी प्रकार सरकार पूंजीगत निवेश के साथ एक ऐसा नया ढांचा बनाने की कोशिश कर रही है, जिससे आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने में मदद मिलेगी।

कल्पना चाहे कितनी भी लुभावनी क्यों न हो, लेकिन यह भी सच है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने वक्तव्यों में भारत के प्रति कभी हां और कभी न की नीति पर चलते हुए पचास फीसद शुल्क को घटाने के लिए फिलहाल तैयार नजर नहीं आते हैं। उनके आर्थिक सलाहकारों के बयान भी यही आ रहे हैं कि भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदकर और उसे परिशोधित करके यूरोप तथा तीसरी दुनिया के देशों को बेचकर इतना लाभ कमाया है कि उस पर दंड स्वरूप यह शुल्क लगना ही चाहिए। मगर भारत सरकार ने अमेरिकी शुल्क से अपने निर्यात उद्योगों को हतोत्साह होने से बचाने के लिए जीएसटी दरों में सुधार के जरिए कर में राहत दी है। अब कर की दो दरें पांच फीसद और अठारह फीसद है। बारह और अट्ठाईस फीसद की कर श्रेणी को खत्म कर दिया गया है। जीएसटी प्रणाली देश में एक जुलाई 2017 को लागू की गई थी। अब आठ साल बाद भले ही इसमें व्यापक सुधार किया गया है, लेकिन इससे निवेश घटने की आशंका भी बनी रहेगी।

सरकार को उम्मीद है कि जीएसटी दरों के कम हो जाने का असर लगभग 400 वस्तुओं पर पड़ेगा। जब कर घटेंगे तो निवेश की प्रतिस्पर्धी ताकतें भी मैदान में आ जाएंगी और इस तरह से निर्यात क्षेत्र में निवेश की कमी से जो असर होगा, वह वस्तुओं के सस्ता हो जाने के कारण नए उत्पादन को बढ़ावा देगा। सरकार को ऐसी हालत में नवउद्यमों से भी बहुत उम्मीदें हैं और माना जा रहा है कि अगर भारत की पहचान उसकी घरेलू दस्तकारी या कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के रूप में सामने आए तो इससे देश में बेरोजगारी की वह जटिल समस्या हल होने लगेगी, जिसे अभी तक अनुकंपा और मुफ्तखोरी की नीति से संतुलित करने का प्रयास किया जा रहा है।

लेकिन कुछ और संभावनाएं भी हैं, जिनको ऐसे वक्त में हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक संभावना तो यही है कि चाहे जीएसटी की दरें कम हो रही हैं, पर क्या इसका असर उन सभी 375 वस्तुओं पर दिखाई देगा, जिनके कर कम हो रहे हैं। या करों की इस कमी को अपने ही उदर में समेटते हुए उत्पादक न तो अपना निवेश या उत्पादन बढ़ाएंगे और न ही रोजगार की नई संभावनाएं पैदा होंगी।

> कल्पना चाहे कितनी भी लुभावनी क्यों न हो, लेकिन यह भी सच है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने वक्तव्यों में भारत के प्रति कभी हां और कभी न की नीति पर चलते हुए पचास फीसद शुल्क को घटाने के लिए तैयार नजर नहीं आते हैं। उनके आर्थिक सलाहकारों के बयान भी यही हैं कि भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदकर और उसे परिशोधित करके यूरोप तथा तीसरी दुनिया के देशों को बेचकर इतना लाभ कमाया है कि उस पर दंड स्वरूप यह शुल्क लगना चाहिए। मगर भारत सरकार ने अमेरिकी शुल्क से अपने निर्यात उद्योगों को हतोत्साह होने से बचाने के लिए जीएसटी दरों में सुधार के जरिए कर में राहत दी है।

ऐसे में अमेरिकी शुल्क का मुकाबला करने के लिए जीएसटी दरों में सुधार का असर एक सीमित स्तर पर ही हो पाएगा।

विशेषज्ञों ने इस संभावना की तहकीकात की है। उनका कहना है कि 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएंगी, लेकिन क्या उसके मुताबिक बाजार में भी सस्ती वस्तुओं का दौर शुरू हो जाएगा। अभी तक देश के बाजारों में ऐसा वातावरण है कि शुरू की रियायतें तो आम जनता को नहीं दी जातीं और कंपनियां उन्हें अपने पूर्व घाटे की भरपाई कहकर ही समेट लेती हैं। इसका बड़ा उदाहरण देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें गिरने के बावजूद इसका लाभ देश की जनता को नहीं मिल पाता है। इसकी कीमतों को लगभग दो साल से उसी स्तर पर स्थिर रखा गया है, क्योंकि पेट्रोलियम कंपनियों का यह कहना था कि अभी तो उन्हें पिछले घाटे की ही भरपाई नहीं हुई। इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि देश के बाजार अपूर्ण भाव से ग्रस्त हैं। इसका अर्थ यह है कि अधिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं की बनावटी मंदी भी पैदा कर दी जाती है।

इस तरह की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर जीएसटी की दरें कम होने के बावजूद संबंधित वस्तुओं की बाजार कीमतें कम नहीं होती हैं, तो इसके लिए उद्योग संगठनों से बातचीत करनी होगी। हालांकि, पिछला अनुभव यही कहता है कि उद्योग संगठन अपनी नीति की परवाह अधिक करते हैं, चाहे वह कृत्रिम कमी का माहौल पैदा करके ही क्यों न हो। एक और संभावना को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और वह है विदेशी व्यापार में हमारी मुद्रा के विनिमय मूल्य का निरंतर कम होते जाना। हालांकि सरकार का कहना है कि ऐसा रुख डालर की कीमतों में ही नजर आएगा। मगर, हमारे निर्यात और आयात के आंकड़े बता रहे हैं कि हम अभी तक अपनी अर्थव्यवस्था का तेवर नहीं बदल सके। हमारी अर्थव्यवस्था निर्यात आधारित नहीं है। अब जब अधिक निर्यात की बात हो रही थी, तो उस पर अमेरिकी शुल्क का प्रहार होता नजर आ रहा है। समस्या यह है कि जब हम अपने देश में अलग-अलग क्षेत्रों के उत्पादन और निवेश को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो पता चलता है कि हम उसके कच्चे माल के लिए अभी भी अन्य देशों पर निर्भर हैं।

हमें इस बात का गर्व है कि हमने पिछले वर्षों में अपने दवा उद्योग को तरक्की दी है और दवाइयों के निर्यात को बढ़ाया है। मगर जब इनके लिए कच्चे माल की ओर देखते हैं, तो पाते हैं कि इसका बहुभाग आयात करने के लिए हमें चीन जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। पिछले दिनों चीन के साथ संबंधों में कटुता के कारण चीनी सामान के बहिष्कार की बात होती रही, लेकिन जब हम आयात-निर्यात का पैमाना देखते हैं तो पाते हैं कि चीन से वस्तुओं का आयात भारत से सामान के निर्यात के मुकाबले कहीं अधिक है। अब हम जब रूस समेत चीन के साथ हाथ मिलाकर एक नई शुरुआत करने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या यह आवश्यक नहीं होगा कि पहले हम भारत को अपना कच्चे माल खुद तैयार करने में आत्मनिर्भर बनाएं। मगर यह आत्मनिर्भरता कब और कैसे होगी, इसी के आधार पर भारत के लिए नई परिस्थितियों का निर्माण संभव हो सकेगा।

संवाद की संवेदना

दुनिया मेरे आगे

अनिता वर्मा

आज समय तेजी से भाग रहा है। किसी के पास किसी को देखने-सुनने या बात करने की फुरसत नहीं दिखती है। सब भागे जा रहे हैं। भौतिकतावादी जीवन शैली के प्रभाव से शायद कोई नहीं बच पाया है। उच्चवर्ग, मध्यमवर्ग, निम्न मध्यम, निम्न वर्ग आर्थिक दृष्टि से जब भी किसी को अवसर मिलता है, सब भागने लगते हैं। शहर हमेशा जागता रहता है। मुश्किल से एक दो घंटे गाड़ियों की रफ्तार थमती होगी। सब अपनी दुनिया में मस्त हैं। सुबह-सुबह अगर चार बजे भी हम उठ जाते हैं, तो देख सकते हैं कि आटो रिक्शा पर सवारियां और सब्जी बेचने वाले अपनी टोकरियां लादे बैठे दिखाई देंगे दोस्त, मित्र, पड़ोसी- सब अपने आप में मगन हो रहे हैं।

ऐसे दृश्य रोज के हैं। लोग केवल एक बात कहते हैं कि समय ही नहीं है। घर से नौकरी, नौकरी से घर। बचा हुआ समय परिवार के लिए। कुछ लोगों को तो यह पता भी नहीं कि पड़ोस में क्या हो रहा है या उनके घर में क्या दिक्कत है। कितना वक्त यों ही गुजर जाता है बिना किसी से इतना भी बोले कि कितना समय हो गया। हालांकि अच्छी जीवन शैली के लिए अर्थ आवश्यक है, मगर मानसिक स्वास्थ्य के लिए सामाजिकता अत्यंत जरूरी है। मनुष्य हमेशा काम नहीं कर सकता। उसे आराम की भी जरूरत होती है। समय सबके पास एक जैसा है। इसलिए त्योहार, मेले, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारिवारिक कार्यक्रम, यात्राएं, तीर्थयात्राएं- सबकी व्यवस्था है। मगर बात यहां संवाद की है। कई बार एक जैसी दिनचर्या से जीवन में नीरसता आ जाती है। हम सबके पास कहने-सुनने को बहुत कुछ होता है। संवाद करने से जो हम कहना चाहते हैं, बातों-बातों में निकलता जाता है। हम भीतर से हल्के होते जाते हैं।

> लोग केवल एक बात कहते हैं कि समय ही नहीं है। घर से नौकरी, नौकरी से घर। बचा हुआ समय परिवार के लिए। कुछ लोगों को तो यह पता भी नहीं कि पड़ोस में क्या हो रहा है या उनके घर में क्या दिक्कत है। कितना वक्त यों ही गुजर जाता है बिना किसी से इतना भी बोले कि कितना समय हो गया।

मनुष्य ने अपने आसपास ऐसा वातावरण निर्मित कर लिया है कि किसी की किसी से बात करने की हिम्मत नहीं होती या मन नहीं होता। जबकि जीवन में सहजता बहुत जरूरी है। जीवन में सब जरूरी है- घर, परिवार, नौकरी, पास-पड़ोस, नहीं तो हम मनुष्य होने का धर्म कैसे निर्वहन करेंगे! केवल अच्छा खाना, होटल, रेस्तरां में, सप्ताहांत पर परिवार और परिजनों के साथ जाना। यही तो जीवन नहीं है। यहां यह तात्पर्य नहीं है कि हम किसी का किसी भी समय जाकर दरवाजा खटखटा दें। सुबह से लेकर शाम तक दस-पांच मिनट जो भी परिचित हो, पडोसी हो, बच्चे-बूढ़े, जिससे जैसे बन पड़े, चेहरे पर अच्छी-सी मुस्कान लेकर केवल इतना ही पूछ लिया जा सकता है कि बाबा कैसे हो... बच्चों आजकल क्या चल रहा है... अम्मा जी आप कैसी हैं! बस फिर डूब जाया जा सकता है कि अपनी दिनचर्या में। मगर वह कुछ मिनट का समय हमारे लिए अतिरिक्त ऊर्जा का काम करता है।

सबके साथ समय प्रबंधन जरूरी है। हम तरोताजा महसूस अवश्य करेंगे। घर-परिवार की जिम्मेदारियां तो उठानी पड़ेगी, पर कभी-कभी यों ही किसी से बिना मतलब भी बातचीत करके हाल पूछ कर देखा जाए। अच्छा लगेगा उसे भी और हमें भी। दिन भर काम के बोझ तले गांभीर्य ओढ़कर जीवन जीना मन और तन दोनों के लिए उचित नहीं है। आज एक बीमारी या कहें, लत ने भी संवादहीनता को जन्म दिया है। छुट्टी या समय मिलते ही लोग घरों में अपना मोबाइल खोल कर लीन हो जाते हैं। घर में जितने सदस्य, उतने मोबाइल। कोई आपस में बात नहीं करता। रील या गेम्स में मशगूल होकर या सोशल मीडिया पर अपनी किसी टिप्पणी या जो भी लोगों को पसंद हो, उसमें मगन रहते हैं। पूर्व में चौपाल पर कहानी, किस्से, बात कहना आदि मनोरंजन के साधन तो थे ही, वहां बच्चे, बूढ़े, युवा आदि सब एकत्र होकर सुनते। उनमें जिज्ञासा पैदा होती थी, प्रश्न पूछते थे। उनमें उत्सुकता का भाव प्रमुख होता था। आज बच्चों का बचपन महत्त्वाकांक्षाओं की भेंट चढ़ रहा है। सब भाग रहे हैं। बच्चे कंधे पर बस्ता टांगे सुबह स्कूल चले जाते हैं। अगर माता-पिता, दोनों कामकाजी हों तो सब सुबह निकल पड़ते हैं और शाम को सब थके-टूटे रहते हैं। मन भर कर संवाद नहीं होता। सब एक निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति कर रहे हैं।

मगर छोटे-छोटे गांव के बीच से होकर आज भी गुजरा जाए तो वहां रोज कुछ बुजुर्ग घर के बाहर चबूतरों पर बैठे आपस में बतियाते दिखाई देते हैं। सर्दी में अलाव तापते बुजुर्ग, युवा हंसते-खिलखिलाते सुबह-शाम दिख जाते हैं। रास्ते में पड़ने वाले किसी दुकान या किसी जगह काम करने वाले परिचित से हो जाते हैं। उनमें से कोई कभी अपनापे के साथ यह पूछ ले सकता है या हम खुद ही उससे पूछ बैठते हैं कि कैसे हैं इन दिनों... गरमी खूब पड़ रही है। यह जवाब आ सकता है कि क्या करें... रोज का यही काम है। कुछ पलों की उस बातचीत से चेहरे पर मुस्कान तैर जा सकती है। अगर हम सिर्फ इतना भी कर लें तो सामने वाला व्यक्ति इस अहसास से खुश हो जा सकता है कि कोई है, जिससे संवाद किया जा सकता है, कोई उसकी सुन सकता है।

सिर्फ इतना भी संवाद के लिए ऊर्जा प्रदान करने वाला होता है। केवल दो बोल कि 'कैसे हो', किसी भी मनुष्य की उदासी, नकारात्मकता, अनमनेपन को दूर कर सकता है। हम जहां प्रतिदिन जाते हैं, कार्य करते हैं, गुजरते हैं तो वहां के परिवेश और लोगों से अवश्य परिचित से हो जाते हैं। सब कुछ पहचाना-सा लगने लगता है। इसलिए हो सके तो घर, परिवार के आसपास मित्रों से, पड़ोस में रिश्तेदारों से परिवार में अन्य लोगों से और कोई बुजुर्ग हैं तो समय निकाल कर उनसे संवाद अवश्य करना चाहिए। सबके पास व्यस्तता है। उन्हीं में से कुछ पल चुराने होते हैं। फिर बिना किसी शक के किसी को भी अच्छा महसूस होगा। थकान और चेहरे की उदासी चंद पलों में गायब हो सकती है।

कसौटी पर नियम

सुप्रीम कोर्ट के हाल के एक निर्णय के तहत सभी बुनियादी शिक्षकों के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है। टेट की अनिवार्यता 2011 से लागू की गई थी, जबकि इससे पहले की नियुक्तियां उस समय के प्रचलित नियमों और योग्यताओं के आधार पर हुई थीं। बेसिक शिक्षा अधिनियम स्पष्ट करता है कि शिक्षक की नियुक्ति उस समय की नियमावली के अनुरूप ही वैध मानी जाएगी। कई शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें बारहवीं और बीटीसी योग्यता पर नियुक्त किया गया था। वे स्नातक नहीं हैं, तो उनके लिए टीईटी परीक्षा देना संभव ही नहीं। इसी प्रकार, अनेक शिक्षक स्नातक व बीटीसी/ बीएड धारक तो हैं, परंतु उनकी नियुक्ति 2011 से पहले की है। ऐसे में नए नियमों को कैसे देखा जाएगा? यह भी कहा गया है कि अगर कोई शिक्षक दो वर्ष के भीतर टीईटी पास नहीं कर सका तो उसे नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा और प्रोन्नति का भी अधिकार नहीं मिलेगा। शिक्षक समाज का मेरुदंड होते हैं। जिन शिक्षकों ने वर्षों तक निष्ठा से बच्चों को शिक्षा दी है, उन्हें अचानक असुरक्षा में धकेलना न्यायसंगत नहीं। यह फैसला पूर्वनियुक्त शिक्षकों की सेवा स्थिरता और बेसिक शिक्षा अधिनियम को कसौटी पर रखता है।

– शकील जावेद, शाहजहांपुर

भ्रम के भरोसे

'चुनौतियों के बीच शिक्षक' (दुनिया मेरे आगे, 6 सितंबर) में वर्णित बातें गंभीर हैं। स्कूलों के अनुपात में शिक्षकों की संख्या की कमी के पीछे मुख्य कारण हैं नीति नियंताओं में शैक्षणिक इच्छाशक्ति में क्रमशः हो रहा क्षरण। सिर्फ प्रक्रियाओं की जटिलता के चलते समय पर शिक्षकों की नियुक्ति जैसे रुक रही है, उससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार संभव नहीं है। नई शिक्षा नीति के गहरे पाठ में अन्य प्रकल्पों पर तो सकारात्मक सूत्र निरुपित किए गए हैं, लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति समय पर हो, इस पर कोई व्यावहारिक नीति नहीं है। कई विद्यालयों में मात्र एक शिक्षक होना शैक्षणिक लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा का प्रमाण है। निजी कोचिंग संस्थाओं के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए सरकारी स्कूलों के पठन पाठन से लेकर शिक्षकों की नियुक्ति में सरकारी उदासीनता मुख्य रूप से जिम्मेदार है। देश की प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं में भी शिक्षकों के स्वीकृत पद खाली हैं। शिक्षा में हमने प्रगति की है, यह अब भी भ्रम है।

– अशोक कुमार, पटना, बिहार

वक्त की जरूरत

भारत में पचास करोड़ से अधिक लोग अभी भी डिजिटल रूप से कटे हुए हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो शारीरिक अक्षमताओं के कारण डिजिटल उपकरणों का उपयोग नहीं कर पाते। इस डिजिटल खाई को पाटना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। आज भी अनेक शिक्षक, राजनेता, मंत्री इससे अनभिज्ञ हैं। जितनी तेजी से दुनिया और हमारा देश बदल रहा है, तकनीक पर निर्भरता बढ़ रही है, उसके मुताबिक डिजिटल साक्षरता केवल एक व्यक्तिगत कौशल नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और राष्ट्रीय आवश्यकता है। यह हमारे देश को सशक्त बनाने, समावेशी विकास को बढ़ावा देने और हर नागरिक को ज्ञान की मुख्यधारा से जोड़ने का एक महत्त्वपूर्ण साधन है। जैसे-जैसे हम इक्कीसवीं सदी में आगे बढ़ रहे हैं, यह स्पष्ट है कि डिजिटल साक्षरता ही वह कुंजी है जो हमें प्रगति, समृद्धि और एक उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाएगी।

– प्रसिद्ध यादव, फुलवारी, पटना

भ्रष्टाचार का रोग

समकालीन भारतीय राजनीति अनेक गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है, जो लोकतंत्र और सामाजिक समरसता पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती हैं। राजनेताओं और नौकरशाहों की रिश्वतखोरी, गबन और भाई-भतीजावाद जैसी गतिविधियों के कारण भ्रष्टाचार जनता के विश्वास को कमजोर करता है और विकास की प्रक्रिया में बाधा डालता है। धार्मिक और वैचारिक ध्रुवीकरण समाज में अस्थिरता और हिंसा को बढ़ावा देता है, जबकि आर्थिक असमानता अमीर और गरीब के बीच गहरी खाई उत्पन्न करती है और लाखों लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति को चुनौती देती है। नौकरशाही की अक्षमताएं और लालफीताशाही कुशल नीति-निर्माण एवं सेवा वितरण में बाधाएं उत्पन्न करती हैं, जबकि लोकलुभावन नेतृत्व अक्सर अल्पकालिक लाभ के लिए दीर्घकालिक नीति निर्धारण को कमजोर कर देता है।

– आशुतोष रंजन, इलाहाबाद विवि, प्रयागराज

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

देशबन्धु

{ संपादकीय }

नई दिल्ली, सोमवार 15 सितम्बर 2025

संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

भारत-पाक मैच, भाजपा का नया प्रयोग

भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच की अनुमति देना मोदी सरकार का एक चालाकी भरा फैसला है। इसके जरिए भाजपा ने देश में एक नया प्रयोग करके देखा है कि जनभावनाओं को नियंत्रित करने की उसकी रणनीतियां, पैंतरें कामयाब हैं या नहीं। सूचना क्रांति के कारण हरेक क्षण में नयी खबर मोबाइल स्क्रीन पर उभरती है। हम एक खबर को ठीक से पढ़ कर उस पर मंथन कर सकें, इससे पहले नयी खबर उसे धकेल कर सामने आ जाती है। टीवी चैनल भी फटाफट वाले अंदाज में 1 मिनट में सौ खबरें सुनाकर दर्शकों को यह अहसास कराते हैं कि अब वो पूरी तरह से बाखबर है। आम नागरिक इस खुशफहमी में अब रहने लगा है कि देश-दुनिया में क्या हो रहा है, इसकी सारी सूचना उसके पास है। हालांकि उसे इतना अवकाश नहीं दिया जा रहा है कि वह खबरों की पुष्टि करे या उसकी पड़ताल कर उसका विश्लेषण कर सके। सत्ता पर बैठे लोग इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं।

भाजपा यह अच्छे से जानती है कि भारत और पाकिस्तान मैच में सबसे अधिक कमाई के मौके होते हैं। भाजपा यह भी अच्छे से जानती है कि जिस पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगाए गए हैं, उसके साथ पहलगाम हमले के बाद मैच खेलने पर देश में सवाल उठेंगे। फिर भी भाजपा ने इस प्रयोग को करने का जोखिम उठाया, क्योंकि उसे पता है कि दोनों ही सूरतों में मुनाफा उसे ही होना है। अगर मोदी सरकार यह कहती कि हम पाकिस्तान के साथ किसी हाल में मैच नहीं खेलेंगे, तो निश्चित तौर पर जनता के बीच उसकी साख बढ़ती। ऑपरेशन सिंदूर में डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर युद्धविराम हुआ और इस पर सरकार की किरकिरी हुई, तो यह एक अच्छा मौका नरेन्द्र मोदी के पास था कि वो अपनी छवि पर लगे दाग मिटा देते। लेकिन क्रिकेट मैच से होने वाली कमाई को देखते हुए मोदी सरकार ने मैच खेलने का फैसला लिया। यहीं उसने एक और प्रयोग किया। जिसके तहत भाजपा नेता अब जनता को यह समझा रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय मैच कभी नहीं खेलेगा, लेकिन एशिया कप में सारी टीमें खेल रही हैं और हम मैच से पीछे हटेंगे तो हमारे प्वाइंट्स कम होंगे। इसलिए मजबूरी में मैच खेलना पड़ रहा है। हालांकि पाकिस्तान को हमने अब भी माफ नहीं किया है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि बापू के अपमान पर प्रज्ञा ठाकुर को वो दिल से माफ नहीं करेंगे लेकिन संसद में प्रज्ञा ठाकुर ने गोडसे की तारीफ की और मोदी अपना दिल ही टटोलते रह गए।

बहरहाल, खबरों के तमाम प्लेटफार्म्स पर अलग-अलग तरीकों से इसी नैरेटिव को आगे बढ़ाया जा रहा है कि मोदी सरकार अब भी पाकिस्तान के खिलाफ है, लेकिन मैच खेलना मजबूरी है। भाजपा जानती है कि जनता का एक बड़ा वर्ग जो मुखर होकर मैच का विरोध कर रहा है, वह भी मौका लगते ही उसका मजा उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। ऐसे लोगों को उलझाने के लिए न्यूज एंकर्स को भी भाजपा ने आगे कर दिया है, जो क्रिकेट खिलाड़ियों को बेहूदे तरीके से चुनौती दे रहे हैं कि इस मैच का बहिष्कार करो, हिम्मत है तो मैदान में मत उतरो। इन एंकर्स में इतनी हिम्मत नहीं है कि वे अमित शाह से सीधा सवाल करें कि आप गृहमंत्री हैं और आपके अधीन आने वाली जांच एजेंसियों की विफलता के कारण पहलगाम हमला हुआ। आपके बेटे जय शाह आईसीसी के चेयरमैन हैं और वो भारत-पाक मैच को रद्द नहीं करवा सके। अगर भारत को एशिया कप खेलना ही था तो टीमों का बंटवारा इस तरह भी हो सकता था कि भारत और पाकिस्तान को एक-दूसरे से खेलने की नौबत न आए, या उनके आपस में न खेलने से किसी को भी प्वाइंट्स का नुकसान न हो। लेकिन जय शाह ऐसा करते तो फिर मैच से होने वाली खरबों की कमाई भी हाथ से निकल जाती। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर की जगह अब भाजपा चर्चा चला रही है कि खून और क्रिकेट साथ में चल सकते हैं, क्योंकि खेल, कला ये सब राजनीति से दूर रहने चाहिए। हालांकि इसी भाजपा सरकार ने पाकिस्तानी कलाकारों फवाद खान और हानिया आमिर की उन फिल्मों का प्रदर्शन रुकवा दिया है, जो भारत में बनी हैं। यू ट्यूब, इंस्टाग्राम आदि पर कई पाकिस्तानी हस्तियों के एकाउंट्स बंद किए गए हैं। अपनी सुविधा से राष्ट्रवाद की परिभाषा और कायदे गढ़ने वाली भाजपा देश में प्रयोग कर रही है कि आखिर जनता को भटकाने में वह कहां तक कामयाब हो सकती है।

भाजपा के लिए सत्ता और कमाई से बढ़कर कुछ नहीं है, यह बात एक बार फिर जाहिर हो चुकी है। भारत और पाकिस्तान के किसी भी मैच में विज्ञापनों, मैच की टिकटों, टीवी पर प्रसारण आदि से प्रत्यक्ष तौर पर सफेद कमाई होती है और सट्टेबाजी में परोक्ष तौर पर कमाई की जाती है। खरबों रूपयों की काली कमाई चंद मिनटों में स्विस बैंक जैसे खातों में पहुंचती है। सट्टेबाजी का यह धंधा राजनैतिक सरपरस्ती और प्रशासनिक सहयोग से चलता है। इसलिए क्रिकेट एसोसिएशन्स में राजनेताओं या उनके रिश्तेदारों को मुखिया बनाया जाता है। यह महज संयोग नहीं है कि नरेन्द्र मोदी के सत्ता में आने के बाद सरकार में दूसरे स्थान पर सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले अमित शाह के बेटे जय शाह पहले बीसीसीआई में रहे और अब आईसीसी में चेयरमैन बने हैं। जो 14 तारीख के मैच से बड़ी कमाई की उम्मीद लगाए बैठा है। नरेन्द्र मोदी ने एक बार सही कहा था कि व्यापार उनके खून में है।

मोदी को जेन जी नेपाल में रंग रोगन करता दिख रहा है सरकार बदलता नहीं दिखा!

राष्ट्रवाद देशभक्ति का पर्याय नहीं हो सकता। देशभक्ति का मतलब है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा। सुप्रीम सेक्रिफाइज मतलब खुद को बलिदान कर देने की भावना। लेकिन राष्ट्रवाद का मतलब है अपने स्वार्थों के लिए दूसरे को तकलीफ देना। परपीड़ा से अपने समर्थकों को सुख का अहसास करना।

सैमुअल जानसन ने ऐसे ही नहीं कहा था कि राष्ट्रवाद दुष्ट की अंतिम शरण स्थली है। जानसन अंग्रेजी के प्रसिद्ध साहित्यकार, आलोचक और अंग्रेजी का पहला शब्दकोश बनाने वालों में थे। उन्हें आधुनिक शब्दकोश का जनक भी कहा जाता है। सैमुअल जानसन ने यह प्रसिद्ध उक्ति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट के संदर्भ में कही थी। जिनके बारे में कहा जाता है कि वे हमेशा श्रेष्ठता का भाव प्रदर्शित करते रहते थे। अपनी कमियों को छुपाने के लिए देशभक्ति का गलत इस्तेमाल करते रहते थे।

यह अठाहरवीं सदी की बात है। वही समय जब दुनिया एक नए दौर में प्रवेश कर रही थी। फ्रांसिसी क्रान्ति का समय जिसने सबसे बड़ा राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन लाया। राजशाही के अंत की शुरूआत हुई। लोकतंत्र की अवधारणा आई और राष्ट्रवाद एवं देशभक्ति में फर्क समझने की शुरूआत हुई।

क्या फर्क है दोनों में? देशभक्ति एक स्वाभाविक सकारात्मक भावना मानी जाती है। अपने देश से प्रेम उसके लिए सम्मान। इसमें यह नहीं कहा जाता कि मेरे आने के बाद देश महान हुआ है। उससे पहले यह शर्मनाक स्थिति में था। मेरे से पहले के प्रधानमंत्रियों ने सब गलत काम किए। मैं जो भी करता हूं सब सही करता हूं।

लद्दाख के गलवान में घुस कर चीन हमारे 20 सैनिकों को शहीद कर जाता है मगर हम कहते हैं कि न कोई घुसा था, न कोई है! पहलगाम में हमारे 26 निर्दोष नागरिकों की पाकिस्तान से आए आतंकवादी हत्या कर देते हैं उसके खिलाफ किए हमारे आपरेशन सिंदूर को अचानक अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप रोक देता है, फिर पचास प्रतिशत टैरिफ भी लगा देता है और हम फिर भी उसे क्लोज फ्रेंड और नेचुरल पार्टनर बताते हुए उसका समर्थन करते रहते हैं। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने को भी तैयार हो जाते हैं मतलब सब करते हैं लेकिन हम महान हैं दोष सारा नेहरू और राहुल गांधी का है। इसे देशभक्ति नहीं कहते।

असली देशभक्ति और राष्ट्रवाद का नारा लगाने में यही फर्क है। राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा उदाहरण हिटलर था। दूसरों में कमियां देखना। और उसके जरिए अपने लोगों में उनके प्रति नफरत पैदा करना। यहुदियों के खिलाफ नफरत फैलाना ही उसका मुख्य उद्देश्य था। और यह श्रृंखला एक ऐसी है कि खत्म नहीं होती। अब यहुदियों के नाम पर बना देश इजराइल यही कर रहा है। नफरत का यह सिलसिला वे जारी रखे हुए हैं जो इसके सबसे बड़े शिकार रहे। आज इजराइल

शकील अख्तर

> अखिलेश यादव ने बड़ी चेतावनी दी है। समझने की जरूरत है। देश का युवा निराशा में है। महंगी पढ़ाई लिखाई के बाद भी कोई काम नहीं। आपको बताते हैं एमबीबीएस करने के बाद डाक्टर प्राइवेट नर्सिंग होमों में तीस चालीस हजार रुपए महीने की नौकरी करने पर मजबूर हैं। उनके जाब की कोई नीति नहीं। दूसरी तरफ गांवों में डाक्टर नहीं। सरकारी हेल्थ सिस्टम पूरी तरह खत्म हो गया है। सब कुछ प्राइवेट हाथों में।

दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी देश बना हुआ है। भारी हिचकिचाहट और इधर उधर जाने के बाद मोदी सरकार को भी अभी यूएन में इजराइल के खिलाफ वोट करना पड़ा। नहीं तो अभी तो भारत में वे किसी को फिलिस्तीन का नाम लेने पर जेल भेज रहे थे। लेकिन गलत रास्ते पर हमेशा चलते रहना नहीं हो सकता। मोदी सरकार को चीन और रूस के साथ फिलिस्तिन के साथ आना पड़ा। यह विदेश नीति में देश के हितों के अनुरूप सोचकर किया गया फैसला था, जो देशभक्ति के अंतर्गत आता है। राष्ट्रवाद में फिलिस्तीन का नाम लेने पर उसका झंडा देख लेने पर गिरफ्तारी की जाती है। क्योंकि इससे राजनीतिक लाभ होने की उम्मीद होती है।

राष्ट्रवाद ऐसी ही विचारधारा है। जिसे अकेले अलग से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। बल्कि देशभक्ति की आड़ में ही इसे सामने लाया जाता है। जिसे ढाई सौ साल पहले सैमुअल जानसन ने पहचान लिया था। इस पर गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की उक्ति बहुत सटीक है। उन्होंने कहा था राष्ट्रवाद किसी फोड़े को श्रृंगार करके पेश करने जैसा है। इसका मतलब अपनी कमियों को छुपाकर उन्हें भी रंग रोगन के साथ पेश कर देना। जैसा आजकल गोदी मीडिया से करवाया जा रहा है। वह बेरोजगारी की समस्या को ऐसे पेश करता है कि योग्य उम्मीदवार मिलते ही नहीं हैं। लद्दाख और अरुणाचल के बड़े इलाके पर चीन के कब्जे के बाद तो उसने राजनीतिक नेतृत्व को बचाने के लिए सारा दोष सेना पर डाल दिया था कि सीमाओं पर उन्हें रोकने के लिए प्रधानमंत्री थोड़ी आते।

बातें बड़ी बड़ी करके असली मुद्दों को दबाया जाता है। दो साल से ज्यादा हो गया मणिपुर नहीं गए। मगर अब जब कुछ दूसरे मुद्दे तेजी से उभरने लगे तो वहां जाकर मणिपुर को भारत के मुकुट का रत्न बताकर समझ रहे हैं कि बहुत बड़ी बात बोल दी। नेपाल के युवाओं की तारीफ कर दी कि वह वहां रंग रोगन कर रहा है। यह भूलने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने वहां सरकार बदल दी!

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहुत हिम्मत के साथ सही सवाल किया है कि भारत में भी अगर बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं की गई तो यहां भी नेपाल जैसी हालत हो सकती है। सारे राजनीतिक नेता यह बोलने से बच रहे हैं। मीडिया के तो बेरोजगारी का सवाल उठाने का सवाल ही नहीं। वह तो पकौड़े तल कर बेचने का प्रोग्राम बनाकर बताता है कि इस में कितना मुनाफा है। और अगर नाले के पास बनाए जाएं, तो वहां की गैस से चाय भी बना कर साथ में दी जा सकती है। मगर यह इतने लकीर के फकीर हैं कि बिल्ली के बाहर जाने के लिए एक छेद और उसके बच्चे के बाहर जाने के लिए दूसरा छेद ही बनाने की सलाह अभी तक दे रहे हैं। केवल चाय नाले के गैस से बनाने की बात करते हैं। पकौड़े नहीं। मतलब चाय उस आग से बन जाएगी, पकौड़े नहीं बन पाएंगे! क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो केवल नाले के गैस से चाय बनाने की बात कही है। प्रधानमंत्री जी कह दीजिए कि पकौड़े भी बन जाएंगे तो एक नया और बढ़िया पैकेज टीवी वालों के लिए तैयार हो जाएगा।

देश की आम जनता के मानसिक स्तर को नीचे ले जाने का काम हो रहा है। देशभक्ति में उपर ले जाया जाता है। पिछले 11 साल में आप देख रहे हैं सिवाय नफरत और विभाजन के लोगों के मन में कुछ और नहीं भरा। नतीजा यह हुआ कि आज भयानक बेरोजगारी के बाद भी कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं।

अखिलेश यादव ने बड़ी चेतावनी दी है। समझने की जरूरत है। देश का युवा निराशा में है। महंगी पढ़ाई लिखाई के बाद भी कोई काम नहीं। आपको बताते हैं एमबीबीएस करने के बाद डाक्टर प्राइवेट नर्सिंग होमों में तीस चालीस हजार रुपए महीने की नौकरी करने पर मजबूर हैं। उनके जाब की कोई नीति नहीं। दूसरी तरफ गांवों में डाक्टर नहीं। सरकारी हेल्थ सिस्टम पूरी तरह खत्म हो गया है। सब कुछ प्राइवेट हाथों में।

सोचिए जब देश में सबसे ज्यादा सामाजिक प्रतिष्ठा की डिग्री पाने वालों का यह हाल है तो बाकी डिग्री वालों का क्या होगा।

पहले पढ़ाई सरकारी थी। स्वास्थ्य सुविधाएं सरकारी थीं। मुफ्त। मगर अब सब कुछ उन प्राइवेट हाथों में जो बातें बड़ी बड़ी करने में नेताओं का मुकाबला कर रहे हैं। अभी अडानी ने अपने खिलाफ लिखने पर दिल्ली के एक कोर्ट में क्या कहकर स्टे लिया कि उसके खिलाफ लिखना देश का विरोध करना है। भाजपा, गोदी मीडिया भी यही कहता है कि मोदी सरकार के खिलाफ मतलब देश के खिलाफ!

युवा का नौकरी मांगना भी देश के खिलाफ है! युवा जिसे आज जेन जी कहा जा रहा है क्या करे?

बहुत सारे वास्तविक सवाल हैं। जवाब सब राष्ट्रवाद की अवास्तविक बातों में लिपटे हुए। फ्रांसिसी क्रान्ति से लेकर हिटलर और नेपाल सब यह समझते कि उनके खिलाफ नहीं होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं!

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार है)

प्रतिबंध और आजीविका संबंधी चिंताओं में संतुलन बनाना समय की मांग

■ **डॉ. ज्ञान पाठक**

2025 की दिवाली थोड़ी अलग हो सकती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी-अभी पटाखों पर प्रतिबंध के लिए अखिल भारतीय नीति बनाने का आह्वान किया है, साथ ही आश्वासन दिया है कि वह 22 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई में आजीविका संबंधी चिंताओं पर भी सुनवाई करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को प्रतिबंध पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश भी जारी किए हैं और केंद्र से राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) के परामर्श से स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। सर्वोच्च न्यायालय का आह्वान स्वागत योग्य है, लेकिन पटाखों पर प्रतिबंध और आजीविका संबंधी चिंताओं के बीच संतुलन बनाने की स्पष्ट आवश्यकता है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी आरगवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने 12 सितंबर, 2025 को पटाखा निर्माताओं द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, जिनमें दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री और निर्माण पर एक साल से चल रहे प्रतिबंध का विरोध किया गया था, पटाखों पर केवल एनसीआर में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया। सीजेआई ने कहा, 'अगर पटाखों पर प्रतिबंध लगाना है, तो पूरे देश में लगाया जाना चाहिए।'

सीजेआई गवई ने कहा, 'अगर एनसीआर के शहरों को स्वच्छ हवा का अधिकार है, तो दूसरे शहरों के लोगों को क्यों नहीं? जो भी नीति होनी चाहिए, वह अखिल भारतीय स्तर पर होनी चाहिए। हम केवल दिल्ली के लिए नीति नहीं बना सकते क्योंकि वे देश के कुलीन नागरिक हैं। मैं पिछले साल सर्दियों में अमृतसर गया था, और वहां प्रदूषण और भी बदतर था।'

> अदालत ने इस बिंदु पर सहमति व्यक्त की और कहा, 'जब हम श्रमिकों पर प्रतिबंध लगाते हैं, तो वे बिना काम के रह जाते हैं। इसका खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ता है।' इसके बाद न्यायालय अगली सुनवाई पर मामले की जांच करने के लिए सहमत हो गया। केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी ने भी कहा कि हरित पटाखों पर कोई भी सूत्रीकरण विशेषज्ञों के परामर्श से किया जाता है, और वे नीरी द्वारा किए गए नवीनतम शोध उपलब्ध कराएंगे।

आवेदनों पर नोटिस जारी करते हुए, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन ने कहा, 'अगर एनसीआर के नागरिक प्रदूषण मुक्त हवा के हकदार हैं, तो दूसरे शहरों के लोगों के लिए ऐसा क्यों नहीं है।' याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इस उद्योग पर निर्भर कई परिवारों की आजीविका का मुद्दा भी है।

अदालत में यह उल्लेख किया गया कि 3 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम आदेश पर, शीर्ष अदालत ने अपने प्रतिबंध में बदलाव करने से इनकार कर दिया है, और यहां तक कि उनके द्वारा तैयार किए गए हरित पटाखों के फॉर्मूलेशन पर भी केंद्र और विशेषज्ञ संस्था नीरी ने विचार नहीं किया है।

याचिकाकर्ता पटाखा व्यापारी, एसोसिएशन ऑफ फायर वर्क ट्रेडर्स, इंडिककलेक्टिव एंड हरियाणा फायर वर्क मैन्युफैक्चरर्स ने बताया था कि शीर्ष अदालत द्वारा पारित आदेश के कारण, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं, जबकि यह 2027-28 तक वैध है।

न्यायमित्र के रूप में न्यायालय की सहायता कर रही वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने न्यायालय को बताया कि जब दिल्ली में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध सहित आपातकालीन उपायों का प्रस्ताव रखा गया था, तब भी न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया था कि काम के नुकसान से प्रभावित श्रमिकों को मुआवज़ा दिया जाए।

अदालत ने इस बिंदु पर सहमति व्यक्त की और कहा, 'जब हम श्रमिकों पर प्रतिबंध लगाते हैं, तो वे बिना काम के रह जाते हैं। इसका खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ता है।' इसके बाद न्यायालय अगली सुनवाई पर मामले की जांच करने के लिए सहमत हो गया। केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी ने भी कहा कि हरित पटाखों पर कोई भी सूत्रीकरण विशेषज्ञों के परामर्श से किया जाता है, और वे नीरी द्वारा किए गए नवीनतम शोध उपलब्ध कराएंगे।

गौरतलब है कि पिछली दिवाली 2024 के दौरान देश के कई राज्यों ने पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिनमें न केवल दिल्ली-एनसीआर, बल्कि बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल भी शामिल थे। कई शहरों में पटाखों की अलग-अलग विशिष्टताओं के साथ प्रतिबंध लगाए गए थे।

फिर भी, आजीविका और प्रतिबंध के बीच संतुलन बनाना आसान काम नहीं होगा। पटाखे, खासकर दिवाली और अन्य त्योहारों के आसपास, वायु और ध्वनि प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसी संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न राज्य सरकारों ने प्रतिबंध लगाए हैं, कभी पूर्ण प्रतिबंध, तो कभी आंशिक प्रतिबंध, जिसमें केवल हरित पटाखों की अनुमति देना भी शामिल है। समस्या यह है कि ये प्रतिबंध अक्सर अस्थायी होते हैं, कभी असंगत, और प्रवर्तन में मिला-जुला रवैया होता है, जिससे व्यवसायों और उपभोक्ताओं के बीच भ्रम की स्थिति पैदा होती है।

प्रतिबंध का असर श्रमिकों और निर्माताओं पर भी पड़ता है। भारत का पटाखा केंद्र, तमिलनाडु में शिवकाशी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 4 लाख श्रमिकों को रोजगार देता है। श्रमिक मुख्यत: दिहाड़ी मजदूर हैं और उनके पास वैकल्पिक रोजगार के सीमित अवसर हैं। बार-बार प्रतिबंध लगाने से अनिश्चितता, उत्पादन में कमी, नौकरियों का नुकसान और वेतन में कटौती जैसी समस्याएं पैदा होती हैं।

देश भर में लाखों खुदरा विक्रेता और छोटे व्यवसाय भी दिवाली की बिक्री पर निर्भर हैं। अचानक प्रतिबंध या पाबंदियों से भंडार में नुकसान होता है, क्योंकि नमी और मान्य अवधि समाप्ति तिथि के कारण पटाखों को आसानी से दोबारा नहीं बेचा जा सकता। वे कम मुनाफे पर काम करते हैं और उनके लिए नुकसान विनाशकारी साबित होता है।

मुद्रण, पैकेजिंग, परिवहन और कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता जैसे सहायक उद्योग भी प्रभावित होते हैं। इसके अलावा, जब बिना किसी विकल्प के प्रतिबंध लागू किए जाते हैं, तो पटाखों की अवैध बिक्री बढ़ जाती है।

इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय को इस समस्या का कोई संभावित समाधान निकालना होगा, शायद प्रतिबंध और आजीविका के बीच संतुलन बनाने का कोई मध्य मार्ग, क्योंकि दोनों ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

संभावित समाधान हो सकता है कि सीएसआईआर-नीरी द्वारा विकसित हरित पटाखों को समझदारी से अनुमति दी जाए, जिससे प्रदूषण कम होता है। लेकिन ये अभी भी विवादास्पद हैं, और कुछ राज्यों को उनकी सुरक्षा और प्रभावशीलता पर संदेह है। चरणबद्ध तरीके से बदलाव एक और कदम हो सकता है, जिसके तहत आजीविका खोने वाले श्रमिकों के लिए पुन: कौशल कार्यक्रम के साथ-साथ क्रमिक प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। श्रमिकों के लिए मुआवजे और सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों के साथ-साथ अखिल भारतीय व्यापक नीति पर स्पष्टता आवश्यक है।

ललित सुरजन की कलम से

लाहौर : गुलाबी पगड़ी, शाकाहारी दावत

'प्रधानमंत्री मोदी को यह समझ आ रहा है कि पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारना देश की शांति और सुरक्षा के लिए पहली शर्त है। वे अगर विवादों और लंबित प्रश्नों को सुलझा पाए तो अपना नाम इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा लेने के अधिकारी हो जाएंगे। देश के हर प्रधानमंत्री ने इस दिशा में भरसक प्रयत्न किए हैं, किन्तु कहीं न कहीं जाकर बात टूटते गई। आज वैश्विक राजनीति में आर्थिक मुद्दे पहले से कहीं ज्यादा प्रभावी हो गए हैं, वित्तीय पूंजी का दखल बढ़ गया है, कार्पोरेट घराने राजनीति के माध्यम से अपना वर्चस्व बढ़ाने में लगे हैं। इन घरानों ने श्री मोदी से बहुत आशाएं बांध रखी हैं। वे अगर पाकिस्तान में नवाज शरीफ के साथ-साथ वहां के सैन्यतंत्र के साथ पटरी बैठा सके तो भारत-पाक मैत्री के रास्ते की बाधाएं दूर हो सकती हैं। इस दिशा में एक बड़ी अड़चन भारत में संघ के मनोगत को लेकर है। राम माधव का बयान इस ओर इशारा करता है। हम प्रतीक्षा करेंगे कि नए वर्ष में यह भेंट क्या रंग लाती है।'

(देशबन्धु में 31 दिसंबर 2015 को प्रकाशित)

https://lalitsurjan.blogspot.com/2015/12/blog-post_30.html

गुरवाणी विचार

सोरठ महला 5

सरब सुरवां का दाता सतगुरू तांकी सरणी पाइओ।
दरसन मेहत होत अनंदा दूख गइआ हरि जाइओ।
हर रस पीवहो भाई।
नाम जपहि नामो आराध गुरू पूरी की सरपाई (रहाओ)
तिपति परापत जिस धुरि लिखिआ सोई पूरन भाई।
नानक की बेनती प्रभु जी नमि रहा लिव लाई।

गुरवाणी की यह पंक्तियां सोरठ राग से ली गई है जो श्री गुरू ग्रंथ साहिब के 730 अंग पर सुशोभित है। इन पंक्तियों द्वारा पांचवे नानक श्री गुरू अर्जुन देव जी मानव मन को समझाईश देते हुए फरमा रहे हैं कि इस पूरे संसार को सुख देने वाला केवल एक प्रभु परमात्मा है। क्या भिखारी क्या व्यापार, क्या नेता, क्या राजा सब को सुख प्राप्ति हेतु उसी प्रमात्मा की याचना करना पड़ता है इसलिय हर इंसान को उस प्रभु परमात्मा को शरण में जाना चाहिये। प्रभु परमात्मा की सिमरन भक्ति के बिना सुख कहां मिलने वाला है।

सुख नाही बहुता धन खोट सुख नाही पेखत नृत नोट।
सुख नाहि बहु देश भरमाये सरब सुख प्रभु हरि हरि गाये।

हर आदमी सोचना है कि धन अधिक संचय कर लेने से सुख प्राप्त किया जा सकता है। नाटक चेटक देखने में सुख प्राप्त किया जा सकता है या देश विदेश घूमने से सुख मिल जावेगा यह उसका वहम हे क्योंकि उसी त्रिशना कभी खतम नहीं होती इसलिए जब तक वह प्रभू सिमरन में मन नहीं लगाता तब तक उसको शांति मिलने वाली नहीं है इंसान अगर टूटी फूटी झोपड़ी में भी रह रहा हो तो इमानदारी से अपना कार्य बिहार करते हुए प्रभु सिमरन में मन रमाये रखता है तो सह एक राजा से भी ज्यादा सुखी हो जाता है इसलिये हर इंसान को चाहिये कि वह प्रभु द्वारा दिये गये प्रत्येक शंवास को प्रभु भक्ति में लगा देवे।

सासि सास सिमरओ गोविंद-मन अंतरि की उतरे चिंद

इसीलिये गुरवाणी द्वारा हमें बार-बार यह समझाया गया है जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। इसलिये हमें ऐसी साध संगत में जाना चाहिए जहां केवल प्रभु नाम की कथा कीर्तन होती हो पर हमारे बड़े अच्छे भाग हो तभी हमें ऐसी साध संगत प्राप्त हो पाती है।

बिन भागां सतसंग न लमै।
बिन संगत मैल मरीजै जीओ।

साध संगत में जाने पर प्रभु नाम सिमरन कथा कीर्तन सुनते रहने पर धीरे-धीरे हमारा मन भी प्रभु भक्ति में जुड़ जायेगा इसलिये हम हर वक्त प्रभु परमात्मा से विनती करते रहे।

तुम करो दया मेरे साईं।
ऐसी मति दीजे मेरे ठाकुर सदा-सदा तुझ धिआई।

प्रतिदिन ऐसी अरदास करते रहने पर कभी न कभी प्रभु कीकृपा दृष्टि हो जी जावेगी।

करन करावन हरि अंतरि यामी जन अपने की राखै।
जै जै कार हो जग भीतर शब्द गुरू रस चाखे।

हमारा मानव जीवन पान तभी सार्थक माना जावेगा जब हम प्रभु परमात्मा की भक्ति कर उसी प्राप्ति कर लेवें।

-इंदर सिंह आहूजा

आपके पत्र

एक दिवस में क्यों बंधे, हिन्दी का अभियान

हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन हमें यह सोचने का अवसर देता है कि हिंदी का स्थान आज हमारे समाज, शिक्षा, साहित्य और तकनीक में कहां है। लेकिन एक सवाल हमेशा उठता है-क्या किसी भाषा का सम्मान केवल एक दिन मनाने तक ही सीमित रह जाना चाहिए? भाषा तो जीवन की धारा है, वह हर दिन, हर पल हमारे साथ बहती है। इसीलिए यह दोहा हमें झकझोरता है कि हिंदी का अभियान किसी दिवस में क्यों बंधे? हिंदी को तो भारतवासियों की सांसों में रचा-बसा रहना चाहिए।

हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की पहचान और आत्मा है। यह भाषा हमें जोड़ती है, हमारी संस्कृति को अभिव्यक्त करती है और देश की विविधता में एकता का सूत्र बनाती है। अंग्रेज़ी, विज्ञान और तकनीक की भाषा हो सकती है, लेकिन हिंदी हमारे हृदय की भाषा है। इसे केवल भाषणों, आयोजनों और सरकारी औपचारिकताओं में सीमित कर देना इसके महत्व को छोटा करना है।

आज के दौर में यह और भी आवश्यक हो गया है कि हम हिंदी को एक दिवस तक सीमित न रखें। अंग्रेज़ी का प्रभुत्व इतना बढ़ गया है कि लोग यह मानने लगे हैं कि सफलता की गारंटी केवल अंग्रेज़ी सीखने से मिलती है। अभिभावक अपने बच्चों को अंग्रेज़ी माध्यम स्कूलों में भेजने को ही भविष्य की सुरक्षा मानते हैं। लेकिन यह एक गहरी भ्रांति है। दुनिया के जिन देशों ने प्रगति की है-जापान, कोरिया, चीन, जर्मनी-उन्होंने अपनी मातृभाषाओं को शिक्षा और विकास का आधार बनाया है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां अपनी ही भाषा को हीन दृष्टि से देखा जाता है। यह मानसिकता बदलनी होगी।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) ने इस सोच को सुधारने का प्रयास किया है। इसमें प्रावधान है कि कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय भाषा हो। इसका सीधा अर्थ है कि हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। इससे बच्चों की समझ और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जब शिक्षा अपनी भाषा में होगी तो बच्चे बोझ महसूस नहीं करेंगे और पढ़ाई को आनंदपूर्वक आगे बढ़ाएंगे। इस नीति को सही मायनों में लागू करना हिंदी के अभियान को निरंतरता देगा।

हिंदी दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में अक्सर बड़े-बड़े नारे लगाए जाते हैं, भाषण दिए जाते हैं और हिंदी के गौरव का बखान होता है। लेकिन समस्या यह है कि यह सब अगले ही दिन ठंडा पड़ जाता है। हमें यह तय करना होगा कि हिंदी का उपयोग रोज़मर्रा की जिंदगी में कैसे बढ़ाया जाए। दफ्तरों में, अदालतों में, तकनीकी संस्थानों में, यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी हिंदी का स्थान और सशक्त होना चाहिए। केवल मंच पर हिंदी का गुणगान करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसे व्यवहारिक जीवन में उतारना होगा।

आज हिंदी इंटरनेट की दुनिया में तेजी से फैल रही है। आंकड़े बताते हैं कि हिंदी कंटेंट उपभोक्ताओं की संख्या अंग्रेज़ी से कहीं अधिक तेज़ी से बढ़ रही है। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब जैसी कंपनियाँ हिंदी में विशेष रूप से सामग्री उपलब्ध करा रही हैं। इसका अर्थ है कि हिंदी की संभावनाएँ अपार हैं। हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और हिंदी को आधुनिकता से जोड़ना चाहिए। हिंदी में विज्ञान, तकनीक, प्रबंधन और कानून की शब्दावली विकसित कर इसे समकालीन जरूरतों के अनुरूप बनाना होगा।

जब हिंदी का अभियान किसी एक दिवस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समाज के हर क्षेत्र में रच-बस जाएगा, तभी यह भाषा सचमुच हिंदुस्तान की आत्मा बन पाएगी।

- डॉ प्रियंका सौरभ

https://t.me/AllNewsPaperPaid

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770

ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

चिंतन

अपने बयानों से बार-बार फजीहत करवा रहे ट्रंप

दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कह दें, कब क्या कर दें, कोई समझ ही नहीं सकता। अपने बेतुके बयानों और फैसलों से अपनी तो फजीहत करा ही रहे हैं, दुनियाभर को भी उलझन में डाले हुए हैं। उनके जो मन में आए, वह करने को स्वतंत्र हैं, लेकिन यदि वे यह समझ रहे हैं कि भारत, रूस, चीन समेत दुनिया के अन्य देश उनकी दादागीरी के आगे झुक जाएंगे तो इसकी संभावना दूर-दूर तक नजर नहीं आ रही है। क्योंकि भारत समेत अनेक देशों ने उन्हें जवाब देना शुरू कर दिया है। उनका अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है। यह भी दिख रहा है कि वे कुंठा से ग्रस्त होकर विवेक खो रहे हैं। दुनिया को भी एक कुंठित-अहंकारी अमेरिकी राष्ट्रपति के अहं को तुष्ट करने के बजाय उसका सामना साहस और संयम से करने के लिए कमर कस लेनी चाहिए। ट्रंप दुनियाभर के देशों को रूस से व्यापार न करने की धमकी दे रहे हैं। इसी कारण भारत पर अमेरिका ने 50 फीसदी टैरिफ लगाया है, लेकिन यूरोपीय संघ का वर्ष 2024 में रूस के साथ 67.5 अरब यूरो का द्विपक्षीय कारोबार था। यह भारत के रूस से कुल कारोबार से ज्यादा रहा है। यूरोप और रूस में अभी भी उर्वरक, खनन उत्पादों, रसायन, लोहा व इस्पात आदि का कारोबार हो रहा है। जहां तक अमेरिका की बात है तो वह अभी भी रूस से यूरेनियम की खरीद कर रहा है। अपने इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए रूस से पैलेडियम खरीद रहा है। ट्रंप इस पर कभी बात नहीं करते। अब उन्होंने एक बार फिर टैरिफ का राग छेड़ा है। ट्रंप ने शनिवार को कहा कि नाटो देश रूस से तेल खरीदना बंद कर दें। साथ ही चीन पर रूस से तेल खरीद के लिए 50 से 100 फीसदी तक टैरिफ लगाया जाए। ऐसा होने पर रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म होने का रास्ता बन सकता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में नाटो देशों और चीन की बात की लेकिन भारत का नाम नहीं लिया। ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट में लिखा, 'नाटो की जीत के लिए प्रतिबद्धता अब तक 100 फीसदी से काफी कम रही है। कुछ देशों की रूसी तेल की खरीद चौंकाने वाली है। इससे रूस के साथ आपकी समझौते की पोजीशन और बार्गेनिंग पावर कमजोर होती है। मैं प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हूं, जब नाटो देश तेल खरीद रोकने के लिए तैयार हों तो बताएं'। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के अनुसार, 2023 से नाटो सदस्य तुर्की, चीन और भारत के बाद रूसी तेल का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार रहा है। रूसी तेल खरीदने में शामिल 32 देशों के गठबंधन के अन्य सदस्यों में हंगरी और स्लोवाकिया भी शामिल हैं। इन देशों की ओर से ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया नहीं आई है। उन्होंने भारत पर चुप्पी साधते हुए चीन पर भारी टैरिफ 100 फीसदी तक का प्रस्ताव दिया है। ये वही ट्रंप हैं, जो कुछ दिनों पहले तक चीन पर किसी प्रकार का अतिरिक्त टैरिफ लगाने से इनकार कर रहे थे। असल में रूस-युक्रेन युद्ध रुकवाने में अब तक असफलता और टैरिफ लगाने के बाद भारत को न झुका पाने के कारण ट्रंप हताश हो रहे हैं। उन्हें लगता था कि वे धमकी देकर किसी को भी झुका सकते हैं, लेकिन भारत ने उनके दबाव को मानने से साफ इनकार कर दिया। एससीओ समिट ने ट्रंप के जख्म पर नमक डालने का काम किया। जहां भारत, रूस और चीन के मधुर होते संबंधों ने उन्हें तनाव में ला दिया है। वे कभी भारत को निशाने पर ले रहे हैं तो कभी चीन को। अगर ट्रंप युद्ध रुकवाना चाहते हैं तो उन्हें टैरिफ की बजाए कूटनीति पर भरोसा करना होगा। जो न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा।

पर्यावरण

ज्ञानेन्द्र रावत

दुनियाभर में जंगलों की तबाही का मंडराया खतरा

दुनिया में आज जलवायु परिवर्तन से मुकाबले की दिशा में पेड़ और जंगलों की महत्ता की चर्चा जोरों पर है। इसका अहम कारण जलवायु परिवर्तन के कारण समूची दुनिया में संतुलित और समग्र विकास के लक्ष्य का लगातार भीषण चुनौती बनकर सामने आना है। दुनिया में जिस तेजी से पेड़ों की तादाद कम होती जा रही है, उससे पर्यावरण तो प्रभावित हो ही रहा है, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, कृषि और मानवीय जीवन ही नहीं, बल्कि भूमि की दीर्घकालिक स्थिरता पर भी भीषण खतरा पैदा हो गया है। जहां तक जंगलों के खत्म होने की गति का सवाल है,उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि वह दिन दूर नहीं जब दुनिया से जंगलों का नामोनिशान तक मिट जायेगा और वह किताबों की वस्तु बनकर रह जायेंगे। हकीकत में हर साल दुनिया में एक करोड़ हेक्टेयर जंगल लुप्त होते जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र भी इसकी पुष्टि करता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया में कीडे-मकोडे भी 3.5 करोड़ हैक्टेयर जंगल हर साल बर्बाद कर रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि इंसान तो क्या दूसरे जीव भी जीवन के लिए जरूरी पेड़ों-जंगलों के दुश्मन बनते जा रहे हैं। यदि देश की बात करें तो अकेले उत्तराखंड में बीते 8-9 बरसों के दौरान ढाई लाख से ज्यादा पेड़ काट दिये गये हैं। इनमें एक लाख से ज्यादा पेड़ आल वैदर रोड के नाम पर और शेष पर्यटन, देहरादून से लेकर दिल्ली तक सड़क चौडीक़रण, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना व सुरंग आधारित परियोजनाओं आदि के नाम पर देवदार, बांज, राई, कैल जैसी दुर्लभ प्रजातियों के पेड़ों का अस्तित्व ही मिटा दिया गया है। पिछले बीस सालों के दौरान 40,000 हेक्टेयर जंगल आग की समाधि बने हैं जिसमें लाखों पेड़ जलकर राख हो गये हैं। विकास के नाम पर पेड़ों के अंधाधुंध कटान का सिलसिला पूरे देश में जारी है। पहाड़ दुनिया के 85 फीसदी से ज्यादा पक्षियों, स्तनधारियों और उभयचरों के आश्रय स्थल हैं। इस बारे में एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप का जायजा लें तो पाते हैं कि पहाड़ी जंगलों के खात्मे की दर में एशिया 39.8 मिलियन हैक्टेयर वन नुकसान के मामले में सर्वोपरि है। गौरतलब है कि हर साल जितना जंगल खत्म हो रहा है, वह एक लाख तीन हजार वर्ग किलोमीटर में फैले देश जर्मनी, नार्डिक देश आइसलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड जैसे देशों के क्षेत्रफल के बराबर है। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात यह है कि इसके अनुपात में नये जंगल लगाने की गति बेहद धीमी है। लंदन के थिंक टैंक एनर्जी ट्रांसमिशन कमीशन की मानें तो समूची दुनिया में हर मिनट औसतन दस फुटबाल मैदान के बराबर यानी 17.60 एकड़ जंगल काटे जा रहे हैं। बीते 30 सालों में 42 करोड़ हैक्टेयर जंगल को मैदान बना दिया गया है। बढ़ते तापमान, भयावह सूखा, वनों की अंधाधुंध कटाई और जंगलों में आग की बढ़ती घटनाओं के चलते अमेजन के जंगल खतरे के दायरे में हैं। हकीकत में अब अमेजन के लिए 'रेड अलर्ट' का ऐलान करने का समय आ गया है। इसमें जलवायु परिवर्तन के चलते पड़ने वाले सूखा और गर्मी व आग सहित बहुतेरे कारकों की बड़ी भूमिका है। जंगलों के खात्मे में आग भी एक अहम कारक है जिसके चलते दुनिया में हर साल लाखों हैक्टेयर जंगल आग की भेंट चढ़ जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अमेजन वनों का लगभग आधा हिस्सा 2050 तक खत्म हो जाएगा। 1990-2020 के बीच के तीस वर्षों में 42 करोड़ हैक्टेयर जंगलों का खात्मा हुआ है। यदि मैरीलैंड यूनीवर्सिटी और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के ग्लोबल वाच की हालिया रिपोर्ट की मानें तो भारत में 2023 के दौरान 21,672 हैक्टेयर जंगल खत्म हो गये। देश में 2022 में 21,839 हैक्टेयर जंगलों का खात्मा हुआ। इसमें भारत देश के पांच राज्यों यथा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर हैं जहां देश में आग से सबसे ज्यादा जंगल तबाह हुए हैं और यह सिलसिला आज भी जारी है। जैव विविधता को संरक्षित करने में वन की उपयोगिता जगजाहिर है लेकिन विडम्बना है कि हम उन्हीं के साथ खिलवाड़ कर अपने जीवन के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। बीते तीन दशक इसके सबूत हैं कि उनमें हमने तकरीबन एक अरब वन मानवीय स्वार्थ के चलते खत्म कर दिये हैं। दुख इस बात का है कि जंगल बचाने की लाख कोशिशों के बावजूद दुनिया में वनों की कटाई में और तेजी आई है। मौजूदा दौर की हकीकत यह है कि दुनिया में हर मिनट 21. 1 हैक्टेयर में फैले जंगलों का खात्मा हो रहा है। देखा जाये तो जल, जंगल और जमीन के मुद्दे आपस में गहरे तक जुड़े हुए हैं। प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन आज की सबसे बड़ी जरूरत है। तभी सामुदायिक प्रयासों को प्रोत्साहित कर धरती को बचाया जा सकता है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं पर्यावरणविद हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

नवाचार

राव इंद्रजीत सिंह

डिजिटल क्रांति से आर्थिक बदलाव

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शन में विकसित एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) ने भारतीयों के लेन-देन के तरीके में क्रांति ला दी है। किसी मित्र को पैसे भेजने के एक अनूठे तरीके के रूप में शुरू किया गया यह तरीका शीघ्र ही छोटे व्यवसायों, सब्जी विक्रेताओं और गिग वर्कर्स की जीवनरेखा बन गया। आज, भारत में प्रति माह 17 बिलियन से अधिक यूपीआई के माध्यम से लेनदेन होते हैं। जैसे-जैसे भारत अपने 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, नए आयाम उभर रहे हैं, एआई-सक्षम शासन, विकेन्द्रीकृत वाणिज्य, और बहुभाषी, मोबाइल-प्रथम डिजिटल सेवाएं जो सबसे गरीब व्यक्ति तक पहुंच सकती हैं।

पिछले एक दशक में भारत में एक ऐसी डिजिटल क्रांति आई है जो असाधारण है। जो प्रक्रिया लक्षित प्रौद्योगिकीय अंतःक्षेपों की एक श्रृंखला के रूप में शुरू हुई थी, वह अब एक व्यापक परिवर्तन के रूप में विकसित हो चुकी है, जो भारतीय जीवन के लगभग हर पहलू जैसे अर्थव्यवस्था, शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, वाणिज्य, और देश के कोने-कोने में बसे किसानों और छोटे उद्यमियों के जीवन को भी प्रभावित कर रही है। यह यात्रा आकस्मिक नहीं थी। इसे भारत सरकार द्वारा ठोस नीति निर्धारण, अंतरमंत्रालयी सहयोग और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से सावधानीपूर्वक प्रबंधित किया गया है। जब संबद्ध मंत्रालयों जैसे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), वित्त मंत्रालय (एमओएफ), कृषि मंत्रालय, और अन्य मंत्रालयों ने बड़े पैमाने में ज़मीनी स्तर पर परियोजनाओं को पूरा किया तो दूसरी ओर नीति आयोग ने अभिसरण को बढ़ावा देकर, विचारों को नेतृत्व देकर, और स्केलेबल, नागरिक-प्रमुखता वाले नवाचारों की ओर प्रणाली को प्रेरित कर नीति इंजन का काम किया है।

जन धन-आधार-मोबाइल (जेएएम) ट्रिनिटी की शुरुआत के साथ इसमें एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है। लगभग 55 करोड़ बैंक खातों के खोलने के साथ-साथ, करोड़ों लोगों को, जो पहले वित्तीय प्रणाली की पहुंच से बाहर थे, उन्हें अकस्मात बैंकिंग व्यवस्था और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तक पहुंच प्राप्त हुई है। ओडिशा के एक छोटे से गांव में पहली बार बिना बिचौलिए की सहायता से एक सिंगल मदर को कल्याणकारी लाभ सीधे उनके खाते में प्राप्त करने में सक्षम बनाया गया। उनकी कहानी भारत भर के करोड़ों लोगों की कहानी बन गई है। यह वृहद वित्तीय समावेशन आंदोलन वित्त मंत्रालय के समर्थन और आधार तथा मोबाइल पैठ की सक्षम सहायता से अगला कदमः एक वित्तीय-प्रौद्योगिकी विस्फोट का आधार बना। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शन में विकसित एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) ने भारतीयों के लेन-देन के तरीके में क्रांति ला दी है। किसी मित्र को पैसे भेजने के एक अनूठे तरीके के रूप में शुरू किया गया यह तरीका शीघ्र ही छोटे व्यवसायों, सब्ज़ी विक्रेताओं और गिग वर्कर्स की जीवनरेखा बन गया। आज, भारत में प्रति माह 17 बिलियन से अधिक यूपीआई के माध्यम से लेनदेन होते हैं, और यहां तक कि सड़क किनारे के विक्रेता वाले भी एक साधारण क्यूआर कोड के ज़रिए डिजिटल भुगतान स्वीकार कर रहे हैं। इसी दौरान, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत भारत के डिजिटल अवसंरचना के मुख्य तंत्र को धीरे-धीरे और निरंतरता से तैयार किया जा रहा है। भारतनेट जैसी परियोजनाओं ने दो लाख से अधिक ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुंचाया है, जबकि इंडिया स्टैक ने कागज़-रहित, उपस्थिति-रहित और नकदी-रहित सेवाओं का ढाँचा तैयार किया। डिजी-लॉकर ने छात्रों को अपने प्रमाणपत्र डिजिटल रूप में रखने और ई-हस्ताक्षर ने महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों के लिए दूरस्थ प्रमाणीकरण प्रदान किया। डिजी-यात्रा एक अग्रणी पहल है जो चेहरे के पहचान की तकनीक का उपयोग करके निर्बाध, कागज़-रहित और संपर्क-रहित हवाई यात्रा को संभव बनाती है।

यह त्वरित चेक-इन, बेहतर यात्री अनुभव और बेहतर हवाई अड्डे की क्षमता में सुधार सुनिश्चित करती है, साथ ही विकेंद्रीकृत पहचान प्रबंधन के माध्यम से डेटा गोपनीयता की सुरक्षा भी करती है। यह भारतीय विमानन के भविष्य की तैयारी और यात्री-अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये मात्र ऐप ही नहीं हैं - ये एक डिजिटल गणराज्य की आधारशिला हैं। डिजिटल गवर्नेंस ने भी गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) के शुभारंभ के साथ बड़ी उछाल लगाई है। सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए डिज़ाइन किए गए, जेमने 1.6 लाख से अधिक सरकारी क्रेताओं को 22 लाख से अधिक विक्रेताओं से जोड़ा है। राजस्थान के एक छोटे हस्तशिल्प विक्रेता के लिए, इसका अभिप्राय सरकारी संविदाओं तक पहुंच प्रदान करना था जो पहले अकल्पनीय था। कृषि क्षेत्र, जिसे प्रायः परिवर्तन के प्रतिरोधी के रूप में देखा जाता है, ने भी डिजिटल साधनों को अपनाना शुरू कर दिया है। पीएम-किसान जैसे प्लेटफ़ॉर्म ने यह सुनिश्चित किया कि आय सहायता किसानों तक सीधे पहुंचे। ई-नैम ने राज्यों की कृषि मंडियों को जोड़ा, जिससे किसानों को अपनी उपज के बेहतर दाम मिल सकें। डिजिटल मृदा स्वास्थ्य कार्ड ने उन्हें यह समझने में मदद की कि उन्हें कौन सी फसलें उगानी चाहिए और अपनी भूमि में कौन से पोषक तत्वों का प्रयोग करना चाहिए। झारखंड के ग्रामीण-क्षेत्रों में, स्थानीय उद्यमियों द्वारा संचालित सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) उनके लिए एक प्रकार से डिजिटल जीवन रेखा बन गए, जो टेली-मेडिसिन से लेकर बैंकिंग और कौशल विकास कार्यक्रमों तक, हर चीज की पेशकश करते हैं। महामारी भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए एक कठिन परीक्षा थी जिसमें हम बखूबी सफल हुए। स्कूल बंद होने के बावजूद, दीक्षा और स्वयं जैसे प्लेटफॉर्मों ने यह सुनिश्चित किया कि पढ़ाई अनवरत चलती रहे। इसके साथ ही, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने अपना आकार लिया, जिससे नागरिकों को एक डिजिटल आईडी के माध्यम से अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंच प्राप्त हुई और अस्पतालों एवं राज्यों में एक सहज वातावरण बन सका।

वाणिज्य में भी एक शांत क्रांति देखी गई। डीपीआईआईटी की एक पहल, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) अब छोटी किराना दुकानों और हथकरघा बुनकरों को बड़ी ई-कामर्स कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बना रही है। डिजिटल कॉमर्स के कार्यों को एकीकृत करके, ओएनडीसी प्रतिस्पर्धा के मैदान को समतल कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छोटे व्यवसाय आसानी से लॉजिस्टिक्स, भुगतान और ग्राहक प्रतिक्रिया प्रणालियों तक पहुँच सकें। नीति आयोग की अभिसरण भूमिका-मंत्रालयों, राज्यों, स्टार्टअप्स और उद्योग जगत को एकजुट करना है, जो सुनिश्चित करता है कि डिजिटल सार्वजनिक वस्तुएं अंतर-संचालनीय, समावेशी और स्केलेबल हों। जैसे-जैसे भारत अपने 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, नए आयाम उभर रहे हैं, एआई-सक्षम शासन, विकेन्द्रीकृत वाणिज्य, और बहुभाषी, मोबाइल-प्रथम डिजिटल सेवाएं जो देश के सबसे गरीब व्यक्ति तक पहुंच सकती हैं। लेकिन यह सिर्फ़ एक सरकारी सफलता से जुड़ी कहानी नहीं है। यह एक राष्ट्र की कहानी है, करोड़ों नागरिकों की कहानी है जिन्होंने बदलाव को अपनाया, उद्यमियों की कहानी है जो डिजिटल रेल पर आगे बढ़े, और स्थानीय लीडरों की कहानी है जिन्होंने सेवा वितरण की नई कल्पना की। भारत का डिजिटल दशक सिर्फ़ तकनीक का नहीं है, यह बदलाव का दशक भी है और यह कहानी का अभी प्रारंभिक चरण ही है।

(लेखक केंद्रीय राज्यमंत्री हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

निंदा का परित्याग

संकलित
दर्शन

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में निर्वहन के लिए व्यक्ति के सामाजिक गुणों का अत्यंत महत्व है। गुणी व्यक्ति को प्रत्येक जगह सम्मान की प्राप्ति होती है। संसार के प्रत्येक प्राणी में कुछ गुण तो कुछ अवगुण पाए जाते हैं, परंतु कुछ लोग हैं जो दूसरे के अवगुणों को ही देखते हैं। वे किसी भी सकारात्मक पक्ष में नकारात्मकता देखने के अभ्यस्त हो जाते हैं। प्रायः ऐसे लोगों में निंदा की प्रवृत्ति पाई जाती है। वे ऐसा करके खुद को समाज में श्रेष्ठ एवं दूसरे को नीचा साबित करना चाहते हैं। निंदा एक नशे की भांति है, जो एक बार इसका आदी हो गया, वह दिन-प्रतिदिन इसके पाश में जकड़ता चला जाता है। मनीषियों ने निंदा को दुर्व्यसन के समान माना है, जो निंदा करने वाले व्यक्ति को अंदर ही अंदर नैतिक रूप से समाप्त करती रहती है। एक बार एक आचार्य अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान कर रहे थे। शिक्षा प्राप्ति के दौरान एक शिष्य अन्य शिष्यों की ओर संकेत करते हुए आचार्य से कहने लगा कि 'वे अपना कार्य सही से नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है इन लोगों को कार्य करना ही नहीं आता।' आचार्य बोले, 'तुमको छोड़ अन्य सारे शिष्य सही से कार्य कर रहे हैं।' इस पर शिष्य असहज हो गया। उसने आचार्य से पूछा, 'वह कैसे?' आचार्य बोले, 'क्योंकि वे लोग अपने कार्य में संलग्न हैं, किंतु तुम अपने कार्य पर ध्यान न देकर, दूसरों के कार्य की निंदा करने में अपने समय की बर्बादी कर रहे हो।'

जब कोई झूठा आरोप लगे तो धैर्य न छोड़ें

संकलित
प्रेरणा

द्वारका में एक सूर्य भक्त था सत्राजित। उसे सूर्य देव ने स्यमंतक नाम की चमत्कारी मणि दी थी। ये मणि रोज बीस तोला सोना उगलती थी। एक दिन श्रीकृष्ण ने सत्राजित से कहा कि आप ये मणि राजकोष में देंगे तो इससे मिले धन से प्रजा की अच्छी देखभाल हो सकेगी। सत्राजित ने श्रीकृष्ण को मणि देने से मना कर दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद सत्राजित के भाई प्रसेनजित ने मणि चुरा ली। प्रसेनजित मणि लेकर जंगल में भाग गया। जंगल में एक शेर ने प्रसेनजित को मार दिया और खा गया। मणि जंगल में ही गिर गई। सत्राजित को जब प्रसेनजित और अपनी मणि नहीं मिली तो उसने श्रीकृष्ण पर आरोप लगा दिया कि कृष्ण ने ही मेरी मणि चुराई है और मेरे भाई की हत्या कर दी है। श्रीकृष्ण पर चोरी और हत्या का कलंक लग गया। श्रीकृष्ण आरोप को गलत साबित करने के लिए जंगल की ओर चल दिए। जंगल में श्रीकृष्ण को शेर के पैरों के निशान दिखे।श्रीकृष्ण समझ गए कि प्रसेनजित को शेर ने मार दिया है और मणि यहीं कहीं गिर गई है। श्रीकृष्ण मणि खोजते हुए एक गुफा में पहुंच गए। गुफा में जामवंत रहते थे। श्रीकृष्ण ने मणि मांगी तो जामवंत ने नहीं दी। इसके बाद दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध में श्रीकृष्ण जीत गए। इसके बाद जामवंत ने मणि श्रीकृष्ण को दे दी और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी भगवान के साथ कर दिया। द्वारका लौटकर श्रीकृष्ण ने वह मणि जामवंत से लेकर सत्राजित को दे दी और पूरी सच्चाई बता दी।

अंतर्मन

आज की पाती

साइबर क्राइम के बढ़ते कदम रोकने होंगे

जिस गति से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, यह आम आदमी के लिए एक मुसीबत बन गई है और लुटेरों के लिए जैसे मनोरंजन और लॉटरी लगी है। हैरानी इस बात की है कि इस मर्ज की दवा किसी के पास नहीं। किसी को जब चाहें, अपराधी बंधक बना कर सब कुछ लूट लेते हैं और उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। देश में बड़ी संख्या में लोग इस क्राइम के शिकार हो रहे हैं। यह अत्यंत गंभीर समस्या है और इससे आंख नहीं फेरी जा सकती। जहां डिजिटलाइजेशन के अनेक लाभ हैं, इससे कई गुणा हानियां भी हैं। द्वंद्व यह है कि इसे अपनाएं या नहीं? इस पर सभी को गंभीरता एवं शीघ्रता से समाधान निकालना होगा। आज नहीं तो कल हर कोई इसका शिकार होगा। *- अशोक साहू, कोड़ागांव*

करंट अफेयर

टेक्सास में शरिया कानून पर प्रतिबंध की घोषणा

टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने कहा है कि उनके प्रांत ने इस्लामी शरिया कानून के क्रियान्वयन पर प्रतिबंध लगा दिया है और निवासियों से व्यवसायों या व्यक्तियों पर 'शरिया अनुपालन' थोपने के किसी भी प्रयास की सूचना देने का आग्रह किया। एबॉट की यह टिप्पणी ह्यूस्टन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद आई है, जिसमें एक मुस्लिम धर्मगुरु लाउडस्पीकर के माध्यम से दुकानदारों से शराब, सूअर का मांस या लॉटरी टिकट नहीं बेचने का आग्रह करते हुए दिख रहा है। गवर्नर ने इस घटना को उत्पीड़न बताया और कहा कि टेक्सास सार्वजनिक जीवन में धार्मिक आचार संहिता लागू करने के प्रयासों को बर्दाश्त नहीं करेगा।

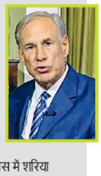

एबॉट ने मंगलवार को 'एक्स' पर पोस्ट किया, 'मैंने टेक्सास में शरिया कानून और शरिया कानूनी प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। किसी भी व्यवसाय और किसी भी व्यक्ति को ऐसे मूर्खों से डरना नहीं चाहिए।' उन्होंने कहा, 'यदि यह व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति शरिया अनुपालन थोपने का प्रयास करता है, तो इसकी सूचना स्थानीय कानून प्रवर्तन या टेक्सास लोक सुरक्षा विभाग को दें।'

ऑफ बीट

'इंटरवल रनिंग' भी सेहत के लिए बेहद उपयोगी

दौड़ना न केवल बीमारियों से बचाव करता है, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है बल्कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी धीमा करता है। इंटरवल रनिंग वास्तव में हाई-इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग (एचआईआईटी) का एक हिस्सा है, जिसमें तीव्र गति से दौड़ने के छोटे सत्रों के बाद विश्राम या धीमी गति से दौड़ने का समय शामिल होता है। यह पद्धति पिछले कुछ वर्षों में टबाटा और क्रॉसफिट जैसे वर्कआउट्स के ज़रिये लोकप्रिय हुई है। कैसे काम करता है इंटरवल रनिंग : एचआईआईटी में, उदाहरण के तौर पर, 30 सेकंड तक तेज़ गति से दौड़ने के बाद 30 सेकंड का आराम किया जाता है। यह प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है। इसी सिद्धांत को दौड़ने में शामिल करते हुए, "10-20-30 विधि" अपनाई जा सकती है, जिसमें पहले 30 सेकंड तक चलना या हल्की दौड़, फिर 20 सेकंड तक मध्यम गति की दौड़ और फिर 10 सेकंड की तेज़ स्प्रिंटिंग यानी तेज गति से दौड़ शामिल होती है। फार्टलेक स्वीडिश शब्द है जिसका अर्थ 'स्पीड प्ले' होता है। व्यायाम के लिए यह विधि भी एक आसान तरीका है जिसमें धीमी दौड़ के बीच-बीच में कुछ सेकंड की तेज़ दौड़ शामिल होती है।

ट्रेंड

रिपोर्ट कार्ड की राजनीति

पहले राजनीति सिर्फ़ काम न करने, परिवार-केंद्रित हितों, भ्रष्टाचार, जातिवाद और तुष्टिकरण पर केंद्रित होती थी। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम, जवाबदेही और रिपोर्ट कार्ड की राजनीति को जन्म दिया है।

- जेपी नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री

ग्लोबल बोर्ड का स्वागत

एचएसबीसी ग्रुप चेयरमैन सर मार्क टकर के नेतृत्व में ग्लोबल बोर्ड का स्वागत करते हुए बेहद खुशी हो रही है। बोर्ड से आग्रह किया कि वे विकास और समृद्धि के सह-निर्माण में हमारे साथ साझेदारी करें और भारत को वैश्विक परिवर्तन का केंद्र बनाएँ।

-पीयूष गोयल, केंद्रीय उद्योग मंत्री

राजभाषा का संवर्धन

हिंदी सिर्फ़ भाषा नहीं, यह हमारी संस्कृति और सभ्यता की पहचान है। आप सभी देशवासियों को 'हिंदी दिवस' की हार्दिक शुभकामनाएँ। आइये, हम हमारी मातृभाषा और राजभाषा के संवर्धन का संकल्प लें।

- अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय मंत्री

दिल से खेलिए

टीम इंडिया शोर-शराबे और राजनीति को दिल पर मत लीजिए। आपके सारे फैन और देशवासी मैदान और रणभूमि का फर्क समझते हैं। दबाव लेने नहीं, बनाने मैदान में जाइए ; स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलिए, बाकी देश आपके साथ मजबूती से खड़ा है। दिल से खेलिए, दिल भी जीतिए !

-डॉ. रामदास अठावले, राज्यसभा सांसद

अपने विचार
हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid